सत्यमेव जयते



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

इंदिरा आवास योजना

की निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार (सिविल)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

2014 की प्रतिवेदन संख्या 37

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

इंदिरा आवास योजना

की निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार (सिविल)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

2014 की प्रतिवेदन संख्या 37

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ
	प्राक्कथन	v
	कार्यकारी सारांश	vii
अध्याय 1	**इंदिरा आवास योजना - एक विहंगावलोकन**	01
अध्याय 2	**लेखापरीक्षा दृष्टिकोण तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संगठन**	11
2.1	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	11
2.2	लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संगठन	15
2.3	आभार प्रकट	15
अध्याय 3	**लाभार्थियों की पहचान एवं चयन**	16
3.1	जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा मकानों की कमी का आकलन	16
3.2	स्थायी प्रतीक्षा सूचियों तथा वार्षिक योजनाओं की तैयारी के लिए प्रक्रिया	18
3.3	लाभार्थी का चयन	21
3.4	घरों का आवंटन	35
3.5	वस्तु सूची निर्माण	38
अध्याय 4	**घरों का निर्माण तथा गुणवत्ता**	40
4.1	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि	40
4.2	अपूर्ण घरों पर निष्फल व्यय	41
4.3	ठेकेदारों/विभाग द्वारा इं.आ.यो. के घरों का अनियमित निर्माण	48
4.4	इं.आ.यो. के घरों के रुपरेखा प्रकार की अस्वीकृति	49
4.5	निर्माण कार्य को समन्वित करने हेतु समिति का गठन	50
4.6	इं.आ.यो. के घरों की लागत प्रभावकारिता तथा स्थायित्व	51
4.7	प्रशिक्षण सेमीनार तथा कार्यशालाएँ	51
4.8	गुणवत्ता निरीक्षण/तकनीकी पर्यवेक्षण का अभाव	53
अध्याय 5	**वित्तीय प्रबंधन**	57
5.1	निधियन एवं लागत - हिस्सेदारी	57

	विषय	पृष्ठ
5.2	अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए निधियों को चिन्हित करना और उपयोग में लाना	58
5.3.	केन्द्रीय आवंटन से कटौती	62
5.4	प्रयुक्त निधियों के अधिक बयानी के कारण ₹ 163.14 करोड़ का अतिरिक्त निर्गम	63
5.5	वित्तीय रिपोर्टिंग में असंगति	63
5.6	अव्ययित शेषों पर ब्याज का परिकलन न करना	65
5.7	बैंक खातों का संचालन	67
5.8	राज्य अंश का कम निर्गम	69
5.9	राज्य अंश के कार्यान्वयन अभिकरणों के निर्गम में विलम्ब	70
5.10	निधियों का निष्क्रिय पड़े रहना	72
5.11	उपयोगिता प्रमाण पत्रों में बढ़ाया हुआ व्यय	73
5.12	खातों का गैरसुमेलन	74
5.13	लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र	74
5.14	गैर अनुमेय मदों पर निधियों का विपथन एवं व्यय	76
5.15	प्राकृतिक आपदाओं के लिए निधियों को चिन्हित करना	76
5.16	अलेखांकित व्यय या निधियों का दुर्विनियोजन	79
5.17	लाभार्थियों को सहायता का भुगतान	80
5.17.1	गैर-कंपित आधार पर सहायता का भुगतान	83
5.17.2	लाभार्थियों को सहायता के भुगतान/गैर भुगतान में विलम्ब	83
5.17.3	लाभार्थियों को सहायता से ₹ 139.37 करोड़ की अप्राधिकृत कटौती	84
5.17.4	सहायता के भुगतान में अनियमितताएँ	85
5.17.5	नगद/धारक चैकों/सेल्फ चैक निर्माण समिति/सरपंचों के माध्यम से किये गये भुगतान	86
5.17.6	लाभार्थियों को दुहरा/अतिरिक्त भुगतान	86
अध्याय 6 अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण		**88**
6.1	प्रस्तावना	88
6.2	अभिसरण कार्यों का अभाव	88
6.3	मासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से मॉनीटरिंग का अभिसरण	97

	विषय	पृष्ठ
6.4	अभिसरण हेतु जागरूकता की कमी	101
6.5	निष्कर्ष	101
अध्याय 7	**मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन**	**104**
7.1	मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन रूपरेखा	104
7.2	केन्द्रीय स्तर पर मॉनीटरिंग	105
7.3	राज्य स्तर मॉनीटरिंग	111
7.4	प्रारंभिक स्तर पर ध्यानपूर्वक मॉनिटरिंग	118
7.5	प्रभाव का मूल्यांकन	119
अध्याय 8	**वासभूमि स्थलों की योजना**	**121**
8.1	वासभूमि स्थलों की योजना का कार्यान्वयन	121
8.2	वासभूमि के अंतर्गत अतिरिक्त घरों हेतु प्रोत्साहन	124
अध्याय 9	**संयुक्त भौतिक निरीक्षण**	**130**
9.1	प्रस्तावना	130
9.2	लाभार्थियों की जागरूकता का स्तर	131
9.3	भुगतान का माध्यम	133
9.4	इं.आ.यो. सूचना पट्ट का प्रदर्शन	133
9.5	घर के निर्माण में ठेकेदार की नियुक्ति	134
9.6	घरों में सुविधाएँ	134
9.7	सरकार/गै.स.सं. द्वारा प्रदत विशेषज्ञ राय/सूचना	136
9.8	अभिसरण	138
9.9	जी.बी.नि. से सहायता	139
9.10	घर रुपरेखा प्रकार की गुणवत्ता तथा वांछनीय विशिष्टताएँ	140
9.11	वासभूमि स्थलों की योजना	141
अध्याय 10	**निष्कर्ष**	**142**
	अनुबंध	**145**

प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष हेतु इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सामान्य तथा सामाजिक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, संघ सरकार की इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो.) के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वह है जो अप्रैल 2008 से मार्च 2013 की अवधि हेतु नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए थे।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो.), ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जो ग.रे.नी. परिवारों को जो या तो आवासहीन है या उनके पास आवास की अपर्याप्त सुविधाएं हैं के लिए सुरक्षित तथा टिकाऊ घर के निर्माण में सहायता प्रदान कर रही है। सभी जरूरतमंदों को आश्रय प्रदान करने का यह प्रयास सरकार की बड़ी कार्यनीति का भाग है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समाज के वंचित भाग के लिए ग्रामीण आवास मुहैया कराना गरीबी के विरुद्ध एक मुख्य उपाय है। आवास की पहचान न केवल एक आश्रय तथा एक रिहायशी स्थान के रूप में ही नहीं होती है अपितु एक ऐसी परिसम्पत्ति है जो कि आजीविका में सहायक है तथा सामाजिक स्थिति के प्रतीक के रूप में भी होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को उनकी रिहायशी इकाईयों के निर्माण/सुधार में सहायता करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गांरटी कार्यक्रम (ग्रा.रो.गा.का.) की उप-योजना के रूप में इं.आ.यो. का आरंभ 1985 में किया गया था। इं.आ.यो. अप्रैल 1989 से जवाहर रोजगार योजना (ज.रो.यो.) का एक भाग थी तथा जनवरी 1996 से एक स्वंतत्र योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया था। इं.आ.यो. के अंतर्गत लाभार्थी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर, गरीबी रेखा से नीचे (ग.रे.नी.) की श्रेणी के अल्पसंख्यक तथा अन्य गरीबी रेखा से नीचे गैर-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ग्रामीण परिवार, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों/अर्धसैनिक बलों की विधवाओं तथा करीबी रिश्तेदार (उनके आय मापदण्ड पर विचार किए बिना), भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य जो अन्य शर्तों को पूरा करते हैं, अर्थात लाभार्थी

बेघर होना चाहिए अथवा कच्चा घर होना चाहिए तथा वह गाँव में रह रहा हो, हैं।

हमने इस लेखापरीक्षा को संचालित क्यों किया?

हमने नवम्बर 2001 और जुलाई 2002 के मध्य में अप्रैल 1997 से मार्च 2002 की अवधि को शामिल करते हुए इं.आ.यो. के साथ भारत सरकार की अन्य ग्रामीण आवासीय योजनाओं की समीक्षा की तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को 2003 के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.3 में शामिल किया था। तब से, इं.आ.यो. के व्यय में बहुत वृद्धि हुई है। 2008-09 से 2012-13 के दौरान इं.आ.यो. का केन्द्रीय अंश ₹45,838 करोड़ था। इं.आ.यो. में प्रगति की समीक्षा की दृष्टि से, हमने इं.आ.यो. के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में अप्रैल 2008 से मार्च 2013 की अवधि को शामिल किया तथा इसमें 27 राज्यों तथा चार संघ शासित क्षेत्रों के 168 जिलों, इन जिलों के अंतर्गत 392 ब्लॉकों तथा इन ब्लॉकों के अंतर्गत 2,960 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया गया था।

मुख्य निष्कर्ष

लाभार्थियों की पहचान एवं चयन

हमने पाया कि आवासों की कमी का आकलन मुख्य रूप से ग्रामीण आवास पर योजना आयोग के अंतर्गत कार्यदल के अनुमानों पर आधारित था। 14 राज्यों अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल** तथा **पंजाब (तीन जिलों)** में आवासों की वास्तविक कमी का आकलन नहीं किया गया था। तीन राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मेघालय** तथा **लक्षद्वीप** में स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूचियों को अनुरक्षित नहीं किया गया था।

(पैरा 3.1 एवं 3.2.1)

हमने यह भी पाया कि बहुत से अयोग्य लाभार्थियों का चयन किया गया था। 12 राज्यों में, 36,751 गैर-ग.रे.नी. परिवारों को ₹89.15 करोड़ की सहायता प्रदान की गई थी। 11 राज्यों में, 10,184 अयोग्य लाभार्थियों का चयन किया गया था तथा ₹31.73 करोड़ उन्हें अदा किए गए थे। सात राज्यों में, 33,536 लाभार्थियों का चयन स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची के बाहर से किया गया था तथा ₹138.02 करोड़ की सहायता अदा की गई थी। आठ राज्यों में, 1,654 लाभार्थियों, जिन्होंने ₹5.37 करोड़ की सहायता प्राप्त की थी, के पास पहले से पक्के घर थे। आठ राज्यों में, 5,824 लाभार्थियों का एक से अधिक बार चयन किया गया था तथा उनको ₹14.67 करोड़ का भुगतान किया गया था। छह राज्यों में, परिवार के महिला सदस्यों के नाम पर रिहायशी इकाईयों के आवंटन को प्राथमिकता नहीं दी गई थी।

(पैरा 3.3 तथा 3.4)

आवास का निर्माण एवं गुणवत्ता

ग्रामीण आवास पर योजना आयोग के अंतर्गत कार्यदल ने 2008-13 हेतु इं.आ.यो. के अंतर्गत 170 लाख आवासों के निर्माण के लक्ष्य निर्धारित किए थे। हालांकि, इस अवधि के दौरान केवल 128.92 लाख मकानों (कार्यदल लक्ष्य के प्रति 75.84 *प्रतिशत*) का निर्माण हुआ था जो कि यह दर्शाता है कि इं.आ.यो. देश में आवासों की कमी को पूरी तरह दूर नहीं कर पाई थी।

(पैरा 4.1)

लेखापरीक्षा ने कई मामलों में आवासों के पूर्ण होने में दो वर्षों से अधिक के विलंब के मामले पाए थे। नौ राज्यों अर्थात् **असम, बिहार, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय** एवं **राजस्थान** के 48 चयनित जिलों में, दो वर्षों से अधिक की चूक के बावजूद 61,293 आवास अपूर्ण रहे जिसके परिणामस्वरूप इन अपूर्ण मकानों के संबंध में ₹150.22 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले जिसमें लाभार्थियों द्वारा पूरी राशि प्राप्त करने के पश्चात भी इं.आ.यो. के आवास खाली पड़े रहे थे, ऐसे

मामले जहां लाभार्थियों को प्रथम किस्त मिलने के पश्चात न तो दूसरी किस्त का दावा किया गया था न ही उसका भुगतान उन्हें किया गया था; इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के उल्लंघन मे ठेकेदारों को लगाए जाना; आदि मामले थे।

(पैरा 4.2 एवं 4.3)

13 राज्यों अर्थात् **बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, ओडीशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड** एवं **पश्चिम बंगाल** के 91 जिलों के 214 ब्लॉकों के अंतर्गत 1,639 ग्रा.पं. (2,960 चयनित ग्रा.पं. का 55.37 *प्रतिशत*) में किसी स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों/तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किसी गुणवत्ता निरीक्षणों/तकनीकी पर्यवेक्षणों को संचालित नहीं किया गया था। हमने निर्माणों की खराब गुणवत्ता तथा निर्माण हेतु घटिया सामग्री का उपयोग पाया था।

(पैरा 4.8)

वित्तीय प्रबंधन

हमने पाया कि राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग की धीमी गति/कम उपयोग के कारण उनको देय केन्द्रीय आवंटन में से ₹2,451.84 करोड़ की कटौती की गई थी। केन्द्रीय अंश में कटौती के कारण राज्यों का अनुरूप अंश, जिसे उनके द्वारा दिया जाना चाहिए था, ₹810.08 करोड़ परिकलित किया गया था। इसका परिणाम 7.25 लाख लाभार्थियों को सहायता की अस्वीकृति में हुआ।

(पैरा 5.3)

बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान तथा **उत्तर प्रदेश** में चयनित जिलों, ब्लॉकों तथा ग्रा.पं. में इं.आ.यो. निधियों को रखने हेतु राष्ट्रीयकृत अनुसूचित अथवा सहकारी बैंक अथवा डाकघर में एक विशिष्ट अलग बैंक खाते के अनुरक्षण के प्रति कई बैंक खाते (2 से 20 तक) संचालित किए जा रहे थे। 11 राज्यों में चयनित जिलों (24) तथा आठ ब्लॉको में इं.आ.यो. निधियों को चालू खाते में अथवा व्यक्तिगत बही खाते में रखा गया

था। चालू खातों में निधियों को रखने के परिणामस्वरूप छः राज्यों (**असम, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, ओडीशा, पंजाब** तथा **राजस्थान**) में ₹4.22 करोड़ की ब्याज की हानि हुई।

(पैरा 5.7)

हमने 13 राज्यों एवं दो सं.शा.क्षे. में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रति ₹37.12 करोड़ की इं.आ.यो. निधियों का विपथन तथा सात राज्यों में अस्वीकार्य मदों पर ₹2.20 करोड़ का व्यय भी पाया था।

हमने **असम, बिहार** तथा **झारखंड** में ₹4.91 करोड़ के दुर्विनियोजन के मामले तथा नौ राज्यों में ₹9.76 करोड़ के संदिग्ध दुर्विनियोजन के मामले पाए।

तीन राज्यों में लाभार्थियों को देय भुगतानों में से प्रशासनिक प्रभारों, धुंआ रहित चुल्हों/स्वच्छ शौचालय/इं.आ.यो. प्रतीक चिन्ह आदि के गैर-निर्माण/गैर-स्थापना के कारण ₹139.37 करोड़ की अप्राधिकृत कटौती तथा छः राज्यों में ₹19.07 करोड़ का कम भुगतान था।

तीन राज्यों में इं.आ.यो. के लाभार्थियों को ₹7.16 करोड़ का दोहरा/अधिक भुगतान पाया गया था।

(पैरा 5.14/5.16 एवं 5.17)

अभिसरण

यह योजना इं.आ.यो. अभिसरण गतिविधियों के साथ अन्य भा.स. की योजनाओं अर्थात् मकानों में स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए कुल स्वच्छता अभियान, बिजली प्रदान करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना; पेय जल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम; ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए ब्याज की अंतर दर योजना, ग्रामीण ग.रे.नी. परिवारों तथा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए बीमा योजनाएं तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के

अंतर्गत जॉब कार्ड परिकलित करती है ताकि इन योजनाओं के अंतर्गत संभावित लाभों को इं.आ.यो. लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान देशभर में 107.58 लाख मकानों में से केवल 25.48 लाख (23.68 *प्रतिशत*) में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण हुआ था जिससे 76.32 *प्रतिशत* मकानों की कमी हुई। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 21 राज्यों में, मुफ्त विद्युत कनेक्शन प्रदान करने हेतु इं.आ.यो. को रा.गा.ग्रा.वि.यो. के साथ अभिसरित नहीं किया गया था। 24 राज्यों/सं.शा.क्षे. में, इं.आ.यो के लाभार्थी रा.ग्रा.ज.आ.का.पी. के साथ अभिसरण के लाभों से वंचित थे।

राज्यों/जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा लाभार्थियों को क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय के प्रयासों के अभाव के कारण 13 राज्यों में लाभार्थियों द्वारा डी.आर.आई. योजना के अंतर्गत ऋण सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया था।

21 राज्यों/सं.शा.क्षे. में, ग्रामीण ग.रे.नी. परिवारों के लिए जन श्री बीमा तथा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों हेतु आम आदमी बीमा योजनाओं के अभिसरण को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(पैरा 6.2)

मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन

केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग अपूर्ण थी। राष्ट्रीय स्तर मॉनीटरों (रा.स्त.मॉ.) के माध्यम से केन्द्रीय स्तर पर नियमित मॉनीटरिंग में वर्ष 2008-09 से 2012-13 में देश के सभी जिलों, को आवृत्त नहीं कर सकी थी, जहाँ इं.आ.यो. कार्यान्वित की जा रहीं थी तथा रा.स्त.मॉ. रिर्पोटों पर अप्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई हुई थी।

मंत्रालय ने इं.आ.यो. को मॉनीटर करने के लिए लाभार्थी-वार डाटा रखने के लिए *आवाससॉफ्ट* नामक वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) की शुरूआत की थी। यह साधन प्रबंधन, रिर्पोटों की तैयारी, जारी की गई निधियों

पर नजर रखने, आवासों के निर्माण में प्रगति तथा सभी परिकलित लाभों के अभिसरण के लिए था। यद्यपि 15 राज्यों/सं.शा.क्षे. ने *आवाससॉफ्ट* का परिचालन किया था लेकिन इसे पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं बनाया जा सका था। इसके अतिरिक्त, ग्रा.पं./ब्लॉक/जि.ग्रा.वि.अ. स्तर पर अपलोड किए गए डाटा की यथार्थता की जांच करने के लिए कोई विशिष्ट तंत्र नहीं था।

15 राज्यों/सं.शा.क्षे. में राज्य स्तर सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समितियों (रा.स्त.स.मॉ.स.) में मंत्रालय के प्रतिनिधि/नामांकित व्यक्ति ने भाग नहीं लिया था। 25 राज्यों/सं.शा.क्षे. में, 2008-13 के दौरान केवल एक से 10 रा.स्त.स.मॉ.स. की बैठकें हुई थी।

(पैरा 7.2 एवं 7.3)

22 राज्यों में, बुनियादी स्तर पर इं.आ.यो. के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के लिए इं.आ.यो. की सामाजिक लेखापरीक्षा को संचालित नहीं किया गया था।

(पैरा 7.4.1)

वासभूसि स्थलों हेतु योजना

इं.आ.यो. के भाग के रूप में, उन ग्रामीण ग.रे.नी. परिवारों, जिनके पास न तो कृषि भूमि है और न ही मकान स्थल है, को वासभूमि स्थलों को प्रदान करने के लिए अगस्त 2009 में एक योजना की शुरूआत की गई थी। ₹1,000 करोड़ के प्रस्तावित केन्द्रीय आवंटन के प्रति इन राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर नौ राज्यों को ₹347.47 करोड़ जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009-13 के दौरान 17 राज्यों/सं.शा.क्षे. अर्थात् **असम, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव** तथा **लक्षद्वीप** में यह योजना कार्यान्वित नहीं की गई थी। राज्यों द्वारा भूमि की पहचान/कब्जे के बिना ही **आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र,**

राजस्थान एवं **उत्तर प्रदेश** को योजना के अंतर्गत निधियां जारी कर दी गई थी।

(पैरा 8.1)

अनुशंसाओं का सारांश

1. राज्यों में आवासों की कमियों का आवधिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि इं.आ.यो. के अंतर्गत निधियों का आवंटन अधिक वास्तविक एवं वर्तमान आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए।
2. इं.आ.यो. के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन पारदर्शी कर दिया जाना चाहिए जिसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थायी प्रतीक्षा सूचीयों को तैयार किया जाना तथा इसका नियमित अद्यतन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
3. लाभार्थियों के नाम के साथ आवासों की अद्यतित सूची को सभी कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अनुरक्षित किया जाना चाहिए।
4. आवासों के निर्माण की कम गुणवत्ता पर लेखापरीक्षा की विभिन्न अभ्युक्तियों को ध्यान में रखते हुए, निर्माणाधीन आवासों के निरीक्षण का संचालन किया जाना चाहिए तथा कार्यान्वयन अभिकरणों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निरीक्षणों की प्रलेखित निरीक्षण रिपोर्ट को अनुरक्षित किया जाना चाहिए।
5. इं.आ.यो. के अंतर्गत आवास के निर्माण/सुधार हेतु सहायता को संस्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभार्थी का एक बैंक खाता हो। संबंधित प्राधिकारियों से उचित सत्यापन प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात ही उनके बैंक खातों में दूसरी किस्त जारी की जानी चाहिए।

6. जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (जि.ग्रा.वि.अ.) जिला पंचायती राज अधिकारियों (जि.पं.रा.अ.) को आवासों की संस्वीकृति के समय पर लाभार्थियों के बीच अभिसरण गतिविधियों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए और जिला स्तर पर अन्य संबंधित प्राधिकारियों के साथ भी समन्वय से काम करना चाहिए ताकि इं.आ.यो. के मकानों में पीने योग्य पानी, स्वच्छता, बिजली आदि हेतु प्रावधान को सुनिश्चित किया जा सके। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को उनकी उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर बिजली के विकल्प के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

7. शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण को बढ़ावा देकर तथा उनके शीघ्र निपटान द्वारा शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त बनाया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को त्रैमासिक आधार पर मॉनीटर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित अवधि से अधिक के लिए कोई शिकायत लंबित न रहे।

8. सामाजिक लेखापरीक्षा का उपयोग प्रभावी माध्यम के रूप में किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्य लाभार्थियों का चयन हो और समय पर उनके लिए अच्छी गुणवत्ता के आवासों का निर्माण हो। सामाजिक लेखापरीक्षा के सशक्तिकरण हेतु प्रख्यात गै.स.सं. को प्रक्रिया में लगाए जाने के बारे में विचार किया जा सकता है।

9. इं.आ.यो. के कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करने के लिए राज्य स्तर मूल्यांकन अध्ययनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

अध्याय-1: इंदिरा आवास योजना - एक विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

मानव जीवन के लिए आवास एक मूलभूत आवश्यकता है। एक व्यक्ति के लिए आवास होना उसे महत्वपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा तथा समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करता है। ग्रामीण आवास गरीबों के जोखिम को कम करने तथा स्वास्थ्य और उत्पादकता को सुधारने में योगदान देता है। इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो.) ग्रामीण विकास मंत्रालय की ग्रामीण ग.रे.नी. परिवारों को निवासीय इकाईयों के निर्माण/उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक प्रमुख योजना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा.ग्रा.रो.का.) जो 1980 में आरम्भ हुआ तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (ग्रा.भू.रो.गा.का.) जो 1983 में आरंभ हुआ, के अंतर्गत आवासों का निर्माण एक प्रमुख क्रियाकलाप था। तथापि, राज्यों में ग्रामीण आवासीय हेतु कोई एकरूप नीति नहीं थी। जून 1985 में ग्रा.भू.रो.गा.का. निधि का एक भाग आ.जा./अ.ज.जा. तथा उन्मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए आवासों के निर्माणों हेतु निर्दिष्ट था। परिणामत: इं.आ.यो. 1985-86 के दौरान ग्रा.भू.रो.गा.का. की उप योजना के रूप में आरंभ की गई थी। तत्पश्चात इं.आ.यो., अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना (ज.रो.यो.) एक उप योजना के रूप में जारी रही। जनवरी 1996 से इं.आ.यो., ज.रो.यो. से अलग हो गई थी और एक स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित की गई थी।

योजना आयोग के अंतर्गत ग्रामीण आवास पर कार्यकारी समूह के आकलन के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आवासीय कमी 400 लाख थी। यह माना गया था कि कुल आवासीय कमी में से आधी (200 लाख) के लिए इं.आ.यो. तथा ब्याज परिदान सहायता के माध्यम से वित्तपोषण की आवश्यकता होगी। शेष 200 लाख आवास राज्य योजनाओं, उनके स्वयं के संसाधनों अथवा वित्त के अनौपचारिक स्रोतों जैसे साहूकारों, उधार आदि पर लेने आदि के माध्यम से निर्मित किए जाएंगे।

समय-समय पर इं.आ.यो. में अनेक संशोधन किये गये थे। मुख्यत: वित्तीय सहायता के स्तर से संबंधित संशोधनों को **चार्ट-1** में सारांशीकृत किया गया है।

चार्ट-1: इं.आ.यो. दिशानिर्देशों में संशोधन

1996
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग.रे.नी. परिवारों के लक्ष्य इं.आ.यो. को ज.रो.यो. से अलग करके एक स्वतंत्र योजना बनाई गई थी।
- मैदानी क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता ₹ 14,000 से ₹ 20,000 तक तथा पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के लिए ₹ 15,800 से ₹ 22,000 तक बढ़ा दी गई थी।

1999
- कुछ गरीब वर्गों के लिए अव्यवहार्य कच्चा आवास के उन्नयन हेतु प्रावधान बनाने की पहल करना और क्रेडिट एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- ग्रामीण आवासों में लागत प्रभाव, आपदा प्रतिरोधी तथा पर्यावरण मैत्री प्रौद्योगिकियों पर बल दिया गया है।

2004
- 'नवीन धारा के लिए ग्रामीण आवास के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम नामत: ग्रामीण आवासों तथा प्राकृतिकवास विकास', समग्र आवास योजना तथा ग्रामीण भवन केन्द्रों (ग्रा.भ.के.) को बन्द करके इं.आ.यो. में मिला दिया गया था।
- मैदानी क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता ₹ 20,000 से ₹ 25,000 तक, पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए ₹ 22,000 से ₹ 27,500 तक तथा उन्नयन हेतु सहायता ₹ 10,000 से ₹ 12,500 तक बढ़ा दी गई थी।

2007
- इं.आ.यो. के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए निर्दिष्ट 15 *प्रतिशत* निधियों को आरंभ करना।

2008
- अन्तरीय ब्याज दर (अ.ब्या.द.) योजना आरंभ की गई थी।
- मैदानी क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता ₹ 25,000 से ₹ 35,000 तक, पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए ₹ 27,500 से ₹ 38,500 तक तथा दोनों क्षेत्रों में उन्नयन हेतु सहायता ₹ 12,500 से ₹ 15,000 बढ़ा दी गई थी।

2009
- इं.आ.यो. के भाग के रूप में, उन ग्रामीण ग.रे.नी. परिवारों जिनके पास न तो कृषि भूमि है और न ही आवास स्थल है, को आवासभूमि स्थल देने के लिए एक योजना आरंभ की गई थी।
- योजना के अंतर्गत, प्रति लाभार्थी ₹ 10,000 की वित्तीय सहायता या वास्तविक लागत, जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी।

2010
- मैदानी क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता ₹ 35,000 से ₹ 45,000 तक, पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए ₹ 38,500 से ₹ 48,500 तक बढ़ा दी गई थी ।
- वाम दल के अतिवादियों (वा.द.अ.) से प्रभावित जिलों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अधिक इकाई लागत के प्रयोजन हेतु कठिन क्षेत्रों के रूप में लिया गया था।

2013
- वित्तीय सहायता मैदानी क्षेत्रों के लिए ₹ 45,000 से ₹ 70,000 तक तथा पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए ₹ 48,500 से ₹ 75,000 तक बढ़ा दी गई थी।
- आवासभूमि स्थल हेतु वित्तीय सीमा ₹ 10,000 से ₹ 20,000 तक बढ़ा दी गई थी।

1.2 इं.आ.यो. का उद्देश्य

इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक रूप से लाभार्थियों को एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आवासीय इकाइयों का निर्माण/उन्नयन करने में सहायता करना है।

1.3 लाभार्थियों की पहचान करना

इं.आ.यो. के अंतर्गत लाभभोगी निम्नानुसार हैं:-

- उन्मुक्त बंधुआ मजदूर,
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे (ग.रे.नी.) के परिवार;
- गैर अनुसचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के ग्रामीण ग.रे.नी. के परिवार,
- विधवाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसी युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों/अर्धसैनिक बलों के निकट संबंधी (उनकी आय के बिना),
- भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक बल के सेवानिवृत्त सदस्य कुछ निश्चित शर्तें पूर्ण करने पर, जैसे लाभभोगी बेघर होना चाहिए अथवा उसका कच्चा आवास तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए।
- ग.रे.नी. के अल्पसंख्यक।

1.4 इं.आ.यो. के अंतर्गत वित्तीय सहायता

प्रत्येक इं.आ.यो. लाभभोगी को 2008-09 से 2012-13 के दौरान अनुपयोगी कच्चा आवास के उन्नयन तथा नए आवास के निर्माण हेतु दी गई सहायता की सीमा निम्नानुसार थी।

क	आवास का निर्माण	01.04.2008 से 31.03.2010	मैदानी क्षेत्रों में ₹ 35,000 तथा ₹ 38,500 पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में
		01.04.2010 से 31.03.2013	मैदानी क्षेत्रों में ₹ 45,000 तथा 60 वाम बल अतिवादी (वा.ब.अ.) केन्द्रित जिलों सहित पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में ₹ 48,500।
ख	अनुपयोगी आवासों का उन्नयन	01.04.2008 से 31.03.2013	दोनों क्षेत्रों में ₹ 15,000

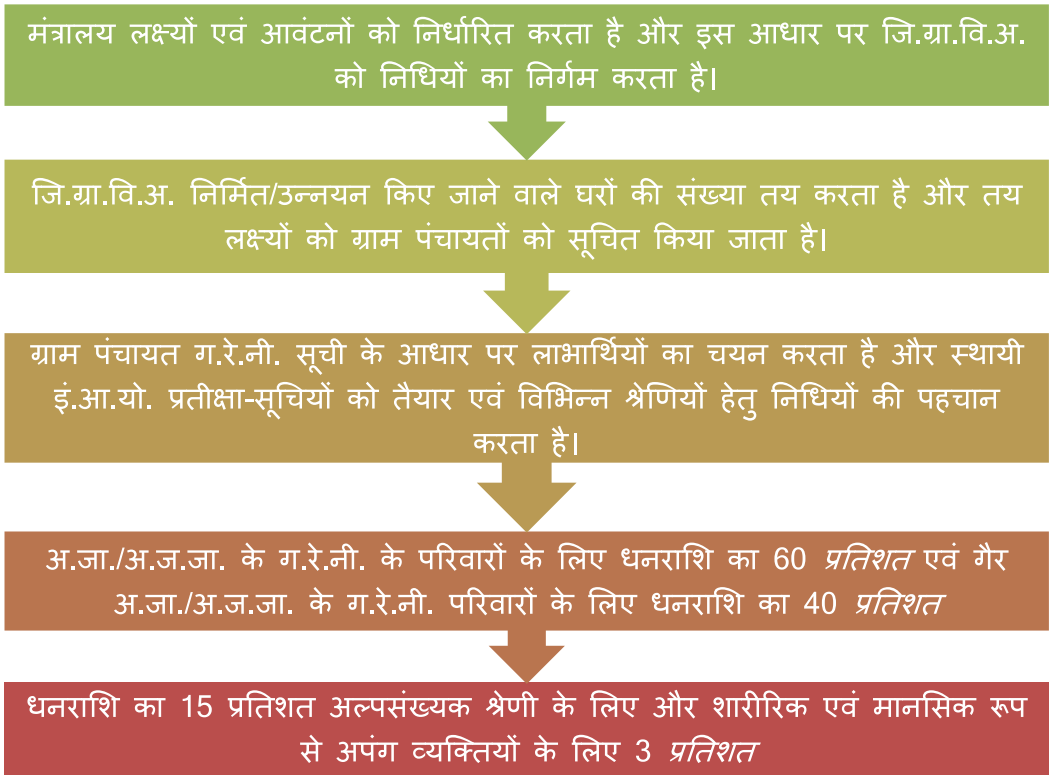
1.5 इं.आ.यो. आवास की अवस्थापना

इं.आ.यो. निवासीय इकाईयां सामान्यत: गांव के मुख्य वास में व्यक्तिगत प्लॉटों पर निर्मित की जानी चाहिए। मकानों को वास स्थान के भीतर एक समूह में बनाया जा सकता है जिससे अवसंरचना जैसे आंतरिक सड़कें, जल निकासी पेय जल आपूर्ति आदि के विकास को सरल बनाया जा सके।

1.6 इं.आ.यो. का कार्यान्वयन

इं.आ.यो. ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) तथा जिला परिषदों (जि.प.)/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (जि.ग्रा.वि.अ.) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है तथा आवास लाभभोगियों द्वारा स्वयं निर्मित/उन्नयनित किए जाते हैं। लाभभोगियों का चयन और विभिन्न श्रेणियों हेतु चिन्हित उपलब्ध संसाधनों के उपयोग **चार्ट-2** में दिये गये हैं:

चार्ट-2: विभिन्न श्रेणियों हेतु निर्धारित निधियों की पहचान



लाभभोगियों को, सामग्री के अधिप्रापण, कुशल श्रमिक को कार्य पर लगाने तथा परिवार को भी श्रम में योगदान देने के लिए स्वयं प्रबंध करने की आवश्यकता होती है। जि.पं./जि.ग्रा.वि.अ. लाभभोगियों की इच्छा या अनुरोध करने पर नियंत्रित दरों पर कच्चा माल प्राप्त करने में सहायता कर सकती है।

निवासीय इकाई का आवंटन लाभभोगी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर होना चाहिए। तथापि यदि उपलब्ध परिवार में कोई पात्र महिला नहीं है या जीवित नहीं है तो आवास पात्र ग.रे.नी. परिवार के पुरुष सदस्य को भी आवंटित किया जा सकता है। प्रत्येक इं.आ.यो. आवास में स्वच्छ शौचालय तथा धुंआरहित चूल्हा आवश्यक है। इं.आ.यो. आवासों में स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (स.स्व.अ.)[1] के अंतर्गत निधियां प्रदान की गई हैं। राजीव

[1] स.स्व.अ. 2017 तक खुले में मलत्याग की प्रक्रिया को हटाने के मुख्य उद्देश्य से 1999 में आरंभ किया गया था।

गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (रा.गा.ग्रा.वि.यो.)[2] के अंतर्गत इं.आ.यो. के ग्रामीण ग.रे.नी. परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान की जानी थी।

1.7 संगठनात्मक ढांचा

केन्द्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान करता है और जिले-वार लक्ष्य निर्धारित करता है। राज्यों में, राज्य सरकार जि.ग्रा.वि.अ./जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत तथा ग्राम पंचायत को इं.आ.यो के कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग के विभिन्न स्तरों का कार्य सौंपा गया है। इं.आ.यो. के नियोजन, निष्पादन तथा मॉनीटरिंग में केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर विभिन्न प्राधिकारियों की भूमिका **चार्ट-3** में दर्शाई गयी है।

[2] रा.गा.ग्रा.वि.यो., भा.स. द्वारा जिन गांवों में बिजली नहीं थी उनमें बिजली देने तथा ग्रामीण ग.रे.नी. परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए मार्च 2005 में आरंभ की गई थी।

चार्ट-3: संगठनात्मक ढ़ांचा



1.8 इं.आ.यो. का आवृतन

इं.आ.यो. चंडीगढ़ तथा दिल्ली के अलावा देश के सभी जिलों में कार्यान्वित की गई है ।

1.9 निधियन पद्धति

इं.आ.यो. का व्यय केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा आपस में बांटा जाता है। निधियन पद्धति निम्न **तालिका 1** में दर्शाई गई है:

तालिका 1 : निधियन पद्धति

	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश
उत्तर पूर्वी राज्य तथा सिक्किम	90 *प्रतिशत*	10 *प्रतिशत*
उत्तर पूर्वी राज्य तथा सिक्किम के अलावा राज्य	75 *प्रतिशत*	25 *प्रतिशत*
संघ शासित क्षेत्र	100 *प्रतिशत*	--

1.10 इं.आ.यो. के अंतर्गत वित्तीय तथा भौतिक निष्पादन

2008 -09 से 2012-13 के दौरान राज्यों के पास कुल उपलब्ध निधियों का 58 तथा 85 *प्रतिशत* के बीच व्यय किया गया, जैसा कि नीचे दिया गया है:

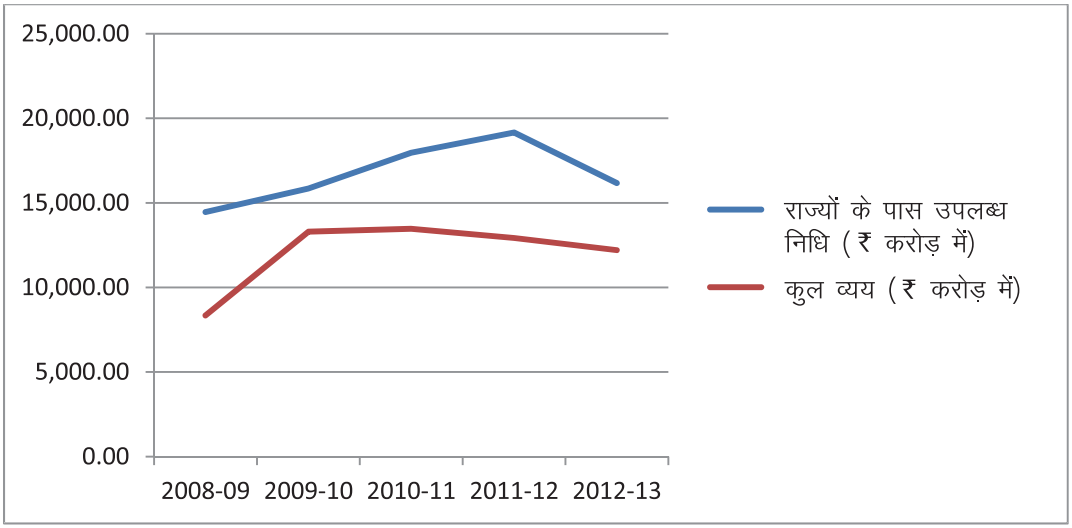
विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अथ शेष (₹ करोड़ में)	2,373.62	4,231.01	4,321.81	5,994.76	5,316.83
केन्द्रीय अंश (₹ करोड़ में)	8,795.79	8,635.74	10,139.45	9,864.78	8,402.67
राज्य अंश (₹ करोड़ में)	2,931.25	2,681.16	3,155.77	3,055.58	2,176.24
विविध प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	359.69	304.43	339.51	244.18	276.61
राज्यों के पास उपलब्ध निधियां (₹ करोड़ में)	14,460.35	15,852.35	17,956.54	19,159.30	16,172.35
कुल व्यय (₹ करोड़ में)	8,348.34	13,292.46	13,465.73	12,926.33	12,206.83
व्यय की प्रतिशतता	58	85	75	67	75

निर्मित किए जान वाले आवासों का लक्ष्य (लाख में)	21.27	40.52	29.09	27.27	30.10
निर्मित किए गए आवास (लाख में)	21.34	33.86	27.15	24.71	21.86

नीचे **चार्ट 4** दर्शाता है कि पिछले चार वर्षों में इं.आ.यो. पर व्यय पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा है, बल्कि यह प्राय: स्थिर रहा। यह भी दर्शाता है कि उपलब्ध निधियों तथा व्यय के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है तथा 2011-12 में यह अंतर बहुत अधिक था।

चार्ट: 4

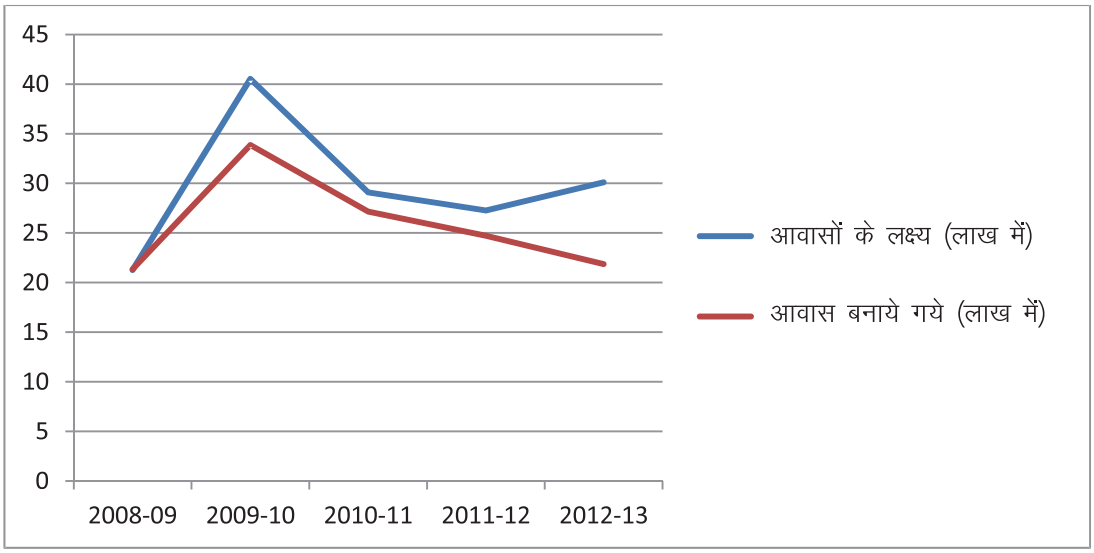
2008-09 से 2012-13 के दौरान इं.आ.यो. के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन



*निम्न **चार्ट 5** दर्शाता है कि आवासों के लक्ष्य कभी भी पूर्ण नहीं किए गए थे तथा लक्ष्यों तथा निर्मित आवासों के बीच अंतर 2011-12 के बाद से अधिक बढ़ रहा है।*

चार्ट: 5

2008-09 से 2012-13 के दौरान इं.आ.यो. के अंतर्गत भौतिक निष्पादन



अध्याय-2: लेखापरीक्षा दृष्टिकोण तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संगठन

2.1 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2.1.1 लेखापरीक्षा पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा को मंत्रालय के साथ 30 अप्रैल 2013 को एक प्रवेश सम्मेलन, जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, क्षेत्र, उद्देश्य तथा मापदण्ड पर चर्चा की गई थी, के साथ प्रारम्भ की गई। इं.आ.यो. के कार्यान्वयन से संबंधित प्रक्रियाओं की जांच में ग्रा.पं., ब्लॉक, जिला, राज्य तथा मंत्रालय स्तर पर अभिलेखों तथा प्रक्रियाओं का निरीक्षण शामिल है। निर्मित/उन्नयनित मकानों के अस्तित्व तथा उनकी स्थिति को सत्यापित करने हेतु तैयार एक संरचनाबद्ध प्रश्नावली की सहायता से इं.आ.यो. के अंतर्गत मकानों का एक संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया गया था। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समेकन के पश्चात 9 जुलाई 2014 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ निर्गम सम्मेलन हुआ था जिसमें पृथक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर भी निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें राज्य-विशिष्ट निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। प्रतिवेदन में विभिन्न स्तरों पर कार्यकारी अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को ध्यान में रखा गया है।

2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इं.आ.यो. की निष्पादन लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए प्रारम्भ की गई थी कि क्या:

- इं.आ.यो. लाभार्थियों की पहचान तथा चयन हेतु स्थापित प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं तथा निधियों के आवंटन, निवास इकाईयों का निर्माण तथा उन्नयन पर्याप्त तथा इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के अनुकूल था।
- निर्मित तथा उन्नत की गई इकाईयों की संख्या के अनुसार इं.आ.यो. के अंतर्गत भौतिक निष्पादन वैसा था जैसा योजना तथा लक्ष्य किया गया

था तथा कि निर्माण इं.आ.यो. दिशानिर्देशों में निर्धारित गुणवत्ता तथा प्रतिमानों के अनुकूल था।

- इं.आ.यो. के अंतर्गत निधियों का आवंटन तथा निर्गम पर्याप्त तथा सामयिक प्रकार से किया था तथा उनका इं.आ.यो. के प्रावधानों के अनुसार मितव्ययी तथा दक्षता से उपयोग किया गया था।
- अन्य कार्यक्रमों के साथ इं.आ.यो. का अभिसरण, जैसी कल्पना की गई थी, प्रभावी रूप से प्राप्त किया था तथा पूर्ण क्रियात्मक निवास इकाईयों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया था।
- इं.आ.यो. के परिणामों की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु स्थापित प्रक्रिया पर्याप्त तथा प्रभावी थी।

2.1.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मापदण्ड के मुख्य स्रोत थे:

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रा.वि.मं.), भा.स. द्वारा जारी इं.आ.यो. के दिशानिर्देश (31 जुलाई 2012 तक अद्यतित की गई)।
- ग्रा.वि.मं. का परिणाम बजट
- ग्रा.वि.मं. द्वारा निर्धारित आवधिक रिपोर्ट/रिर्टन।
- ग्रा.वि.मं. द्वारा जारी इं.आ.यो. पर परिपत्र/अनुदेश।
- सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.), 2005।

इं.ग्रा.यो. के निष्पादन का निर्धारण ग्रामीण ग.रे.नी. परिवारों को घर प्रदान करने के लिए मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के आधार पर किया गया था। इं.आ.यो. हेतु निष्पादन संकेतक थे:

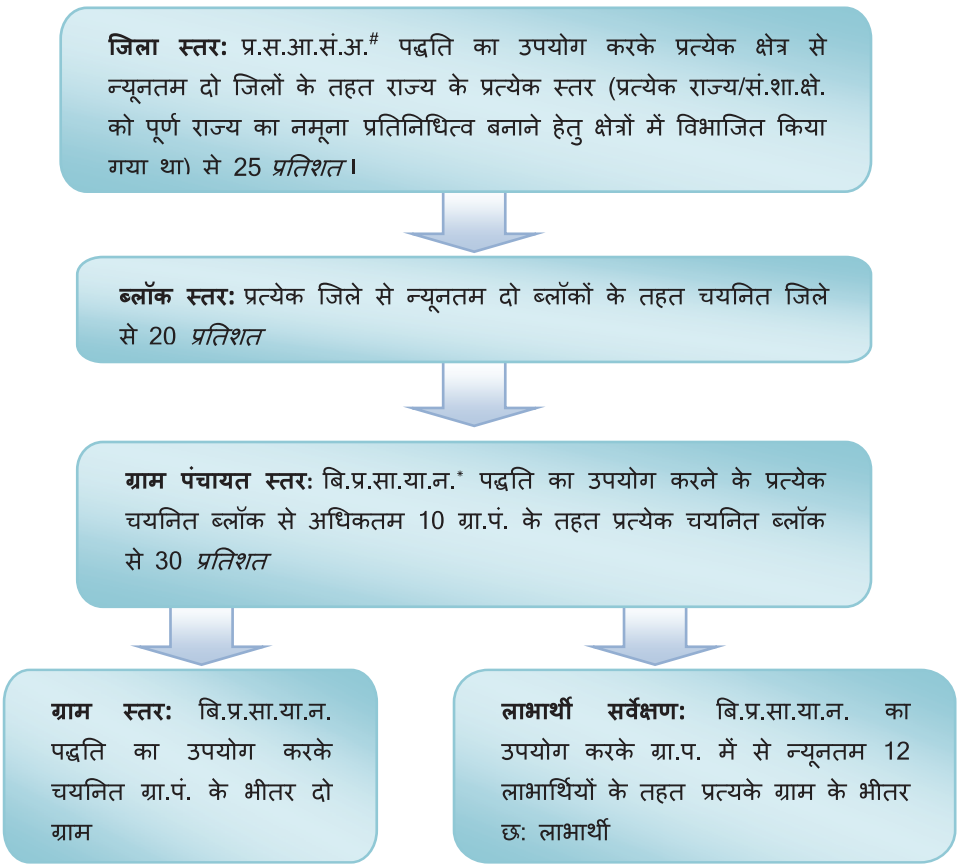
- ग्रामीण ग.रे.नी. बेघर व्यक्तियों की संख्या में कमी।
- कमजोर वर्गों पर ध्यान।
- भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति।
- समग्र एवं नियमित रूप से अद्यतित लाभार्थी सूची।
- निर्मित/उन्नत सभी मकानों ने पक्के घरों के मापदण्ड को पूरा किया था।
- निर्मित/उन्नत मकान की गुणवत्ता तथा इं.आ.यो. दिशानिर्देशों में निर्धारण के अनुसार डिजाइन
- पारदर्शी शिकायत सुधार प्रक्रिया का होना।

- इं.आ.यो. के मूल्यांकन की आवृत्ति।

2.1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र का नमूना

निष्पादन लेखापरीक्षा ने 27 राज्यों[1] तथा चार संघ शासित क्षेत्रों[2] में 2008-09 से 2012-13 तक इं.आ.यो. के अंतर्गत कार्यों को शामिल किया। नमूनों का स्तरीकृत बहु चरणीय नमूना डिजाईन का उपयोग करने के लिए चयन किया गया था अर्थात् चयन जिला, ब्लॉक, ग्रा.पं., ग्राम तथा लाभार्थी स्तर पर था। उपयोग की गई नमूना योजना को नीचे **चार्ट 6** में दर्शाया गया है:

चार्ट-6: इं.आ.यो. हेतु बहु चरणीय नमूना योजना



#प्र.स.आ.सं.अ.: प्रतिस्थापन सहित आकार के संभाव्यता अनुपातिक
*बि.प्र.सा.या.न.: बिना प्रतिस्थापन सामान्य यादृच्छिक नमूना

[1] सिक्किम को छोड़कर

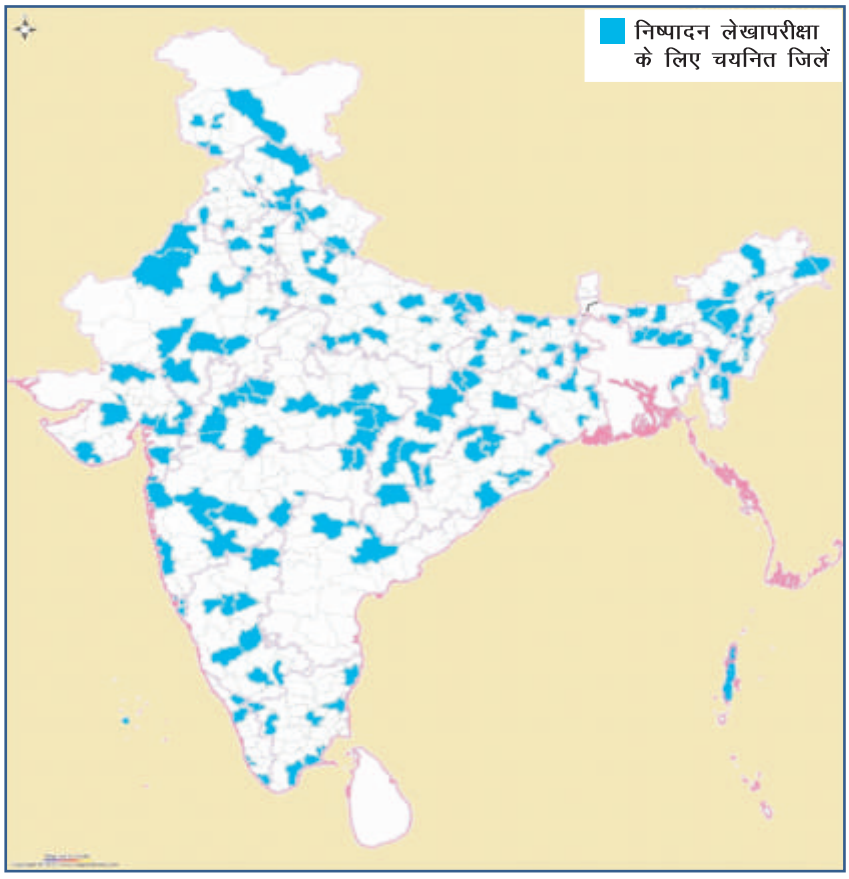
[2] पुदुचेरी को छोड़कर

उपर्युक्त बहु-चरणीय नमूने के परिणाम निम्नानुसार थे:

- 617 जिलों में 168 जिले/जि.ग्रा.वि.अ.[3];
- 168 चयनित जिलों के 392 ब्लॉक[4];
- 392 चयनित ब्लॉकों में 2,960 ग्राम पंचायते[5]।
- संयुक्त भौतिक निरीक्षण हेतु 2,960 ग्रा.पं. में 4,804 गांव
- प्रश्नावली का उत्तर देने हेतु 4,804 गांवों में 29,923 घरों/लाभार्थियों का चयन किया गया था

चयनित नमूने के विवरण **अनुबंध 2.1 तथा 2.2** में दिए गए हैं। जिलों का आवृतन **मैप-I** में अंकित किया गया है। नीला रंग किए गए जिलों को नमूना योजना के अंतर्गत चयन किया गया था।

मैप: 1 नमूना योजना के अंतर्गत चयनित जिले



[3] केरल में ग्रामीण विकास आयुक्त के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन इकाई (ग.उ.इ.) जिला स्तर पर इं.आ.यो. हेतु कार्यान्वयन अभिकरण है।

[4] छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत तथा ओडिशा में पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय पंचायत के समान है।

[5] नागालैंड में ग्राम विकास बोर्ड (ग्रा.वि.बो.), मिजोरम में ग्राम परिषद (ग्रा.प.), लक्षद्वीप में ग्राम द्वीप पंचायत (ग्रा.द्वी.पं.) अन्य राज्यों/सं.शा.क्षे. में ग्रा.पं. के बराबर है।

2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संगठन

लेखापरीक्षा मामलों का देशव्यापी परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण किया गया है तथा विभिन्न राज्यों/सं.शा.क्षे. में निष्कर्षों पर केवल संक्षिप्त सारांशीकृत सूचना प्रदान की गई है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विभिन्न अध्यायों में बताया गया है। इस प्रतिवेदन का अध्याय 1 तथा 2 योजना का संक्षिप्त विहंगावलोकन तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों तक पहुँचने हेतु अपनाई गई लेखापरीक्षा पद्धति प्रदान करते हैं। अध्याय 3 लाभार्थियों की पहचान तथा चयन में कमियों का ब्यौरा देता है तथा अध्याय 4 में घरों के निर्माण तथा उनकी गुणवत्ता से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा की गयी है। अध्याय 5 इं.आ.यो. के वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताओं को उजागर करता है। अध्याय 6 इं.आ.यो. के आवृतन पहलुओं को शामिल करता है। अध्याय 7 इं.आ.यो. की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन में त्रुटियों को उजागर करता है अध्याय 8 में वासभूमि स्थल वर्तमान में शुरू की गयी एक योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को प्रकट करता है। अध्याय 9 में हमने संयुक्त भौतिक निरीक्षण पर निष्कर्षों को प्रस्तुत किया है। अध्याय 10 में अंतिम टिप्पणी दी गयी है।

2.3 आभार प्रकट

लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न चरणों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों, कार्यान्वयन विभागों तथा उनके अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग तथा सहायता हेतु आभार प्रकट करती है।

अध्याय 3 : लाभार्थियों की पहचान एवं चयन

मकानों की कमी तथा मकानों की वर्तमान उपलब्धता के मध्य के अंतर को संबोधित करने के लिए मकानों की कमी के उचित आकलन तथा लाभार्थियों की पहचान का सर्वोच्च महत्व है।

3.1 जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा मकानों की कमी का आकलन

ग्रामीण आवास पर योजना आयोग के अंतर्गत कार्यदल ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए ग.रे.नी. परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 426.90 लाख मकानों की कमी का आकलन किया था। इसमें से, इं.आ.यो. के अंतर्गत 150 लाख (प्रति वर्ष 30 लाख मकान) मकानों की कमी को पूरा किया जाना था। इसके अतिरिक्त, 2012-13 के लिए 50 लाख मकानों की कमी का आकलन किया गया था। इस प्रकार, कार्यदल ने 2008-13 के लिए इं.आ.यो. के अंतर्गत 170 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके विरूद्ध, 2008-13 के दौरान मंत्रालय ने निर्माण के लिए 148.25 लाख मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया था।

30 लाख मकानों की कमी की वार्षिक औसत को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने गरीबी अनुपात को 25 *प्रतिशत* वेटेज और ग्रामीण आवास की कमी को 75 प्रतिशत वेटेज देते हुए जनपद पंचायत/जिला पंचायत/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (जि.ग्रा.वि.अ.) को केन्द्रीय सहायता आवंटित करता है। मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तथा किए गए आवंटनों के आधार (इं.आ.यो. दिशानिर्देशों का पैरा 2.1) पर ज.पं./जि.पं./जि.ग्रा.वि.अ. वित्तीय वर्ष के दौरान निर्माण/उन्नत किए जाने वाले मकानों की संख्या निश्चित करती है तथा निराश्रित लाभार्थियों की पहचान करती है। लाभार्थियों की पहचान करने के लिए मकानों की कमी का आकलन करना महत्वपूर्ण था।

हमने पाया कि 14 राज्यों अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल** और **पंजाब** (तीन जिले) में मकानों की कमी का आकलन नहीं किया गया था। तीन राज्यों अर्थात् **बिहार, मिजोरम तथा ओडीशा** में मकानों की कमी के आकलन से संबंधित विश्वसनीय डाटा/अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इस पहलू को सात राज्यों अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, नागालैण्ड, पंजाब** तथा **पश्चिम बंगाल** के संबंध में 2003 की नि.म.ले.प. के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 में इंगित किया गया था।

जम्मू एवं कश्मीर में, ब्लॉक के पास मकानों की कमी के विवरण उपलब्ध थे लेकिन जिला स्तर पर इसे समेकित नहीं किया गया था। **असम** में, जनगणना 2002 के अनुसार, मकानों की कमी 18.73 लाख थी लेकिन राज्य ने जनगणना 2001 के आधार पर मकानों की कमी का आकलन 22.41 लाख किया था। इस प्रकार, राज्य में मकानों की कमी का आकलन गलत था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2014) कि राज्यों की निधियों का आवंटन करने के लिए, जनगणना परिचालन विभाग द्वारा आकलन की गई मकानों की कमी को ध्यान में रखा जाता था। ब्लॉक/ग्रा.पं. स्तर तथा जिला में भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण के लिए इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता था। हालांकि, लाभार्थियों की पहचान के लिए, प्रत्येक पांच वर्षों के बाद राज्यों द्वारा ग.रे.नी. सर्वेक्षण को संचालित किया जाता था तथा उस सर्वेक्षण के आधार पर ग.रे.नी. सूची/स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची बनायी जाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2002 के दौरान पिछला सर्वेक्षण संचालित किया गया था जो कि दर्शाता है कि आंकडों को नियमित रूप से अद्यतित नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011 के दौरान एक सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना को संचालित किया गया था जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना था।

इस प्रकार, मंत्रालय का उत्तर दर्शाता है कि उसके द्वारा मकानों की कमी पर डाटा पुराना था तथा यथार्थवादी नहीं था।

3.2 स्थायी प्रतीक्षा सूचियों तथा वार्षिक योजनाओं की तैयारी के लिए प्रक्रिया

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 2.1 के अनुसार, मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की सूचना ग्रा.पं. को दी जानी थीं। इस संख्या तक सीमित, प्रत्येक ग्रा.पं. में लाभार्थियों को सूची में वरिष्ठता के क्रम में ग.रे.नी. के आधार पर तैयार की गई स्थाई इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूचियों में से किया जाना था। ग्रा.पं. को ग.रे.नी. सूची में से बेघर परिवारों को, सूची में से सख्ती से रैंकिंग के अनुसार निकालना था। इन श्रेणियो को मकानों के 60 *प्रतिशत* के आवंटन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ी इं.आ.यो. सूची में से रैंक के क्रम के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों की अलग सूची को निकाली जानी थी। इस प्रकार, किसी भी समय, दो इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूचियां, एक अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों के लिए दूसरी गैर अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों के लिए उपलब्ध होनी थी। इन सूचियों को कलेक्टर द्वारा नामांकित सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक था। ग्राम सभा द्वारा चयन अंतिम था तथा किसी उच्च प्राधिकरी द्वारा किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।

इसके अतिरिक्त, इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 ख (viii) के अनुसार, स्थायी प्रतीक्षा सूची के आनुपालन को, जहाँ तक लाभार्थियों का चयन संबंधित था सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक योजना को भी तैयार किया जाना था।

3.2.1 स्थायी प्रतीक्षा सूचियों को तैयार न किया जाना

तीन राज्यों के चयनित जिलों तथा एक सं.शा.क्षे. अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मेघालय तथा लक्षद्वीप** में स्थायी प्रतीक्षा सूचियां तैयार नहीं की गई थीं। तीन राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. अर्थात् **मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** में अ.जा./अ.ज.जा. तथा गैर अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग प्रतीक्षा सूचियां अनुरक्षित नहीं की गई थीं। लेखापरीक्षा ने विभिन्न राज्यों में स्थायी प्रतीक्षा सूचियों को तैयार करने में असमान क्रियाएं तथा लाभार्थियों को

शामिल न किया जाना, नामों का दोहरीकरण तथा सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को अ.जा./अ.ज.जा. सूची में शामिल किया जाना आदि जैसी अनियमितताएं पाईं। विवरण **अनुबंध-3.1** में दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में, जिला लखनऊ के ब्लॉक माल में, ग.रे.नी. सूची में सामान्य श्रेणी के 13 लाभार्थियों को इं.आ.यो. की प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जाति में दर्शाया गया था।

3.2.2 ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था

हमने पाया कि दो राज्यों (**उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश**) और **मध्य प्रदेश** के 25 ग्रा.पं. में ग्राम सभा द्वारा स्थायी सूचियां अनुमोदित नहीं की गई थी। तीन राज्यों अर्थात् **कर्नाटक, मिजोरम, ओडिशा** में कलेक्टर द्वारा नामांकित व्यक्ति ग्राम सभा बैठकों में उपस्थित नहीं हुए थे। **कर्नाटक** में, 51 ग्रा.पं. में, बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के 7,212 लाभार्थियों का चयन किया गया था।

असम में, दो चयनित जिलों नागॉव एवं सोनितपुर के दो ब्लॉकों के 10 ग्रा.पं. में 1,383 लाभाथिर्यों का चयन ग्राम सभा की बजाय ग्रा.पं./ब्लॉक/विधायकों द्वारा किया गया था। जिला कचार में ब्लॉक बोरखोला में, ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना स्थानीय विधायक द्वारा चयनित 72 लाभार्थियों को ₹34.70 लाख की राशि जारी की गई थी। **हरियाणा** में, ग्राम सभा की बजाय जि.ग्रा.वि.अ. के द्वारा लाभार्थियों का चयन किया गया था। **झारखण्ड** में 18 चयनित ब्लॉकों में से 14 में, 25,424 लाभार्थियों का चयन बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के हुआ था और उन्हें ₹92.63 करोड़ की सहायता जारी कर दी गई थी। **कर्नाटक** में, जि.पं. गदाग के तीन ग्रा.पं. में 243 लाभार्थियों का चयन बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के किया गया था। **तमिलनाडु** में, तीन चयनित जिलों के तीन ब्लॉकों, तिरूप्पुर (पल्लाडम), त्रिरूचिरापल्ली (तिरूवेराम्बुर) एवं तिरूवन्नामलाई (तिरूवन्नामलाई) में, ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना 110 लाभार्थियों का चयन किया गया था जिसमें ₹76.95 लाख का व्यय शामिल था तथा ब्लॉक तिरूवेराम्बुर में, कार्य साधक संख्या के बिना

ग्राम सभा द्वारा 12 लाभार्थियों का चयन किया गया था। **पश्चिम बंगाल** में, जिला मालदा के चयनित ग्रा.पं. में से किसी में भी ग्राम सभा द्वारा स्थायी प्रतीक्षा सूचियां अनुमोदित नहीं की गई थीं और जिला बीरभूम के दो ब्लॉकों (सूरी-II, मयुरेश्वर-II) में छः लाभार्थियों तथा जिला कूच बिहार के दो ग्रा.पं. (बरारंग्रास, खानग्राबारी) में पांच लाभार्थियों को ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना क्रमश: ₹2.10 लाख और ₹1.75 लाख के लाभ दिए गए थे।

3.2.3 वार्षिक योजना को तैयार न किया जाना

हमने पाया कि प्रतीक्षा सूचियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक योजना 16 राज्यों और एक सं.शा.क्षे. अर्थात् **असम, छत्तीसगढ़, गोवा,गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडीशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड एवं लक्षद्वीप** में तैयार नहीं की गयी थीं। **आन्ध्र प्रदेश** में जबकि आन्ध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड (आं.प्र.रा.आ.नि.लि.) ने बताया कि उसने वार्षिक योजना तैयार की थी लेकिन इसे लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। **अरूणाचल प्रदेश** में तीन चयनित जिलों (लोहित, अंजॉ, पपुमपरे) में वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई थी। **बिहार** में, भागलपुर एवं मधुबनी जहॉ 2008-13 के दौरान दो और तीन वर्षों (2008-10 के लिए भागलपुर, तथा 2010-13 के लिए मधुबनी) के लिए अधूरे वार्षिक योजनाए तैयार की गई थी को छोडकर किसी भी चयनीत जिले में वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई थी। **महाराष्ट्र** में गोंडिया जिले में, वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई थी। इस प्रकार, इन राज्यों/जिलों में इस कार्यक्रम को अनियोजित तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा था।

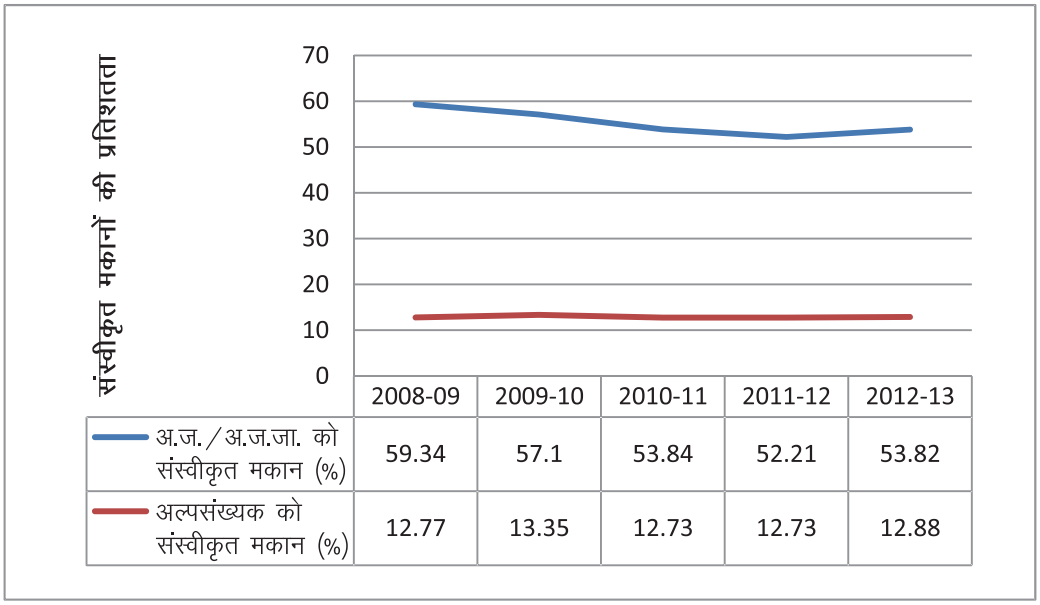
3.3 लाभार्थी का चयन

3.3.1 निर्दिष्ट श्रेणियों के लाभार्थियों के चयन में कमी

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 1.5 के अनुसार, इं.आ.यो. संसाधनों का 60 *प्रतिशत* अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों के लिए तथा गैर अ.जा./अ.ज.जा. ग.रे.नी. के परिवारों के लिए 40 *प्रतिशत* चिन्हित किया जाना था। इसका तात्पर्य है कि अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों का चयन कुल भौतिक लक्ष्यों का 60 *प्रतिशत* होना चाहिए और गैर-अ.जा/अ.ज.जा. के लिए कुल भौतिक लक्ष्यों का 40 *प्रतिशत* होना चाहिए इसके अतिरिक्त, ग.रे.नी. अल्पसंख्यकों के लिए 15 *प्रतिशत* भौतिक लक्ष्य तथा शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उपरोक्त श्रेणियों का तीन *प्रतिशत* चिन्हित किया जाना था।

हमने पाया कि इं.आ.यो. के अंतर्गत 2008-09 से 2012-13 के दौरान 166.88 लाख संस्वीकृत मकानों में से अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों के लिए केवल 55 *प्रतिशत* (92.35 लाख) मकानों को संस्वीकृत किया गया था तथा अल्पसंख्यकों को 12 प्रतिशत (21.56 लाख) अनुमोदित किया गया था जैसा कि **चार्ट-7** में दर्शाया गया है।

चार्ट-7: अ.जा./अ.ज.जा. तथा अल्पसंख्यकों को संस्वीकृत इं.आ.यो. के मकान



	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अ.ज./अ.ज.जा. को संस्वीकृत मकान (%)	59.34	57.1	53.84	52.21	53.82
अल्पसंख्यक को संस्वीकृत मकान (%)	12.77	13.35	12.73	12.73	12.88

इसके अतिरिक्त, 13 राज्यों में निर्दिष्ट श्रेणियों में से लाभार्थियों का चयन इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार नहीं था जिसका विवरण **अनुबंध 3.2** में दिया गया है। लाभार्थियों के चयन में कुछ अन्य मुद्दे पाए गए थे जो कि निम्नलिखित हैं:-

- **उत्तराखण्ड** में, चार चयनित जिलों में 131 लाभार्थियों की श्रेणी को सामान्य से अ.जा./अ.ज.जा. में परिवर्तित कर दिया गया था तथा 43 लाभार्थियों की श्रेणी को अ.जा./अ.ज.जा. से सामान्य में परिवर्तित कर दिया गया था। तथ्यों को जिला प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया था जिसने बताया कि मामले को देखा जा रहा है।

- **राजस्थान** में, जिला भीलवाड़ा, करौली, सीकर एवं उदयपुर के जि.ग्रा.वि.अ. ने बताया कि इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूचियों में अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई लंबमानता नहीं थी जबकि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार अल्पसंख्यकों के लाभार्थियों की 46, 165, 10 एवं 122 संख्या लंबित थी। इस प्रकार, जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की सच्चाई संदेहपूर्ण थी।

- **नागालैण्ड** में, यद्धपि 2,051 शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आवृत्त बताया गया था। लेखापरीक्षा के समक्ष 695 लाभर्थियों के साथ हुए साक्षात्कार के दौरान इस श्रेणी का कोई भी लाभार्थी सामने नहीं आया था। शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की इतनी अधिक संख्या का आवृतन अवास्तविक लगा था। विभाग ने स्वीकार किया (अगस्त 2013) कि इं.आ.यो. के लिए लक्ष्य निर्धारित करते समय इस श्रेणी के लाभार्थियों को पहचाना नहीं गया था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि इन श्रेणियों के लिए आवास की कमी समाप्त की जा रही थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि कई राज्यों में, अल्पसंख्यक

परिवारों की बहुत कम संख्या है जबकि **मेघालय, मिजोरम** एवं **नागालैण्ड** में कोई अल्पसंख्यक जनसंख्या नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर सामान्य था तथा लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई राज्य विर्निदिष्ट अनियमितताओं की व्याख्या नहीं करता। चूंकि अल्पसंख्यकों की संख्या प्रत्येक राज्य में भिन्न होती है सभी राज्यों के लिए सामान्य दिशानिर्देश होने की उपयुक्तता प्रश्न योग्य है।

3.3.2 गैर- ग.रे.नी. के लाभार्थियों का चयन

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 1.4 के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे रक्षा सेवाओं/अर्धसैनिक के ड्यूटी पर मारे गए सेनाबलों के परिवारों/कर्मियों की विधवाओं को छोडकर गरीबी रेखा से नीचे (ग.रे.नी.) के परिवार इं.आ.यो. के अंतर्गत लक्ष्य समूह थे। हमने पाया कि 12 राज्यों के 34 चयनित जिलों में 67 ब्लॉकों के 670 ग्रा.पं. में ₹89.15 करोड़ की सहायता 36,751 गैर - ग.रे.नी. के परिवार जो कि रक्षा सेवाओं/अर्धसैनिक बलों से संबंधित नहीं थे को दी गई थीं। **अनुबंध 3.3** में इसके विवरण दिए गए हैं। अन्य अनियमितताएं जिनकी चर्चा निम्न वर्णित है:-

- **केरल** में, लाभार्थियों का चयन बेघर परिवारों की ऐसी सूची में से हुआ था जो कि अन्य राज्य आवास योजना के लिए तैयार की गई थी अर्थात् 2008-09 में शुरू की गई इलमकुलम मनक्कल संकर्न (इं.म.सं.) आवास योजना जिसमें ग.रे.नी. तथा गैर-ग.रे.नी. दोनों से संबंधित बेघर परिवार शामिल थे।

- **ओडीशा** में, जिला गंजम में, 118 लाभार्थी ग.रे.नी. कार्ड धारकों के रिश्तेदार थे तथा इन रिश्तेदारो के ग.रे.नी. कार्डों के आधार पर उनके लिए ₹34.97 लाख की इं.आ.यो. सहायता जारी कर दी गई थी।

- **गोवा** में, ग.रे.नी. सूची-2002 के अनुसार केवल 1,188 लाभार्थी थे जबकि 12,255 व्यक्तियों का चयन नए मकानों के निर्माण के लिए किया गया था। और ग.रे.नी. सूची-2002 के अनुसार कच्चे मकानों वाले 3,917 लाभार्थी थे परंतु, 4,713 व्यक्तियों का चयन मकानों में सुधार के लिए किया गया था।

- **असम** में, दो जिलों (कार्बी अंगलोंग, बरपेटा) में, 680 ग.रे.नी. व्यक्ति थे लेकिन इन ग.रे.नी. कार्डों के प्रति 1,376 लाभार्थियों का चयन किया गया था।

- **आन्ध्र प्रदेश** में, इं.आ.यो. दिशानिर्देशों जो कि केवल ग्रामीण परिवारों के आवृतन की अनुमति देता है, के प्रावधानों के उल्लंघन में शहरी क्षेत्रों में 164 लाभार्थियों को इं.आ.यो. निधियों से लाभ हुआ था। उन्हें ₹40.67 लाख की राशि का भुगतान किया गया था।

झारखंड का मामला अध्ययन

दो जिलों के पांच ब्लॉकों रांची (रातु, मंदार, नागरी) तथा देवघर (देवघर सदर, मधुपुर) में, ग.रे.नी. सूची में '0' अंक वाले 50 लाभार्थियों का चयन किया गया था और उन्हें ₹17.79 लाख का भुगतान किया था। हमने पाया कि चयनित लाभार्थियों के पास मकानों के निर्माण हेतु अपनी भूमि थी जबकि मानदंडों के अनुसार '0' अंक वाले लाभार्थियों के पास भूमि का कब्जा नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, तीन जिलों अर्थात गोड्डा, पूर्व सिंघभूम एवं रांची में, गलत ग.रे.नी. प.प. के प्रति 474 लाभार्थियों को ₹1.29 करोड की सहायता दी गई थी और चार जिलों देवघर, पूर्व सिंहभूम, गढ़वा तथा गोड्डा में बिना ग.रे.नी. प.प. के ही 485 लाभार्थियों को ₹1.01 करोड की सहायता मिली थी। इस प्रकार, ग.रे.नी. सूची की यथार्थता संदेहपूर्ण थी।

3.3.3 अयोग्य लाभार्थियों का चयन

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 1.4 के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे ड्यूटी पर मारे गए रक्षा सेवाओं/अर्धसेना के बल के परिवार/विधवाओं को छोड़कर बेघर ग.रे.नी. परिवार इं.आ.यो. के अंतर्गत योग्य लाभार्थी हैं। हमने पाया कि 11 राज्यों में 10,184 अयोग्य लाभार्थियों का चयन किया गया था और उन्हें ₹ 31.73 करोड़ का भुगतान किया गया था जिसका विवरण नीचे **तालिका -2** में दिया गया है:

तालिका:2 अयोग्य लाभार्थियों को भुगतान

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	लाभार्थी	राशि (₹लाख में)	टिप्पणी
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	2	2	21	6.94	आन्ध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड (आ.प्र.रा.आ.नि.लि.) के परियोजना निदेशक द्वारा समेकित सर्वेक्षण दल की रिर्पोटों के आधार पर अयोग्य घोषित किये जाने के बावजूद 21 लाभार्थियों को भुगतान किया गया था।
2.	गोवा	1	2	12	959	334	संपन्न परिवारों को पुर्ननिर्माण अनुदान दिया गया था।
3.	गुजरात	1	2	उ.न.	870	391.50	ग.रे.नी. में 17 से 20 अंक वाले लाभार्थियों को सहायता दी गई थी।
4.	हरियाणा	5	10	129	470	174.00	गलत सूचना प्रदान करके अयोग्य व्यक्तियों को ग.रे.नी. कार्ड मिले।
		3	3	--	15	5.45	उन व्यक्तियों को भुगतान किए गए जो कि राज्य आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी थे।
5.	जम्मू एवं कश्मीर	2	2	2	12	3.58	लाभार्थी शहरी क्षेत्रों से थे।
		5	9	--	1154	338.10	लाभार्थियों के पास पहले से ही पक्के/अर्ध पक्के मकान थे।
		6	12	--	6423	1779.55	गैर-ग.रे.नी. लाभार्थियों को भुगतान।
6.	झारखण्ड	1	1	4	5	1.45	दो लाभार्थियों को पहले भी मकान आवंटित किए गए थे और तीन लाभार्थियों का गलत तरीके से चयन हुआ था।
7.	मध्य प्रदेश	1	1	--	7	1.00	अयोग्य व्यक्तियों को भुगतान
8.	पंजाब	1	1	--	9	3.15	अयोग्य व्यक्तियों को भुगतान
9.	राजस्थान	2	5	--	77	21.26	अयोग्य व्यक्तियों को भुगतान
10.	तमिलनाडु	3	6	22	129	102.20	लाभार्थियों के अंक 17 से अधिक थे।
11.	उत्तर प्रदेश	2	2	--	33	11.14	जिला गोंडा के अम्बेडकर गॉव खिरोरा शाहबाजपुर (ब्लॉक इतियाथोक) में, 25 अयोग्य

							व्यक्तियों को ₹8.44 लाख का भुगतान किया गया था जोकि जुलाई 2013 तक वसूल नहीं किया जा सका था। जिला रामपुर के ब्लॉक मिलाक के गॉव पुरानिया खुर्द में आठ अयोग्य व्यक्तियों को 2011-12 में ₹2.70 लाख का भुगतान किया गया था। जुलाई 2013 तक दानों मामलों में वसूली लंबित थी।
12.	कुल	**35**	58		**10,184**	**3,173.32**	

राजस्थान के तीन चयनित जिलों में, ऐसे 541 लाभार्थियों को ₹1.22 करोड़ की प्रथम किस्ते जारी कर दी गई थी, (2011-12 के दौरान जिला बूंदी में 363 लाभार्थियों को ₹82.00 लाख, 2008-12 के दौरान जिला सिकर में 153 लाभार्थियों को ₹34.00 लाख और जिला श्रीगंगानगर में 25 लाभार्थियों को ₹6.00 लाख) जिन्होंने अपने मकानों के निर्माण कार्य शुरू नहीं किया था। हमने पाया कि जिला बूंदी में 363 लाभार्थियों ने उन्हें जारी किए गए ₹82.00 लाख की वित्तीय सहायता का गलत उपयोग किया था। यह एक विभागीय सर्वेक्षण में प्रमाणित हुआ था तथा विभाग ने वित्तीय सहायता की वसूली हेतु प्र.सू.रि. दर्ज करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी।

महाराष्ट्र मामला अध्ययन:- इं.आ.यो. के अंतर्गत नाबालिग को एक मकान आवंटित कर दिया गया था

जिला अहमदनगर, ब्लॉक अकोल में ग्रा.पं. पैठन में, 11 वर्ष की आयु के एक नाबालिग को एक रिहायशी इकाई आवंटित की गई थी और उसे ₹68,045 की सहायता का भुगतान किया गया था। उसके माता-पिता के जीवित होने के बावजूद ग.रे.नी. सूची 2002 में जब उसकी उम्र लगभग तीन वर्ष की थी, में से तैयार स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची में नाबालिग का नाम परिवार के मुखिया के रूप में दर्शाया गया था।



अयोग्य लाभार्थियों को दी गई वित्तीय सहायता के नमूना तस्वीरें (दक्षिण गोवा जिले में एक ग.रे.नी. परिवार के दो सदस्य





अपने मौजूदा मकान के सामने श्रीमती 'एक्स' एवं श्रीमती 'वाई'



श्रीमती 'एक्स' का नया मकान



श्रीमती 'वाई' का निर्माणधीन नया मकान

मामला अध्ययन: कर्नाटक

(i) अयोग्य व्यक्तियों को दी गई सहायता

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के अनुसार, घरों के सुधार क्षेत्र 20 वर्ग मीटर से कम नही होना चाहिए। हमने पाया कि लाभार्थी को प्रदत्त संस्वीकृति आदेश निर्धारित करता था कि घर का आकार 40 वर्ग मीटर होना चाहिए, यद्यपि इं.आ.यो. दिशानिर्देश में घर की ऊपरी सीमा का उल्लेख नहीं था।

संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान, 76 मामलों में, यह पाया गया था कि 70 से 120 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र के मध्य में विशाल घर बनाये गये थे जैसा कि निम्न चित्र में देखा जा सकता है। निर्माण की गुणवत्ता, जो इन चित्रों से प्रमाणित होता है कि निर्माण की लागत ₹ 5.00 लाख के नीचे की श्रेणी अंतर्गत नहीं आएगी। अत: लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से नहीं आते थे और इस तरह इं.आ.यो. के अंतर्गत सहायता के हकदार नहीं थे।



हेब्बदी गाँव, मेलापुरा ग्रा.पं., एस.आर.पट्टन टी.पी. मंड्या जि.पं. में इं.आ.यो. घर



मंचनयकनहल्ली ग्रा.पं., रामनगर टी.पी., रामनगर जि.पं. में इं.आ.यो. घर

(ii) निर्मित घरों के विस्तार हेतु प्रयुक्त सहायता

इं.आ.यो. दिशानिर्देश के अनुसार, घरों के निर्माण और रहने के लिए अयोग्य कच्चे घरों के सुधार के लिए सहायता दी जानी थी। मुक्त बंधुआ मजदूरों के संदर्भ में, अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों आदि को सहायता प्रदान की जाएगी। दिशानिर्देश के विपरीत, उन परिवारों को सहायता दी गयी जिनके पास पहले से ही रहने योग्य घर थे। 45 नमूना परीक्षित ग्रा.पं. में, हमने लाभार्थियों के स्वामित्व में मौजूद घरों के विस्तार के रूप में निर्मित घरों के 89 मामले देखे थे जैसा निम्न चित्र में देखा जा सकता है। अत: इन लाभार्थियों को प्रदान की गयी सहायता दिशानिर्दिशों के उल्लंघन में थी।



बेनगहल्ली ग्रा.पं., चन्नपटन टी.पी., रामनगर जि.पं. में इं.आ.यो. घर

3.3.4 प्रतीक्षा सूची से बाहर के लाभार्थी का चयन

इ.आ.यो. दिशानिर्देश के पैरा 2.1 के अनुसार लाभार्थियों का चयन स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची से वरीयता के क्रम में होना था। हमने पाया कि:-

i) **असम** में, चार चयनित जिलों के 28 ब्लॉकों में, 10,694 लाभार्थियों का चयन स्थाई इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची से बाहर से किया गया था और घरों के निर्माण हेतु इं.आ.यो. के अंतर्गत ₹ 40.01 करोड़ की सहायता प्रदान की गयी थी;

ii) **मणिपुर** में, चार चयनित जिलों के सात ब्लॉकों में ₹9.87 करोड़ के लाभ प्रतीक्षा सूची से बाहर के 3,118 लाभार्थियों को प्रदान किये गये थे;

iii) **मिजोरम** में, दो चयनित जिलों के अंतर्गत 25 गॉवों में, 398 लाभार्थियों में से 53 लाभार्थियों का प्रतीक्षा सूची के बाहर से चयन किया गया था और घरों के निर्माण हेतु ₹23.71 लाख की सहायता दी गयी थी;

iv) **ओडिशा** में, गंजम जिले के तीन ब्लॉक में, ₹88.60 लाख का सहायता व्यय करते हुए 314 लाभार्थियों का चयन प्रतीक्षा सूची से बाहर से किया गया था;

v) **उत्तर प्रदेश** में, चार चयनित जिलों के 17 ब्लॉकों में प्रतीक्षा सूची से बाहर के 19,131 लाभार्थियों को ₹86.05 करोड़ की सहायता प्रदान की गयी थी।

vi) **उत्तराखण्ड** में हरिद्वार जिले में, प्रतीक्षा सूची के बाहर से 156 लाभार्थियों का चयन किया गया और ₹72.93 लाख की सहायता प्रदान की गयी थी;

vii) **पश्चिम बंगाल** में, चयनित जिलों के तीन ग्रा.पं.[1] में, ₹23.70 लाख राशि का इं.आ.यो. का लाभ 70 लाभार्थियों को दिया गया था जो प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं थे पर उनके नाम कूच बिहार (4 लाभार्थी, ₹1.23 लाख), मालदा (दो लाभार्थी, ₹0.60 लाख) एवं बीरभूम (64 लाभार्थी, ₹21.87 लाख) के ग्रा.पं. द्वारा अनुमोदित थे।

3.3.5 प्रतीक्षा सूची में वरीयता की उपेक्षा करते हुए लाभार्थियों का चयन

इं.आ.यो. दिशानिर्देश के पैरा 2.1 के अनुसार, लाभार्थियों का चयन स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची से वरीयता के क्रम में किया जाना था। हमने देखा कि नौ राज्यों एवं एक सं.शा.क्षे. के 29 जिलों में 47 ब्लॉकों के 236 ग्रा.पं. में, 4,796 लाभार्थियों का चयन **अनुबंध -3.4** में दिये गये ब्यौरे के अनुसार प्रतीक्षा सूची में वरीयता को अनदेखा करते हुए किया गया था। **असम** में, चयनित दो जिलों (नगांव, सोनितपुर) में, स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची में 1,083 लाभार्थी पहचान पत्रों के प्रति 2,235 लाभार्थियों को चयनित किया गया था।

उत्तर प्रदेश में, आठ चयनित जिलों में, जि.ग्रा.वि.अ. ने मंत्रालय से प्राप्त कुल लक्ष्यों में से राज्य सरकार द्वारा चिन्हित अम्बेडकर एवं लोहिया ग्रामों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लक्ष्यों को चिन्हित किया। इन गॉवों में 17,752 गरीबी

[1] शल्वरी-II (कूच बिहार), सियान-मुलुक (बीरभूम), मशलदा (मालदा)

रेखा से नीचे के बेघर परिवारों को ₹72.06 करोड़ की सहायता इं.आ.यो. के अंतर्गत प्रदान की गयी थी, जो प्रतीक्षा सूची में उनकी वरीयता की संगति में नहीं थी। अत: राज्य सरकार ने इं.आ.यो. निधि से प्रतीक्षा सूची में वरीयता निर्धारित किये बगैर अपनी योजना का निष्पादन किया था।

छत्तीसगढ़ में, सरगुजा जिले के नर्मदापुर ग्रा.प. में, गरीबी रेखा से नीचे के 22 परिवारों को, जो प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं थे, 2009-10 के दौरान ₹7.70 लाख की सहायता प्रदान की गयी थी।

3.3.6 पक्के घर वाले लाभार्थियों का चयन

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायतों द्वारा ग.रे.नी. प्रतीक्षा सूची की सहायता से तैयार की गयी आश्रयहीनों के लिए स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची से किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ राज्यों के चयनित 24 जिलां में 39 ब्लॉकों के 365 ग्रा.पं. में, पक्के घरों वाले 1,654 लाभार्थियों का चयन किया गया था और उन्हें ₹5.36 करोड़ की सहायता प्रदान की गयी थी विवरण **तालिका-3** में दिए गए हैं।

तालिका: 3 पक्के घरों वाले लाभार्थियों को भुगतान

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	बिहार	4	8	22	128	46.52
2.	हरियाणा	6	8	21	40	15.88
3.	जम्मू एवं कश्मीर	5	9	288	1,154	338.10
4.	कर्नाटक	4	7	23	288	117.66
5.	राजस्थान	1	1	2	4	1.71
6.	उत्तर प्रदेश	2	3	4	22	9.90
7.	उत्तराखण्ड	1	2	4	10	4.41
8.	पश्चिम बंगाल	1	1	1	8	2.80
	योग	**24**	**39**	**365**	**1,654**	**536.98**

एक लाभार्थी (ग.रे.नी.प.प: 4323), देहरादून, उत्तराखंड के पक्के मकान का नमूना चित्र जिसे कि वर्ष 2011-12 के दौरान इं.आ.यो. का मकान संस्वीकृत किया गया था।



एक लाभार्थी (ग.रे.नी.प.प: 292), देहरादून, उत्तराखंड के पक्के मकान का नमूना चित्र, जिसे वर्ष 2011-12 के दौरान इं.आ.यो. का मकान संस्वीकृत किया गया था।



3.3.7 लाभार्थियों हेतु सहायता

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 के अनुसार, कच्चे घरों हेतु अनुमेय सहायता प्रति इकाई लागत के अनुदान की सीमा ₹15,000 थी। हमने देखा कि नये निर्माण हेतु निर्धारित दर की वृद्धि के लिए (₹35,000 या ₹45,000) सहायता प्रदान की गयी थी। राज्य वार विवरण नीचे दिए गए हैं:-

- **बिहार** में, सुपौल जिले के प्रतापगंज ब्लॉक में, कच्चे घरों वाले 25 लाभार्थियों को नये घरों के निर्माण हेतु इं.आ.यो. के अंतर्गत ₹10.85 लाख की सहायता प्रदान की गयी थी।
- **जम्मू एवं कश्मीर** में, चयनित 11 (12 में से) ब्लॉकों में कच्चे घरों वाले 9,831 लाभार्थियों में से 3,764 को नये घरों के निर्माण हेतु इं.आ.यो. के अंतर्गत ₹6.96 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी थी।

मंत्रालय ने बताया कि यह आवश्यक नहीं है कि कच्चे घरों वाले लाभार्थी को उन्नयन के लिए सहायता मिले और यह लाभार्थी पर निर्भर करता है कि वह मौजूदा कच्चे घर का उन्नयन करे या मौजूदा घर को गिराकर एक नया घर बनाये और इसी के अनुसार इं.आ.यो. के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी गयी थी।

मंत्रालय का उत्तर उनके द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था।

3.3.8 एक से अधिक बार लाभार्थियों का चयन

हमने देखा कि आठ राज्यों के 30 चयनित जिलों में 141 ब्लॉकों के अंतर्गत 700 ग्रा.पं. में, 5,824 लाभार्थियों का चयन एक से अधिक बार हुआ था और **तालिका-4** में निम्न विवरण के अनुसार उन्हें ₹14.67 करोड़ का भुगतान किया गया था।

तालिका-4: एक से अधिक बार एक ही लाभार्थी को भुगतान

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	लाभार्थी	राशि (₹ लाख में)	टिप्पणी
1	आन्ध्र प्रदेश	2	76	272	4,809	1,106.82	967 लाभार्थियों को दुबारा/तिबारा चयनित किया गया और उनको ₹2.58 करोड़ का भुगतान किया गया था; पर उनसे कोई वसूली नहीं की गयी। {करीमनगर (102), ₹28.22 लाख एवं खम्मम (865), ₹229.94 लाख} खम्मम में 3,842 लाभर्थियों को एक से अधिक घर एक ही राशन कार्ड पर दिये गये थे जिस पर ₹8.49 करोड़ की वित्तीय हानि हुई।
2	असम	4	28	248	513	194.18	कार्बी अंगलोंग, नगांव, बर्पेटा एवं सोनितपुर जिलों में, 513 लाभार्थियों का चयन दुबारा या तो उसी वर्ष किया उसके बाद आने वाले वर्ष में किया गया और उन्हें ₹194.18 लाख का भुगतान किया गया था। इसके अलावा कोकराझार जिले में 87 मामले दोबारा आवंटन के पाए गए जिसमें देबीतोला (52) एवं कचुगांव (35) के मामले थे।
3	जम्मू एवं कश्मीर	5	7	19	20	5.60	सात चयनित ब्लॉकों में 20 मामले में घरों के निर्माण हेतु सहायता एक ही लाभार्थी को दो बार दी गयी थी जो ₹5.60 लाख के अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुआ।
4	झारखण्ड	6	12	44	134	43.06	134 लाभार्थियों को 279 घर आवंटित हुए थे, जिसके कारणवश ₹43.06 लाख के खर्च पर 145 अतिरिक्त घरों के जालसाजी पूर्ण आवंटन हुआ।
5	कर्नाटक	4	4	5	6	2.55	पाँच[2] ग्रा.पं, छः लाभार्थियों को ₹2.55 लाख की सहायता दुबारा दी गयी थी।
6	मणिपुर	4	8	69	243	77.61	243 लाभार्थियों को चार चयनित जिलों में दुबारा/तिबारा सहायता प्राप्त हुई थी।

[2] नेम्मारू (चिकमगलूर जेड.पी.), येलीवाला तथा हीरेनथी (धारवाड़ जि.प.), में मारालाहल्ली (कोप्पल जि.पं.), हरोकप्पा (रामनगर जि.प.)

7	उत्तर प्रदेश	3	3	23	59	22.95	तीन जिलों वाराणसी, महाराजगंज एवं फतेहपुर में 57 पहचान पत्र संख्याओं के प्रति लाभार्थियों को 116 घर आवंटित किये गये थे।
8	उत्तराखण्ड	2	3	20	40	14.54	देहरादून जिले के दो चयनित ब्लॉकों सहासपुर, एवं रायपुर में 77 लाभार्थियों का चयन 38 ग.रे.नी.- प.प के प्रति हुआ था। एवं ₹14.19 लाख की सहायता 39 लाभार्थियों को प्रदान की गयी थी। सहासपुर में एक ग.रे.नी.प.प. के प्रति तीन लाभार्थियों का चयन हुआ था। इसके अतिरिक्त टिहरी जिले के देवप्रयाग ब्लॉक में एक लाभार्थी को ₹35,000 की सहायता दी गयी थी।
	कुल	**30**	**141**	**700**	**5,824**	**1,467.31**	

इस प्रकार, मकानों की कमियों के उचित आकलन के बिना इं.आ.यो. को कार्यान्वित किया गया था तथा मकानों के आवंटन में पारदर्शिता का अभाव था जैसे कि ऊपर चर्चा की गयी है।

3.4 घरों का आवंटन

3.4.1 महिला सदस्यों को घरों के आवंटन में प्राथमिकता नहीं देना

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 2.4 के अनुसार, रिहायसी इकाईयों का आवंटन लाभार्थी परिवार के महिला सदस्य के नाम से होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, इसे पति एवं पत्नी दोनों के नाम से आवंटित किया जा सकता है। तथापि, यदि परिवार में कोई योग्य महिला सदस्य मौजूद/जीवित नहीं हो, किसी पात्र ग.रे.नी. परिवार के पुरूष सदस्य को घर का आवंटन किया जा सकता है। 2005-06 में, भारत सरकार ने पहली बार लिंग आधारित बजट की शुरूआत की थी जिसमें विभिन्न योजनाओं का स्त्रियों को लाभ पहुंचाने में अहमियत को सामने रखा गया था। हमने पाया कि इं.आ.यो. हेतु संपूर्ण आवंटनों को लिंग आधारित बजट में शामिल किया गया था, प्रत्यक्षत: इसलिए क्योंकि इं.आ.यो. के अंतर्गत निर्मित घरों को महिला सदस्यों के नाम से पंजीकृत किया जाना था।

हमने पाया कि 166.88 लाख घरों की संस्वीकृति में से इं.आ.यो. के अंतर्गत 2008-09 से 2012-13 के दौरान केवल 61 *प्रतिशत* (101.15 लाख) मकान महिलाओं के नाम पर संस्वीकृत हुए और 13 *प्रतिशत* (22.07 लाख) परिवार के पुरूष सदस्यों के नाम पर संस्वीकृत हुए थे। पति एवं पत्नी दोनों के नाम पर संस्वीकृत घर 26 प्रतिशत (43.66 लाख) थे।

इसके अतिरिक्त, छः राज्यों में रिहायशी इकाइयों का परिवार के महिला सदस्यों के नाम पर आवंटन को प्राथमिकता नहीं दी गयी थी और 50 से 100 *प्रतिशत* मामलों में पुरूष सदस्यों को प्राथमिकता दी गयी थी एवं आठ राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. में परिवार के महिला सदस्यों के नाम से रिहायसी इकाइयों के आवंटन को 54 से 99 प्रतिशत मामलों में प्राथमिकता दी गयी थी, जिसका विवरण **अनुबंध-3.5** में है। कई राज्यों में, परिवार में योग्य महिला सदस्य की उपस्थिति के बावजूद मकानों को महिला सदस्यों के नाम पर आवंटित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून/जुलाई 2014) कि 80 *प्रतिशत* से अधिक घरों को महिलाओं के नाम से या पति एवं पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से आवंटित किया गया था और 2012-13 के दौरान 28.34 लाख संस्वीकृत घरों में से, 24.66 लाख घरों को महिला के नाम या पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम पर संस्वीकृति दी गयी थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि संशोधित दिशानिर्देशों में विधवा/अविवाहित/अलग हुए व्यक्ति के मामलों को छोडकर पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से आवंटन किया जा सकता था।

तथापि, मंत्रालय का उत्तर कि महिला के नाम पर या परिवारों में पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर 80 *प्रतिशत* से अधिक के मकानों को आवंटित किया गया था जैसा कि लेखापरीक्षा में प्रमाणित हुआ था जो केवल उत्तराखंड से संबंधित थी, तथा कई मामलों में विभिन्न मामलों में महिला को आवंटन के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के उत्तर में, जैसा कि 15 राज्यों/सं.शा.क्षे. के मामले में महिला सदस्यों की घरों के आवंटन के प्रावधानों की गैर-अनुपालना हेतु विस्तृत कारण प्रदान नहीं किए गए थे, **(अनुबन्ध 3.5)** लिंग आधारित बजट के अंतर्गत इं.आ.यो. के लिए पूरे आवंटन को रखने से मंत्रालय की यह सुनिश्चित करने की प्रतिबध्दता बन जाती है कि इं.आ.यो. आवंटन महिलाओं को मजबूत बनाता है जो तभी संभव है यदि घरों के आवंटन विशेष रूप से महिला सदस्यों के नाम से ही किये जाते।

3.4.2 घरों के आवंटन में अन्य अनियमितताएं

विभिन्न प्रकृति की अनियमितताएं भी घरों के आवंटन में देखी गयीं थीं जो निम्नानुसार हैं:-

- पांच राज्यों के 11 चयनित जिलों में 33 ब्लॉकों के 94 ग्रा.पं. में, राज्य विकास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले 126 लाभार्थियों को इं.आ.यो के अंतर्गत ₹46.93 लाख की सहायता प्रदान की गई थी जिसके विवरण **अनुबंध-3.6** में दिये गये हैं।
- **तमिलनाडु** में तिरूचिरापल्ली के चयनित तीन ब्लॉकों[3] में 37 ग्राम पंचायतों में 664 लाभार्थियों में से 144 चयन राज्य योजना (100 *प्रतिशत* राज्य द्वारा वित्तपोषित) के अंतर्गत किया गया था और राज्य योजना के अंतर्गत आधारभूत चरण समाप्त करने के पश्चात, "नये निर्माण" श्रेणी के अंतर्गत इं.आ.यो. में नये निर्माण श्रेणी में राज्य वित्त पोषित योजना से किये जा चुके भुगतान को समायोजित कर 2012-13 के दौरान अंतरित कर दिया गया था और ₹61.15 लाख राशि की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी थी।

[3] तिरूवेरम्बूर, तुरय्युर एवं उप्पीलियापुरम

3.5 वस्तु सूची निर्माण

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 5.9 के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों के पास इं.आ.यो. के अंतर्गत निर्मित/उन्नयन किये गये घरों की एक संपूर्ण वस्तु-सूची होनी चाहिए, जिसमें रिहायशी इकाई के निर्माण के शुरूआत की तिथि एवं कार्य पूर्ण की तिथि के ब्यौरे जहॉ घर अवस्थित या उसके गॉव एवं ब्लॉक के नाम, लाभार्थियों के पेशे एवं श्रेणी तथा अन्य प्रासंगिक ब्यौरे शामिल हों।

हमने देखा कि घरों की वस्तु-सूची 14 राज्यों एवं एक सं.शा.क्षे. में नहीं बनाई गयी थी, उनके नाम है- **अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा (उत्तरी गोवा), जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा,** एवं **लक्षद्वीप**। **आंध्र प्रदेश** ने घरों की वस्तु सूची ठीक से बनायी थी। 2003 के पिछले नि.म.ले.प. प्रतिवेदन सं.3 में भी यह 12 राज्यों के मामले में इंगित किया गया था, यथा **अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब एवं राजस्थान**। **मिजोरम** में, चार ब्लॉकों में से केवल दो यथा तलग्नुयाम एवं खवजावल ब्लॉकों ने घरों की पूर्ण वस्तु-सूची अनुरक्षित की थी। वस्तु-सूची के अनुरक्षण में अन्य अनियमितताएं भी देखी गयी थीं जो नीचे दी गयी हैं:-

- **गुजरात** में, सूरत जिले के दो तालुके[4] और वडोदरा जिले के दो तालुके[5] में घरों की वस्तु-सूची अनुरक्षित नहीं की थी, जबकि वडोदरा जिले के दभोई तालुके में 2009-10 तक वस्तु सूची का अनुरक्षण नहीं हुआ था। 2009-10 के पश्चात अनुरक्षित वस्तु-सूची अधूरी थी क्योंकि आवश्यक सभी सूचना भरी नहीं गयी थी। आनंद, दाहोद, सुरेन्द्रनगर एवं बनस्कंठ के छ: तालुको[6] के चयनित ग्रा.पं. में अनुरक्षित वस्तु-सूचियाँ भी अधूरी पायी गयी थी।

---

[4] कमरेज एवं मांडवी

[5] कर्जन एवं संखेड़ा

[6] आनंद, तारापुर (आनंद), चोटिला, सायुला (सुरेन्द्रनगर), दांतेवाड़ा, पालनपुर (बनस्कंठ), लिम्खेड़ा, जालोद (दाहोदा),

- **नागालैण्ड** में लाभार्थियों को दिये गये सी.जी.आई. शीट से संबंधित अभिलेख को घरों के वस्तु-सूची के रूप में लिया गया था। इसने प्रत्यक्ष निरीक्षण को महत्वहीन कर दिया क्योंकि लेखापरीक्षा वास्तविक इं.आ.यो. घरों की पहचान नहीं कर पाया।
- **कर्नाटक** में, आर.जी.आर.एच.सी.एल. द्वारा विकसित किये गये सॉफ्टवेयर को ग्रा.पं. में निर्मित/उन्नयन किये गये घरों से संबंधित ब्यौरों को अभिलिखित करने में 2006-07 से ही प्रयोग में लाया जा रहा था। हालांकि, इसमें निर्माण के आरंभ की तिथि घर के बनवाने की तिथि एवं लाभार्थी द्वारा घर के अधिभोग की तिथि जैसे महत्वपूर्ण ब्यौरे अभिलिखित नहीं थे।
- **उत्तराखंड** में, सभी पांच वर्षों के लिए घरों की पूरी वस्तु सूची टिहरी गढ़वाल, यू.एस. नगर एवं देहरादून के जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा तैयार नहीं की गयी थी। इन जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा वर्ष 2008-10 के दौरान तैयार किये गये और संस्वीकृत घरों की विषय-सूची उपलब्ध थी परंतु उसे नियमित रूप से अद्यतित नहीं किया गया था।

अनुशंसाएं:

- राज्यों में घरों की कमी का आवधिक आकलन किया जाए ताकि इं.आ.यो. के अंतर्गत निधियों के आवंटन को अधिक यथार्थवादी एवं वर्तमान आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जा सके।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थायी प्रतीक्षा-सूचियों के निर्माण एवं उसके नियमित अद्यतन को सुनिश्चित कर इं.आ.यो. के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
- लाभार्थियों के नामों के साथ मकानों की अद्यतित सूची को सभी कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अनुरक्षित किया जाना चाहिए।

अध्याय 4 : घरों का निर्माण तथा गुणवत्ता

4.1 भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

ग्रामीण आवास पर योजना आयोग के अंतर्गत कार्य दल ने XIवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) हेतु ग.रे.नी. के परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 426.90 लाख घरों की कमी का निर्धारण किया। इसमें से, 150 लाख (30 लाख घर प्रति वर्ष) घरों की कमी को इं.आ.यो. के अंतर्गत पूरा किया जाना था। इसके अतिरिक्त, XIवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्ष में 2012-13 हेतु 50 लाख घरों की कमी को निर्धारित किया गया था। इस प्रकार, कार्य दल ने 2008-13 हेतु इं.आ.यो. के अंतर्गत 170 लाख घरों के निर्माण के लक्ष्य को निर्धारित किया। तथापि, उसी अवधि हेतु मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदत्त बजटीय परिव्यय के आधार पर इं.आ.यो.के अंतर्गत निर्माण किए जाने वाले केवल 148.25 लाख घरों का लक्ष्य निर्धारित किया। हमने पाया कि 148.25 लाख घरों के लक्ष्य के प्रति केवल 128.92 लाख घरों (मंत्रालय के लक्ष्य के प्रति 86.96 प्रतिशत तथा कार्य दल लक्ष्य के प्रति 75.84 प्रतिशत) का निर्माण किया गया था जैसा नीचे तालिका 5 में दर्शाया गया है:

तालिका : 5 भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धि

(आंकड़े ₹लाख में[1])

वर्ष	व्यर्थ दल के अनुसार लक्ष्य	मंत्रालय के अनुसार लक्ष्य	वास्तव में पूर्ण घर
2008-09	30.00	21.27	21.34
2009-10	30.00	40.52	33.86
2010-11	30.00	29.09	27.15
2011-12	30.00	27.27	24.71

[1] आंकड़े पूरे देश से संबंधित है।

2012-13	50.00	30.10	21.86
कुल	**170.00**	**148.25**	**128.92**

हमने पाया कि, इं.आ.यो. 2008-13 के दौरान ₹60,239 करोड़ के व्यय के बावजूद भी देश में घरों की कमी में अंतराल को काफी हद तक पूरा नहीं कर सकी क्योंकि XIवीं पंचवर्षीय योजना (426.90 लाख) की शुरूआत पर मूल्यांकन की गई घरों की कमी की समस्या, XIIवीं पंचवर्षीय योजना (400 लाख)के प्रारम्भ में लगभग समान रही।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि इं.आ.यो. के अंतर्गत लक्ष्य केा प्रति वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदत्त बजटीय परिव्यय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। हालांकि, लेखापरीक्षा की राय में, लाभार्थी के चयन में गैर-पारदर्शिता के साथ के साथ दोबारा/तीबारा आवंटन, जैसी योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न कमियां उपलब्ध आंवटनों के बेहतर उपयोग हेतु सीमा तथा आश्रयहीनता को शीघ्रता से समाप्त करने को रोकता है।

4.2 अपूर्ण घरों पर निष्फल व्यय

इं.आ.यो. की दिशानिर्देशों के पैरा 5.10 के अनुसार, इं.आ.यो. घरों को निर्माण में दो वर्षों से अधिक नहीं लिए जाने चाहिए।

नौ राज्यों अर्थात् असम, बिहार, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मंघालय तथा राजस्थान के 48 चयनित जिलों में दो वर्षों से अधिक के बीत जाने के बावजूद भी 61,293 घर अपूर्ण रहे जिसका परिणाम इन अपूर्ण घरों के संबंध में ₹150.22 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ। ब्यौरे नीचे **तालिका-6** में दिए गए हैं:

तालिका: 6 अपूर्ण इं.आ.यो. घरों के ब्यौरे

राज्य/सं.शा.क्षे.	जिलों की संख्या	दो वर्षों से अधिक से अपूर्ण घर	अपूर्ण घरों में शामिल राशि (₹ करोड़ में)
असम	02	750	1.48
बिहार	10	13,405	36.87
गुजरात	06	16,607	**34.91
जम्मू एवं कश्मीर	05	1,035	1.94
झारखण्ड	06	6,396	14.80
कर्नाटक	08	13,625	15.78
महाराष्ट्र	05	6,432	35.19
मेघालय	01	83	0.25
राजस्थान	05	2,960	8.70
कुल	**48**	**61,293**	**150.22**

** 12,717 अपूर्णघरों की राशि क्योंकि शेष 3,890 घरों की राशि को परिकलित नहीं किया जा सका।

मामला अध्ययन: – गुजरात तथा झारखण्ड में इं.आ.यो. घरों की भौतिक प्रगति को गलत सूचित किया जाना

गुजरात के आणंद जिले के तारापुर तालुका में दो घरों के निर्माण को लिनटेल स्तर तक पूर्ण रूप में दर्ज किया गया था तथा लाभार्थियों को लिनटेल स्तर तक स्वीकार्य सहायता की राशि अदा की गई थी। तथापि, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि घर लिनटेल स्तर तक पूर्ण नहीं हुए थे जैसा **चित्र 1** तथा **2** में नीचे दर्शाया गया है। इसी प्रकार, आनंद तालुका में कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत समापन प्रमाण-पत्र तथा फोटों के आधार पर घर केा पूर्ण किया गया के रूप में दर्शाया गया था। लाभार्थी केा अंतिम किश्त प्रदान की गई थी। तथापि,संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि वह घर अपूर्ण थे जैसा **चित्र 3** या **4** में नीचे दर्शाया गया है। इस प्रकार, संबंधित अभिलेख ने सही स्थिति को नहीं दर्शाया।

तालूका विकास अधिकारी (ता.वि.अ.) ने बताया (जून 2013) कि मामले की जांच की जाएगी तथा संबंधित तालती (अन्य राज्यों में पटवारी के समान पंचायत में पंचायत मंत्री) तथा अतिरिक्त सहायक अभियंता (अ.स.अ.) से स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी तथा सभी संबंधितों को अंतिम समापन प्रमाणपत्र पस्तुत करते समय उचित स्थान रखने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।



चित्र 1: आणन्द जिले के तारापुर तालुका में मोराज में इं.आ.यो. का घर



चित्र 2: आणन्द जिले के तारापुर तालुका में मोराज में इं.आ.यो. का घर

कार्यालय अभिलेख के अनुसार फोटो



चित्र 3: आणन्द जिले में आणन्द तालुका में समारखा गांव में इं.आ.यो. का घर

स्थल यात्रा के अनुसार वास्तविक फोटो



चित्र 4: आणन्द जिले में आणन्द तालुका में समारखा गांव में इं.आ.यो. का घर

झारखण्ड में, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि ₹62.98 लाख के भुगतान हुए 151 घर अपूर्ण थे जबकि अभिलेखों के अनुसार इन घरों को पूर्ण किया गया सूचित किया गया था। इस प्रकार, उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि घरों की भौतिक प्रगति जैसा कि अभिलेखों में उल्लेखित की गई थी, गलत थी तथा समापन प्रमाणपत्र की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। नमूना मामलों का चित्र 5 एवं 6 में नीचे दर्शाता गया है।



चित्र-5: डोडा जिले के गोडा सदर ब्लॉक में गोरसंदा ग्रा.पं में योजना सं.51/08-09 में इं.आ.यो. का घर तथा लाभार्थी को ₹34,300 (अंतिम भुगतान) अदा किए गए थे।



चित्र-6: रांची जिले के नामकुम ब्लाक में सोदाग ग्रा.पं. योजना सं. 198/08-09 में इं.आ.यो. का घर तथा लाभार्थी को ₹35,000(अंतिम भुगतान) अदा किए गए थे।

अपूर्ण घरों के संबंध में देखी गयी कुछ अनियमितताएं निम्नानुसार हैं:

- **गोवा** में, 2010-11 तक संस्वीकृत 4,111 नए घर तथा 1316 सुधार मामले, कार्य स्थल पर राज्य/जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा उपयुक्त निरीक्षण की कमी तथा घरों के निर्माण के विभिन्न चरणों पर अप्रभावी मॉनीटरिंग के कारण 31 मार्च 2013 तक अपूर्ण थे।

- **हिमाचल प्रदेश** में, 2008-09 के आरम्भ में, 1,442 घर निर्माणधीन थे। 2008-13 के दौरान 31570 घर संस्वीकृत किए गये थे। संस्वीकृत 33,012 घरों के प्रति मार्च 2013 तक 963 घरों का अपूर्ण छोड़ते हुए 32,049 घरों को पूर्ण किया गया था। तथापि, निदेशक, आर.डी.डी. ने मंत्रालय को अपूर्ण के रूप में 269 घरों को सूचित किया। सूचित किए गए आंकड़ों के बेमेलता होने का कारण विभाग से प्रतीक्षित था।

- **मध्य प्रदेश** में, 13 चयनित जिलों में, 2008-13 के दौरान 21,574 अपूर्ण घरों को मासिक प्रगति रिपोर्ट में गलत आकलन के कारण पूर्ण के रूप में सूचित किया गया था।
- **मेघालय** में, चार जिलों[3] में सात चयनित ब्लॉकों[2] में लेखापरीक्षा अपूर्ण घरों, यदि कोई हो, की स्थिति का पता नहीं लगा सकी तथा परिसम्पत्ति सूची/परिसम्पत्ति रजिस्टर के अनुरक्षण न करने के कारण यह भी निर्धारित नहीं कर सकी कि क्या इं.आ.यो. के घरों को वास्तव में दो वर्षों की निर्धारित अवधि में पूर्ण किया गया था।
- **त्रिपुरा** में, 2008-09, 2009-10 तथा 2012-13 के दौरान राज्य द्वारा प्रेषित वार्षिक उपलब्धि रिपोर्ट में पिछले वर्ष के 26,398 अपूर्ण इं.आ.यो. के घरों की स्थिति को मंत्रालय को सूचित नहीं किया गया था। इस प्रकार, 26,398 अपूर्ण इं.आ.यो. के घरों की स्थिति सूची के अनुरक्षण न किए जाने के कारण, पता न लगाने योग्य रही।
- **उत्तराखण्ड** में, राज्य स्तर पर अभिलेख ने प्रकट किया कि अप्रैल 2008 से पहले, पूरे राज्य (12 जिलों) में 1353 अपूर्ण घर थे जबकि तीन चयनित जिलों में ही अपूर्ण घरों की संख्या 3,084 थी जोकि खराब रिपोर्टिंग नियंत्रणों को दर्शाता है।

पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी **गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक** तथा **उत्तराखण्ड** में लाभार्थियों द्वारा सहायता की एक अथवा दो किश्त की प्राप्ति के पश्चात घरों के परित्याग/गैर-समापन को भी इंगित किया गया था।

---

[2] पिनूर्सला, मॉवशीर्न्त, माक्रीवटा, रीसूबेलपारा, सांगसाक, डालू, टिकरीकिला

[3] पूर्व खासी हिल्स, पश्चिम खासी हिल्स, पूर्व गारो हिल्स, पश्चिम गारो हिल्स

मंत्रालय ने बताया (जून 2014) कि घरों को दो से तीन वर्षों में पूर्ण किया गया है। इस प्रकार, एक वर्ष की समाप्ति पर अपूर्ण रहे घर को बाद के वर्ष के दौरान पूर्ण किया जाता है। मंत्रालय का उत्तर इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों में वर्तमान प्रावधानों के प्रतिकूल है जो प्रावधान करते हे कि किसी भी मामले में धर के समापन में दो वर्षों से अधिक नहीं लिया जाना चाहिए तथा लेखापरीक्षा में उन मामलों को इंगित किया जिनमें घर दो वर्षों से अधिक तक अपूर्ण रहे।

उत्तराखंड में अपूर्ण घरों की नमूना तस्वीरें



एक लाभार्थी (बी.पी.एल. आई.डी.: 634), देहरादून, रायपुर बद्रीपुर में (संस्वीकृत वर्ष 2011-12)



एक लाभार्थी (बी.पी.एल. आई.डी.: 634), देहरादून, रायपुर

मामला अध्ययन: झारखण्ड में लाभार्थियों द्वारा पूर्ण राशि प्राप्त किए जाने के पश्चात परित्याग किए गए इं.आ.यो. के घर

झारखण्ड में, ₹8.32 लाख का व्यय करने के पश्चात भी 25 घरों का विभिन्न कारणों अर्थात् भूमि विवादों, लाभार्थी की मृत्यु आदि के कारण परित्याग कर दिया गया था। कुछ मामलों में अंतिम भुगतान प्राप्त करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था राँची, पूर्वी सिंहभूम तथा देवघर जिलों में परित्याग किए घरों का कुछ नमूना चित्र नीचे दिये गये हैं:



रॉची जिले के रातू ब्लॉक में पाली ग्रा.पं. में योजना सं. 67/2009-10 में इं.आ.यो. का घर तथा लाभार्थी के ₹35000 (अंतिम भुगतान) अदा किए जाने के पश्चात परित्याग किया गया था



रॉची जिले के रातू ब्लॉक में हुरहुरी ग्रा.पं. में योजना सं. 88/2009-10 में इं.आ.यो. का घर तथा लाथार्थी को ₹35000 (अंतिम भुगतान) अदा किए जाने के पश्चात् परित्याग किया गया था।



पूर्वी सिंह भूम जिले के गुरूबंदा ब्लॉक में फोरेस्ट ब्लाक में योजना सं. 115/2010-11 में ₹48500 (अंतिम भुगतान) अदा किए जाने के पश्चात् परित्याग किया गया था



पूर्वी सिंहभूम जिले के गुरूबंदा ब्लॉक में फोरेस्ट ग्रा.पं. में योजना सं. 115/2010-11 में ₹48500 (अंतिम भुगतान) अदा किए जाने के पश्चात परित्याग किया गया था।

मामला अध्ययन: निर्माण का प्रारम्भ न होना

<u>असम</u>

कोकराझार जिले के दो ब्लाकों (काचूगांव, कोकराझार) में 8,500 तथा 8,458 इं.आ.यो. लाभार्थियों में से, क्रमश: 767 तथा 1,907 लाभार्थियों ने निर्माण आरम्भ नहीं किया था जबकि उनको ₹3.44 तथा ₹7.72 करोड़ की निधियां जारी की गई थीं। (100 प्रतिशत सहायता)।

लाभार्थियों द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की विफलता के कारण अभिलेख में नहीं थे।

मामला अध्ययन: कुल ₹3.87 करोड़ का व्यर्थ व्यय <u>जम्मू एवं कश्मीर-</u>

छ: चयनित जिलों के 10 ब्लॉकों में, 2008-12 के दौरान 1,903 लाभार्थियों केा इं.आ.यो. के घरो के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में कुल ₹3.87 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इन मामलों में दूसरी किस्त जारी नहीं की गई थी तथा विभाग ने निर्माण की स्थिति को मॉनीटर नहीं किया था। निर्माण/निर्माण पश्चात कार्य तथा संबंधित डाटा की किसी भी मॉनीटरिंग के अभाव में लेखापरीक्षा इन मामलों के निर्माण के बारे में पता नहीं लगा संकी थी। ब्ला.वि.मं. ने उत्तर दिया कि लाभार्थियों का चयन ग्रा.पं. द्वारा किया गया था। उत्तर समस्या का निपटान करने हेतु उपचारी उपायों की आवश्यकता को अनदेखा करता है।

4.3 ठेकेदारों/विभागों द्वारा इं.आ.यो. के घरों का अनियमित निर्माण

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों का पैरा 5.1 अनुबंध करता है कि इं.आ.यो. के अंतर्गत आवसीय इकाईयों के निर्माण में कोई ठेकेदार शामिल नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो भारत सरकार को उन इं.आ.यो. के घरों हेतु राज्य

को किए गए निर्गमों को वसूलने का अधिकार होगा। घरों का निर्माण किसी भी सरकारी विभाग द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

असम, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में इं.आ.यो. के घरों के निर्माण हेतु इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में ठेकेदारों की नियुक्ति को पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी इंगित किया गया था। हमने वर्तमान की लेखापरीक्षा में भी वही स्थिति पाई। पांच राज्यों/सं.शा.क्षे. अर्थात् **असम, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह** में आठ चयनित जिलों के 12 ब्लॉकों में ₹7.88 करोड़ की लागत के इं.आ.यो. के घरों का निर्माण ठेकेदारों द्वारा अथवा विभागीय रूप से किया गया था। राज्यवार ब्यौरे **अनुबंध 4.1** में दिए गए हैं।

4.4 इं.आ.यो. के घरों के रूपरेखा प्रकार की अस्वीकृति

इ.आ.यो. के दिशानिर्देशों का पैरा 5.3 प्रत्येक राज्य सरकार को तकनीकी तथा सामग्री विशिष्टताओं सहित इं.आ.यो. के घरों के लिए रूपरेखा प्रकार को अंतिम रूप देने हेतु आज्ञा देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि घर स्थाई दीवारों तथा छत के साथ पक्का बना है।

हमने पाया कि 22 राज्यों अर्थात् **अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल** के सभी 140 चयनित जिलों में राज्य सरकारों द्वारा रूपरेखा प्रकार को अंतिम रूप/स्वीकृत नहीं किया गया था।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इं.आ.यो. के घरों के निर्माण हेतु डिजाईन प्रदान किए (अक्तूबर 2010)। भूकम्पीय क्षेत्र में आने वाले इं.आ.यो. के घरों में आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकी को अपना कर घरों का निर्माण हेतु पूर्व-अपेक्षित था। तथापि, घरों के निर्माण हेतु आपदा प्रतिरोधी विशिष्टता वाले डिजाईनो को नहीं अपनाया गया था। विभाग ने बताया कि आपदा प्रतिरोधी विशिष्टताओं को अपनाना निर्माण की लागत को बढ़ाएगा। तथापि, हमने पाया कि प्रशासन ने आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु सहायता की

राशि को बढ़ाने के लिए मामले को कभी भी मंत्रालय के साथ नहीं उठाया था। प्रशासन ने बताया कि ग.रे.नी. के लाभार्थियों को आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएंगे।

मंत्रालय ने बताया कि राज्यों ने इं.आ.यो. के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त निधियों की मांग की थी तथा 2013-14 से राज्यों को प्रशासनिक व्ययों के रूप में इं.आ.यो. निधि के चार प्रतिशत का उपयोग करने हेतु अनुमत किया गया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि राज्य सरकारों को लाभार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु प्रकार डिजाईनों, जो इं.आ.यो. के घरों हेतु स्थानीय रूप से संगत थे को तैयार करने तथा अपने स्तर पर, आई.आई.टी. दिल्ली के सहयोग से, ग्रामीण आवासीय ज्ञान नेटवर्क पोर्टल, रूपरेखा प्रकार, निर्माण तकनीक तथा ग्रामीण आवासीय क्षेत्र में व्यवसायियों के संबंध में सूचना पर एक ज्ञानकोष, को स्थापित करने का अनुरोध किया गया था।

4.5 निर्माण कार्य को समन्वित करने हेतु समिति का गठन

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के पैरा 2.3 के अनुसार, इं.आ.यो. के घरों के निर्माण कार्य को समन्वित करने हेतु डी.आर.डी.ए./जि.पं. स्तर पर एक समिति, यदि ऐसा वांछित हो, गठित की जा सकती है। समिति को घरों के डिजाईनों में आपदा प्रतिरोधी विशिष्टता केा शामिल करने हेतु सुग्राही बनाया जाएगा।

हमने पाया कि 16 राज्यों अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा,गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड,** तथा **पश्चिम बंगाल** के सभी 102 चयनित जिलों में ऐसी कोई समितियां गठित नहीं की गई थी।

4.6 इं.आ.यो. के घरों की लागत प्रभावकारिता तथा स्थायित्व

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के पैरा 5.2 तथा 7.2 के अनुसार, स्थानीय सामग्री को अधिकतम संभावित सीमा तक उपयोग करने तथा लागत प्रभावी आपदा प्रतिरोधी तथा वतावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। जिलों को इं.आ.यो. के लाभार्थियों को इन रूपरेखाओं पर अपने घरों का निर्माण/सुधार करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए अभिनव प्रौद्योगियों, सामग्रियों, रूपरेखाओं तथा पद्धतियों पर सूचना की मांग हेतु स्थापित ग्रामीण निर्माण केन्द्रों, हुडको आदि से संपर्क करना चाहिए।

18 राज्यों/सं.शा.क्षे. अर्थात् **बिहार, छत्तीसगढ़ गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडीशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल** तथा **लक्षद्वीप** में सभी 250 चयनित ब्लॉकों तथा 110 चयनित जिलों में कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा आपदा प्रतिरोधी घरों के निर्माण/सुधार हेतु इं.आ.यो. लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के कोई प्रयास नहीं किए गए थे।

4.7 प्रशिक्षण सेमिनार तथा कार्यशालाएं

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों का पैरा 5.7 निर्धारित करता है कि राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर इं.आ.यो. के साथ कार्य कर रहे अधिकारियों को घरों में अपनाए जाने वाली विभिन्न आपदा प्रतिरोधी विशिष्टताओं में प्रशिक्षित किया जाना था तथा इनके फील्ड दौरों के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना था कि इसकी अनुपालना की गई है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय बढ़ई तथा मिस्त्रीयों को एस.जी.एस.वाई के अंतर्गत कौशल सुधार, एवं निम्न लागत प्रौद्योगिकी तथा स्थानीय सामग्री के उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया जाना था। जिला तथा ब्लॉक स्तर पर निम्न लागत प्रौद्योगिकियों की प्रदर्शनियों,सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से आपदा प्रतिरोधी तथा वातावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों संबंध में

लाभार्थियों के बीच जागरूकता उत्पन्न की जानी थी। उस उद्देश्य हेतु राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (रा.ग्रा.वि.सं.), विस्तारित प्रशिक्षण केन्द्रों की सेवाओं का भी उपयोग किया जाना था।

4.7.1 इं.आ.यो. के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा बढ़ईयों/मिस्त्रीयों को प्रशिक्षण की कमी

- 26 राज्यों/ सं.शा.क्षे. अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** तथा **लक्षद्वीप** में 148 चयनित जिलों के 341 चयनित ब्लॉकों में राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं थे। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध 4.2 में दिए गए हैं।

- 22 राज्यों/ सं.शा.क्षे. अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा गुजरात, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** में 125 चयनित जिलों के 285 चयनित ब्लॉकों में स्थानीय बढ़ईयों तथा मिस्त्रीयों को उनके कौशल सुधार, आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकी तथा निम्न लागत प्रौद्योगिकी तथा स्थानीय सामग्री के उपयोग हेतु प्रशिक्षित नहीं किया गया था। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध 4.2** में दिए गए हैं।

4.7.2 लाभार्थियों की जागरूकता हेतु कार्यशालाओं/सेमिनारों का अभाव

11 राज्यों/सं.शा.क्षे. अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तथा अण्डमान एवं निकोबार, द्वीपसमूह में 77 चयनित जिलों के 176 चयनित ब्लॉकों तथा में समीक्षा अवधि के दौरान जिला तथा ब्लॉक स्तर पर इं.आ.यो. के घरों हेतु आपदा प्रतिरोधी, वातावरण अनुकूल तथा निम्न लागत प्रौद्योगिकियों के संबंध में लाभार्थियों के बीच किसी भी जागरूकता कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, सेमिनारों अथवा कार्यशालाओं का आयोजन नहीं किया गया था जैसा ब्यौरा अनुबध 4.2 में है।

4.8 गुणवत्ता निरीक्षण/तकनीकी पर्यवेक्षण का अभाव

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के पैरा 5.7.1 के अनुसार, इं.आ.यो. के घरों के निर्माण हेतु तकनीकी पर्यवेक्षण प्रदान किया जाना चाहिए तथा चूंकि नीव डालना तथा लिंटेल स्तर घर की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण चरण हैा इसलिए कम से कम इन दो चरणों पर तकनीकी पर्यवेक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

13 राज्यों, अर्थात्, **बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, नागालैण्ड,ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड** तथा **पश्चिम बंगाल** में 91 जिलों के 214 ब्लॉकों के अंतर्गत 1,639 ग्रा.पं. (2,960 चयनित ग्रा.पं. का 55.37 प्रतिशत) में संबंधित प्राधिकारियों/तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किसी भी चरण पर कोई गुणवत्ता निरीक्षण/ तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया गया था। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध 4.3** में दिए गए हैं।

गुणवत्ता निरीक्षण में पाई गई अन्य अनियमितताएं नीचे दी गई हैं:

- **असम** में, परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. (जिला, कर्बी एंगलोंग) ने संयुक्त ब्लॉक भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया कि:-
  - लोंगसोंम्पी के अंतर्गत 14 लाभार्थियों के घरों के निर्माण में स्तम्भों को बिना नीव के खड़ा किया गया था।

- ब्लॉक रोगरवांग के हारू माटीखोला क्षेत्र में 2011-12 के दौरान निर्मित घरों की गुणवत्ता खराब थी। कोई प्लिनथ नहीं था तथा दरवाजों एवं खिड़कियां निम्न गुणवत्ता की लकड़ी से बनी थी। छत के लिए उपयोग किए गए लोहे के पुलिंदों की गुणवत्ता भी बेकार थी।
- ब्लॉक सोचेंग के अंतर्गत चार लाभार्थियों के घर घटिया सामग्री से बनाए गए थे। खिडकियों को कमजोर बांस की दीवारों तथा बिना चौखट के लगाया गया था। परिणामस्वरूप, लाभार्थी इन मकानों में रहने के लिए अनिच्छुक थे।

- **मणिपुर** में,संयुक्त भौतिक सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्मित घरों की गुणवत्ता बेकार थीं जबकि डी.आर.डी.ए. ने पाया कि निर्माण के दौरान घरों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की गई थी।
- **मेघालय** में तकनीकी पर्यवेक्षण प्रदान करने तथा इं.आ.यो. के घरों की गुणवत्ता का निरीक्षण करने हेतु ग्राम स्तर पर केवल अवर अभियंता (अ.अ.) तथा ग्राम सेवक (ग्रा.से.) नियुक्त किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि अपर अभियंता को ब्लॉक स्तर पर केवल एक मात्र तकनीकी व्यक्ति होने से, उसके लिए उसके अंतर्गत ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम के इं.आ.यो. कार्यकलापों में पूर्ण रूप से शामिल होना सम्भव नहीं था।

घरों की बेकार गुणवत्ता के नमूना फोटों



उत्तराखण्ड में टेहरी गढ़वाल जिले की गेड ग्रा.पं, जोनपुर ब्लॉक में इं.आ.यो. का घर (संस्वीकृति को वर्ष: 2011-12) (भु.ति. 27.05.13)



उत्तराखण्ड में टेहरी गढ़वाल जिले की जाखेद ग्रा.पं. दीयोपराग ब्लॉक में इं.आ.यो. का घर (संस्वीकृति का वर्ष: 2009-10) भु.ति. 21.05.2013)

मामला अध्ययन: कर्नाटक में इं.आ.यो. के घर का निर्माण

गैर-आवासीय उद्देश्य हेतु उपयोग किए गए घर

इं.आ.यो. सहायता से निर्मित घरों का उपयोग मानव निवास हेतु किया जाएगा। संयुक्त भौतिकी निरीक्षण के दौरान, 31 चयनित ग्रा.पं. में यह पाया गया कि 44 घरों का गैर-आवासीय उद्देश्यों अर्थात् जैसे पशु-शेड, गोदाम, ईंट फैक्टरी, किराना की दुकान, होटल आदि के लिए किए जा रहे थे। नीचे दिए गए चित्र में, दर्शाया गया मकान होटल के रूप में उपयोग किया जा रहा था।



चिकमगलूर जिला जिले की मुगलावल्ली ग्रा.पं., चिकामगलूर तालूका में होटल के रूप में उपयोग किया गया इं.आ.यो. का घर

अनुशंसा :

- मकानों के निर्माण की निम्न गुणवत्ता पर लेखापरीक्षा की विभिन्न अभयूक्तियों को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन अभिकरणों की जवावदेही को सुनिश्चित करने के लिए, निर्माणाधीन घरों के निरीक्षण कराए जाएं और ऐसे निरीक्षणों की प्रलेखित निरीक्षण रिपोर्टें अनुरक्षित की जाएं।

अध्याय 5: वित्तीय प्रबंधन

5.1 निधियन एव लागत-हिस्सेदारी

इं.आ.यो. का वित्त-पोषण भारत सरकार (भा.स.) एवं राज्य सरकारों के मध्य 75:25 के अनुपात में लागत-हिस्सेदारी के आधार पर होता है। तथापि, उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में, इसके वित्त पोषण का अनुपात 90:10 है। जबकी संघ शासित क्षेत्रों में, पूरी निधि भा.स. द्वारा दी जाती है।

इं.आ.यो. के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता राज्यों/सं.शा.क्षे. के मध्य 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आवास कमी को 75 प्रतिशत प्राथमिकता देते हुए एवं 25 प्रतिशत प्राथमिकता राज्य/सं.शा.क्षे. के योजना आयोग द्वारा 2004-05 में निर्धारित गरीबी अनुपात को देते हुए आबंटित की जाती है।

किसी राज्य/सं.शा.क्षे. के अंदर अंतर्जिला आबंटन 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आवास की कमी को 75 प्रतिशत प्राथमिकता देते हुए और संबंधित जिले के ग्रामीण अ.जा./अ.ज.जा. जनसंख्या को 25 प्रतिशत प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा। ब्लॉकों के अंदर किसी जिला एवं ग्राम पंचायतों हेतु वित्तीय आबंटन इसी सिद्धांत पर निर्धारित किये जाएंगे।

हमने देखा कि पूरे **असम** में, ब्लॉकों एवं ग्रा.पं. केा निधियों के आबंटन हेतु उपरोक्त वर्णित सिद्धांतों का पालन 2008-13 के दौरान नहीं किया गया था।

केरल में, चयनित चार जिलों में से तीन (अलप्पुझा, तिरूवनंतपुरम एवं वयनद) की गरीबी उन्मूलन इकाईयों (ग.उ.इ.) ने ब्लॉक पंचायतों को निधियों के आबंटन हेतु सिद्धांत का पालन नहीं किया था। जिलों की ग.उ.इ. ने, जिले के ग्रामीण अ.जा./अ.ज.जा. जनसंख्या को 25 प्रतिशत प्राथमिकता नहीं दी थी। बेघर परिवारों और अ.जा./अ.ज.जा. के आधार पर निधियो को आबंटित करने की बजाय तिरूवनंतपुरम के ग.उ.इ. ने निधि का आबंटन कुल जनसंख्या को प्राथमिकता देते हुए किया था, और वयनद के ग.उ.इ. ने निधि का आबंटन 2009-10 तक 2002 के ग.रे.नी. सूची में शामिल किये गये

ग.रे.नी. परिवारों की कुल संख्या के आधार पर किया। 2009-10 से, निधि आबंटन एलमकुलम मनक्कल संकरन आवास योजना सूची के अनुसार बेघर परिवारों की कुल संख्या के आधार पर किया गया था। इं.आ.यो. दिशानिर्देशों में संसाधनों के आबंटन हेतु परिकल्पित मानदण्ड से अलग मानदण्ड अपनाने के कारण, जिले में कुछ ब्लॉक पंचायतों ने अपनी हकदारी से अधिक निधियां प्राप्त की थीं, जबकि दूसरों को कम राशि प्राप्त हुई। जहॉ 14 ब्लॉक पंचायतों में निधियों का अतिरिक्त आबंटन ₹7.20 लाख एवं ₹117.00 लाख के मध्य था, वहीं निधियों का कम आंबंटन ₹3.15 लाख एवं ₹193.50 लाख के मध्य था।

पंजाब के तीन चयनित जिलों (पटियाला, एस.ए.एस. नगर एवं तरन तारन) में, इं.आ.यो. दिशानिर्देशो में निर्धारित मानदण्ड का पालन ब्लॉकों के निधियों के अंतरण के समय नहीं किया गया था क्योंकि घरों की कमी से संबंधित कोई डाटा डी.आर.डी.ए./जि.पं. के पास 2008-13 हेतु मौजूद नहीं था।

5.2 अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए निधियों को चिन्हित करना और उपयोग में लाना

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 1.5 के अनुसार, उपलब्ध संसाधनों को जिलों में निम्नानुसार विभिन्न श्रेणियों हेतु चिन्हित करना था:

i. कुल निधियों और भौतिक लक्ष्यों का कम से कम 60 प्रतिशत, अ.जा./अ.ज.जा. ग.रे.नी. परिवारों के लिए रिहायशी इकाइयों के निर्माण/उन्नयन हेतु उपयोग में लाया जाए।

ii. राज्यों/डी.आर.डी.ए. वर्ष हेतु अपने वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों का 15 प्रतिशत जिला से पंचायत स्तर के अल्पसंख्यकों[1] के लिए चिन्हित करें।

[1] योग्य अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 धारा 2 (घ) के अंतर्गत अनुसूचित-मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी किये गये थे। तथापि, जिन राज्यों में अल्पसंख्यक बहुसंख्या में है, केवल दूसरी अल्पसंख्यक जनसंख्या को ही अल्पसंख्यक माना जाता है। जम्मू एवं कश्मीर में मुस्लिम, पंजाब में सिख, और मेघालय, मिजोरम तथा नागालैण्ड में इसाइयों की संबधित राज्यों में अल्पसंख्यक नही माना जाता है।

यदि कोई विशेष श्रेणी किसी जिले में समाप्त हो जाए या उपलब्ध न हो, आबंटन को किसी अन्य श्रेणी हेतु इं.आ.यो. दिशानिर्देशों में दी गयी प्राथमिकता के अनुसार, संबंधित जिला परिषद/डी.आर.डी.ए. द्वारा इस आशय का प्रमाणीकरन करने जाने के पश्चात उपयोग में लाया जाना था।

मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत जिला-वार वित्तीय प्रदर्शन की विवरणी के अनुसार, अ.जा., अ.ज.जा. एवं अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए निधियों का उपयोग 2008-13 के दौरान निर्धारित सीमा से कम था जिसका विवरण निम्न तालिका-7 में दिया गया है:

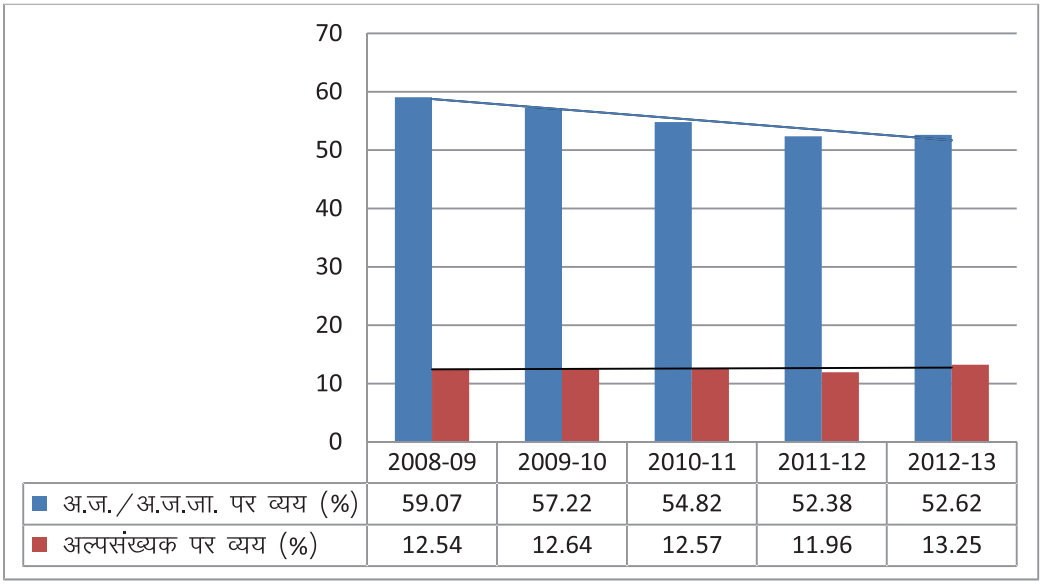
तालिका-7 :अ.जा., अ.ज.जा. एवं अल्पसंख्यकों पर व्यय (₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	कुल व्यय	श्रेणीवार व्यय एवं व्यय की प्रतिशतता[2]					
		अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	प्रतिशत	अल्पसंख्यक	प्रतिशत
2008-09	8,348.34	3,512.55	1,418.91	4,931.46	59.07	1,046.85	12.54
2009-10	13,292.46	5,201.30	2,405.18	7,606.48	57.22	1,680.70	12.64
2010-11	13,465.73	4,947.12	2,435.03	7,382.15	54.82	1,692.20	12.57
2011-12	12,926.33	4,306.30	2,464.60	6,770.90	52.38	1,545.94	11.96
2012-13	12,206.83	4,154.54	2,268.24	6,422.78	52.62	1,617.76	13.25
कुल	**60,239.69**	**22,121.81**	**10,991.96**	**33,113.77**	**54.97**	**7,583.45**	**12.59**

जैसाकि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, अ.जा. एवं अ.ज.जा. श्रेणियों के अंतर्गत व्यय का प्रतिशत 2008-13 के दौरान 60 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर से कम था। अल्पसंख्यकों के लिए भी व्यय की प्रतिशतता 2008-13 हेतु 15 प्रतिशत के कम थी, जैसा चार्ट-8 में दर्शाया गया है।

[2] सिक्किम तथा पुडुचेरी शामिल है।

चार्ट-8 : कुल व्यय में से अ.ज./अ.ज.जा. एवं अल्पसंख्यको पर किए गए व्यय का प्रतिशत



	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अ.ज./अ.ज.जा. पर व्यय (%)	59.07	57.22	54.82	52.38	52.62
अल्पसंख्यक पर व्यय (%)	12.54	12.64	12.57	11.96	13.25

नवम्बर 2008 में, मंत्रालय ने संबंधित जिला परिषदों/जि.ग्रा.वि.प्रा.को स्पष्ट कर दिया कि किसी राज्य में इं.आ.यो. के घरों का लाभ उठाने के लिए पात्र ग.रे.नी. के अल्पसंख्यक परिवारों के अब नहीं होने की स्थिति में, इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र जिला परिषद/जि.ग्रा.वि.प्रा. द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाए ताकि राज्य के लक्ष्यों को किसी अन्य राज्य को अंतिरित किया जा सके।

मेघालय में अभिलेखों के लेखापरीक्षा जाँच के दौरान यह देखा गया था कि पूरे 2008-13 के दौरान अल्पसंख्यकों को जारी निधियां सिर्फ 0.50 एवं 6.47 प्रतिशत के ही मध्य थीं। राज्य के सभी जिलों को जारी की गयी ₹241.74 करोड़ की कुल निधि (केन्द्रीय एवं राज्य का भाग) में से, केवल ₹6.09 करोड़ (2.51 प्रतिशत ही अल्पसंख्यकों को 2008-13 के दौरान जिलों द्वारा जारी किए गये थे।

मेघालय के सी.एण्ड आर.डी. विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि एक इसाई बहुल राज्य होने के कारण, राज्य में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत एकदम नगण्य था और उनमें से अधिकांश केवल पश्चिमी गारो पहाड़ी जिले में ही बसे हुए थे। इसके अतिरिक्त इसने बताया कि यद्यपि ये संख्या में नगण्य थे, उन्हें

इं.आ.यो. के अंतर्गत सहायता से वंचित नहीं कियागयाथा और उनका लक्ष्य हमेशा बनाये रखा गया था।

उत्तर तथापि यह स्पष्ट नहीं करता कि राज्य ने मंत्रालय के पास निर्धारित प्रमाण-पत्र क्यों नहीं भेजा ताकि राज्य के लक्ष्यों को दूसरे राज्य को अंतरित किया जा सके ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, मिजोरम सरकार द्वारा सांख्यिकी हैण्डबुक मिजोरम 2010 में प्रकाशित जनगणना डाटा 2001 के अनुसार, मिजोरम के आठ जिलों में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 13 प्रतिशत था। हमने देखा कि 2008-13 के दौरान, राज्य के किसी जि.ग्रा.वि.प्रा. द्वारा एक भी लाभार्थी का अल्पसंख्यकों में से चयन नहीं किया गया था। अत: राज्य के कुल जनसंख्या के 13 प्रतिशत अल्पसंख्यकों इं.आ.यो. के तहत लाभों से वंचित थे।

पंजाब के छ: चयनित जिलों में से पांच (मुक्तसर, नवां शहर,एस.ए.एस. नगर, पटियाला एवं तरन तारन)में अल्पसंख्यकों को प्रदान किये गये किसी प्रकार के वित्तीय सहायता से संबंधित कोई अभिलेख 2008-13 की अवधि हेतु अनुरक्षित नहीं किया गया था। इस वजह से यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि इं.आ.यो. के अंतर्गत लाभ उन्हें दिये गये थे या नहीं।

राजस्थान के भिलवाड़ा, सिकर, करौली, एवं उदयपुर जिलों के जि.पं ने बताया कि इं.आ.यो. प्रतीक्षासूची में अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई लंबमानता न थी जबकि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार जिलों में क्रमश: 46,10,165 एवं 122 अल्पसंख्यकों की लंबमानता थी।

मंत्रालय ने बताया (जून 2014) कि समय के साथ अ.जा./अ.ज.जा. एवं अल्पसंख्यक श्रेणियों के घरों की कमी खत्म हो गयी जो एक शुभ संकेत था।

मंत्रालय का उतर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि इसने इन श्रेणियों के समाप्त होने से संबधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था।

5.3 केन्द्रीय आबंटन से कटौती

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के पैरा 4.2(ii)के अनुसार अथशेष के अतिरिक्त राशि के आगे बढ़ाने पर कटौती (उपलब्ध निधियों के 10 प्रतिशत की अतिरिक्ता में) एवं राज्य के अंश में गिरावट दूसरे किस्त के निर्गम के समय किया जाना था।

2008-09 से 2012-13 के दौरान इस निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल 27 राज्यों को मंत्रालय द्वारा किये गये निर्गमों से संबंधित सूचना के लेखापरीक्षा जांच और विश्लेषण से प्रकट हुआ कि केन्द्रीय आबंटन से ₹2,451.84 करोड़ की कटौती अतिरिक्त राशि को आगे बढ़ाने (₹1,563,.54 करोड़) राज्य अंश का कम निर्गम (₹251.56 करोड़), प्रस्ताव की देर से प्राप्ति (₹98.85 करोड़) एवं अन्य विविध कारणों (₹537.89 करोड़) से हुई थी। केन्द्रीय अंश से कटौती के प्रति संगत राज्य अंश का योगदान उनके द्वारा किया जाना चाहिए जो ₹810.08 करोड़ बैठता है। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-5.1 में दिये गये हैं।

इस प्रकार, राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग की धीमी गति/कम उपयोग एवं उनके द्वारा संगत अंश का योगदान न होना 7.25 लाख लक्षित लाभार्थियों (@ ₹45,000 प्रतिलाभार्थी) को सहायता नहीं दिये जाने में परिणत हुआ था।

मंत्रालय ने बताया (जून/जुलाई 2014) कि कुछ राज्यों से काटी गयी राशि को वर्ष के अंत में राज्य के ही अंदर के बेहतर प्रदर्शन वाले जिलों को पुन: वितरित कर दिया गया था और इं.आ.यो. निधियों को अभ्यर्पित नही किया गया था और इस प्रकार संपूर्ण लक्ष्यों में कोई कमी नहीं आयी थी क्योंकि लक्ष्य एक जिले से दूसरे में अंतरित हो गये थे। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने बताया कि इन प्रावधानों को बनाने का मूल प्रयोजन यह था कि अधिकतम धनराशियों का उपयोग कर लिया गया था और दूसरी किस्त के लिए प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत कर दिया गया था, हालांकि इस प्रावधान को जून 2013 में संशोधित इं.आ.यो दिशानिर्देशों से हटा दिया गया था।

मंत्रालय ने उन जिलों में इं.आ.यो. निधियों के कम खपत के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था, जो लक्षित लाभार्थियों को घर प्रदान नहीं कर सके थे। पूरे बजटीय आबंटन का उपयोग मात्र ही इं.आ.यो. का उद्देश्य नहीं था।

5.4 प्रयुक्त निधियों के अधिक बयानी के कारण ₹163.14 करोड़ का अतिरिक्त निर्गम

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, यदि अव्ययित शेष पूर्व वर्ष के दौरान उपलब्ध निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक हो, अतिरिक्त केन्द्रीय अंश को दूसरी किस्त जारी करते समय अनपातिक रूप से घटाया जाना था। तथापि, मंत्रालय द्वारा इस कटौती को किसीऐसे मामले में छूट दी गयी थी जब कोई जिला संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक उपलब्ध निधियों के कम से कम 75 प्रतिशत का व्यय सूचित करे।

हमने देखा कि पांच चयनित जिलों असम के बर्पेता, करबी अंगलोंग, नगांव एवं सोनीतपुर तथा महाराष्ट्र के शोलापुर) को 2008-13 के दौरान इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के प्रावधान को उल्लंघन करते हुए ₹163.14 करोड़ जारी किया गया था। बर्पेता जिले ने अंत शेष की राशी को कम बताया, करबी अंगलोंग एवं सोनीतपुर जिलों ने निधियों के उपयोग को ब्याज से होने वाली आय को दबाकर अधिक बताया और नगांव जिले ने निधियों को उपयोग को अधिक करके बताया था। शोलापुर जिले ने दो वर्षों में समान व्यय होने का दावा किया। इन अनियमितताओं के ब्यौरे **अनुबंध-5.2** में दिये गये हैं।

5.5 वित्तीय रिपोर्टिंग में असंगति

मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार, 33 राज्यों/सं.शा.क्षे. के संबंध में इं.आ.यो. का केन्द्रीय अंश ₹45,888.43 करोड़ था। 2008-13 के दौरान लेखापरीक्षा में चयनित 31 राज्यों/सं.शा.क्षे. में वित्तीय निष्पादन निम्न तालिका-8 में दी गयी है:

तालिका-8: राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा वित्तीय निष्पादन की रिपोर्टिंग में असंगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निधियों की उपलब्धता एवं राज्यों एवं सं.शा.क्षे. द्वारा व्यय (राज्यों एवं सं.शा.क्षे. द्वारा प्रदत्त सूचना से एकत्रित आंकड़े, 31 राज्य/सं.शा.क्षे.[3])						31 राज्यों/सं.शा.क्षे. से संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना/आंकड़े		निर्गमों में अंतर	व्यय में अंतर
	अथ शेष	केन्द्रीय निर्गम	राज्य निर्गम	विविध प्राप्तियां	कुल	व्यय	राज्यों एवं सं.शा.क्षे. को निर्गम	व्यय		
2008-09	1824.07	7953.43	2117.33	151.04	12045.87	7907.93	8790.00	8341.24	836.57	433.34
2009-10	4140.25	8498.81	3961.20	308.08	16908.34	12583.77	8627.73	13284.27	128.92	700.47
2010-11	4324.80	9879.55	3823.15	366.03	18393.53	12468.44	10130.93	13452.44	251.38	984.01
2011-12	5925.09	9333.99	3580.52	502.99	19342.59	13588.17	9859.76	12916.09	525.77	(-) 672.10
2012-13	5754.42	8301.63	3569.78	489.11	18114.94	13184.11	7855.55	12201.43	(-) 446.08	(-) 982.67
कुल		**43967.41**	17051.98	1817.25	64660.71	59732.42	45263.97	60195.47	1296.56	463.05

₹64,660.71 करोड़ के निधि की कुल उपलब्धता के प्रति, राज्यों/सं.शा.क्षे. ने ₹59,732.42 करोड़ (92 प्रतिशत) व्यय किया था।

2008-13 के दौरान राज्य/सं.शा.क्षे. वार जारी की गयी एवं व्यय की गयी निधियों के ब्यौरे **अनुबन्ध-5.3.1 से 5.35** में देये गये हैं।

2008-09 से 2011-12 के दौरान, राज्यों एवं सं.शा.क्षे. ने ₹1,742.64 करोड़ से केन्द्रीय अंश की कम प्राप्ति दर्शायी थी जबकि 2012-13 के दौरान उसे ₹446.08 करोड़ की अतिरिक्ता में दर्शाया गया था। इसके प्रभाववश, राज्यों/सं.शा.क्षे. ने 2008-13 के दौरान ₹1,296.**56** करोड़ की कम प्राप्ति दिखायी थी। **असम**, **बिहार**, **छत्तीसगढ़ गुजरात एवं ओडिशा** राज्यों में प्रमुख विविधताएं देखी गयी थीं।राज्य/सं.शा.क्षे. वार ब्यौरे अनु-5.3.6 में दिये गये हैं।

मंत्रालय एवं राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा दिये गये व्यय के आंकड़े भी अलग थे। तीन वर्षों 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 तक राजयों/सं.शा.क्षे. द्वारा किये गये व्यय को मंत्रालय द्वारा राज्यों एवं सं.शा.क्षे. के व्यय के आंकड़ों से क्रमश: ₹433.34 करोड़ ₹700.47 करोड़ एवं ₹984.01 करोड़ अधिक बताया गया था, जबकि 2011-12 एवं 2012-13 हेतु, मंत्रालय के व्यय के आंकड़ों राज्यों एवं सं.शा.क्षे. द्वारा दिये गये व्यय के आंकड़ों से क्रमश: ₹672.10

[3] सिक्किम एवं पुडुचेरी को छोड़कर

करोड़ एवं ₹982.67 करोड़ अधिक थे। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एवं तमिलनाड़ राज्यों में प्रमुख विविधिताएं देखी गयी थीं। राज्य/सं.शा.क्षे.-वार ब्यौरे अनु.-5.3.7 में दिये गये हैं।

मंत्रालय/राज्य/सं.शा.क्षे. के आंकड़े में शीघ्र सुमेलन की आवश्यकता थी जिसमें संगति का अभाव था, जैसा कि ऊपर ब्यौरा दिया गया है।

5.6 अव्ययित शेषों पर ब्याज का परिकलन न करना

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 4.7 के अनुसार, इं.आ.यो. निधियों को किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित अथवा सहकारिता बैंक या डाक घर में एक अलग बचत खाते में जि.ग्रा.वि.प्रा. द्वारा रखा जाना था। पैरा 4.8 व्यवस्था करता है कि इं.आ.यो. निधियों के जमा पर अर्जित ब्याज की राशि को इं.आ.यो. संसाधनों के रूप में ही लिया जाए। अत: इं.आ.यो. की जमाओं पर अर्जित ब्याज केा समुचित सूचना मंत्रालय द्वारा निधियों के निर्गम के समय उन्हें परिकलित करने के लिए आवश्यक थी। राज्यों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जॉच से निम्नलिखित बाते प्रकट हुई:

आन्ध्र प्रदेश में, संबंधित जिलों के जि.ग्रा.वि.प्रा. ने भारत सरकार की निधियों को, मंत्रालय के रसीद पर, आन्ध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड (आं.प्र.रा.आ.नि.लि.) के संबंधित परियोजना निदेशकों (पं.नि.) को अंतरित कर दिया था जिसने बदले में आं.प्र.रा.आ.नि.लि. के प्रबंध निदेशक को निधियां प्रेषित कर दी जो इं.आ.यो. निधियों के लिए एक अलग केन्द्रीय पूल खाता अनुरक्षित करते थे। इन निधियों को आगे चार शीर्ष बैंक खातों में लाभार्थियों को आगे से वितरण हेतु अतंरित कर दिया गया था। चूंकि ये शीर्ष बैंक खाते इं.आ.यो. के अतिरिक्त राज्य आवास योजना(इंदिराम्मा) हेतु संयुक्त रूप से अनुरक्षित किये जाते थे, भा.स. के हिस्से पर अर्जित ब्याज एवं इं.आ.यो. निधियों के राज्य के मेल खाते हिस्सों को निर्धारित नहीं किया जा सका, इं.आ.यो. निधियों के लिए अलग खातों का अनुरक्षण नहीं करने के कारण। लेखापरीक्षा ने देखा कि आं.प्र.रा.आ.नि.लि. के प्र.नि. द्वारा अनुरक्षित पूल

खाते में उपलब्ध इं.आ.यो. निधियों पर जनवरी 2010 से जनवरी 2013 की अवधि हेतु ब्याज के रूप में अर्जित ₹1.52 करोड़ की राशि को इं.आ.यो. संसाधनों के रूप में नहीं दर्शाया गया था। अर्जित ब्याज की ये राशि आं.प्र.रा.आ.नि.नि.लि. के पूल खाते में जिला कार्यालयों द्वारा अंतरित कर दी गयी थी।

पांच जिलों (कचार, करबी अंगलोंग, करीमगंज, शिवसागर एवं सोनीतपुर);

₹2.68 करोड़ एवं असम के नगांव जिले ने भी ₹36.91 लाख (₹1.06 करोड़ में से) 2008-13 के दौरान इं.आ.यो. खाते में उपलब्ध निधियों पर अर्जित ब्याज को अंतरित नहीं किया था। बिहार के तीन चयनित जिलों (भोजपर, मधुबनी एवं सुपौल) ने ₹3.73 करोड़ का ब्याज अर्जित किया परंतु उसे रोकड़ बहियों में दर्शायानहीं गया था।

झारखंड में, चयनित छ: जिलों[4]के अंतर्गत12 ब्लॉकों और एक जि.ग्रा.वि.प्रा. ने इं.आ.यो. निधियों पर अर्जित कुल ₹1.05 करोड़ के ब्याज को परिकलित नहीं किया था जबकि बैंकों द्वारा उनके पास बुकों में यह राशि नामे कर दी गयी थी। इसके अतिरिक्त, छ: चयनित जिलों के छ: नमूना परीक्षित जि.ग्रा.वि.प्रा. के सनदी लेखाकारों (स.ले.) ने सूचित किया कि जिलों के अंदर 85 ब्लॉकों ने 2008-13 के दौरान ₹555 करोड़ की उपलब्ध निधियों पर ब्याज का परिकलन नहीं किया था। स.ले. ने जि.ग्रा.वि.प्रा. केा ब्लॉकों के विरूद्ध रोकड़ बहियों में क्रमश: प्रत्येक वर्ष अर्जित ब्याजों को शामिल नहीं करने के लिए उचित कार्रवाई करने का सुझाव दिया था तथापि, जि.ग्रा.वि.प्रा. ने न तो ब्लॉकों के विरूद्ध कोई कार्रवाई शुरू की और न ही उनसे बैंक ब्याज को परिकलित नहीं करने के कारणों की मांग की। फलस्वरूप, ब्लॉकों के पास उपलब्ध निधि शेषों पर अर्जित ब्याज की स्थिति से जिले अनभिज्ञ रहे। परिस्थितियों को देखते हुए, सरकारी धन के गलत उपयोग/गबन/दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार

---

[4] देवधर जिले के ब्लॉक मधुपुर ने 2008-13 के दौरान, ब्लॉक घाटशिला (2012-13), पूर्वी सिहंभूमि जिले का ब्लॉक गुरबंदा (2011-13), गोड्डा जिले के ब्लॉक ठकुरगंग्त्री 2008-13 के दौरान पलामू जिले के ब्लॉक चैनपुर, मेदिनीनगर सदर, लेसलीगंज, बिसरामपुर 2008-13 के दौरान, रांची जिले के ब्लॉक नमकोन (2009-10) एवं रातु तथा रांची जि.ग्रा.वि.प्रा. 2008-13 के दौरान

नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, ब्याज को परिकलित न करना कमजोर वित्तीय नियंत्रण का संकेतक था।

5.7 बैंक खातों का संचालन

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 4.6 के अनुसार, इं.आ.यो. निधियों (केन्द्र के साथ राज्य अंश भी) को किसी राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित बैंक अथवा किसी डाक घर में जि.ग्रा.वि.प्रा. द्वारा एक विशेष अलग बचत खाते में रखना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनेक बैंक खाते (2 से लेकर 20) बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में चयनित जिलों तथाब्लॉकों में इं.आ.यो. निधियों को रखने के लिए परिचालित किये जा रहे थे।

इसके अतिरिक्त, इं.आ.यो. निधियों को अन्य केन्द्रीय योजना निधियों यथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, बारहवें वित्त आयोग आदि के साथ आन्ध्र प्रदेश, बिहार एवं झारखण्ड के चयनित चार जिलों (मंदार, सदर देवधर, घाटशिला, एवं गौरबंदा) में जोड़ दिया गया था)। इं.आ.यो. निधियों के लिए कोई अलग बैंक खाते छत्तीसगढ़ में 13 चयनित ब्लॉकों में से सात में और त्रिपुरा के सभी चयनित ब्लॉकों में खोले नहीं गये थे।

आन्ध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में, ₹14.45 करोड़ की इं.आ.यो. निधियों 63 विभिन्न शाखाओं में आं.प्र.रा.आ.नि.लि. के प्रधाननिदेशक द्वारा सावधि जमाओं में रखे गये (दिसम्बर 2010) थे। लेखापरीक्षा द्वारा जब इंगित किया गया (सितम्बर 2013), राज्य सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2013) कि निधियों को आ.प्र.रा.आ.नि.लि. के प्रबंध निदेशक को हस्तांतरित कर दिया गया था)

गुजरात में, भारत सरकार,गुजरात में, भारत सरकार, एवं राज्य सरकारों से जि.ग्रा.पं.वि.प्रा. द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों को पहले साझे खाते में जमा किया जाता था और इं.आ.यो. हेतु अनुरक्षित अलग बैंक खातों में हस्तांतिरत कर दिय जाता था। इ.आ.यो. निधियों के साझे खाते से इं.आ.यो. बैंक में हस्तातंरण में 247 दिनों तक के विलंब थे।

कर्नाटक के छः चयनित जिलों में, इं.आ.यो. अनुदान का केन्द्रीय अंश पहले जि.पं. सामान्य लेखे (एक साझा खाता जिसमें भारत सरकार योजना अनुदानों को ई-हस्तांतरण के माध्यम से सीधे जमा करता है) में सीधे जमा किया गया था और उसके बाद जि.प. के अलग इं.आ.यो. खाते में हस्तांतरित किया गया था। हमने पाया कि पांच चयनित जि.प्र. (चिकमंगलूर, चित्रदुर्गा, गडग, मंड्या, रामनगर) ने केन्द्रीय अंश को इं.आ.यो. खाते में 13 एवं 314 दिनों के बीच विलंब के साथ जमा किया था। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान 39.25 लाख का अर्जित ब्याज (लगभग चार प्रतिशत प्रति वर्ष) इं.आ.यो. बैंक खातों में हस्तांतरित नहीं किया गया था।

ओडिशा में, 11 ब्लॉकों ने 2008-13 के दौरान इं.आ.यो. निधियों पर बैंक द्वारा जमा किये गये ₹2.00 करोड़ के ब्याज को परिकलित नहीं किया था।

पंजाब में, भारत सरकार से 2008-13 के दौरान प्राप्त ₹28.70 करोड़ को अलग बैंक खातों (इं.आ.यो. निधियों को छोड़कर) में रखा गया था और संबंधित इं.आ.यो. बैंक खातों में जि.ग्रा.वि.प्रा./ जि.प. द्वारा 6 से 223 दिनों के बाद हस्तांतरित किया गया था। तथापि, ₹15.51 लाख राशि का ब्याज इं.आ.यो. खातों में हस्तांतरित नहीं किया गया था।

राजस्थान के सिकर जिले के जि.पं. (ग्रा.वि. प्रकोष्ठ) ने उच्च प्राधिकारियों के निर्देशों पर इंआ.यो. बचत बैंक खाते से ₹50.00 लाख की राशि आहरित की और उसे अस्थायी रूप से (मार्च 2009) कैनरा बैंक के दूसरे बचत बैंक खाते में जमा कर दिया था।

उत्तराखण्ड के पाँच चयनितजिलों में, मुख्य बैंक खाते में जमा केन्द्रीय अंश को इं.आ.यो. बैंक खातों में 10 एवं 349 दिनों के मध्य विलंब के पश्चात, मुख्य बैंक खाते में इं.आ.यो. निधि को रोके रखने की अवधि हेतु उपार्जित ₹54 लाख के ब्याज के बगैर ही (@ चार प्रतिशत वर्ष) 2008-13 के दौरान हस्तांतरित कर दिया गया था।

मंत्रालय द्वारा जि.ग्रा.वि.प्रा., उत्तरी एवं मध्य अण्डमान को जारी की गयी इं.आ.यो. निधियॉ इं.आ.यो. खाते से अलग एक खाते में अक्तुबर 2011 तक

रखी गयी थीं और उसे इं.आ.यो. खाते में हस्तांतरित किया जाना था। मंत्रालय ने इं.आ.यो. से संबंधित निधियों केा को सही में हस्तांतरित करने में पर्याप्त सतर्कता नहीं रखा था।

यह भी पाया गया था कि 11 राज्यों यथा असम (एक जिला), छत्तीसगढ़ (एक जिला), जम्मू एवं कश्मीर (एक ब्लॉक), झारखण्ड (दो ब्लॉक), कर्नाटक (11 जिले), मिजोरम (दो ब्लॉक), ओडिशा (एक जिला), पंजाब (दो ब्लॉक), राजस्थान (छ: जिले), उत्तर प्रदेश (दो जिले) एवं उत्तराखण्ड (एक ब्लॉक एवं एक जिलाके आठ चयनित ब्लॉकों एवं 24 चयनित जिलों ने इं.आ;यो. निधियों को चालू खाते या निजी लेजर खातों में रखा था। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा ने देखा कि छ: राज्यों[5] में 2008-13 के दौरान मौजूदा ब्याज दरों पर (3.5 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत प्रति वर्ष) ₹4.22 करोड़ की ब्याज हानि में उक्त राशि को चालू खाते में नहीं रखने के कारण हुई।

अत: अनेक बैंक खातों के परिचालन के कारण, इं.आ.यो. निधियों के अन्य योजना निधियों में जुडाव, प्रयुक्त इं.आ.यो. निधियों पर उपार्जित जहाँ यह अन्य योजना निधियों की परिकलन नहीं करने के कारण, के साथ संबंद्ध किया गया हो उसकी सटीक स्थिति का निर्धारणलेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2014) कि संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, एक जि.ग्रा.वि.प्रा. द्वारा केवल एक ही बैंक खाता ही रखना था जो सी.पी.एस.एम.एस. के साथ पंजीकृत है निधियों को इलेक्ट्रानिक रूप से केवल उसी खाते में डालना था। मंत्रालय ने आगे बताया कि 2014-15 से, इं.आ.यो. निधियॉ केवल राज्य के ही समेकित निधियों को जारी की जा रही थीं।

5.8 राज्य अंश का कम निर्गम

राज्य सरकारों के निधियों के निर्गम से संबंधित अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि 11 राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा 2008-13 के लिए ₹255.71

---

[5] असम (₹1.10 करोड़) जम्मू एवं कश्मीर (₹0.03 करोड़), कर्नाटक (₹2.51 करोड़), ओडिशा (₹0.10 करोड़), पंजाब (₹0.08 करोड़), राजस्थान (₹0.40 करोड़)

करोड़ की राशि के इं.आ.यो. निधियों उनके अंशों का कम निर्गम हुआ था कम निर्गमों के ब्यौरे अनु.- 5.4 में दिये गये है। राज्य के अंश में गिरावट ने इं.आ.यो. के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कुल निधियों की उपलब्धता को प्रतिकूलत: प्रभावित किया था जिससे लक्षित ग.रे.नी. परिवारों के लिए निर्मित होने वाले घरों की संख्या घट गयी।

मंत्रालय ने (जून 2014) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और कहा कि राज्य अंश के कम निर्गम अथवा गैर-निर्गम की स्थिति में, संबंधित जिले के दूसरे किस्त में से अनुपातिक केन्द्रीय अंश की कटौती की गयी थीं। मंत्रालय ने आगे बताया कि कटौती की राशिको राज्य के अंदर बेहतर प्रदर्शन वाले जिलों को पुन: वितरित कर दिया गया था।

5.9 राज्य अंश के कार्यान्वयन अभिकरणों को निर्गम में विलम्ब

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 4.6 के अनुसार, राज्य अंश को जि.ग्रा.वि.प्रा. को केन्द्रीय सहायता के निर्गम के बाद एक माह के अंदर जारी कर दिया जाना था और उसकी एक प्राप्ति मंत्रालय को पृष्ठांकित करनी थी।

19 राज्यों में, राज्य अंश को राज्य सरकार द्वारा 744 दिनों तक के विलंब के साथ जारी किया गया था। ब्यौरे **अनुबंध-5.5** में दिये गये हैं। निधियों के विलंबित निर्गम से लाभार्थियों तक निधियों का विलंबत हस्तांतरण हुआ और इस प्रकार इं.आ.यो. के कार्यान्वयन को प्रतिकूलत: प्रभावित किया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जून 2014) और बताया कि राज्यों के वित्तीय सीमाओं के कारण अथवा केन्द्रीय अंश के निर्गम की संस्वीकृत आदेशों के देर से प्राप्ति के कारण, राज्य अंश का निर्गम कई बार देर से हुआ।

मामला अध्ययन : आंध्र प्रदेश में इं.आ.यो का निष्पादन

- आन्ध्र प्रदेश में, इं.आ.यो. का निष्पादन आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड (आं.प्र.रा.आ.नि.लि.) द्वारा किया गया था। इं.आ.यो. में दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, राज्य ने आपने स्वयं की निधि प्रवाह प्रणली को प्रयुक्त किया था। इस प्रणालीके तहत, संबंधित जिलों के जि.ग्रा.वि.प्रा. को भारत सरकार निधियों को, मंत्रालय से प्राप्ति पर, आ.प्र.रा.आ.नि.लि. के संबंधित परियोजना निदेशाकों को अंतरिक करेगा, जो उसके बाद उसे आ.प्र.रा.नि.लि., हैदराबाद के प्रबंध निदेशक को हस्तांतरित करेगा जहॉ इं.आ.यो. निधियों के लिए एक केन्द्रीय पूल अलग से अनुरक्षित किया गया था । राज्य सरकार ने अपना समान अंश आं.प्र.रा.नि.लि. के प्र.नि. के निजी खाते में जारी कर दिया जिसे खास तौर से सभी राज्य निधियों के पिचालन हेतु अनुरक्षित किया गया था। इन निधियों को आगे चार शीर्ष बैंक खातों में लाभार्थियों तक आगे से वितरण के लिए हस्तांतरित कर दिया गया था। इं.आ.यो. के अतिरिक्त, ये शीर्ष बैंक खाते राज्य आवसय कार्यक्रम, इंदिरम्मा ग्रा.क्षे. में समेकित नव विकास एवं मॉडल नगर क्षेत्र हेतु अनुरक्षित किये जाते थे और इसलिए इं.आ.यो. निधियोंहेतु खास बैंक खातों के गैर-अनुरक्षण के कारण, भारत सरकार द्वारा जारी निधियों और राज्य के समान अंश पर उपार्जित ब्याज को निर्धारित नहीं किया जा सका।
- यह देखा गया कि 2008-13 के दौरान इंदिरम्मा के अंतर्गत निम्नतर कीमत (इं.आ.यो. के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त घरों की इकाई कीमतकी तुलना में) पर पहले से आये/बने घरों को इं.आ.यो. घरों में परिवर्तित किया गया था और उसके अनुसार लाभार्थियों को इं.आ.यो. दिशानिर्देशों में निर्धारित (@35,000 एवं 45,000) इकाई कीमत से का भुगतान किया गया था। लाभार्थियों को इकाई कीमत के कम निर्गम के कार,₹367.59 करोड़ (लगभग) को राशि राशि आं.प्र.रा.अ.नि.लि. द्वारा (केन्द्रीय अंश ₹275.57 करोड़ एवं राज्य समान अंश: ₹91.89 करोड़) 2008-09 से 2010-11 की अवधि हेतु रखी गयी थी।

5.10 निधियों का निष्क्रिय पडे रहना

बिहार, झारखण्ड, राज्स्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश के पांच राज्यों में ₹86.16 करोड़ की राशि एक एवं आठ वर्षों की अवधि के मध्य जिला /ब्लॉक/ ग्रा पं स्तरों पर निष्क्रिय/अप्रयुक्त पड़ी रहीं जिसका विवरण निम्न तालकिा-9 में दिया गया हैः

तालकिा-9: निधियों की निष्क्रियता

राज्य	अभ्युतियां
बिहार	किशनगंज जिले द्वारा मार्च 2011 में प्राप्त की गयी बिहार ₹10.60 करोड़ की इं. आ.यो. सहायता (केन्द्रीय अंश ₹7.95 करोड़ एवं राज्य अंश ₹2.65 करोड़) दो वर्षों तक अप्रयुक्त पड़ी रही। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर (मई 2013), निधियों को जून 2013 में ब्लॉकों को जारी किया गया सुपौल जिले में, इं.आ.यो. के अंतर्गत 2004-05 में प्राप्त की गयी ₹ 3.04 करोड़ का अव्ययित शेष आठ वर्षों तक अप्रयुक्त रहा पश्चिमी चंपारण जिले में ₹5.68 करोड़ की राशि 18 ग्राम पंचायतों द्वारा 2008-09 से तक अप्रयुक्त रहीं। ग्राम पंचायतों के पास पड़े अव्ययित शेष को ब्लॉकों में हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी।
झारखण्ड	वास्तविक आवश्कता का मूल्यांकन नहीं करने के कारण, गोड्डा पालमू एवं रॉची जिलों के 24 ब्लॉकों में ₹24.86 करोड़ 2008-13 के दौरान अप्रयुक्त पड़ा रहा। दो जि.ग्रा.वि.प्रा. (रांची एवं पूर्वी सिंहभूमि) में, 2010-11 के दौरानब्लॉकों को प्रदान किये गये ₹21.61 करोड़ के चैक 2011-12 के दौरान भुनाये गये। पलामू के जि.ग्रा.वि.प्रा. में, 2011-12 से 2013-14 (सितम्बर 2013 तक) तक 48.00 लाख अप्रयुक्त पड़ा था। जि.ग्रा.वि.प्रा.सिंहभूमि में, 2008-09 से पूर्व की अवधि के ₹1.75 करोड़ सितम्बर 2013 तक अप्रयुक्त रहे। 2008-13 के दौरान इं.आ.यो. निधि पर अर्जित ₹17.00 लाख का ब्याज भी जून 2013 तक प्रयुक्त नहीं हुआ था।
राजस्थान	छः जिलों के आठ ब्लॉकों ने जि.पं. को ₹1.00 करोड़ वापस लौटाया था जो उनके पास अप्रयुक्त पड़ा था और इं.आ.यो. खाते की बजाय निजी जमा खाते में रखा हुआ था।

तमिलनाडु	तीन ब्लॉकों थिरूवेरंबुर (त्रिची, श्रीवैकुंठम एवं त्रिचेन्दुर जिला-जिला टुटीकोरीन) में, 77 लाख 62 ग्राम पंचायतों के बचत बैंक खातों में 31 अगस्त 2013 तक रखा गया था। इसके अतिरिक्त, तीन ब्लॉकों में (कोणगिरि-जिला नीलगिरि, कम्मपुरम-जिला कुड्डालोर एवं रामनाथपुरम जिला रामनाथपुरम) ₹1.07 करोड़ बचत बैंक खातों में अप्रैल 2012 तक रखा गया था।
उत्तर प्रदेश	जिला रामपुर ने अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी हेतु 2011-12 के लिए चिन्हित ₹2.33 करोड़ को इन श्रेणियों में लाभार्थियों की मौजूदगी के बावजूद न तो अभ्यर्पित किया और न ही उपयोग में लाया। देवरिया जिलों में,₹8.59 करोड़ 2011-12 से ही अप्रयुक्त पड़ा रहा क्योंकि अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के अंदर लाभार्थी समाप्त हो गये थे। मेरठ जिले में, ₹4.38 करोड़ 2009-10 से ही इं.आ.यो. सहायता हेतु योग्य परिवारों की अनुपलब्धता के कारण अप्रयुक्त पड़ा रहा।

मंत्रालयने बताया कि जिलास्तर पर उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत का उपयोग अगली किस्तों को निर्गम हेतु अनिवार्य था और ब्लॉक एवं जि.पं. स्तर पर क्षेत्र 40 प्रतिशतमें से कुछ निधियों के अप्रयुक्त रहने की संभावना थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि विषय को संबंधित राज्यों के समक्ष उठाया जाएगा। हालांकि, लेखा परीक्षा में रेखांकित कुछ मामले चार या पाँच वर्षों पूर्व किये गये निर्गमों से संबंधित हैं।

5.11 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (उ.प.) में बढाया हुआ व्यय

असम के तीन चयनित ब्लॉकों (नंगाव जिले के अंतर्गत राहा सोनीतपुर जिले के अंतर्गत बागमारा एवं चैदुआर) ने अपने रोकड़ बहियों में मार्च 2008 एवं मार्च 2012 के माह में ग्रा.पं. को ₹2.22 करोड़ का हस्तांतरण दिखाया था हालॉकि उन्हें या तो किसी नये खातेमें अस्थायी रूप से हस्तांतरित किया गया था या कॉल जमा रसीदें 2007-08 एवं 2011-12 में निधि उपयोग को दर्शाने के लिए बनायी गयी थीं। निधियों को वास्तविक रूप से जि.पं. को अगामी वित्त-वर्षों में हस्तांतरित किया गया था।

कर्नाटक में (यादगिर जि.प. को छोडकर) तीस जि.पं. (₹331.75 करोड़),केरल में दो पी.ए.यू. (अलाप्पुजा एवं वयनद ₹3.93 करोड़), ओड़िशा (बलसोर एवं गंजम) में चयनित दो जिलों (₹23.35 करोड़) एवं उत्तराखण्ड (टिहरी एवं उधम सिंह नगर) ने दो चयनित जिलों (₹1.52 करोड़) ने मंत्रालय को प्रस्तुत 2008-13 के दौरान उ.प्र. में ₹360.55 करोड़ बढ़ाकर व्यय सूचित किया था।

ओडिशा के दो जिलों (बलसोर एवं गंजम) के अंदर पांच चयनित ब्लॉकों ने भी 2008-13 की अवधि के दौरान हुए वास्तविक व्यय से ₹12.62 करोड़ अधिक बढ़ाकर उ.प्र. प्रस्तुत किये थे। त्रिपुरा में छ: चयनित ब्लॉकों ने ₹7.60 करोड़ के उ.प्र. 2008-13 के दौरान व्यय किये बगैर प्रस्तुत किया था। तिरूवन्नमलाई जि.ग्रा.वि.प्रा. (तमिलनाडु) ने रोकड़ बही के अनुसार उपलब्ध निधि को केवल 51.68 प्रतिशत ही उपयोग किया जबकि वर्ष 2011-12 के लिए दूसरे किस्त के प्रस्ताव में इसे 72 प्रतिशत के रूप में बताया गया था।

मंत्रालय ने बताया कि मामले को संबंधित राज्यों के साथ उठाया जाना था।

5.12 खातों का गैरसुमेलन

हमने पाया कि खातों का मासिक सुमेलन सात राज्यों यथा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर एवं ओडिशा के चयनित जिलों, ब्लॉकों एवं ग्रा.पं. में समान रूप से नहीं किया गया था। बैंक शेषों और रोकड़ बही शेषों के मध्य सुमेलन करीमनगर जिले में 2009-10 से 2012-13 के दौरान कभी भी नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, रोकड़ बही और पास बुक के अंत शेषों के मध्य ₹23.38 करोड़ की विसंगति को लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता था। बैंक शेषों और रोकड़ बहियों के मध्य सुमेलन कर्नाटक में चयनित 119 ग्रा.पं. में से 28 में नहीं किया गया था।

5.13 लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों का पैरा 4.2 (ख) (**vi**)जिला परिषद/जि.ग्रा.वि.प्रा. द्वारा दूसरी किस्त क लिए अन्य शर्तें पूरी करने के अलावा निर्धारित प्रारूप में एक उ.प्र. पुस्तुत करने का प्रावधान करता है। मंत्रालय द्वारा प्रदान सूचना के

अनुसार,**2006-07** से 2011-12 तक से संबंधित ₹ 137.52 करोड़ के उ.प्र. 15 राज्यों के पास लंबित थे, जिनके ब्यौरे तालिका-10 में दिये गये हैं:

तालिका-10: लंबित उपयोग प्रमाण-पत्र

राज्य	जिलों की सं.	राशि (₹लाख में)	वर्ष से संबंधित उ.प्र.
अरूणाचलप्रदेश	1	4.76	2010-11
असम	23	4,992.60	2008-09 एवं 2011-12
हिमाचल प्रदेश	1	10.25	2010-11
जम्मू एवं कश्मीर	5	700.24	2010-11 एवं 2011-12
झारखण्ड	9	4,748.19	2009-10 एवं 2010-11
कर्नाटक	1	26.25	2010-11
मध्य प्रदेश	12	676.08	2005-06, 2007-08, 2009-10 एवं 2010-11
महराष्ट्र	15	305.39	2006-07, 2007-08 एवं 2010-11
मणिपुर	1	20.79	2010-11
ओडीशा	1	17.03	2009-10
सिक्किम		126.00	2010-11
तमिललाडु	1	59.44	2009-10
त्रिपुरा	1	22.34	2010-11
उत्तर प्रदेश	17	120.75	2009-10 एवं 2010-11
पश्चिम बंगाल	3	1,921.88	2011-12
	योग	13,751.99	

5.14 गैर अनुमेय मदों पर निधियों का विपथन एवं व्यय

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 (ख) (ii)के अनुसार, जि.ग्रा.वि.प्रा. को मंत्रालय से दूसरी किस्त मांगते समय एक गैर विपथन एवं गैर-गबन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना था। यद्यपि जि.ग्रा.वि.प्रा. ने गैर-विपथन-पत्र प्रस्तुत किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹37.12 करोड़ 13 राज्यों एवं दो सं.शा.क्षे. में अन्य योजनाओं यथा मनरेगस, एस.जी.एस.वाई., राज्य आवास योजनाओं, आदि में विपथित किये गये थे, राज्य विशिष्ट निष्कर्ष **अनुबंध- 5.6.1** में वर्णित हैं। विपथित निधियों में से,₹**28.40** करोड़ की आपूर्ति इं.आ.यो. निधि को 10 से 261 दिनों के विलंब के साथ कर दी गयी थी।

इसके अतिरिक्त, ₹2.20 करोड़ इं.आ.यो. के अंतर्गत निर्धारित मदों यथा लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान, लेखा-सामग्री, आकस्मिकताओं, आदि के अलावा अन्य गैर-अनुमेय मदों पर खर्च किया गया था। इसके ब्यौरे **अनुबंध - 5.6.2** में दिये गये हैं।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2014) कि अन्य योजनाओं के लिए या गैर-अनुमेय प्रयोजनों हेतु निधियों के विपथन पाये जाने के मामले में,जि.ग्रा.वि.प्रा.की धनराशि की आपूर्ति इं.आ.यो. में तुरंत करने और रोकी गयी निधियों को जारी करने का परामर्श दिया गया था और यदि समय कम हो और वित्त वर्षका अंत हो रहा हो, दूसरी किस्त को सशर्त जारी किया गया था जिसे आगामी वर्ष में मानीटर किया गया था।

5.15 प्राकृतिक आपदाओं के लिए निधियों को चिन्हित करना

दिशानिर्देशो के पैरा 4.4.1 के अनुसार, इ.आ.यो के अंतर्गत कुल आवंटित निधियों के पांच प्रतिशत को प्राकृतिक आपदाओं या पंगे, आगजनी, अग्नि, असाधारण परिस्थितियों में पुनर्वास आदि के उत्पन्न परिस्थितियों के कारण आयी जरूरतों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर अलग से रखना या

जिसमें वार्षिक आबंटन (राज्य अंश को मिलाकर) का 10 प्रतिशत या ₹70.00 लाख, जो ही अधिक हो, की जिला-वार[6]अधिकतम सीमा होगी।

इस प्रयोजन हेतु प्रस्तावों को राज्य सरकारों/सं.शा.क्षे. के प्रशासन से हानि के प्रसार एवं बनाये जाने वाले प्रस्तावित इं.आ.यो. घरों से संबंधित अनुमानित निधि आवश्यकता को दर्शाते हुए प्राप्त किया जाना था बशर्ते कि घर के निर्माण हेतु सहायता किसी अन्य स्रोत से प्राप्त न की गयी हो। राहत को, इं.आ.यो. के अंतर्गत किसी इं.आ.यो. घर के लिए निर्धारित सहायता की प्रति इकाई अधिकतम सीमा से संबंधित मानदण्ड़ों के अनुसार होना था।

दंगा, एवं आगजनी की स्थिति में समय पर पीड़ितों को राहत पहुंचाने और क्षतिग्रस्त घरों के शीघ्र पुननिर्माण को सुगम बनाने के लिए जिला स्तर पर कलक्टरो/जिला न्यायाधीशो/उप आयुक्त सर्वप्रथम ऐसी आपदाओं में पीड़ितों को सहायता प्रदान करने और खर्च करने के लिए प्राधिकृत थे। व्यय के उनके आपने संसाधनों या जिले के आबंटन से पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार किये गये व्यय के केन्द्रीय अंश की प्रतिपूर्ति मंत्रालय द्वारा होनी थी सहायता प्राप्त परिवार के विवरणों और व्यय किये राशि हेतु उ.प्र. के साथ की प्रतिपूर्ति हेतु, कलक्टर द्वारा यथोचित रूप से हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मत्रांलय द्वारा प्रतिपूर्ति होनी थी। कलक्टर को घटना और क्षति के विस्तार को प्रमाणित करना था कि घर के निर्माण हेतु उक्त पीडितों को किसी अन्य स्रोत से सहायता नहीं प्रदान की गयी थी।

असम के नगांव जिले में, लाओखोवा ब्लॉक में बाढ़ क्षरण के 114 गैर-ग.रे.नी पीडितों को 55.00 लाख घरों के निर्माण हेतु प्रदान किया गया था तीन ब्लॉकों (बाजियागंव, बरहमपुर एवं जुगीजन) के दूसरे 137 तूफान प्रभावित पीड़ितों को 66.00 लाख घरों के निर्माण हेतु घटना/तूफान आने की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये बगैर और कोई तैयार किये बिना प्रदान किया गया था। किसी अन्य स्रोत से इस प्रयोजन हेतु निधियों के गैर-उपयोग पर कलक्टर से प्रमाण-पत्र जैसा अपेक्षित है, भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। तीन राज्यों

---

[6] मंत्रालय के आदेश सं. एच-11011/1/2002-आर.एच. दिनांक 14/;2/2012 के माध्यम से वार्षिक आबंटन (राज्य अंश मिलाकर) का 10 प्रतिशत राज्य-वार अधिकतम सीमा

बिहार(औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, किशनगंज, मधुबनी, सरन एवं सुपौल में कुल ₹6.43 करोड), उत्तर प्रदेश (गोंडा, हमीरपुर, मैनपुरी एवं रामपुर में कुल ₹1.15 करोड़) एवं उत्तराखण्ड (नैनीताल, टिहरी गढ़वाल एवं यू.एस. नगर में कुल ₹12 लाख) के चौदह जिलों ने प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितो को सहायता प्रदान करने के लिए ₹7.70 करोड़ व्यय किया, हालॉकि, 13 जिलों (मैनपुरी जिले को छोडकर) ने मंत्रालय से केन्द्रीय अंश के लिए दावा नहीं किया था उत्तर प्रदेश में, 14 चयनित जिलों में से दो जिलों (गोंडा तथा मैनपुरी) में प्राकृतिक आपदाओं के वास्तव में घटने का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था फिर भी, प्राकृतिक आपदाओं के कारण ₹1.01 करोड़ का व्यय किया गया था।

जि.ग्रा.वि.प्रा. (दक्षिण), गोवा ने 115 बाढ़ पीड़ित परिवारों को इं.आ.यो. निधि से 20,000 प्रत्येक को वित्तीय सहायता जारी (अक्तुबर 2009) किया था। 115 परिवारों मं से, 50 परिवार गरीबी रेखा से ऊपर (ग.रे.उ.) से संबंधित थे। संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जि.ग्रा.वि.प्रा. (दक्षिण) को कलेक्टर कार्यालय, दक्षिण गोवा से ग.रे.उ. परिवारों की संवितरित धनराशि की वसूली करने को प्रस्तुति करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार से ₹10.00 लाख की वसूली हेतु दावों की प्रस्तुत करने की बजाय, जि.ग्रा.वि.प्रा. (दक्षिण) के कार्य को सही ठहराने के लिए उपरोक्त सभी ग.रे.उ. परिवारों को ग.रे.नी. सूची में अनियमित रूप से जोड़ दिया गया था।

कर्नाटक में, भा.स. ने ₹9.98 करोड़ और कर्नाटक सरकार ने ₹5.15 करोड़ दिसम्बर 2009 के दौरान इं.आ.यो. के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के लिए जारी किया था। ₹15.00 करोड़ में से, ₹3.48 करोड़ मार्च 2013 के अंत तक उपयोग में लाया गया था। चूंकि न तो कार्यान्वयन अभिकरण (रा.गा.ग्रा.भा.नि.)[7] द्वारा और न ही जि.पं./ग्रा.पं. द्वारा कोई अलग अभिलेख अनुरक्षित किया गया था। लेखापरीक्षाग्रा.पं. द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के लिए कियेगये लक्ष्य की शुद्धता को सुनिश्चित नहीं कर पाया।

मणिपुर में, सेनापति जिले के तदुबी उप-प्रभाग में सजौबा गांव में सितम्बर 2007 के व्यापक भू-स्खलन के 120 पीड़ितों में से 114 पीड़ितों को सहायता

[7] राजीव गांधी ग्रामीण आवासीय निगम

पहँचाने में एक वर्ष नौ माह से लेकर तीन वर्ष 10 माह का विलंब हुआ था। छः पीडितों को इं.आ.यो. घरों की सहायता धनराशि उपलब्ध न होने के कारण नहीं पहुँचायी जा सकी थी।

नागालैण्ड में, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ₹37.50 लाख का 2007-08 से संबंधित जि.ग्रा.वि.प्रा. मोकोक्चुंग के प्रति 2008-09 के दौरान हुए भुगतान के अलावा कोई व्यय नहीं किया गया।

राजस्थान के 12 जिलों (बांसवाड़ा, बाड़मेर, चितौरगढ़, डुंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाढ़, पाली, राजसामंद, सिरोही, उदयपुर एवं टोंक) के पास उपलब्ध ₹166 लाख में से, 31 मार्च 2013 तक केवल ₹86.00 लाख ही उपयोग में लाया गया और ₹80.00 लाख अव्ययित पड़ा रहा। न तो उ.प्र. जमा किये गये और न ही अच्ययित शेष को सामान्य इं.आ.यो. अनुदान के प्रतितीन वर्षों के बीत जाने पर भी समायोजित किया गया था।

त्रिपुरा में, कलक्टर द्वारा ₹2.45 करोड़ पियचिमी त्रिपुरा में 10 कार्यान्वयन अभिकरणों को आत्मसर्म्पण कर चुके 631 उग्रवादियों को इं.आ.यो. के अंतर्गत घर प्रदान करने के लिए जारी किया (2008-13 के दौरान) आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों केा 31 इं.आ.यो. घर प्रदान करने के लिए जारी किया। इं.आ.यो. दिशानिर्देशों, जो इं.आ.यो. के अंतर्गत आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों को शामिल करने की कोई व्यवस्था नहीं करता, से ऐसे विपथन हेतु मंत्रालय से कोई अनुमोदन प्राप्त किया हुआ दिखायी नहीं दिया। राज्य सरकार ने बताया कि उग्रवादी आत्मसमर्पण कर चुके अतिवादी थे और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वास की आवश्यकता थी।

5.16 अलेखांकित व्यय या निधियों का दुर्विनियोजन

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 (ख) (**vii**)जि.ग्रा.वि.प्रा. द्वारा मंत्रालय से दूसरी किस्त का दावा करते समय गैर-गबन प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति को आवश्यक करता है। हमने पाया कि जि.ग्रा.वि.प्र. ने गैर-गबन प्रमाण-पत्र की सामान्य तरीके से यथोचित सतर्कताका पालन किये बगैर कर दिया था।

इं.आ.यो. निधियों के दुर्विनियोजन के ₹4.91 करोड़ की धनराशि के साथ 15 सुनिश्चित मामले असम, बिहार एवं झाखण्ड में देखे गये थे।

लेखा परीक्षा ने यह भी पाया कि असम, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मणिपुर,नागालैण्ड, औडिशा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के नौ राज्यों के 15 मामलों मे लाभार्थियों को सहायता के अंतरण एवं निर्माण सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु भुगतानोंसे संबंधित कोई समर्थक वाउचर/ अभिलेख नहीं थे। इसमें ₹9.76 करोड़ की धनराशि सम्मिलित थी। इन मामलों में निधियों के संदिग्ध दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता है।

दुर्विनियोजन के निश्चित और संदिग्ध मामलों के ब्यौरे **अनुबंध -5.7** में दिये गये हैं।

मंत्रालय ने बताया कि लेखा परीक्षा द्वारा संदर्भित विशेष मामलों की जाँच की जाएगी तथा की गयी कार्रवाई को संबंधित राज्य सरकारों से आगत को प्राप्त करने के पश्चात प्रस्तुत किया जाएगा।

5.17 लाभार्थियों को सहायता का भुगतान

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 4.10 के अनुसार, लाभार्थी को कार्य की प्रगति के अनुसार धीर-धीरे होना था और समूची धनराशि एकमुश्त रूप में नहीं दी गयी थी। कार्य की प्रगति से भुगतान के किस्तों का जुडाव का निर्णय राज्य सरकार राज्य या जिला स्तर पर निर्णय किया जा सकता था आदर्श रूप में सहायता दो-किस्तों में वितरित करनी थी, पहली किस्त संस्वीकृति आदेश के साथ और दूसरी किस्त जब निर्माण सरदलस्तर पर पहुँच जाए। लेखापरीक्षा द्वारा लाभार्थियों को सहायता के वितरण में पाई गई विशेषताओं का विवरण निम्नलिखित मामला अध्ययन में उल्लिखित है:

मामला अध्ययन: अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड एवं त्रिपुरा में इं.आ.यो. के कार्यान्वयन में विशेषताएं

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, इं.आ.यो. का 2008-13 के दौरान कार्यान्वयन लाभार्थियों को नालीदार जस्ती लोहे (सी.जी.आई.) की चादरों के रूप में निर्माण सामग्री प्रदान करने तक ही सीमित रहा था। अरूणाचल प्रदेश एवं नागालैण्ड ने इं.आ.यो. के अंतर्गत 2008-13 के दौरान क्रमश: ₹202.30 करोड़ एवं ₹214.20 करोड़ का व्यय किया जो पूरी तरह से सी.जी.आई. चादरों के प्रापण पर हुआ था।

इं.आ.यो. दिशानिर्देशोंमें निर्धारित वित्तीय सहायता के प्रति नागालैण्ड में प्रत्येक लाभार्थी को सी.जी.आई चादरों के पॉच से लेकर सात गट्ठर दिये गये थे और अरूणाचल प्रदेश में, लाभार्थियों को इा.आ.यो. के अंतर्गत अनुमेय वित्तीय सहायता के बराबर सी.जी.आई. चादरें प्रदान की गयी थीं।

इ.आ.यो. दिशानिर्देशों में निर्धारण के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करने से, लाभार्थियों को घर के निर्माण के प्रकार में पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गयी थी। इसके अतिरिक्त, केवल सी.जी.आई. चादरें प्रदान करने से घर नहीं बन जाता क्योंकि इं.आ.यो. लाभार्थी को घर के निर्माण हेतुसामग्री एवं श्रमिकों की कीमत देनी होगी।

नागालैण्ड में, 68,805 लाभार्थियों (ग्रामीण विकास विभाग, नागालैण्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना) को इ.आ.यो. के अंतर्गत 2008-13 के दौरान सहायता प्रदान की गयी थी। इन लाभार्थियों के लिए 4,43,553 सी.जी.आई. चादरों के गट्ठरों के प्रापण की आवश्यकता थी (2008-09 के दौरान 19,041 लाभार्थियों के लिए प्रति लाभार्थी चादरों के पांच गट्ठर एवं 2009-13 के दौरान 49,764 लाभार्थियों के लिए प्रति लाभार्थी चादरेां सात गट्ठर। हालॉकि, विभाग ने 5,285 गट्ठर सी.जी.आई चादरों के 2008-13 के दौरान जाकर अधिप्राप्त कराये। अत: वास्तविक हकदारी के प्रति लाभार्थियों को सी.जी.आई चादरों के 5,285 गट्ठरों का कम वितरण हुआ था। तीन चयनित जिलों के संयुक्त प्रत्यक्ष सहायता के समय इसका खुलासा हुआ जहाँ 720 में से 369 लाभार्थियों ने पुष्टि की कि 2008-13 के दौरान उन्होंने चादरों के 2,551 गट्ठरों के पात्रता के प्रति केवल 1,744 गट्ठर ही प्राप्त किये। सी.जी.आई. दादरों के कम वितरण के कार, 2008-13 हेतु वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि अधिक थी। (41,189 घरों की संख्या के लक्ष्यों के प्रति 68,805 घर पूरे हुए थे)। विभाग ने बताया कि अतिरिक्त उपलब्धि ₹12,500 प्रति लाभार्थी के कम निर्गम से बची राशि के उपयोग द्वारा अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने के कारण हुई थी (₹48,500 के मूल्य के सी.जी.आई चादरों की पात्रता के प्रति, प्रत्येक लाभार्थी को सिर्फ ₹36,000 मूल्य के सी.जी.आई चादर ही वितरित किये गये थे।) विभागने लक्ष्य से अधिक लाभार्थियों को, इं.आ.यो. के अनुसार दिशानिर्देशों लाभार्थियों की वितिय पात्रता से कम कीमत वाले सी.जी.आई चादरों के गट्ठरों को संख्या में वितरित कर शामिल किया था। अत: विभाग द्वारा दावित लक्ष्य की अतिरिक्त उपलब्धि इं.आ.यो. के पात्रता में कमी करने की कीमत पर अर्जित की गयी थी।

अरूणाचलप्रदेश के पश्चिम सीयांग जिले में 3,032 लाभार्थियों की 1,681.30 मैट्रिक टन की उनकी पात्रता के प्रति 1,545.64 मैट्रिक टन सी.जी.आई. चादरें प्रदान की गयी थी। अत: लाभार्थी इं.आ.यो. के पूरे लाभ से वंचित रहे। लोहित जिले में,जिन 2,191 लाभार्थियों को नये घर बनाने के लिए सहायता प्रदान की गयी थी उन्हें 2008-13 के दौरान ₹328.65 लाख राशि को सहायता कच्चे घरों के उन्नयन के लिए भी प्रदान की गयी थी। जि.ग्रा.वि.प्रा. ने बताया कि ₹38,500 की छोटी राशि (प्रति इकाई नये निर्माण के लिए सहायता) से, भौगोलिक रूप से प्रतिकूल पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाना मुश्किल था, इसलिए नये निर्माण और उन्नयन दोनों के लिए ही रखी राशि लाभार्थियों को दे दी गयी थी। जि.ग्रा.वि.प्रा.का कार्य ई.आ.यो. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के विरूद्ध था और यह लाभार्थियों केा नये निर्माण के अंतर्गत ₹328.65 लाख के अतिरिक्त निर्गम में भी परिणत हुआ था।

त्रिपुरा में,लाभार्थियों को 2008-10 के दौरान घरों के निर्माण के तरीके में संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गयी थी। इं.आ.यो. के घरों के निर्माण का कार्य विभागीय कार्यान्वयन अधिकारियों (पंचायत सचिवों/कनिष्ठ अभियंताओं) को सौंपा गया था। ग्राम पंचायतों द्वारा लाभार्थियों के चयन के बाद, निर्माण आदेश कार्यान्वयन अधिकारी के नाम से चयनित लाभार्थियों के लिए इं.आ.यो. घरों के निर्माण के लिए जारी किये गये थे। सी.जीआई चादरें के अलावा, नालीदार ट्रस्स (छत बनाने के लिए निर्मित लोहे के काले पाइप से निर्मित संरचना), आर.सी.सी. खंभा एवं बांस की चटाई के दीवार और मिट्टी के दीवार लाभार्थियों केा प्रदान किये गये थे। लाभार्थियों केा कोई धनराशि नहीं दी गयी थी। सी.जी.आई चादर और नालीदारट्रस्स का प्रबंध कार्यान्वयन अधिकारी द्वारा उसे प्रदत्त इ.आ.यो. निधियों से किया गया था और और इं.आ.यो. घरों के बनने के बाद अग्रिमों का समायोजन जमा कर दिया गया था। उपरोक्त सभी व्यय इ.आ.यो. के अंतर्गत प्रति लाभार्थी उपलब्ध सहायता तक ही सीमित था। 2008-10 के दौरान ₹132.68 करोड़ का पूरा व्यय इसी तरीके से किया गया था।

त्रिपुरा एवं नागालैण्ड में सी.जी.आई. शीटों से बने मकानों के नमूना चित्र



त्रिपुरा के खोवाई ब्लॉक के लक्ष्मी नारायण पुर गाँव का इं.आ.यो. का घर



त्रिपुरा के खोवाई ब्लॉक के लक्ष्मी नारायण पुर गाँव का इं.आ.यो. का घर



5.17.1 गैर-कंपितआधार पर सहायता का भुगतान

हमने देखा कि 11 राज्यों (**असम, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाड़, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल**) के 32 चयनित जिलों के 74,872 लाभार्थियों को ₹107.53 करोड़ का भुगतान एकमुश्त/घरों के निर्माण की प्रगति से जोड़े बगैर किया गया था। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध 5.8 में दिया गया है।

5.17.2 लाभार्थियों को सहायता के भुगतान / गैर-भुगतान में देरी

पाँच राज्यों **(असम, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान एवं तमिलनाडु)** के 14 चयनित जिलों में, पहली (दूसरी किस्त का संवितरण नियत तिथि से 14 से 1,140 दिनों के विलंब के बाद किया गया था। ब्यौरे **अनुच्छेद 5.9.1** में दिये गये है।

गोवा में जि.ग्रा.वि.प्रा. (दक्षिण) से इं.आ.यो. लाभार्थियों को ₹1.42 करोड़ राशि के चैक जारी करने में मंत्री के सुविधा से सार्वजनिक बैठक के प्रबंध में विलंब के कारण आठ माह से अधिक के असाधारण विलंब थे।

हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के 17 चयनित जिलों में, 13,038 लाभार्थियों को दूसरी किस्त जारी नहीं की गयी थी। इन 13,038 लाभार्थियों द्वारा पहली किस्त का उपयोग लेखापरीक्षा द्वारा पुष्ट नहीं किया जा सका। ब्यौरे **अनुबंध- 5.9.2** में दिये गये हैं।

गुजरात के तीन चयनीतजिलों (दाहोद, जूनागढ़ एवं बडोदरा) के चार ब्लॉकों (जालोद, लिमखेड़ा, केशोद एवं संखेदा) में, 983 इं.ओ.यो. लाभार्थियों को बैंक खातों की अनुपलब्धता/बैंक खातों में असंगति के कारण कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई थी।

पंजाब के तीन चयनित जिलों (नवां शहर, पटियाला, एवं एस.ए.एस नगर) में, 56 लाभार्थियों को ₹13.28 लाख का भुगतान नहीं किया गया था। पश्चिम बंगाल के कालीगंज पी.एस. (नदिया जिला) में एवं ब्लॉक सुरी-।। के अंतर्गत दोमदोमा ग्रा.पं. में, यद्यपि लाभार्थियों का चयन हुआ था और क्रमश:

₹4.32 करोड़ एवं ₹51.00 लाख की निधि उपलब्ध थी, 2008-11 के दौरान किसी लाभार्थी को भुगतान नहीं किया गया था।

गोवा (दक्षिण) जिले में, 123 लाभार्थियों के नाम से आहरित ₹20.00 लाख के चैक बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिये गये थे। मंत्री के मौखिक निर्देश के अनुसार भुगतान किन्हीं अन्य लाभार्थियों को किये गये थे जिन्होंने बाद में आवेदनकिया। जम्मू एवं कश्मीर में, विभाग ने लाभार्थियों को चैक के द्वारा सांसद /विधायक/मंत्रियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों में भुगतान करने का निश्चय किया था जो लाभार्थियों को सहायता के विलंबित भुगतान में परिणत हुआ।

5.17.3 लाभार्थियों को सहायता से ₹139.37 करोड़ की अप्राधिकृत कटौती

निम्नलिखित तीन राज्यों में, लेखा परीक्षा ने पाया कि ₹139.37 करोड़ इं.आ.यो. लाभार्थियों को दी गयी सहायता से निम्नानुसार काटे गये थे:

राज्य	कटौती (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ
आन्ध्र प्रदेश	139.12	₹11.02 लाख लाभार्थियों से 2008-13 के दौरान आवेदन शुल्क, लाभार्थी अंशदान एवं प्रशासनिक शुल्कों के प्रति वसूली।
गुजरात	0.11	दो चयनित जिलों (आनंद एवं दाहोद) चार चयनित ब्लॉकों (आनंद, तारापुर, जालोद एवं लिमखेड़ा) में 2008-13 के दौरान 2,298 लाभार्थियों के मामले में धुआँ रहित चुल्हा/स्वच्छ शौचालय/इं.आ.यो. प्रदर्शन पट्टी के गैर-संस्थान/गैर-निर्माण के प्रति कटौती।
झारखंड	0.14	चार चयनित जिलों (देवघर, गढवा, गोड्डा एवं रांची) के नौ चयनित ब्लॉकों (सदर, मधुपुर, गोड्डा, सदर, ठाकुरगंग्ती, चिनिया, डंडई, नगरूतरी, गढ़वा सदर,

		रातू एवं मंडार) में 2008-12 के दौरान 2,925 लाभार्थियों से धुआँ रहित चुल्हा/स्वच्छ शौचालय/इ.आ.यो. प्रदर्शन पट्टी के गैर-संस्थापन/गैर-निर्माण के प्रति।
कुल	139.37	

यह कटौती अनियमित थी चूंकि दिशानिर्देशों में लाभार्थियों की दी गयी सहायता से किसी प्रकार के कटौती की अनुमति नहीं देते।

5.17.4 सहायता के भुगतान में अनियमितता

छः राज्यों (असम, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, एवं उत्तराखण्ड) के 16 चयनित जिलों में, 21,413 लाभार्थियों को ₹19.07 करोड़ की सहायता निर्धारित दरों से कम दरों पर की गयी थीं। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-5.10** में दिये गये हैं।

अभिलेखों के अनुसार, ₹47.00 लाख 131 लाभार्थियों को मणिपुर के सेनापति जिले में अदा किया गया दिखाया गया था। तथापि, संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान यह देखा गया था। तथापि, संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण में यह देखा गया था कि इन लाभार्थियों को केवल ₹19.00 लाखमूल्य को ही सी.जी.आई चादरें दी गयी थीं। इसके अतिरिक्त, 89 लाभार्थियों द्वारा (जिलों के घरों के प्रत्यक्ष रूप से सत्यापन हुए थे) सात ब्लॉकों में प्राप्त की गयी राशिउनके लिए निर्गमित राशि से ₹14.67 लाख कम थी। मणिपुर के चार चयनित जिलों (चुरावंदपुर, पूर्वी इंफाल, सेनापति, थौबल) में 336 लाभार्थियों की उनकी पात्रता से ₹78.68 लाख अतिरिक्त रूप से अदा किया गया था।

उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की सहायता के भुगतान में अनियमितता

उत्तर प्रदेश में तीन चयनित जिलों (अमरोहा, बदायूं, देवरिया एवं गोडा) में 7,961 लाभार्थियों को 2008-13 के दौरान, कुल ₹22.34 करोड़ के व्यक्तिगत चैक जारी किये थे। बैंक खातों के ब्यौरों की अनुपलब्धता के कारण, लाभार्थियोंके खाते में वित्तीय सहायता के वास्तविक जमा को लेखापरीक्षा में निधारित नहीं किया जा सका।

5.17.5 नगद/धारक चैकों/सेल्फ चैक निर्माण समिति/सरपंचों के माध्यम से किये गये भुगतान

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 4.10 के अनुसार, लाभार्थियों को सहायता किसी बैंक या डाक घर में उनके खाते में सीधे हस्तांतरित किये जाने चाहिए। हमने देखा कि पांच राज्यों (गुजरात, झारखंड, मणिपुर, मेघालय एवं पंजाब) के 12 चयनित जिलों में 8,964 लाभार्थियों को ₹28.97 करोड़ का भुगतान इं.आ.यो. दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए नकद/धारक चैक/सेल्फ चैकों में किया गया था। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-5.11** में दिये गये है।

इसमें से, पंजाब के तरन तारन के चयनित जिले तरन तारन ब्लॉक में लाभर्थियों को जारी ₹6.00 लाख मूल्य के 28 धारक चैक मार्च 2013 तक भुनाये नहीं गये थे।

इसके अतिरिक्त, असम[8] के छह चयनित जिलों तथा पंजाब[9] के 276 ग्रा.पं.में 23.28 करोड़ की सहायता पहले निर्माण समिति या सरपंचों को, लाभार्थियों को आगे भुगतान करने के लिए हस्तांतरित किया गया था। जो इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के विरूद्ध था। ₹2.15करोड़ की निधियों के उपयोग से संबंधित अभिलेख असम में ब्लॉक एवं ग्रा.पं. स्तरों पर उपलब्ध नहीं थे। अभिलेख असम में, लेखा परीक्षा इं.आ.यो. के अंतर्गत निर्मित घरों पर निधियों के वास्तविक उपयोग का निर्धारण नहीं कर सका।

5.17.6 लाभार्थियों को दुहरा/अतिरिक्त भुगतान

तीन राज्यों (बिहार, जम्मू एवं कश्मीर तथा राजस्थान) के 11 चयनित जिलों में ₹7.16 करोड़ का दुहरा/अतिरिक्त भुगतान 3,833 लाभार्थियों को किया गया था। ब्यौरे **अनुबंध-5.12** में है।

---

[8] असम : दो चयनित जिलों के 48 ग्रा.पं. में ₹2.15 करोड़

[9] पंजाब : चार चयनित जिलों के 228 ग्रा.पं. में ₹21.13 करोड़

अनुशंसा:

- इं.आ.यो. के अंतर्गत घर के निर्माण/उन्नयन हेतु सहायता संस्वीकृति करने के पूर्व, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभार्थी का बैंक खाता हो। दूसरी किस्त को संबंधित प्राधिकारियों से यथोचित सत्यापन प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के पश्चात ही उनके बैंक खाते में जारी किया जाना चाहिए।

अध्याय 6: अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण

6.1 प्रस्तावना

इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो.) के दिशानिर्देशों के पैरा 5.11 के अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (जि.ग्रा.वि.अ.) को केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं, जिन्हें इं.आ.यो. के साथ समन्वित किया जा सके जिससे इं.आ.यो. के लाभार्थी ग्रामीण ग.रे.नी. के परिवारों हेतु प्रत्याशित इन योजनाओं के लाभों को प्राप्त कर सके, की पहचान करने हेतु संगठित प्रयास करने थे। यह विचार किया गया था कि इं.आ.यो. के आवासों में स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु पूर्ण स्वच्छता अभियान; बिजली प्रदान करने हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना; पेय जल प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम; ऋण सुविधा का लाभ उठाने हेतु ब्याज की विशिष्ट दर योजना; ग्रामीण ग.रे.नी के परिवारों तथा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों हेतु बीमा नीतियों; तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत जॉब कार्ड के अंतर्गत कार्यों एवं प्रदत्त निधियों के साथ इं.आ.यो. का अभिसरण होना चाहिए जिससे कि इन योजनाओं के अंतर्गत संभावित लाभों का इं.आ.यो. के लाभार्थियों तक विस्तार किया जा सके।

6.2 अभिसरण कार्यों का अभाव

6.2.1 पूर्ण स्वच्छता अभियान (पू.स्व.अ.) के अंतर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण

हमने पाया कि 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान पूरे देश में 107.58 लाख घरों में से केवल 25.48 लाख (23.68 *प्रतिशत*) में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया गया था। इस प्रकार, 76.32 *प्रतिशत* घर पू.स्व.अ. के लाभों से वंचित थे क्योंकि इन घरों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, 16 राज्यों/सं.शा.क्षे. अर्थात **अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा** (पांच जिलों में), **जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड** तथा **अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** के चयनित जिलों में पू.स्व.अ. के साथ अभिसरण नहीं किए गए थे।

छत्तीसगढ़ में पांच चयनित जिलों तथा 13 ब्लॉकों में, इं.आ.यो. तथा पू.स्व.अ. के बीच अभिसरण के संबंध में जागरूकता की कमी थी। इं.आ.यो. के लाभार्थियों को पू.स्व.अ. के अंतर्गत सहायता को सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों की ओर से कोई संगठित प्रयास नहीं थे। स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के स्थान पर अभिकरणों ने इं.आ.यो. के अंतर्गत सहायता के निर्गम हेतु अपनी संस्वीकृति में अनुबंधित किया कि इं.आ.यो सहायता के एक भाग का उपयोग स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु किया जाना था। इस प्रकार, पू.स्व.अ. के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने के बजाए लाभार्थियों को इं.आ.यो. सहायता में से स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना था। **उत्तराखण्ड** में इं.आ.यो. के घरों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण पू.स्व.अ. के अंतर्गत किया जाना था परंतु वास्तव में वह इं.आ.यो के अंतर्गत निधिबद्ध थे। **उत्तर प्रदेश** में 15 चयनित जिलों में इं.आ.यो. के अंतर्गत घर की संस्वीकृति करते समय स्वच्छ शौचालय की संस्वीकृति को सुनिश्चित नहीं किया था। जिला पंचायत राज अधिकारी (जि.पं.रा.अ.), जिसके अंतर्गत पू.स्व.अ. कार्यान्वित किया जा रहा था, स्वतंत्र रूप से कार्य रह थे न कि जि.ग्रा.वि.अ. के समन्वय में। जि.ग्रा.वि.अ. ने स्थिर रूप से जि.पं.रा.अ. को इं.आ.यो. के अंतर्गत संस्वीकृत घरों की सूची नहीं भेजी थी तथा स्वच्छ शौचालय के निर्माण को भी सुनिश्चित नहीं किया था। घर के निर्माण के साथ स्वच्छ शौचालय को संस्वीकृत करने तथा निर्माण को सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। हमने पाया कि 15 चयनित जिलों में, से नौ जिलों[1] में 2008-13 के दौरान 4,41,409 संस्वीकृत घरों के प्रति केवल 55,635 स्वच्छ शौचालयों (12.60 प्रतिशत) का निर्माण किया गया था।

[1] अमरोहा, देवरिया (केवल ब्लॉक भटानी के), गोंडा, कुशीनगर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, रामपुर तथा वाराणसी

आन्ध्र प्रदेश में, आन्ध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड (आ.प्र.रा.आ.नि.लि.) ने अन्य भा.स. के कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ इं.आ.यो. के अभिसरण के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि दो चयनित जिलों करीमनगर तथा खम्माम में, 2,04,569 संस्वीकृत घरों[2] में से केवल 34,487 घरों[3] (16.86 *प्रतिशत*) को स्वच्छ शौचालय सहित संस्वीकृत किया गया था।

महाराष्ट्र में, आठ चयनित जिलों में से तीन जिलों (अहमदनगर, रतनगिरी, थाणे) में इं.आ.यो. के साथ अभिसरण किया गया था। चार चयनित जिलों (भांद्रा, सोलापुर, बीद, गोंडिया) तथा नांदेड़ जिले के दो ब्लॉकों (अर्धपुर, किनवत) में इं.आ.यो. के साथ कोई अभिसरण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को इं.आ.यो. की सहायता से स्वच्छ शौचालय का निर्माण करने को बाध्य किया गया था क्योंकि राज्य सरकार ने जि.ग्रा.वि.अ. को जब तक लाभार्थियों द्वारा स्वच्छ शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता इं.आ.यो. की अंतिम किश्त जारी न करने का अनुदेश दिया था। यह अनुदेश दिशानिर्देशों के प्रतिकूल था तथा इसने इं.आ.यो. के लाभार्थियों को पू.स्व.अ. के लाभों से वंचित रखा।

मामला अध्ययन

उत्तर प्रदेश

जिला पंचायत राज अधिकारी (जि.पं.रा.अ.), वाराणसी ने 2009-11 के दौरान स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु इं.आ.यो. के लाभार्थियों के बैंक खातों में क्रेडिट करने के लिए जि.ग्रा.वि.अ. वाराणसी को ₹1.35 करोड़ जारी किए जिसमें से जि.ग्रा.वि.अ. ने इं.आ.यो. के लाभार्थियों को ₹36 लाख जारी किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹5.50 लाख का जि.ग्रा.वि.अ. के स्टाफ के वेतन के भुगतान तथा ₹0.34 लाख का एक इं.आ.यो लाभार्थी को प्रथम किश्त हेतु विपथन किया गया था। ₹1.04 करोड़ (ब्याज सहित) की राशि अप्रयुक्त रहीं (फरवरी 2013)।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि जि.पं.रा.अ. से अभिसरण के अंतर्गत निधियों की प्राप्ति के पश्चात जि.ग्रा.वि.अ. वाराणसी ने 2010-11 में 739 लाभार्थियों को स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु 1,500 प्रत्येक को प्रथम किश्त जारी की तथापि, इन लाभार्थियों को दूसरी किश्त जारी नहीं की गई थी (मई 2013)। परिणामस्वरूप न तो स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया गया था और न ही संवितरित राशि (₹11.09 लाख) को उपयोग में लाया गया था।

---

[2] (करीमनगर-51,107 तथा खम्माम- 1,53,462)

[3] (करीमनगर-13,914 तथा खम्माम-20,573)

6.2.2 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (रा.गां.ग्रा.वि.यो.) के साथ अभिसरण

21 राज्यों अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश (एक जिला), जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखण्ड** तथा **उत्तर प्रदेश** के चयनित जिलों में मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करने हेतु इं.आ.यो. का रा.गां.ग्रा.वि.यो. के साथ अभिसरण नहीं किया गया था।

6.2.3 राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (रा.ग्रा.ज.आ.का.) के साथ अभिसरण

हमने पाया कि 24 राज्यों/सं.शा.क्षे. अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश (एक जिला), जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल** तथा **अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** के चयनित जिलों में इं.आ.यो. के लाभार्थी रा.ग्रा.ज.आ.क. के साथ अभिसरण के लाभों से वंचित थे।

मध्य प्रदेश में, 13 चयनित जिलों से नौ जिलों[4] ने सूचित किया कि रा.ग्रा.ज.आ.क. के साथ अभिसरण सुनिश्चित नहीं था। दो जिलों (मांडला, खाण्डवा) ने रा.ग्रा.ज.आ.क. के साथ अभिसरण सूचित किया, फिर भी, सत्यापन हेतु लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे तथा शेष दो जिलों (दिनदोरी, उज्जैन) ने बताया कि उनके पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

---

[4] बालघाट, बार्वानी, धार, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़ तथा शाजापुर

6.2.4 ब्याज की विशिष्ट दर (ब्या.वि.द.) योजना के साथ अभिसरण

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 तथा 3.3 के अनुसार, इं.आ.यो. के अंतर्गत प्रदत्त सहायता के अतिरिक्त एक इं.आ.यो. लाभार्थी इं.आ.यो. के अंतर्गत मात्रक सहायता को पूरा करने हेतु ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से चार *प्रतिशत* प्रति वर्ष की ब्याज दर पर अपने लिए ₹20,000 प्रति आवासीय इकाई तक के ऋण का लाभ उठा सकेगा। उन लाभार्थियां, जो इच्छुक हैं, को क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय करने की संबंधित राज्य सरकार/जि.ग्रा.वि.अ. की जिम्मेदारी होगी।

हमने ने पाया कि 13 राज्यों अर्थात् **अरूणाचल प्रदेश**, **असम**, **बिहार गोवा**, **जम्मू एवं कश्मीर**, **कर्नाटक**, **महाराष्ट्र**, **मणिपुर**, **मेघालय**, **नागालैण्ड**, **राजस्थान**, **उत्तर प्रदेश**, **तथा पश्चिम बंगाल** के चयनित जिलों में 2008-13 के दौरान क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय में राज्यों/जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा प्रयासों तथा लाभार्थियों में ब्या.वि.द. योजना की जागरूकता के अभाव के कारण ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत ऋण सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया था।

आन्ध्र प्रदेश में, आ.प्र.रा.आ.नि.लि. द्वारा ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत लाभार्थियों हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए थे। तथापि, प्रत्येक अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थी राज्य आवासीय कार्यक्रम (इंदिराम्मा) के अंतर्गत ₹20,000 के ऋण का पात्र था।

छत्तीसगढ़ में, पांच चयनित जिलों में 2011-13 के दौरान मामलों में से केवल 1,639 मामलों (तीन *प्रतिशत*) को ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत ऋण हेतु बैंकों को प्रेषित किया गया था। इनमें से केवल 552 मामलों (एक *प्रतिशत*) में ऋण संस्वीकृत किए गए थे। ब्या.वि.द. के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु जि.पं. द्वारा बैंकों को प्रेषित मामलों तथा ब्या.वि.द. ऋण का लाभ उठा रहे लाभार्थियों की प्रतिशतता पर्याप्त स्तर तक नहीं थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह भी पाया गया था कि लाभार्थी योजना से अवगत नहीं थे जो

दर्शाता है कि कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा योजना के संबंध में विस्तृत जागरूकता उत्पन्न नहीं की गई थी।

गुजरात में, 13 चयनित ब्लॉकों (आणंद, तारापुर, पालनपुर, दीसा, चोटिला, सायला, जालोद, लिमखेड़ा, भेसन, जूनागढ़, केशोद, कामरेज तथा मांडवी) में संस्वीकृत 65,447 घरों में से ऋण हेतु इं.आ.यो. के लाभार्थियों के केवल 25,447 आवेदन पत्रों को बैंको को प्रस्तुत किया गया था तथा 866 आवेदन पत्रों (एक *प्रतिशत*) को ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया गया था।

हरियाणा में, इं.आ.यो. के लाभार्थियों में ब्या.वि.द. योजना के संबंध में जागरूकता को उत्पन्न नहीं किया गया था जिसका परिणाम हुआ कि 2008-13 जिला महेन्द्रगढ़ में केवल एक लाभार्थी ब्या.वि.द. योजना का लाभ उठा सका।

झारखण्ड में, छः चयनित जिलों में से केवल एक जिले (पूर्वी सिंहभूम) में अक्तूबर 2010 तक 456 लाभार्थियों को ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत कुल ₹56.46 लाख के ऋण प्रदान किए गए थे। तथापि, लेखापरीक्षा को लाभार्थियों, संवितरण, आदि के ब्यौरे के संबंध में वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

केरल में, यद्यपि 2.54 लाख लाभार्थियों ने इं.आ.यो. के अंतर्गत सहायता का लाभ उठाया फिर भी उनमें से केवल 2,346 लाभार्थियों ने 2008-13 के दौरान ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया था। दो चयनित जिलों में (थिरूवनन्थापुरम, वायनाड) में किसी भी लाभार्थी ने ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त नहीं किया था। जिला मालापुरम में 2008-13 के दौरान प्रस्तुत 45 आवेदन पत्रों में से केवल 15 आवेदकों को ऋण संस्वीकृत किया गया था तथा शेष 30 आवेदन पत्रों को बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। जिला अलप्पुझा में, प्राप्त 3,345 आवेदन पत्रों में से केवल 934 आवेदन

पत्रों को ऋण संस्वीकृत किया गया था तथा 2,411 आवेदन पत्रों को बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।

मध्य प्रदेश में, 13 चयनित जिलों में से 10 जिलों (बालाघाट, बर्वानी, धार, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर तथा उज्जैन) में इं.आ.यो. लाभार्थी को ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत ऋण की सुविधा प्रदान करने हेतु जिला स्तर पर कोई पहल नहीं की गई थी। दो जिलों (खंडवा, मांडला) ने बताया कि ब्या.वि.द. योजना जि.प./ग्रा.पं. के माध्यम से विज्ञापित की जा रही थी तथा जिला डिंडोरी ने बताया कि जिला स्तर पर पहल की गई थी परंतु सत्यापन हेतु लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे। सभी चयनित जिलों ने बताया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किसी भी लाभार्थी ने ऋण के लिए आवेदन नहीं किया था।

ओडिशा में, 123 ग्रा.पं. के आठ चयनित जिलों में 239 ग्रामों में 1,293 लाभार्थियों का साक्षात्कार किया गया था जिन्होंने ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत ऋण होने से अनजान होना व्यक्त किया। योजना के संबंध में जागरूकता के निम्न स्तर के बावजूद यह पाया गया था कि जिला खुर्दा के दो ब्लॉकों (बोलागढ़, जटनी) में 66 लाभार्थियों ने ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया। जिला खुर्दा के सिवाय, अन्य सात चयनित जिलों में किसी भी लाभार्थी ने ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त नहीं किया था।

त्रिपुरा में, दो चयनित जिलों में छः ब्लाकों में से दासदा ब्लॉक में 2008-09 से 2012-13 के दौरान संस्वीकृत 6,414 घरों में से केवल 119 लाभार्थियों ने ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कोई सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (सा.क्षे.बैं.) ग्राम पं. नील केन्द्र में उपलब्ध नहीं था। चूंकि ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत ऋण केवल लो.क्षे.बैं. के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है इसलिए कथित ग्रा.पं. के लाभार्थी ब्या.वि.द. योजना के लाभों को प्राप्त नहीं कर सकें। ब्लॉक मायाबंदर ने बताया कि ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत ऋण की सीमा से

सहकारी बैंको का बहिष्करण ऐसी सुविधा का लाभ उठाने में एक बाधा थी। जि.ग्रा.वि.अ., दक्षिण अण्डमान ने ब्या.वि.द. योजना के दिशानिर्देशों में बिना कोई उचित संशोधन किए मामले को मंत्रालय के साथ-साथ सहकारी बैंक के साथ उठाया था। (दिसम्बर 2010)।

मंत्रालय ने बताया (जून 2014) कि पात्रता के संबंध में स्पष्टता की कमी के कारण ब्या.वि.द. ऋणों को काफी सीमित संख्या में प्राप्त किया गया था।

6.2.5 जीवन बीमा निगम (जी.बी.नि.) के साथ अभिसरण

इं.आ.यो. के दिशानिर्देश के पैरा 5.11 (vi) के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम (जी.बी.नि.) में ग्रामीण ग.रे.नी. के परिवारों हेतु जीवन बीमा तथा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लाभ हेतु आम आदमी बीमा कहीं जाने वाली बीमा योजनाएं है। जि.ग्रा.वि.अ. को प्रत्येक माह संबंधित नोडल अभिकरण, जो जिलों में दो बीमा योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, को सभी इच्छुक इं.आ.यो. के लाभार्थियों के विवरण प्रस्तुत करने हैं जिससे कि सभी इच्छुक इं.आ.यो. के लाभार्थी इन बीमा नीतियों के अंतर्गत उपलब्ध लाभों को प्राप्त करें।

हमने पाया कि 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान पूरे देश में जनश्री तथा आम आदमी बीमा योजना को क्रमश: केवल 0.97 लाख (0.90 प्रतिशत) तथा 2.95 लाख (2.74 *प्रतिशत*) प्रदान की गई थी।

आगे, 21 राज्यों/सं.शा.क्षे. अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, (दस जिलों में), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल** तथा **अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** के चयनित जिलों में लाभार्थियों द्वारा दोनों बीमा योजनाओं का लाभ नहीं उठाया गया था।

6.2.6 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगस)[5] तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (स्व.ग्रा.स्व.यो.)[6] के साथ अभिसरण

हमने पाया कि 13 राज्यों अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिशा (खुर्दा के सिवाय), पंजाब, तमिलनाडु** तथा **उत्तर प्रदेश** के चयनित जिलों में इं.आ.यो. के लाभार्थियों हेतु दोनो योजनाओं के लाभों को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (जून/जुलाई 2014) कि इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के तहत जारी अन्य योजनाओं अर्थात पू.स्व.अ., रा.गां.ग्रा.वि.यो., रा.ग्रा.ज.आ.का., बीमा योजनाओं तथा मनेरेगस के साथ इं.आ.यो. के अभिसरण के संबंध में अनुदेश सलाहकार प्रकृति के अधिक हैं क्योंकि वह अन्य मंत्रालयों की संबंधित योजना के दिशानिर्देशों पर निर्भर हैं। उसने आगे बताया कि वह अच्छे परिणामों सुनिश्चित करने हेतु एक निरंतर आधार पर अभिसरण मामले को उठाएगा क्या संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार इं.आ.यो. के घर के साथ एक शौचालय पू.स्व.अ. (निर्मल भारत अभियान) के अंतर्गत अनिवार्य है।

मंत्रालय का उत्तर संतोषजनक नहीं है। अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर इं.आ.यो. के दिशानिर्देश परामर्शी प्रवृति के नहीं है क्योंकि वह सुस्पष्ट रूप से बताते हैं कि जि.ग्रा.वि.अ. क्षेत्रीय स्तर पर इन कार्यक्रमों का वास्तविक अभिसरण करने हेतु जिले में योजनाओं को कार्यान्वित कर रह सभी नोडल अभिकरणों के साथ सम्पर्क करने में कोई प्रयास नहीं छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त,

---

[5] ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के आश्वासित रोजगार से जीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से जनवरी 2006 में मनरेगस को कार्यान्वित किया।

[6] ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लगातर उल्लेखनीय स्तर को सुनिश्चित करके काफी समय से सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के उद्देश्य के साथ अप्रैल 1999 में योजना प्रारम्भ की।

इन योजनाओं के साथ अभिसरण यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी असम्बद्ध योजनाओं के आधिक्य के माध्यम ये प्रयासों को दोहराने के बजाए एक बार में लाभ प्राप्त करेंगे।

6.3 मासिक प्रगति रिपोर्ट (मा.प्र.रि.) के माध्यम से मॉनीटरिंग का अभिसरण

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों का पैरा 5.11 (viii) बताता है कि ऊपर चर्चा की गई योजनाओं के अभिसरण की प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु क्षेत्रीय स्तर पर अभिसरण कार्यों के संबंध में डाटा प्राप्त करने के लिए एक मासिक प्रगति रिपोर्ट-3 (मा.प्र.रि.-3) बनायी गयी है तथा जिसे निर्धारित प्रारूप में मंत्रालय को प्रतिमाह ऑनलाईन प्रस्तुत करना था। मा.प्र.रि.-3 को जिलों द्वारा मंत्रालय को वित्तीय सहायता, भौतिक प्रगति तथा अभिसरण प्रगति पर निगरानी को सूचित करने हेतु बनाया गया है।

मंत्रालय में अभिलेखों के विश्लेषण ने प्रकट किया मा.प्र.रि.-3 की ऑनलाईन मॉनीटरिंग मई 2006 में तैयार की गई थी फिर भी ऑनलाईन प्रणाली पूर्ण रूप से क्रियात्मक होने तक डाक द्वारा मा.प्र.रि. की हार्ड प्रतियों को भेजने की प्रणाली तब से निरंतर थी। अप्रैल 2007 से ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली को जिलों द्वारा अपनी मासिक प्रगति रिपोर्टों को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु क्रियात्मक किया गया था।

बिहार में, 2008-13 की अवधि हेतु 10 चयनित जिलों की मा.प्र.रि.-3 ने प्रकट किया कि निर्माण किए गए इं.आ.यो. के घरों में धुआंरहित चूल्हों, स्वच्छ शौचालयों तथा बिजली कनेक्शनों की उपलब्धता क्रमश: केवल पांच, सात तथा दो *प्रतिशत* थी, जबकि ब्लॉक स्तर पर तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया कि किसी भी जिले में अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण नहीं किया गया था। जि.ग्रा.वि.अ. के अधिग्रहण में अभिसरण कार्यों हेतु कार्यान्वित अभिकरणों को भेजे गए मामलों की संख्या के संबंध में आधारित डाटा भी नहीं था।

झारखण्ड में, 2008-09 से 2012-13 के दौरान राज्य में इं.आ.यो. के साथ अभिसरण कार्य **तालिका -11** में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार थे।

तालिका 11: अभिसरण के अंतर्गत सुविधाओं के प्रावधान को दर्शाते ब्यौरे

अवधि	राज्य	पूर्ण इं.आ.यो. के घरों की सं.	प्रतिशतता के साथ पूर्ण इं.आ.यो के घरों की तुलना में अभिसरण					
			निर्मित स्वच्छ शौचालय	प्रदत्त धुआंरहित चूल्हे	रा.गां.ग्रा.वि.यो. के अंतर्गत मुफ्त विद्युत कनेक्शन	आम आदमी बीमा	स्व.ग्रा.स्व यो. के अंतर्गत स्वयं सेवा समूह सदस्यता	मनरेगस के अंतर्गत जारी जॉब कार्ड
2009-13	झारखण्ड	3,37,154	33,035	27,758	4,710	2,757	6,622	59,251
प्रतिशतता अभिसरण			9.80	8.23	1.39	0.81	1.96	17.57

स्रोत राज्य मा.प्र.रि.

इस प्रकार, राज्य में अभिसरण के अंतर्गत सुविधाओं के प्रावधानों की प्रतिशतता 17 से एक *प्रतिशत* से कम के बीच थी। राज्य सरकार ने निर्माण किए घरों में 100 *प्रतिशत* सुविधाओं के प्रावधानों को सुनिश्चित करने हेतु सभी मण्डलीय आयुक्तों/उप आयुक्तों/उप-विकास आयुक्तों को निर्देश दिया (अगस्त/सितम्बर 2011)। तथापि, अभिसरण के अंतर्गत परिस्थिति वही रही।

आगे लेखापरीक्षा ने पाया कि 2008-13 के दौरान छः चयनित जिलों ने न तो इं.आ.यो के साथ अभिसरण हेतु अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ समन्वय किया था और न ही उनके पास पू.स्व.अ., रा.गां.ग्रा.रो.यो., आदि के अंतर्गत प्रदत्त सुविधाओं पर कोई सूचना थी।

मध्य प्रदेश में, 13 चयनित जिलों में से 10 जिलों[7] ने सूचित किया कि अभिसरण हेतु मा.प्र.रि.-3 प्रेषित नहीं की गई थी तथा तीन जिलों[8] ने सूचित किया कि मा.प्र.रि.-3 ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रेषित की जा रही थी।

[7] बालाघाट, बर्वानी, धार, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, रायसेन, खंडवा, शाजापुर, तथा उज्जैन

[8] डिंडोरी, मांडला तथा रायगढ़

मणिपुर में, सभी नौ जिलों (जिला उखरुल तथा तामेगंलॉग ने केवल आंशिक डाटा प्रस्तुत किया) की मा.प्र.रि.-3 ने प्रकट किया कि 2008-13 के दौरान, 28,612 लाभार्थियों ने ब्या.वि.द. तथा रा.गां.वि.यो. के लाभ प्राप्त नहीं किए थे और न ही जनश्री बीमा तथा आम आदमी बीमा योजनाओं का लाभ उठाया था। तीन चयनित जिलों (इम्फाल पूर्वी, थाउबल, सेनापति) ने अभिसरण से संबंधित डाटा उपलब्ध नहीं कराया था।

पंजाब में, छः चयनित जिलों में मा.प्र.रि.-3 का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

उत्तराखण्ड में, सभी पांच जिलों का इं.आ.यो. के साथ अभिसरण हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ समन्वय नहीं था। तथा उनके पास इसके कोई दस्तावेज नहीं था। इसके बावजूद, 2008-13 के दौरान विभाग द्वारा अभिसरण की स्थिति को अपनी मा.प्र.रि.-3 के माध्यम से नियमित रूप से मंत्रालय को सूचित किया जा रहा था जैसा कि **तालिका -12** में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 12: मंत्रालय को सूचित योजनाओं के साथ अभिसरण

2008-13 के दौरान पूर्ण किए गए घरों की संख्या	बनाया गया स्वच्छ शौचालय	धुआंरहित चूल्हे	रा.गां.ग्रा.वि.यो. के अंतर्गत प्राप्त लाभ	जनश्री/आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत नामांकित	स्वच्छ बीमा योजना के के अंकित नामांकित	स्वयं सेवा समूह (स्व.से.सं.) के अंतर्गत सदस्यता	मनरेगस के अंतर्गत जॉब कार्ड
राज्य स्तर पर							
76,781	61,632	48,163	4,460	28,034	9,765	12,060	32,167
प्रतिशतता	80.27	62.73	5.81	36.51	12.72	15.71	41.89
पांच चयनित जिलों में							
55,521	44,465	35,954	3,659	22,676	9,490	10,721	22,954
प्रतिशतता	80.09	64.76	6.59	40.84	17.09	19.31	41.34

(स्रोत: राज्य स्तर तथा पांच चयनित जिलों की मा.प्र.रि.)

आगे, जिला टेहरी गढ़वाल में 874 संस्वीकृत घरों के प्रति जि.ग्रा.वि.अ. स्तर पर 448 धुआंरहित चूल्हों का प्रापण था तथा नौ ब्लॉकों में संवितरण (मई 2012) किया गया था, जिसमें से 45 तथा 62 चूल्हे क्रमश: जौनपुर तथा देवप्रयाग ब्लॉक को प्रदान किए गये थे। दोनों ब्लाकों के ब्ला.वि.अ. ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा प्राप्त किए गए चूल्हों का प्रत्याशित लाभार्थियों को संवितरण नहीं किया गया था। आगे, चयनित ब्लॉकों के ब्ला.वि.अ. ने स्वीकार किया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान अन्य योजनाओं के साथ इं.आ.यो. के समन्वय हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि न तो धुआंरहित चूल्हों का प्रापण किया गया था और न ही इं.आ.यो. के लाभार्थियों को संवितरण किया गया था जबकि मा.प्र.रि. ने वास्तविक स्थिति के प्रति 64 *प्रतिशत* अभिसरण को दर्शाया।

पश्चिम बंगाल में, वर्ष 2012-13 हेतु जिला मालदा की मा.प्र.रि. ने प्रकट किया कि निर्माण किए गए 8,274 घरों में से अभिसरण के लाभों को ब्या.वि.द. (4.64 *प्रतिशत*), पू.स्व.अ. (27.62 *प्रतिशत*), रा.गां.ग्रा.वि.यो. (33.90 *प्रतिशत*) में पाया गया था। 2012-13 के दौरान, जी.बी.नि. के अंतर्गत 1,955 लाभार्थियों तथा अरोग्य रक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 1,805 लाभार्थियों को नामांकित किया गया था। तथापि,10 ग्रा.पं. में 120 इं.आ.यो. लाभार्थियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान उन्होंने ऐसे अभिसरण से इंकार किया।

इसी प्रकार, जिला बीरभूम ने अपनी मा.प्र.रि. में इं.आ.यो. के साथ 11 योजनाओं के अभिसरण को दर्शाया। 2008-09 से 2012-13 के दौरान, निर्माण किए गए 41,898 घरों में से इं.आ.यो. के साथ ब्या.वि.द. (1.11 *प्रतिशत*), पू.स्व.अ. (55.97 *प्रतिशत*), धुआंरहित चूल्हा (22.80 *प्रतिशत*), रा.गां.ग्रा.वि.यो. (4.77 *प्रतिशत*), आम आदमी बीमा (2.03 *प्रतिशत*), मनरेगस (42.39 *प्रतिशत*) का अभिसरण किया गया था जैसा **अनुबंध 6.1** में दिया गया है। तथापि, 108 लाभार्थियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि उन्हें अभिसरण के लाभ प्रदान नहीं किए गए थे। जिले ने बताया कि किसी भी अन्य योजनाओं के साथ कोई अभिसरण नहीं किया गया था तथा रा.गां.ग्रा.वि.यो. को

अलग से कार्यान्वित किया गया था। इस प्रकार, जिलों द्वारा अनुरक्षित मा.प्र.रि. संयुक्त भौतिक सत्यापन से मेल नहीं खाती थी।

6.4 अभिसरण हेतु जागरूकता की कमी

हमने पाया कि नौ राज्यों अर्थात् **अरूणाचल प्रेदश, बिहार, गोवा, झारखण्ड, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड** के चयनित जिलों में सूचना, शिक्षा तथा संचार (सू.शि.सं.) कार्यों तथा अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन अभिकरण से जिलों के समन्वय नहोने के कारण इं.आ.यो. लाभार्थी अभिसरण के लाभों को प्राप्त नहीं कर सके।

6.5 निष्कर्ष

इस प्रकार, चयनित जिलों भा.स. के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं, जिन्हें इं.आ.यो. के साथ समन्वित किया जा सके जिससे इं.आ.यो. के लाभार्थी ग्रामीण ग.रे.नी. के परिवारों हेतु प्रत्याशित इन योजनाओं के लाभों को प्राप्त कर सके, की पहचान करने हेतु कोई संगठित प्रयास नहीं किए गए थे। सामने आया चित्र निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	पू.स्व.अ.	रा.गां.ग्रा.वि.यो.	रा.ग्रा.ज.आ.का.	ब्या.वि.द.	बीमा	मनरेगस/स्व.ग्रा.स्व.यो.
1	आन्ध्र प्रदेश	हॉ (एक जिला)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
2	अरूणाचल प्रदेश	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
3	असम	--	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	---
4	बिहार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
5	छत्तीसगढ़	नहीं	---	नहीं	हॉ	----	---
6	गोवा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7	गुजरात	नहीं	नहीं	नहीं	हॉ	नहीं	नहीं
8	हरियाणा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	---	---
9	हिमाचल प्रदेश (डाटा केवल एक	--	नहीं	नहीं	---	---	---

	जि.ग्रा.वि.अ. से संबंधित है)						
10	जम्मू एवं कश्मीर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
11	झारखण्ड	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
12	कर्नाटक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं (सिवाय एक जिले को छोड़कर)	नहीं	---
13	केरल	नहीं	नहीं	नहीं	--	--	---
14	मध्य प्रदेश	केवल एक जिले में पू.रूव.अ.	नहीं	नहीं	नहीं	चार जिलों में	---
15	महाराष्ट्र	तीन जिलों में पू.स्व.अ.	---	---	नहीं	---	---
16	मणिपुर	तीन जिलों में पू.स्व.अ.	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	---
17	मेघालय	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
18	मिजोरम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	---
19	नागालैण्ड	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	ओडिशा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं (खुर्दा के सिवाय)
21	पंजाब	नहीं	नहीं	नहीं	--	नहीं	---
22	राजस्थान	---	---	---	नहीं	नहीं	---
23	त्रिपुरा	नहीं	----	नहीं		नहीं	नहीं
24	उत्तर प्रदेश	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
25	उत्तराखण्ड	नहीं	नहीं	नहीं		---	----
26	पश्चिम बंगाल	--	--	नहीं	नहीं	नहीं	--
27	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	---

अनुशंसा:

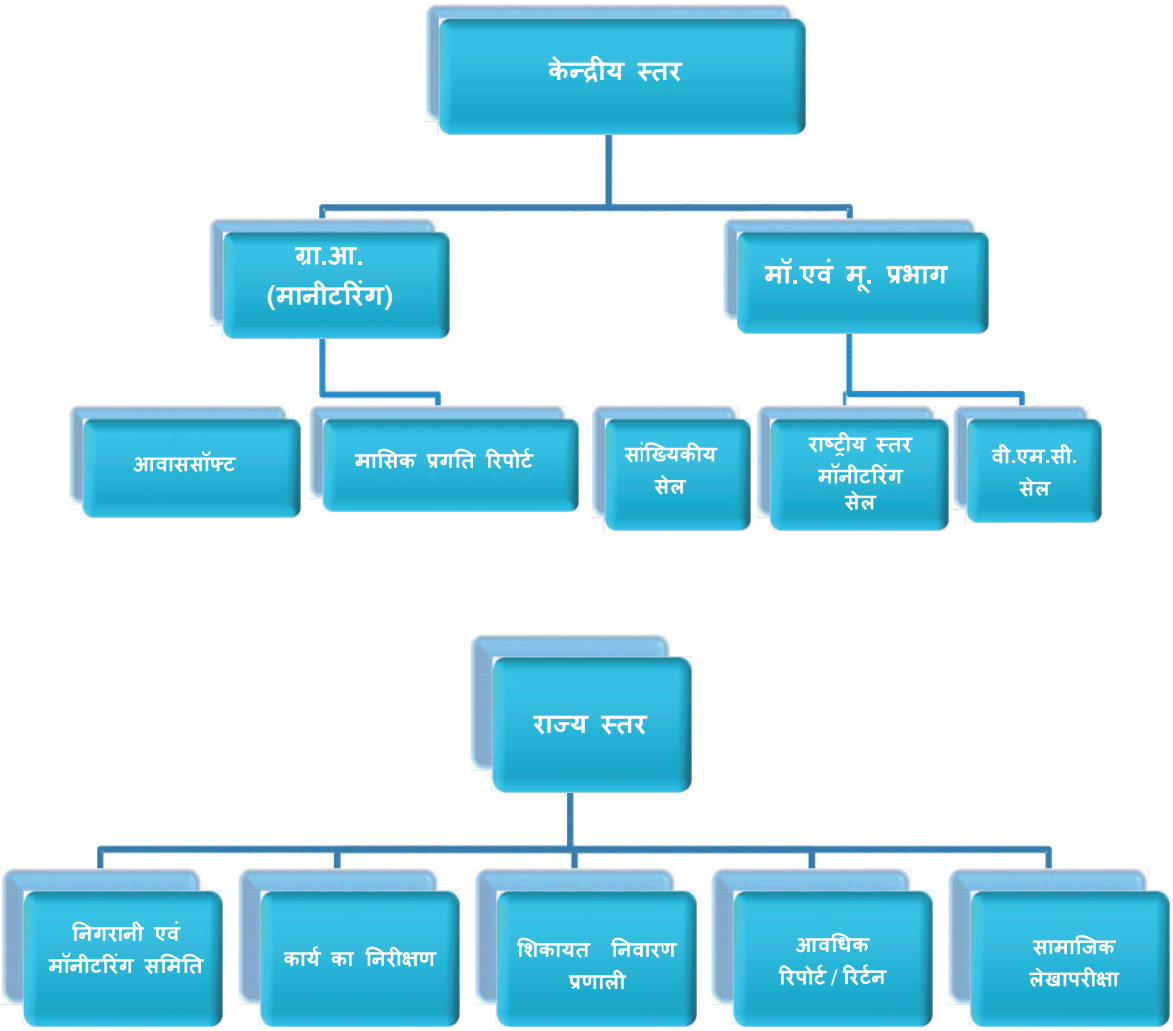
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (जि.ग्रा.वि.अ.)/जिला पंचायती राज अधिकारियों (जि.पं.रा.अ.) को घरों की संस्वीकृति के समय लाभार्थियों के मध्य अभिसरण गतिविधियों के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए और इं.आ.यो. घरों में पेय जल, स्वच्छता, बिजली आदि की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों के साथ भी सहयोगिता के साथ कार्य करना चाहिए। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को इसकी उपलब्धता तथा आवश्यकता के आधार पर बिजली के विकल्प के रूप में विचार किया जाना चाहिए।

अध्याय 7: मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

7.1 मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन रूपरेखा

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों ने सभी स्तरों पर आंतरिक एवं बाह्य मॉनीटरिंग तंत्रों की एक बहुआयामी एवं विस्तृत प्रणाली की कल्पना की है। केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग तंत्र को नीचे चार्ट -9 में दर्शाया गया है:

चार्ट-9



7.2 केन्द्रीय स्तर पर मॉनीटरिंग

केन्द्रीय स्तर पर मॉनीटरिंग इं.आ.यो. के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार ग्रामीण आवास (ग्रा.आ.) प्रभाग तथा केन्द्रीय मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन (के.मॉ.मू.) प्रभाग द्वारा की जाती है जोकि मंत्रालय के अंतर्गत सभी योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मॉनीटर करता है।

7.2.1 ग्रामीण आवास प्रभाग द्वारा मॉनीटरिंग

इं.आ.यो. के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार ग्रामीण आवास (ग्रा.आ.) प्रभाग के पास मॉनीटरिंग के लिए कोई अलग संस्वीकृति कार्यबल नहीं है। अनुभाग अधिकारी के पद का एक अधिकारी राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों को संकलित करता है तथा इं.आ.यो. डाटाबेस को प्रबंधित करता है।

इस प्रभाग द्वारा मॉनीटरिंग हेतु मुख्य साधन मासिक प्रगति रिपोर्ट (मा.प्र.रि.) तथा आवाससॉफ्ट थे। पिछले माह में हुए भौतिक निष्पादन तथा वित्तीय सहायता को रिपोर्ट करने के लिए आने वाले प्रत्येक माह की 15 तारीख तक मंत्रालय द्वारा वेबसाइट पर जिलों द्वारा मा.प्र.रि. को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। मंत्रालय के पास मा.प्र.रि. की अधिकारिता के सत्यापन हेतु कोई तंत्र नहीं था।

हमने पाया कि पांच राज्यों (झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान एवं उत्तराखण्ड) में मा.प्र.रि. तथा **उ.प्र.**/आवाससॉफ्ट में सूचित डाटा मेल नहीं खाता था। संस्वीकृत, निर्माण किए घरों की संख्या तथा निर्माणाधीन घरों की संख्या, किए गए व्यय जैसे विभिन्न डाटा में विभिन्नताएं पाई गई थीं। मा.प्र.रि. में दर्शाया गया डाटा मूल अभिलेखों अर्थात् रोकड़ बही, कार्य रजिस्टर, आदि के साथ मेल नहीं खाता था। राज्य विशिष्ट अभ्युक्तियां **अनुबंध - 7.1** में दी गयी हैं।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां के उत्तर (जून 2014) में बताया कि मा.प्र.रि. तथा आवाससॉफ्ट मे डाटा अपलोड करने में कुछ विसगंतियां हो

सकती हैं, परतु निधियों के उपयोग को जि.ग्रा.वि. द्वारा प्रस्तुत उ.प्र. के माध्यम से मानीटर किया जाता है जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से उचित प्रकार से समर्थित है तथा इस प्रकार उ.प्र. में सूचित राशि विश्वसनीय है।

आवाससॉफ्ट

मंत्रालय ने इं.आ.यो. को मॉनीटरिंग करने के लिए लाभार्थीवार डाटा को प्राप्त करने के लिए, आवाससॉफ्ट नामक एक वेब-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) कार्यक्रम की शुरूआत की (फरवरी 2009)। प्रणाली में ई-गवर्नेस को सुविधाजनक बनाने के लिए आवाससॉफ्ट स्थानीय भाषा में सक्षम कार्य प्रवाह आधारित लेनदेन स्तर का प्र.सू.प्र. है। यह प्रबंधन, सभी रिपोर्टों को बनाने, जारी की गई निधियों पर नजर रखने, मकानों के निर्माण में प्रगति तथा सभी लाभों के अभिसरण का साधन है। इसमें ग्रा.प./ब्लॉक/जि.ग्रा.वि.प्रा. तथा मंत्रालय स्तरों पर शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली है। यह केवल लाभार्थियों समेत सभी पणधारियों के लिए ही नहीं बल्कि नागरिकों के लिए भी सुगम्य है।

हमने पाया कि 15 राज्यों/सं.शा.क्षे. अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश,अरूणाचल प्रदेश, असम एवं छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब** (छः चयनित जिलों में से तीन[1]), उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के चयनित जिलों में आवाससॉफ्ट प्रचलन था, लेकिन नियमित आधार पर डाटा अपलोड नहीं किया गया था। सिस्टम पर अपलोड किए गए डाटा की सत्यता को सत्यापित करने के लिए कोई विशिष्ट तंत्र नहीं था।

यद्यपि फरवरी 2009 में आवाससॉफ्ट की शुरूआत की गई थी फिर भी मंत्रालय ने वर्ष 2012-13 हेतु दूसरी किस्त को जारी करने के लिए इस शर्त के रूप में सभी राज्यों के लिए आवाससॉफ्ट पर 100 प्रतिशत डाटा अपलोड करना जून 2012 में जाकर अनिवार्य किया। हालांकि, दिसम्बर 2012 में उस शर्त को समाप्त कर आवाससॉफ्ट पर डाटा को अपलोड करने की छूट दी की

[1] एस.ए.एस. नगर, पटियाला एवं तरण तारण

(i) उत्तर-पूर्वी राज्य एवं समेकित कार्रवाई योजना (सं.का.यो.) जिलों को दूसरी किस्त जारी करने से पूर्व 40 प्रतिशत प्र.सू.प्र. प्रविष्टि प्राप्त करनी थी (ii) जि.ग्रा.वि.प्रा. जिन्होंने सूचित किया कि प्र.सू.प्र. प्रविष्टि अपलोड की जा रही है, उसे अगली किस्त को जारी किए जाने से पूर्व कम से कम 60 प्रतिशत प्र.सू.प्र. प्रविष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा (iii) जिन जि.ग्रा.वि.प्रा. ने प्र.सू.प्र. प्रविष्टि शुरू नहीं की थी, उन्हें अगली किस्त को जारी किए जाने से पूर्व 60 प्रतिशत प्रविष्टि को पूरा करने की सलाह दी गई थी।

इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा वित्तीय, भौतिक एवं अभिसरण डाटा एवं छूट के संबंध में आवाससॉफ्ट पर डाटा अपलोड करने के लिए अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन न करना गंभीरता के अभाव का परिचायक है। आवाससॉफ्ट को ऑनलाईन मॉनीटरिंग, पारदर्शिता लाने, कुशल निधि प्रबंधन, ग.रे.नी. परिवारों के डाटाबेस के सृजन, आदि के लिए, साधन के रूप में राज्यों तथा मंत्रालय द्वारा प्रभावी रूप से उपयोग में लाया जा सकता है।

मंत्रालय ने बताया (जून/जुलाई 2014) कि प्रारंभिक रूप से प्रगति धीमी थी क्योंकि श्रमशक्ति प्र.सू.प्र. का उपयोग करने में प्रशिक्षित नहीं थी और 2012-13 में प्रशिक्षण के कई दौर होने पर अब स्थिति में सुधार आया है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने बताया कि संशोधित दिशानिर्देशों में प्रशासनिक लागत के प्रावधान ने प्रक्रिया में तेजी लाने में सहायता की है। डाटा की सत्यता के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि इसे राज्यों/जि.ग्रा.वि.प्रा. द्वारा अपलोड किए डाटा पर निर्भर रहना पड़ता है और राष्ट्रीय स्तर के मानीटरो, आदि के माध्यम से क्षेत्र अधिकारियों द्वारा समय-समय पर यादृच्छिक निरीक्षण किया जाता है।

मंत्रालय का उत्तर राज्यों में लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए इन मूल तथ्यों के विरुद्ध था कि सभी राज्य आवाससॉफ्ट का उपयोग नहीं कर रहे थे और जो राज्य आवाससॉफ्ट का उपयोग कर रहे थे वह नियमित आधारपर डाटा अपलोड नहीं कर रहे थे।

हमने यह भी पाया कि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को आवाससॉफ्ट पर शिकायत निवारण प्रणाली को शुरू करने का निर्देश दिया था (जून 2012)।

इसके बावजूद, आवाससॉफ्ट पर शिकायत निवारण प्रणाली अनुप्रयुक्त रही क्योंकि 2012-13 के दौरान उसपर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई थी। मंत्रालय इस बात से सहमत था कि (मार्च 2014) प्रणाली को अभी तक व्यवस्थित रूप से उपयोग में लाया जाना शेष था।

7.2.2 के.मॉ.मू. प्रभाग द्वारा मॉनीटरिंग

ग्रामीण विकास मंत्रालय का केन्द्रीय मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन प्रभाग अन्य प्रमुख योजनाओं अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगस), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) तथा निगरानी एवं मॉनीटरिंग समिति (नि.मॉ.स.) सेल, राष्ट्रीय स्तर मॉनीटरिंग (रा.स्त.मॉ.) एवं सांख्यिकीय सेल के माध्यम से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (स्व.ग्रा.स्व.यो.) के अतिरिक्त इं.आ.यो. की मॉनीटरिंग करता है।

निगरानी एवं मॉनीटरिंग समिति सेल

नि.मॉ.स. सेल को राज्य स्तर के नि.मॉ.स. के लिए सांसद/गैर-सरकारी/गै.स.सं./क्षेत्र अधिकारी को नामांकित करने तथा नि.मॉ.स. रिपोर्ट पर अनुसरणीय कार्रवाई करने का कार्य सौपा गया था। हमने पाया कि सेल के पास वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लिए नि.मॉ.स. की बैठकों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

हमने यह भी पाया कि मंत्रालय के प्रतिनिधि/नामांकित व्यक्ति ने 15 राज्यों/सं.शा.क्षे. अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड,राजस्थान, त्रिपुरा, उत्त्राखण्ड तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह** में रा.स्त.नि.मॉ.स. में भाग नहीं लिया था जबकि केवल छ: राज्यों अर्थात् **गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, ओडिशा, पंजाब तथा तमिलनाडु** में मंत्रालय के प्रतिनिधि/नामांकित व्यक्ति ने 2008-13 के दौरान हुई सभी रा.स्त.नि.मॉ.स. में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के प्रतिनिधि/नामांकित व्यक्ति ने चार राज्यों अर्थात् कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम

एवं उत्तर प्रदेश में हुई 18 बैठकों में से 10 में भाग लिया था। विवरण अनुबंध 7.2 में दिए गए है। मंत्रालय ने राज्यों/सं.शा.क्षे. को निधियां नियमित रूप से जारी की थीं परन्तु विभिन्न राज्यों में पूर्वोक्त बैठकों में भाग नहीं लिया था।

राष्ट्रीय स्तर मॉनीटर

सार्वजनिक हित के लिए स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक सार्वजनिक हित के लिए कार्य करने वाले वरिष्ठ स्तर के सेवानिवृत्त सिविल/रक्षा सेवा अधिकारियों एवं शिक्षकों के साथ राष्ट्रीय स्तर मॉनीटरों की योजना की अवधारणा की गई थी। तीसरे पक्ष के स्वतंत्र मॉनीटरों को शामिल करके मंत्रालय ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निष्पक्ष एवं वस्तुगत मॉनीटरिंग प्राप्त करने की आशा की थी।

(i) रा.स्त.मॉ. द्वारा दौरों की आवृत्ति

मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, रा.स्त.मॉ. की नियमित मॉनीटरिंग, विशेष विषय आधारित मॉनीटरिंग तथा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इं.आ.यो. समेत सभी कार्यक्रमों से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए भी तैनात किया गया था। सभी महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को मॉनीटरिंग करने लिए जिलों में रा.स्त.मॉ. के त्रैमासिक दौरों का प्रावधान था। हमने मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के प्रति रा.स्त.मॉ. के दौरों में काफी कमियां पायी जिसका विवरण नीचे **तालिका-13** में दिया गया है:

तालिका-13 : रा.स्त.मॉ. द्वारा जिलों के कवरेज में कमियां

वर्ष	आवृत्त किए जाने वाले जिलों की संख्या	वास्तविक रूप से आवृत्त जिलों की संख्या	प्रतिशतता की कमी
नियमित मॉनीटरिंग			
2008-09	256	225	12
2009-10	344	251	27

2010-11	604	484	20
2011-12	नियमित मॉनीटरिंग नहीं की जा सकी क्योंकि रा.स्व.मॉ. को पैनल में लाए जाने की प्रक्रिया चल रही थी।		
2012-13	690	591	14
अक्तूबर 2010 में मंत्रालय ने यह लागू करते हुए कि देश के सभी जिलों को एक वर्ष में आवृत्त किया जाएगा, नियमित मॉनीटरिंग के अंतर्गत जिलों के कवरेज के लिए प्रत्येक त्रैमासिक दौरे में लगभग 150 जिलों का संशोधित लक्ष्य दिए थे।			
विशेष मॉनीटरिंग			
2008-09	91	86	5
2009-13	नहीं की गई		

इस प्रकार, रा.स्त.मॉ. 2008-13 के दौरान नियमित एवं विशेष मॉनीटरिंग हेतु लक्षित जिलों को आवृत्त नहीं कर पाया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2014) कि असंतोषजनक निष्पादन के कारण कुछ रा.स्त.मॉ. को कार्य न सौंपे जाने, व्यक्तिगत रा.स्त.मॉ. को कार्य पैनल मे लाए जाने, रा.स्त.मॉ. की उपलब्धता न होने, रा.स्त.मॉ. के पहले से कार्य कर रहे होने, आदि के कारण लक्षित जिलों को आवृत्त नहीं किया जा सका था।

(ii) शिकायत के मामलों में रा.स्त.मॉ. की रिपोर्टों पर कार्रवाई

शिकायत के मामलों में रा.स्त.मॉ. की रिपोर्ट पर राज्यों को शीघ्र कार्रवाई करनी थी। राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित कार्यक्रम प्रभाग को संतुष्ट होना था। यदि एक पूरे वित्तीय वर्ष से अधिक के लिए राज्य/जिलो द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जाती है तो विशेष योजना के अंतर्गत ऐसे राज्य/जिले को आगे जारी होने वाली निधियों को रोक लिया जाएगा।

शिकायतों तथा की गई कार्रवाई की स्थिति को निधियों को जारी करने वाले प्रस्तावों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनना था ताकि निधियों को जारी करने हेतु

प्रस्तावों को सहमति देने से पूर्व मंत्रालय अपने आप को की गई कार्रवाई से संतुष्ट कर पाए।

नौ राज्यों **(असम, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश)** जहॉ जॉच हेतु रा.स्त.मॉ. तैनात किए गए थे, उसने संबंधित 2011-12 और 2012-13 से संबंधित 21 इं.आ.यो. से संबंधित शिकायतों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 17 मामलों में रा.स्त.मॉ. की रिपोर्टों पर राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई लंबित थी (सितम्बर 2013)। असम (दो शिकायतें) एवं उत्तर प्रदेश (एक शिकायत) में दो वर्षों से अधिकतक कार्रवाई लंबित थी परन्तु इन राज्यों से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की लंबिता के बावजूद मंत्रालय ने कोई कार्रवाई नहीं की थीं राज्य स्तर पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों से स्पष्ट है कि मंत्रालय ने रा.स्त.मॉ. दिशानिर्देशों के उल्लंघन में निधियां जारी की थीं।

तीन राज्यों (असम, झारखण्ड एवं मणिपुर) में रा.स्त.मॉ. की तैनाती के संबंध में पता चला कि यद्यपि नियमित मॉनीटरिंग एवं शिकायतों की जांच हेतु रा.स्त.मॉ. को तैनात किया गया था, उन्होंने जिला/राज्य को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी और जहॉ उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की भी थी, राज्य ने कोई कार्रवाई नहीं की थी जिसका विवरण **अनुबंध-7.3** में दिया गया है। इससे पता चलता है कि रा.स्त.मॉ. द्वारा मॉनीटरिंग की प्रभावकारिता हेतु काफी गुंजाइश है।

7.3 राज्य स्तर मॉनीटरिंग

राज्य स्तर पर इं.आ.यो. के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग, निगरानी एवं मॉनीटरिंग समिति (नि.मॉ.स.), निर्माण कार्यों का निरीक्षण, शिकायत निवारण प्रणाली तथा सामाजिक लेखापरीक्षा द्वारा की जानी थी। राज्यों में मॉनीटरिंग तंत्र में पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

7.3.1 निगरानी एवं मॉनीटरिंग समिति (नि.मॉ.स;)

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 6.1 के अनुसार राज्य स्तर निगरानी एवं मॉनीटरिंग समिति (रा.स्त.नि.मॉ.स.) और जिला स्तर पर, जिला स्तर निगरानी एवं मॉनीटरिंग समिति (जि.स्त.नि.मॉ.स.) की जिम्मेदारी है। मंत्रालय द्वारा जारी की गई नि.मॉ.स. के दिशानिर्देशों के अनुसार, रा.स्त.नि.मॉ.स. एवं जि.स्त.नि.मॉ.स. स्तर पर 2008-09 से 2012-13 तक 20 बैठकें (एक वर्ष में चार बैठकें) होनी थी।

हमने पाया कि 25 राज्यों/सं.शा.क्षे. अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** में 2008-09 से 2012-13 के दौरान केवल एक से 10 रा.स्त.नि.मॉ.स. की बैठकें हुई थीं। 2008-09 से 2012-13 के दौरान गोवा तथा जम्मू एवं कश्मीर में रा.स्त.नि.मॉ.स. की कोई बैठक नहीं हुई थी।

कुल मिलाकर 27 राज्यों के सभी चयनित जिलों में, 2008-13 के दौरान अपेक्षित जि.स्त.नि.मॉ.स. की बैठकें नहीं हुई थी चयनित जिलों में जि.स्त.नि.मॉ.स. की बैठकें करने में 16 (मिजोरम) से लेकर 254 (उत्तर प्रदेश) तक की कमी हुई थी।

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जि.स्त.नि.मॉ.स. से संबंधित कोई डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया था। चयनित जिलों में रा.स्त.नि.मॉ.स. और जि.स्त.नि.मॉ.स. का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-7.2** में दिया गया है।

इस प्रकार, रा.स्त.नि.मॉ.स. और जि.स्त.नि.मॉ.स. की अपेक्षित संख्या में बैठकें न करने से राज्यों में इं.आ.यो. के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग को कमजोर बना दिया है।

मंत्रालय ने बताया (जून 2014) कि रा.स्त.नि.मॉ. स. समिति की बैठकों की अध्यक्षता सांसद द्वारा की जाती थी और उनके/उनकी पूर्व व्यस्तता के

कारण, कभी कभी बैठकें करने में देरी हो जाती थी या उन्हें स्थगित करना पड़ता था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। निगरानी एवं मॉनीटरिंग समिति पर दिशानिर्देशों के अनुसार, सामान्य रूप से समिति का अध्यक्ष संबंधित राज्य का ग्रामीण विकास मंत्री अध्यक्ष होगा। इस मंत्रालय के अन्य कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी उपाध्यक्ष होगा। इस मंत्रालय के अन्य विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार के विभागों का प्रभारी रा.स्त.नि.मॉ.स. का उपाध्यक्ष होगा।

7.3.2 निर्माण कार्यों का निरीक्षण

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के पैरा 6.1 के अनुसार,राज्य मुख्यालय में इं.आ.यो. का कार्य करने वाले अधिकारियों को नियमित रूप से जिलों का दौरा करना चाहिए तथा फील्ड दौरों के माध्यम से पता लगाए कि क्या इं.आ.यो. को संतोषजनक रूप से कार्यान्वित किया जा रहा था और क्या मकानों का निर्माण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हो रहा था। राज्य स्तर से ब्लॉक स्तर तक के प्रत्येक पर्यवेक्षी स्तर पदाधिकारी के लिए फील्ड दौरों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करती हो, ऐसी निरीक्षण की एक सारणी बनाई जानी थी तथा इसका सख्ती से पालन होना था।

हमने पाया कि 20 राज्यों अर्थात् **अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल** के चयनित जिलों में फील्ड स्तर पर निर्माण कार्यों के सत्यापन की प्रणाली का पालन नहीं किया गया था और निरीक्षण की सारणी नहीं बनाई गयी थी। **मध्य प्रदेश** में, निरीक्षण की सारणी बनाई गई थी परन्तु निरीक्षण नियमित रूप से नहीं किए गए थे।

आन्ध्र प्रदेश में, निर्माण कार्यों का सत्यापन फील्ड स्तर पर किया गया था तथा आ.प्र.रा.आ.नि.लि. के अभियांत्रिकी स्कंध द्वारा स्तर-वार निर्माण के सत्यापन के पश्चात ही लाभार्थियों को भुगतान किया गया था। **कर्नाटक** में,

निरीक्षण की सारणी निर्धारित नहीं थीं। हालांकि, राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2013) कि फील्ड निरीक्षणों का संचालन नियमित रूप से किया गया था जबकि इस अभिकथन के समर्थन में किसी पकार के दस्तावेजी सबूत लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। **मिजोरम** में, 2008-13 के दौरान संबंधित ब्लॉकों के साथ कार्यरत तकनीकी कर्मचारी द्वारा निरीक्षण की किसी सारणी के बिना ही निर्माण कार्यों के सत्यापन हेतु नियमित फील्ड दौरें किए गए थे। **उत्तराखण्ड** में, निदेशालय स्तर पर इं.आ.यो. के मकानों के लक्षित निरीक्षण/भौतिक सत्यापन के दो प्रतिशत के प्रति, 2008-13 के दौरान संचालित निरीक्षण 0.05 से लेकर 0.08 प्रतिशत तक हुए थे। जिलों में, निर्धारित 20 प्रतिशत निरीक्षण के प्रति, वास्तविक निरीक्षण 5.20 से लेकर 11.99 प्रतिशत तक हुई थी और ब्लॉक स्तर में 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन के प्रति, यह 2 से लेकर 17 प्रतिशत तक थी। निरीक्षण में इस कमी का सीधा प्रभाव पांच चयनित जिलों की भौतिक उपलब्धि पर पड़ा था क्योंकि 2008-13 के दौरान संस्वीकृत मकानों में से केवल 42 प्रतिशत पूर्ण हुए थे।

मामला अध्ययन: फील्ड स्तर पर निर्माण कार्यों का सत्यापन

झारखण्ड

जिला रॉची में, जुलाई 2011 में जि.ग्रा.वि.प्रा. द्वारा सभी 18 ब्लॉकों को आवृत्त करते हुए 2011-12 की अवधि से संबंधित इं.आ.यो. के कार्यान्वयन की सामान्य जांच की गई थी। जांच से लाभार्थियों के चयन तथा 16 ब्लॉकों में 1,002 मामलों में मकानों के आवंटन में अनियमितताओं का पता चला। हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि जन सेवकों (जिसमें से तीन को निलंबित कर दिया गया था) तथा एक के विरूद्ध आरोप लगाये गये थे। यदि संबंधित ब्लॉक/जिला अधिकारियों द्वारा आवधिक मॉनीटरिंग और निरीक्षण किया गया होता तो इस प्रकार के उदाहरणों से बचा जा सकता था।

* प्रतीक्षासूची में न पाए गए लाभार्थियों के नाम 687 मामले, अन्य परिवार के ग.रे.नी. संख्या प्रति आवंटन -158 मामले, अन्य जाति एवं श्रेणी के प्रति मकानों का आवंटन 101 मामले, मकानों का दोहरा आवंटन-16 मामले सरकारी कर्मचारी को मकानों का आवंटन-2 मामले, ग.रे.ज. के परिवार को मकान का आवंटन-5 मामले, ग.रे.नी. के परिवार के अंक को कम करके मकान का आवंटन-25 मामले और ग.रे.नी. के अंक को बढ़ाकर -8 मामले।

मंत्रालय ने बताया (जून/जुलाई 2014) कि इस संदर्भ में जिला/राज्य स्तर अधिकारियों की एक सीमित भूमिका है। हालाँकि, जबकि सारणियां तैयार नहीं की गयी थीं लेकिन ब्लॉक/जिला/राज्य स्तर अधिकारियों द्वारा फील्ड निरीक्षण किए गए थे। आवाससॉफ्ट पर राज्यों द्वारा तस्वीरों सहित फील्ड निरीक्षण को सूचित किया गया है। मंत्रालय ने आगे बताया कि फील्ड निरीक्षणों को करने के लिए प्रशासनिक लागत (जून 2013 में संशोधित इं.आ.यो. दिशानिर्देशों में प्रदत्त) का उपयोग किया जा सकता है।

मंत्रालय का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि दिशानिर्देश सभी स्तरों पर निरीक्षण की सारणियों तथा फील्ड दौरें निर्धारित करते हैं। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां दर्शाती हैं कि फील्ड निरीक्षण नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, अधिकतर राज्यों में आवाससॉफ्ट पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं था तथा नियमित आधार पर इसे अद्यतित नहीं किया जा रहा था इसलिए आवाससॉफ्ट पर की गई रिपोर्टिंग वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाती है। यह मंत्रालय की तरफ से कमजोर मानीटरिंग को दर्शाता है।

7.3.3 शिकायत मॉनीटरिंग प्रणाली

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 6.1.2 के अनुसार, शिकायतों के निवारण हेतु राज्य स्तर पर पर्याप्त स्टाफ के साथ प्रभावी शिकायत मॉनीटरिंग प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए जो कि नियमित निष्पादन स्कंध से स्वतंत्र रहकर दौरा कर सके तथा प्रभावी निवारण हेतु कमियों/खामियों के बारे में कार्यान्वयन अभिकरणों को एक रिपोर्ट दे।

हमने पाया कि 10 राज्यों अर्थात् **अरूणाचलप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, त्रिपुरा, एवं उत्तर प्रदेश** के चयनित जिलों में, लाभार्थियों की समस्याओं/शिकायतों के निपटान हेतु कोई प्रभावी शिकायत मॉनीटरिंग प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी।

शिकायतों के निपटान में विलंब

हमने पाया कि नौ राज्यों अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्त्राखण्ड एवं पश्चिम बंगाल** के चयनित जिलों में मार्च 2013 तक 3,437 शिकायतों में से 2,010 शिकायतें निपटान हेतु लंबित थीं जिसका विवरण **अनुबंध 7.4** में दिया गया है।

आन्ध प्रदेश में, राज्य आवास योजना के लिए आ.प्र.रा.आ.नि.लि, में शिकायत निपटान प्रणाली मौजुद थी, इं.आ.यो. के लिए कोई अलग प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी। इ.आ.यो. एवं राज्य आवास योजना से संबधित 2008-13 के दौरान पूरे राज्य के 2,865 मामले मार्च 2013 तक निपटान हेतु लंबित थे। चूँकि दोनों इ.आ.यो. एवं राज्य आवास योजना के लिए केवल एक शिकायत निपटान प्रणाली को अनुरक्षित किया गया था, इं.आ.यो. से संबधित शिकायतों के वास्तविक विवरण और उसके निपटान का पता नही लगाया जा सका था। **पंजाब** में, 2008-12 के दौरान प्राप्त एवं निपटान की गयी शिकायतों की संख्या से संबधित अभिलेख उपलब्ध नहीं था तथा 2012-13 से संबधित पाँच शिकायते लंबित थीं।

मंत्रालय ने बताया कि इस संदर्भ में शिकायतों के निपटान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (मा.सं.प्र.) को प्रेषित किया गया है (2 अप्रैल 2012)। हालांकि, प्रभावी शिकायत मॉनीटरिंग प्रणाली की स्थापना नही होने से बड़ी संख्या में शिकायतों के एकत्रित होने में परिणत हुई जो संबंधित राज्यों के पास अब तक लंबित हैं। मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय ने कमियों पर कोई प्रभाव नहीं डाला है।

शिकायतों के गैर-निपटान/निपटान में विलंब पर मामला-अध्ययन

असम

- नागरिक सभा को संचालित करने के पश्चात गांव अमरीखोवा में लोगों ने परियोजना निदेशक, जिला बारपेटा को जून 2011 में ब्लॉक सरुखेतरी के अंतर्गत ग्रा.पं. 12 सं. पब सरूखेतरी के ग्रा.पं. अध्यक्ष, क.अ. तथा वार्ड सदस्यों के विरूद्ध इं.आ.यों के मकानों के आवंटन हेतु ₹ 2,000 से लेकर ₹ 15,000 तक की रिश्वतें मांगने की शिकायते दर्ज की थी। जून 2011 में परियोजना निदेशक ने ग्रा.पं. सचिव एवं अध्यक्ष को अपने कर्यालय में आने का निर्देश दिया था परंतु दोनों ही नहीं आए। इसके अतिरिक्त, यदि कोई कार्रवाई की गई हो तो अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी।
- ब्लॉक गोबरधना में फरवरी 2010 एवं अगस्त 2011 के बीच लाभार्थियों द्वारा रिश्वत की मांग, लाभार्थियों को क.अ. द्वारा निम्नतर गुणवत्ता वाले सामान की आपूर्ति, निधियों के दुर्विनियोजन, आवंटन के बावजूद निधियों की प्राप्ति न होने आदि के कारण 18 शिकायतें दर्ज की गई थीं। शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई यदि की गई हो तो अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी।
- जिला काचर में, इं.आ.यों. के मकानों के अनियमित आवंटन के सात शिकायत के मामलें, ₹ 0.72 लाख की निधि के अनियमित आहरण के एक मामले समेत मानकों का ध्यान रखे बिना लाभार्थियों की सूची को अस्वीकार किए जाने का निपटान नहीं हुआ था।
- जिला करीमगंज में, 2008-13 के दौरान ग्राम सभाओं का संचालन न करने इं.आ.यो. को लाभार्थियों के अवैध चयन, आदि से संबंधित दर्ज हुई 30 शिकायतों का निपटारा नहीं किया गया था तथा यह शिकायतें ब्लॉकों के पास जांच स्तर पर थीं।

प.नि. जिला बारपेट ने मार्च 2009 में ग्रा.पं. खेराबरी के अंतर्गत 91 संस्वीकृत लाभार्थियों को जारी करने के लिए ब्लॉक गोबरधन को ₹35.81 लाख जारी किए। ब्लॉ.वि.अ. ने बदले में अक्तूबर 2009 और फरवरी 2010 के दौरान 76 लाभार्थियों को ₹25.79 लाख जारी किए गये थे। मकानो के दो बार आवंटन होने से संबंधित ग्रामवासियों से कुछ शिकायतों की प्राप्ति होने के कारण ₹10.02 लाख का शेष जारी नहीं किया गया था। ब्लॉक स्तर नि.एवं मॉ.स. द्वारा जून 2010 में गठित आंतरिक समिति ने मामले की जांच की और एक वर्ष के विलंब के पश्चात् जुलाई 2011 में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ब्लॉक एवं ग्रा.पं. के संबंधित अभिलेखों एवं रिपोर्ट की संवीक्षा से पता चला कि:

- नौ लाभार्थी जिन्हें 2002-03 से 2005-06 के दौरान पहले भी मकान आवंटित कर दिए गए थे उन्हें वर्ष 2008-09 के लिए आवंटित मकानों के लिए सहायता प्रदान की गई थी जिसके कारणवश ₹3.33 लाख के व्यय समेत नौ मकानों का अनियमित रूप से दो बार आवंटन हुआ था। इस राशि की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे।
- आठ लाभार्थियों जिन्हें ₹ 2.00 लाख की निधि में से ₹ 25,000 की दर पर पहली किस्त जारी की गई थी, हालांकि, दूसरी किस्त जारी न होने के कारणवश जुलाई 2013 तक उनके मकान पूरे नहीं हुए थे इसके कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।
- एक लाभार्थी जिसका नाम 91 लाभार्थियों की संस्वीकृति सूची में नहीं था उसे भी सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के बिना ₹37,350 जारी कर दिए गए थे।
- इसके अतिरिक्त, ग्रा.पं. ने मई 2012 एवं जुलाई 2013 के दौरान असली लाभार्थियों को ₹ 4.57 लाख (₹ 10.02 लाख में से) की दूसरी किस्त जारी की थी। ग्रा.प./ब्लॉक के पास ₹ 5.44 लाख की शेष राशि अनुप्रयुक्त रही थी।

7.4 प्रारंभिक स्तर पर ध्यानपूर्वक मॉनीटरिंग

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 5.8 के अनुसार, साबित हुए अच्छे पिछले कार्य निष्पादन रिकार्ड, वाले गैर-सरकारी संगठनों (गै.स.स) को शामिल करके ध्यानपूर्वक मॉनीटरिंग की जानी चाहिए। इं.आ.यो. के मकानों के निर्माण के पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं मॉनीटरिंग का कार्य गै.स.सं. को सौपां जा सकता है।

छः राज्यो अर्थात **झारखंड, केरल, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान एवं उतराखंड** में हमने पाया कि संबधित जि.ग्रा.वि.अ. एवं ब्लॉ.वि.अ. द्वारा इं.आ.यो. की मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु गै.स.सं. को शामिल करने के लिए कोई प्रयास नही किए गए थे।

7.4.1 सामाजिक लेखापरीक्षा

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 6.3.5. के अनुसार, इं.आ.यो. की सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रणाली का अनुसरण किया जाएगा।

हमने पाया कि 22 राज्यों अर्थात **आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल** के चयनित जिलों में इं.आ.यो. की सामाजिक लेखापरीक्षाओं को संचालित नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, यह नोट किया गया था कि **मध्यप्रदेश** के 13 चयनित जिलों में से छह जिलों (धार, कटनी, डिंडोरी, बरवानी, उज्जैन, राजगढ़) में तथा बिहार में दस चयनित जिलों में से केवल एक जिला (सुपौल) में 2008-13 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा को संचालित किया गया था।

यह दर्शाता है कि किसी भी राज्य द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा प्रणाली को उसका उचित महत्व नहीं दिया गया था।

मंत्रालय ने बताया (जून 2014) कि वर्ष 2013-14 के लिए, योजना का प्रबंध करने के लिए राज्यों को इं.आ.यो. निधियों को जारी किया जा रहा है जिसमें से एक प्रतिशत तक का उपयोग सामाजिक लेखापरीक्षा को संचालित करने के लिए किया जा सकता है।

7.5 प्रभाव का मूल्यांकन

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 6.2 के अनुसार, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को इं.आ.यो. के कार्यान्वयन पर आवाधिक मूल्यांकन अध्ययन को संचालन करना था। भारत सरकार द्वारा संचालित समवर्ती मूल्यांकन द्वारा सामने आए मुद्दों के साथ-साथ कार्यान्वयन पर प्रतिष्ठित संगठनों एवं संस्थानों द्वारा संचालित करवाए जा सकते हैं।

2008-13 के दौरान जून 2009 में 12 राज्यों[2] में योजना आयोग की ओर से सामाजिक कार्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इं.आ.यो. के कार्यान्वयन एवं प्रभाव पर केवल एक राष्ट्रीय स्तर मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर सुधार करने तथा उपयुक्त सुधारत्मक कदम उठाने के लिए कार्य करने के लिए मंत्रालय एवं कार्यान्वयन अभिकरणों को सक्षम बनाना था ताकि योजना उद्दिष्ट लाभों का वितरण कर पाए।

किस्तों को जारी करने में विलंब, अपर्याप्त निधियां, इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची से संबंधित जानकारी न होने तथा लंबी प्रतीक्षा अवधि बैंक खाते के न खोलने तथा इं.आ.यो. सही शर्तों एवं नियमों की जानकारी में कमी, ग.रे.नी. के लिए मानदण्ड का संशोधन, लाभार्थी चयन में ग्राम सभा की अप्रभावी भूमिका, आदि मूल्यांकन अध्ययन के कुछ निष्कर्ष थे।

अध्ययन से विभिन्न सुझाव अर्थात् लाभार्थी के चयन में ग्राम सभाओं की भूमिका को अधिक प्रमुखता देना, वित्तीय सहायता के सामयिक संशोधन की आवश्यकता, राज्य-दर राज्य में सांमाजिक-आर्थिक-स्थिति के आधार पर वित्तीय आवंटन विशिष्ट मॉनीटरिंग तंत्र के साथ एक समान कार्यान्वयन पैटर्न, पारदर्शिता एवं जानकारी होना, आदि समक्ष आए।

योजना आयोग द्वारा मंत्रालय के समक्ष नवम्बर 2012 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। मूल्यांकन अध्ययन पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई प्रतीक्षित थी।

---

[2] असम, बिहार, गुजरात, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश

2008-13 की अवधि के दौरान इं.आ.यो. के कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन करने के लिए 19 राज्यों/सं.शा.क्षे. अर्थात् **असम, आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं लक्षद्वीप** में इं.आ.यो. के कार्यान्वयन पर कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं हुए थे।

मेघालय में, 2007-12 की अवधि के लिए मेघालय सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मूल्यांकन फर्म (नवम्बर 2011) द्वारा इं.आ.यो. के कार्यान्वयन पर मूल्यांकन अध्ययन को संचालित किया गया था। इं.आ.यो. के अंतर्गत सहायता की वृद्धि के संदर्भ में ग.रे.नी. सूची में सुधार के चयन में पारदर्शिता, योजना के चयन में पारदर्शिता, योजना के अभिसरण एवं कड़ी मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षक प्रमुख अनुशंसाए थीं। हालांकि, राज्य सरकार ने इन अनुशंसाओं पर कार्रवाई नहीं की थीं।

अनुशंसाएं:

- शिकायत निवारण तंत्र को, शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण एवं उसके शीघ्र निपटान को प्रोत्साहित कर सुदृढ़ करना चाहिए। संबंधित अधिकारी इस प्रक्रिया का आवधिक आधार पर मॉनीटर करें और सुनिश्चित करें कि एक उचित अवधि से अधिक समय तक कोई शिकायत लंबित न रहे।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि योग्य लाभार्थी चयनित किये जा रहे हैं और उनके लिए समय पर अच्छी गुणवत्ता के घरों का निर्माण हो रहा है, सामाजिक लेखापरीक्षा को एक प्रभावी तरीके के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।
- इं.आ.यो. के कार्यान्वयन में कमजोरियों की पहचान को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन अध्ययन किया जाए।

अध्याय 8: वासभूमि स्थलों की योजना

इं.आ.यो. के भाग के रूप में उन ग्रामीण ग.रे.नी. के परिवारों, जिनके पास न तो कृषि भूमि थी और न ही निवास स्थल था, को वासभूमि स्थल प्रदान करने हेतु एक योजना अगस्त 2009 में प्रारम्भ की गई थी।

8.1 वासभूमि स्थलों की योजना का कार्यान्वयन

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के पैरा 8.1 (X) के अनुसार, निधियों की प्रथम किश्त को केवल राज्यों द्वारा यह प्रमाणित किए जाने के पश्चात ही जारी किया जाना था कि इसके पास (1) ग्रामीण ग.रे.नी. को या तो (क) नियमितिकरण के माध्यम से या (ख) अंतरण के माध्यम से प्रदान करने हेतु कोई भूमि नहीं थी (2) उसने अधिग्रहण/खरीद हेतु भूमि की पहचान कर ली थी। अनुवर्ती किश्तो को राज्य द्वारा पहचान की गई भूमि के अधिग्रहण के पश्चात जारी किया जाना था। इसके अतिरिक्त इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के पैरा 8.1 (vi) के अनुसार ₹10,000 प्रति लाभार्थी अथवा वास्तविक कीमत जो भी कम हो को लगभग 100.250 वर्ग.मी. क्षेत्र के वासभूमि स्थल की खरीद/अधिग्रहण हेतु प्रदान किया जाएगा। निधीयन, केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 50:50 के अनुपात में बांटा जाना था जबकि सं.शा.क्षे. के मामले में यह केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण रुप से वित्तपोषित था। यदि प्रति लाभार्थी राशि कम पड़ती है तो शेष राशि को राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा।

8.1.1 वासभूमि स्थलों हेतु योजना का गैर-कार्यान्वयन

2009-13 के दौरान, वासभूमि स्थल की योजना 17 राज्यों/सं.शा.क्षे अर्थात **असम, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंण्ड, पंजाब, तमिलनाडू, उतराखण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप** में कार्यान्वित नहीं की गई थी।

हमने पाया कि पांच राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. (असम, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, उतराखण्ड तथा अ. एवं नि. द्वीपसमूह) में कुछ चयनित जिलों ने वासभूमि स्थल योजना के अंतर्गत भूमि की खरीद हेतु प्रस्ताव प्रारम्भ किए थे परंतु प्रस्तावों को लाभदायक नहीं बनाया जा सका। राज्य-वार अभ्युक्तियों पर अनुबंध- 8.1 में चर्चा की गई हैं।

8.1.2 वासभूमि स्थलों हेतु योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताएं

Xiवीं पंयवर्षीय योजना (प.व.यो) दस्तावेज के अनुसार एक सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों में से एक '2012 तक सभी को वासभूमि स्थल प्रदान करना' था। 58 वें तथा 59 वें दोर की राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (रा.न.स.सं.) प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार, देश में 77 लाख ग्रामीण ग.रे.नी. के परिवार थे जिनके पास घरों के निर्माण हेतु निवास स्थल नहीं थे। 2012 तक सभी को वासभूमि स्थल प्रदान करने के भा.स द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए 77 लाख परिवारों की 75 प्रतिशत की अनुमानित आवश्यकता को राज्य सरकारों द्वारा उनके द्वारा अधिकृत भूमि, यदि कोई हो, को नियमित करके अथवा अतिरिक्त सरकारी भूमि का आवंटन करके पूरा किया जाना था। इस प्रकार, शेष 25 प्रतिशत (₹ 19.25 लाख) अनुमानित परिवारों, जिनके पास निवास स्थल नहीं है, हेतु भूमि की खरीद/अधिग्रहण की आवश्यकता थी।

इस उदेश्य हेतु, 11वीं पं.व.यो. हेतु प्रस्तावित केन्द्रीय आवंटन ₹ 1,000 करोड़ (2009-10 हेतु ₹ 200 करोड़, 2010-11 हेतु ₹ 300 करोड़ तथा 2011-12 हेतु ₹ 500 करोड़) था।

(i) ₹ 1,000 करोड़ के प्रस्तावित केन्द्रीय आवंटन के प्रति मत्रांलय को राज्य द्वारा भेजे गए प्रस्तावो के आधार पर नौ राज्यों को ₹ 347.47 करोड़ (2009-10 के दौरान बिहार, कर्नाटक, केरल, राजस्थान एवं सिक्किम को ₹ 157.47 करोड़ तथा 2010-11 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं उतर प्रदेश को ₹ 190 करोड़) जारी किए गए थे। किसी भी राज्य को 2011-12 तथा

2012-13 के दौरान निधियां जारी नहीं की गई थी। राज्य-वार निर्गम अनुबंध 8.2 में दिए गए है।

(ii) मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश को इन राज्यों द्वारा भूमि के अधिग्रहण को सुनिश्चित किए बिना एक किश्त में निधियां जारी की तथा निधियों का उपयोग या तो नहीं किया गया अथवा आंशिक रूप से उपयोग किया गया था। अप्रयुक्त वासभूमि निधियों को बाद में नियमित इं.आ.यो. के प्रति समायोजित किया गया था तथा निधियों के विपथन के उदाहरण भी पाए गए थे। राज्य-वार विवरण अनुबंध 8.3 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भूमिहीन ग.रे.नी. के परिवार[1] योजना के लाभों से वंचित थे।

मत्रांलय ने बताया कि वासभूमि योजना, एक मांग संचालित योजना थी तथा योजना के अंतर्गत निधियां केवल उन राज्यो को जारी की गई थी, जिन्होने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों सहित इस सबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करके इसकी मांग की थी। मत्रांलय ने यह भी बताया कि राज्यों द्वारा उस दर, जिस पर निधियां प्रदान की गई थी, पर भूमि न खरीदे जाने के मामले में, उन्होंने जारी की गई राशि का नियमित इं.आ.यो. आवंटन के प्रति समायोजन करने हेतु अनुवर्ती अनुरोध किया था।

मंत्रालय का उत्तर केवल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सिद्ध करता है तथा वासभूमि स्थल योजना की विफलता के मामले का निदान नहीं करता है।

---

[1] राजस्थान के आठ चयनित जिलों मे से केवल पांच जिलो (बूंदी, भीलवाड़ा, सीकर, श्रीगंगानगर तथा उदयपुर) में 2,10,770 भूमिहीन ग.रे.नी. के परिवार थे।

8.2 वासभूमि के अंतर्गत अतिरिक्त घरों हेतु प्रोत्साहन

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के पैरा 8.1 (xii) के अनुसार, राज्य सरकारों को भूमि के नियमितीकरण अथवा खरीद/अधिग्रहण के माध्यम से लाभार्थियो को वासभूमि स्थल प्रदान किए जाने की सीमा तक इं.आ.यो. के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों का आवंटन करके प्रोत्साहित किया जाना था। राज्यों को प्रस्तावित योजना हेतु इसी प्रकार की पहल हेतु अपने वर्तमान बजट से अधिक निधियां प्रदान करना प्रत्याशित था। यह, इस शर्त के तहत भी था कि राज्य योजना हेतु एक राशि, जो उनके पिछले वर्ष के बजट से कम न हो, का आवंटन करना जारी रखेंगें। खरीद के माध्यम से भूमि आंवटित किए गए ग.रे.नी. के परिवार को, सभांवित सीमा तक, उसी वर्ष में गृह निर्माण सहायता प्रदान की जानी थी।

छत्तीसगंढ, गुजरात, झारखण्ड़, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपूरा तथा पश्चिम बंगाल (10 राज्यों) को 2009-13 के दौरान वासभूमि के अंतर्गत अतिरिक्त घरो हेतु प्रोत्साहन के रूप में ₹ 1,750.92 करोड़ जारी किए गए थे। राज्य-वार निर्गम अनुबंध 8.4 में दिए गए हैं।

8.2.1 अतिरिक्त घरो के निर्माण में अनियमितताएँ

हमने पाया कि वासभूमि प्रोत्साहन के अंतर्गत अतिरिक्त घरों के निर्माण हेतु सात राज्यों को निधियां जारी की गई थीं जो अप्रयुक्त रहीं थी अथवा उसका नियमित इं.आ.यो. के अंतर्गत लाभार्थियो, जिनके पास भूमि थी, के घरों के निर्माण के प्रति विपथित किया गया था जैसा **तालिका-14** में विवरण दिया गया है।

तालिका-14: अतिरिक्त घरों के निर्माण में अनियमितताएं

क.सं	राज्य/सं.शा.क्षे.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	छत्तीसगढ़	विकास आयुक्त, रायपुर के आदेशों (फरवरी 2012) के अनुसार, इं.आ.यो. वासभूमि प्रोत्साहन के अंतर्गत सहायता उन ग.रे.नी. भूमिहीन परिवारों जिन्होने बन अधिकार अधिनियम (बनपट्टा घारक) के अंतर्गत भूमि प्राप्त की थी, को प्रदान की जानी थी। 2011-12 के दौरान दो चयनित जिलों (बस्तर: 4,486 लाभार्थी तथा दुर्ग: 784 लाभार्थी) में 5270 लाभार्थियों को ₹12.64 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की गई थी। ब्लॉक अम्बिकापुर (जिला सरगुज) की

क.सं	राज्य/सं.शा.क्षे.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
		ग्रा.पं. घांघरी तथा नन्दमाली में 20 लाभार्थियो जो आ.आ. के तहत बन अधिकार पट्टा के प्राप्तकर्ता नहीं थे, को वासभूमि प्रोत्साहन के अतंर्गत ₹9.70 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। सबंधित ग्रा.पं. द्वारा इन अयोग्य लाभार्थियों को की गई संस्वीकृति को रद्द करने के उनुरोध सहित तथ्य को ब्लॉक अम्बिकापुर के संज्ञान में लाया गया था। संस्वीकृति को रद्द करने के स्थान पर ब्लॉक अम्बिकापुर ने इन लाभार्थियों को दूसरी किस्त जारी की। मु.का.आ. जि.प. अम्बिकापुर द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। भा.स. ने जि.प. बस्तर को 4,486 लाभार्थियों के संबंध में इं.आ.यो. सहायता की प्रथम किस्त के रूप में ₹24250 प्रति लाभार्थी की दर पर ₹10.88 करोड़ जारी किए। जि.प. बस्तर ने मार्च 2012 में लाभार्थियों को निधियों का अंतरण किया। इन लाभार्थियो को मंत्रालय द्वारा निधियों को जारी न किए जाने के कारण दूसरी किस्त जूलाई 2013 तक प्रदान नहीं की जा सकी थी जबकि नवम्बर 2012 में जि.प. बस्तर द्वारा इनकी मांग की गई थी। इसके परिणामस्वरूप घरों के निर्माण में विलम्ब में हुआ।
2.	गुजरात	मत्रांलय ने 18597 घरों हेतु वासभूमि प्रोत्साहन के अतंर्गत पाँच चयनित जिलों (आनन्द, वांसकांथ, दाहौड़, सूरत तथा सुरेन्द्रनगर) को ₹58.71 करोड़ जारी (मार्च 2010, जुलाई 2012, आगस्त 2010 तथा जनवरी 2011) किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी चयनित जिले ने इन लाभार्थियों के लिए दी जाने वाली निधियों के उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया था जिन्हें योजना के अंतर्गत घर स्थल प्रदान किए गए थे, परंतु इन निधियों का उपयोग उन लाभार्थियो, जिनके पास पहले से ही भूमि थी, को घरों के निर्माण हेतु सहायता के भुगतान हेतु किया गया था। इसने भूमिहीन ग.रे.नी. के लाभार्थियों को योजना के लाभ से वंचित किया।
3.	झारखण्ड	छः चयनित जिलों ने घरों के निर्माण हेतु ब्लॉको को ₹47.15 करोड़ (केन्द्रीय निर्गम ₹35.36 करोड़ तथा राज्य का अंश ₹11.79 करोड़) जारी किए जिसमें से तीन जिलों (गढ़वा, गोड्डा तथा पलामू) में निधियां मार्च 2013 तक अप्रयुक्त रही। जबकि अन्य तीन चयनित जिलों (देवघर, पूर्वी सिंहभूम तथा रांची) में मार्च 2013 तक ₹15.44 करोड़ का व्यय किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उन लाभार्थियो, जिनके पास पहले ही भूमि थी, का चयन किया गया था। इस प्रकार, ग्रामीण ग.रे.नी. के परिवारों जिनके पास न तो कृषीय भूमि थी और न ही घर स्थल थे को आश्रय प्रदान करने का योजना का उद्देश्य विफल रहा था।
4.	ओडिशा	मत्रांलय ने ₹181.13 करोड़ (मार्च 2012) जारी किए थे तथा राज्य सरकार ने वासभूमि प्रोत्साहन के अतंर्गत 99,086 अतिरिक्त घरों के निर्माण के संबंध में प्रथम किस्त के रूप में 28 जिलों को ₹60.38 करोड़ (जुलाई 2012) का अपना बराबर का अंश जारी किया। राज्य सरकार ने केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त की प्रत्याशा में अपने बराबर का अंश जारी किया (मार्च 2013) परंतु इसे मत्रांलय द्वारा जारी नहीं किया गया था। वासभूमि प्रोत्साहन के अतंर्गत वित्तीय सहायता सभी ग.र.नी. के लाभार्थियो के लिए उपलब्ध थी फिर भी लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने सहायता प्रदान करने हेतु केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों तथा अन्य परम्परागत बन निवासियो (वन अधिकार अधिनियम 2006

क.सं	राज्य/सं.शा.क्षे.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
		की मान्यता) का चयन किया। राज्य सरकार ने सरकारी भूमि अथवा अतिक्रमित भूमि को संक्रामित करके तथा भूमि की खरीद के भी माध्यम से अन्य योग्य ग.रे.नी. के परिवारों हेतु भूमि का आवटन करने की सम्भाव्यता का अनवेषण नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने पाया था कि पांच चयनित जिलों के आठ ब्लाको (नीलगिरी, बार्ककोट, तिलायबानी, दिग्पाहण्डी, छीकीटी, कोम्मा, सिनापली तथा जामनकीरा) द्वारा 3,432 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रथम किस्त के रूप में ₹8.40 करोड़ (केन्द्रीय तथा राज्य का अंश) की प्राप्ति के प्रति केवल 3,042 लाभार्थियों को ₹5.12 करोड़ की सहायता प्रदान की गई थी।
5.	राजस्थान	कुल ₹154.30 करोड़ (₹115.72 करोड़ का केन्द्रीय अंश तथा ₹38.58 करोड़ का राज्य का अंश) की प्रथम किस्त को अ.ज.जा. ग.रे.नी. के परिवारो, जिन्हे उनकी प्राथमिकता के अनुसार जिलों में स्थायी इं.आ.यो. प्रतिक्षा सूची में शामिल किया गया था, हेतु 68,578 घरो (र45000 की दर पर पांच जिलों[2] मे 25447 घरो हेतु वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तथा 13 चयनित जिलो[3] में 18 जिलों की संबधित जि.प. (अ.वि. कक्ष) को जारी (परवरी 2013) किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निधियां जनवरी 2014 तक संबधित जि.प. (अ.वि. कक्ष) के खाते में रही। इम प्रकार, 68578 लाभार्थी वासभूमि प्रोत्साहन के लाभ सं वचित थे।
6.	त्रिपुरा	वासभूमि योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य द्वारा कोई भूमि अधिप्राप्त नहीं की गई थी इसलिए परम्परागत वन निवासियों, जिन्हे वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि का आबंटन किया गया था, को भा.स. की सस्वीकृति से इं.आ.यो. घर का आबंटन किया गया था. वासभूमि प्रोत्साहन के अंतर्गत जिला पश्चिम त्रिपुरा ने कुछ परिवर्तन के सिवाय केवल अ.ज.जा. लाभार्थियों को इं.आ.यो. घर प्रदान किए गय थे तथा लाभार्थियों का स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची से चयन किया गया था। 2011-12 के दौरान राज्य में चार जि.ग्रा.वि.अ. को वासभूमि प्रोत्साहन के अंतर्गत ₹15.43 करोड़ की दूसरी किस्त मत्रांलय द्वारा जारी नहीं की गई थी जबकि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए समय पर उचित रूप से प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। परिणामस्वरूप, 7,072 घर लाभार्थियों द्वारा निधियों की अप्राप्ति के कारण अपूर्ण रहे। लाभार्थियों को प्रथम किस्त में जारी ₹17.14 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹15.43 करोड़ तथा राज्य का अंश ₹1.71 करोड़) का व्यय भी निष्फल रहा।
7.	पश्चिम बगांल	मत्रांलय ने वासभूमि प्रोत्साहन के अंतर्गत अतिरिक्त 22,310 घरों के निर्माण हेतु 2011-12

[2] बासंवारा: ₹21.66 करोड़, डूंगरपुर: ₹27.80 करोड़, प्रातगढ़: ₹12.96 करोड़, सिरोही: ₹3.31 करोड़ तथा उदयपुर: ₹11.45 करोड़

[3] बारन: ₹8.90 करोड़, भीलवाड़ा: ₹11.49 करोड़, बूंदी: ₹2.09 करोड़, चितौड़गढ़: ₹ 7.69 करोड़, दौसा: ₹3.00 करोड़, जालोर: ₹5.79 करोड़ कारौली: ₹5.15 करोड़ पाली: ₹6.83 करोड़, प्रतापगढ़: ₹4.62 करोड़, राजसमंद: ₹6.41 करोड़, सवाईमाधोपुर: ₹2.76 करोड़, टोंक: ₹4.11 करोड़ तथा उदयपुर: ₹28.20 करोड़

क.सं	राज्य/सं.शा.क्षे.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
		के दौरान ₹39.54 करोड़ जारी किए। ब्लाक सूची-I(जिला वीरभूम) की ग्रा.पं. मल्लिकपुर में एक व्यर्थ भूमि[4] 'नीजो गृह नीजो भूमि योजना' के अंतर्गत 'पट्टा' के रूप मे 20 लाभार्थियों को आबंटन (2012-13) किया गया था. कुल 4.73 लाख की प्रथम किस्त उनको घरो के निर्माण के लिए जारी की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि लाभार्थियों ने वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के एक वर्ष के पश्चात भी भूमि पर घरो का निर्माण नहीं किया था क्योंकि भूमि गहरी थी तथा 31 कटाव के अधिमुख थी। ब्लॉक द्वारा राशि को वसूलने अथवा निर्माण आरम्भ करने हेतु उनको बाध्य करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, नौ ग्रा.पं.[5] में 52 लाभार्थियों का स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची के बाहर से चयन किया गया था तथा घरों के निर्माण हेतु वासभूमि प्रोत्साहन के अतंर्गत उनको ₹14.94 लाख का संवितरण किया गया था। ब्लाक मयूरेश्वर-II में एक लाभार्थी, जिसने कालेश्वर ग्रा.पे. से पहले ही दो किस्त प्राप्त की थीं, का वासभूमि योजना के अंतर्गत लाभार्थी के रूप मे चयन किया गया था तथा अनियमित रूप मे ₹22,500 अदा किए गए थे।

इसका आशय यह है कि मंत्रालय ने राज्यों को, जब भी उन्होंने बिना पर्याप्त सर्वेक्षण के अतिरिक्त् घरों हेतु अथवा अतिरिक्त आवश्यकता पर उनके पास डाटा उपलब्ध न होने पर भी मांग की थी, निधियां जारी की गई थी। जिसका परिणाम राज्यों के पास निधियों के संचयन में हुआ तथा बाद में उन्हें नियमित इं.आ.यो. को विपथित किया गया।

मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान के तहत तहसीलदार/सरपंच द्वारा लाभार्थियों को भू-अधिकार प्रमाण-पत्र जारी करके वासभूमि स्थलों को नियमित किया गया था। 13 चयनित जिलों में से दो जिलों (जबलपुर तथा नरसिंहपुर) में पात्रता को ब्लॉक स्तर पर जि.प. द्वारा गठित दल के द्वारा किए सर्वेक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया गया था, परंतु लेखापरीक्षा सत्यापन हेतु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

हमने संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया कि भू-अधिकार प्रमाण-पत्र वासभूमि के लाभार्थियों को जारी नहीं किया गया था। भू-अधिकार प्रमाण-पत्र गृह स्थल तथा कृषि भूमि वाले लाभार्थियों को जारी किया गया था।

---

[4] भूमी गहरी थी तथा इमे निर्माण हेतु उपयुक्त बनाने हेतु पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड की सहायता से ' फ्लाई ऐश' द्वारा भरा गया था।

[5] मल्लिकपुर(20), पुर्नोदोरपुर(7), रूपुर(6), सत्तौर(3), सारपलेन्हा-अलबांघा(2), रायपुर-सुपुर(2), बाहरी-पचेशोवा(3), कस्बा(4) सिंही(5)

लेखापरीक्षा में पाई गई अनियमितताओं की निम्न मामला अध्ययन में चर्चा की गई है

मामला अध्ययन: मध्य प्रदेश में वासभूमि प्रोत्साहन का कार्यान्वयन

मंत्रालय ने ग.रे.नी. के भूमिहीन परिवारों हेतु 1,05,200 अतिरिक्त घरो के लिए प्रोत्साहन के रूप में मध्य प्रदेश के 48 जिलों को प्रथम किश्त (मार्च 2011) के रूप में 180 करोड़ जारी करने के पश्चात वासभूमि स्थलो के आवंटन का सत्यापन करने हेतु नवम्बर 2011 में शियोपूर, नरसिहंपूर तथा झाबूआ जिलों में रा.स्त.मॉ. नियुक्त करने का निर्णय लिया। रा.स्त.मॉ. ने यह दर्शाने हेतु कि वासभूमि स्थल स्पष्ट शीर्ष के साथ प्रदान किए थे, कोई निर्णायक प्रमाण प्रस्तुत किए बिना फरवरी 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसी बीच, ₹ 175.46 करोड़ की दूसरी किश्त सितंबर 2011 तथा मार्च 2013 के बीच की गई थी।

रा.स्त.मॉ. की अनिर्णायक रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मत्रांलय ने शियोपूर, नरसिहंपूर एंव झाबूआ जिलों में एक विस्तृत जांच करने हेतु एक दल नियुक्त करने का निर्णय लिया (मार्च 2012)। दल मई 2012 में गठित किया गया था तथा इसने तीन जिलो अर्थात शियोपूर, नरसिहंपूर एवं झाबूआ, जिन्हे जांच हेतु मार्च 2012 में स्वीकृत किया गया था, के स्थान पर अक्टुबर 2012 चार जिलों नामत इंदौर, देवास, शोहोर तथा भोपाल का दौरा किया। दल ने अक्टूबर 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा सुनिश्चित किया कि दल द्वारा दौरा किया/भेटं किया कोई भी लाभार्थी भूमिहीन नहीं था। वासभूमि योजना मध्य प्रदेश में कार्यान्वित नहीं की गई थी जैसा इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों में अभिकल्पना की गई थी। जिनके लिए वासभूमि स्थलों का आवंटन किया गया था। मंत्रालय ने फिर से फरवरी 2013 में 30,998 अतिरिक्त घरों हेतु वासभूमि प्रोत्साहन के अतंर्गत ₹ 53.18 करोड़ तथा वन अधिकार अधिनियम के तहत 53,360 घरों हेतु ₹ 92.11 करोड़ की प्रथम किश्त जारी की।

परिणामस्वरूप, मंत्रालय ने राज्य सरकार को अतिरिक्त प्रोत्साहन हेतु संशोधित प्रस्ताव पेषित करने को कहा परंतु मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की तिथि तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया था।

इस प्रकार, मंत्रालय ने राज्य सरकार द्वारा प्रेषित अनियमित दावे के आधार पर दावे की प्रमाणिकता का सत्यापन किए बिना ₹ 500.85 करोड़ (₹ 180.10 करोड़ + ₹ 175.46 करोड़+₹ 145.29 करोड़) जारी किए। इसके अतिरिक्त, ₹ 320.75 करोड़ (₹ 175.46 करोड़ + ₹ 145.29 करोड़) की राशि राज्य द्वारा प्रेषित दावों के सत्यापन की अवधि के दौरान जारी की गई थी। यह मंत्रालय में कमजोर सत्यापन प्रणालियों तथा नियंत्रणों को दर्शाता है

मंत्रालय ने बताया कि वासभूमि प्रोत्साहन योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार उन राज्यों को जारी किए गए थे जिन्होंने या तो सरकारी भूमि के आवंटन द्वारा अथवा भूमि की खरीद/अधिग्रहण द्वारा इं.आ.यो. के घरों के निर्माण हेतु भूमिहीन ग्रामीण ग.रे.नी. को भूमि प्रदान की थी तथा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रोत्साहन का दावा किया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि निधियां नियमित आवंटन जिसे आवंटन हेतु मूल मापदण्ड का अनुपालन करके किया गया था, से अधिक प्रोत्साहन के रूप में जारी की गई थीं।

मंत्रालय का उत्तर सही नहीं है क्योंकि निधियों का आवंटन करने हेतु मापदण्ड (2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आवास कमी हेतु 75 प्रतिशत महत्व तथा राज्यों/सं.शा.क्षे. के गरीबी अनुपात को 25 प्रतिशत महत्व जैसा 2004-05 में योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था) का अनुपालन नहीं किया गया था तथा उतनी निधियां जारी की जो भी राज्य द्वारा मॉग की गई थी।

इस प्रकार, वासभूमि योजना प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं की गई थी क्योंकि योजना के अंतर्गत जारी निधियां लगभग अप्रयुक्त रही थीं तथा भूमिहीन परिवारों को घर प्रदान करने का प्रत्याशित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था।

अध्याय 9: संयुक्त भौतिक निरीक्षण

9.1 प्रस्तावना

इं.आ.यो. के कर्यान्वयन का निर्धारण करने हेतु लेखापरीक्षा दलों द्वारा संबंधित विभागों के स्टाफ की उपस्थिति में 29,923 लाभार्थियों के परिसरों में सयुंक्त भौतिक निरीक्षण किए गए थे तथा उनको एक प्रश्नावली का उत्तर देने का अनुरोध किया गया था। मानकीकृत प्रश्नावली में व्यक्तिगत लाभार्थी वर्णन, भुगतान का माध्यम, जानकारी का स्तर, अभिसरण के माध्यम से मूल सुविधाओं की उपलब्धता, आदि के पहलू शामिल थे। लाभार्थियों से अन्य बातों के साथ निम्नलिखित पर इनपुट प्रदान करने का निवेदन किया गया था;

- निर्माण की स्थिति तथा जारी निधियों के विवरण
- परिवारो (प.) मे उपलब्ध सुविधाओं का प्रकार
- घर रूपरेखा संरचना की गुणवत्ता तथा वांछनीय विशिष्टताएं
- भुगतान का माध्यम
- जानकारी का स्तर
- सरकार/गै.स.सं. द्वारा प्रदत्त विशेषज्ञ राय/सूचना
- वासभूमि स्थल की योजना से संबंधित मामले

9.1.1 बाधाएं

लेखापरीक्षा ने इस कार्य में कुछ बाधाओं का सामना किया जिनका नीचे सारांश दिया गया है;

- **आन्ध्र प्रदेश** में, राज्य में व्यापक तेलगांना विरोधी आन्दोलन के कारण केवल दो जिलों (करीमनगर तथा खम्माम) का निरीक्षण किया जा सका था तथा **मेघालय** में पूर्वी गारो हिल्स जिला के ब्लाक सांगसक में कानून व्यवस्था की समस्या के कारण लाभार्थियों तक पहुंचा नहीं जा सका।

- चूंकि पंचायत/विभागीय कर्मचारियों की उपस्थिति में निरीक्षण किए गए थे तथा उत्तर प्राप्त किए गए थे इसलिए संभव है इसने लाभार्थियों के उत्तर में कुछ दवाब उत्पन्न किए हो।
- यदि लाभार्थी की मृत्यु सहित किसी भी कारण से लाभार्थी उपलब्ध नहीं थे तो परिवार के दूसरे सदस्य को प्रश्नावली का उत्तर देने का अनुरोध किया गया था। ऐसे मामले में, वास्तविक लाभार्थी के विचार, दर्ज किए गए विचार से अलग हो सकते हैं।
- जिस जनसंख्या में से नमूने का चयन किया गया था उसमें केवल लाभार्थी शामिल थे। संभावित लाभार्थियों या इं.आ.यो. में शामिल न हुए व्यक्ति निरीक्षण में शामिल नहीं किए गए थे।

सयुंक्त भौतिक निरीक्षण के निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है :-

9.2 लाभार्थियों की जागरूकता का स्तर

9.2.1 प्राथमिकता सूची के अनुसार आवंटन

29,923 लाभार्थियों में से, 15,482 (52 प्रतिशत) लाभार्थी के चयन हेतु प्राथमिकता सूची से अवगत थे। तथापि, **गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, नागालैण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** तथा **लक्षद्वीप** में कोई भी लाभार्थी प्राथमिकता सूची से अवगत नहीं था। इसके अतिरिक्त, **बिहार** 372(1,647 का 23 प्रतिशत), **गुजरात** 654 (2,008 का 33 प्रतिशत), **झारखण्ड** 321 (1,199 का 27 प्रतिशत) **केरल** 82 (318 का 26 प्रतिशत), **मणिपुर** 122 (816 का 15 प्रतिशत), **ओडिशा** 503(1293 का 39 प्रतिशत), **त्रिपुरा** 294 (624 का 47 प्रतिशत), तथा **पश्चिम बंगाल** 279(600 का 47 प्रतिशत) में 50 प्रतिशत से कम लाभार्थी प्राथमिकता सूची से अवगत थे।

दूसरी तरफ, **हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, उतराखण्ड, दादरा एवं नागर हवेली** तथा **दमन एवं दीव** के मामले में प्राथमिकता सूची स्तर के संबंध में जागरूकता अधिक थी (70 से 100 प्रतिशत के बीच)।

9.2.2 इं.आ.यो. की प्रतीक्षा सूचियां

कुल 11,422 लाभार्थी (38 प्रतिशत) लाभार्थी के चयन हेतु तैयार प्रतीक्षा सूची से अवगत थे जबकि 10,660 लाभार्थियों (36 प्रतिशत) को प्रतीक्षा सूची तैयार करने की पद्धति का ज्ञान था।

अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, तथा **केरल** में लाभार्थियों के चयन हेतु तैयार प्रतीक्षा सूची के संबंध में जागरूकता स्तर 25 प्रतिशत से कम था। तथापि, **गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, नागालैण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** तथा **लक्षद्वीप** में कोई भी लाभार्थी प्रतीक्षासूची से अवगत नहीं था।

दूसरी ओर, **छतीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, दादरा एवं नागर हवेली** तथा **दमन एवं दीव** में जानकारी का स्तर 60 से 100 प्रतिशत के बीच था।

9.2.3 ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत ऋण की जानकारी

इं.आ.यो. के अंतर्गत प्रदत्त सहायता के अतिरिक्त एक लाभार्थी ब्याज की विशिष्ट दर (ब्या.वि.द.) योजना के अंतर्गत चार प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ₹20,000 प्रति अवासीय इकाई तक ऋण प्राप्त कर सकता था।

केवल 1,400 लाभार्थियों (कुल लाभार्थियों का 4.86 प्रतिशत) ने बताया कि वह ब्या.वि.द. योजना से अवगत थे। **अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पजांब, उत्तर प्रदेश,** तथा **दमन एवं दीव** से किसी भी लाभार्थी को ब्या.वि.द. योजना के संबंध में ज्ञान नही था। तथापि, **तमिलनाडु** के मामले में 37 प्रतिशत लाभार्थियों को ब्या.वि.द. योजना के संबंध में जानकारी थी जबकि **आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश** तथा **उतराखण्ड** के मामले में जागरूकता का स्तर क्रमश: 23, 29 तथा 10 प्रतिशत था। शेष राज्यों/सं.शा.क्षे. हेतु जागरूकता का स्तर 10 प्रतिशत से नीचे था।

इसके अतिरिक्त, कुल लाभार्थियों के केवल 0.92 प्रतिशत (275) ने ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत ऋण हेतु आवेदन किया था तथा कुल लाभार्थियों के 0.38 प्रतिशत (115) ने ऋण प्राप्त किया था।

9.3 भुगतान का माध्यम

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के अनुसार, इं.आ.यो. के अंतर्गत निधियों को केवल बैंक अथवा डाक घर में लाभार्थियों के खाते में सीधे अंतरण किया जाना चाहिए।

2,132 मामलों (सात *प्रतिशत*) में बैकिंग करेसपोन्डेन्ट, 917 मामलों (तीन *प्रतिशत*) में नगद, 746 मामलों (दो *प्रतिशत*) में अन्य माध्यमों तथा 42 मामलों (0.14 *प्रतिशत*) में पोस्टल आर्डर के माध्यम के बाद कुल 22,946 लाभार्थियों (77 *प्रतिशत*) ने बैंक/डाक घर खाते के माध्यम से वित्तीय सहायता की प्राप्ति का उत्तर दिया। **मणिपुर** में 816 में से 521 लाभार्थियों (64 प्रतिशत) तथा **मिजोरम** में 150 में से 82 लाभार्थियों (55 प्रतिशत) ने बताया कि उन्होने नगद में भुगतान प्राप्त किया था। नगद भुगतान के कुछ मामले **त्रिपुरा** (116), **आन्ध्र प्रदेश** (49), **असम** (64), **छत्तीसगढ** (दो), **हिमाचल प्रदेश** (दो), **मध्य प्रदेश** (2), **तमिलनाडु** (77), **पश्चिम बंगाल** (एक) तथा **लक्षद्वीप** (एक) में भी सूचित किए थे।

9.4 इं.आ.यो. सूचना पट्ट का प्रदर्शन

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के अनुसार, संबधित जिला परिषद/जि.ग्रा.वि.अ. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण किए गए प्रत्येक घर हेतु एक सूचना पट्ट लगाया जाना चाहिए जो भारत सरकार ग्रामीण आवास लोगो, निर्माण के वर्ष, लाभार्थी के नाम आदि को दर्शाए।

निरीक्षण किए कुल घरो के 65 *प्रतिशत* (19,465) में इं.आ.यो. सूचना पट्ट दर्शाए नहीं गए थे। **असम, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नागर हवेली** तथा **दमन एवं दीव** में निरीक्षण किए गए घरों के 90 *प्रतिशत* अथवा अधिक में इं.आ.यो. सूचना पट्ट उपलब्ध नहीं था। **आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छतीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल** तथा **लक्षद्वीप** में इं.आ.यो. सूचना पट्ट की गैर-उपलब्धता 50 से 89 *प्रतिशत* के बीच थी।

गुजरात, महाराष्ट्र तथा **मिजोरम** में इं.आ.यो. निरीक्षण किए गए घरों के क्रमश: 82.58 तथा 55 *प्रतिशत* में सूचना पट्ट उपलब्ध था।

अधिकांश मामलों में इं.आ.यो. के अंतर्गत निर्माण किए गए घरों पर इं.आ.यो. सूचना पट्ट की गैर-उपलब्धता ने इं.आ.यो. के दिशा-निर्देशों के अनुबंधों की अनुपालना में विफलता को दर्शाया।

9.5 घर के निर्माण में ठेकेदार की नियुक्ति

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के अनुसार इं.आ.यो. के अन्तर्गत रहने हेतु किसी इकाई के निर्माण के लिए किसी ठेकेदार की नियुक्ति नहीं की जानी थी।

गुजरात (139), **आन्ध्र प्रदेश** (20), **कर्नाटक** (नौ), **महाराष्ट्र** (46), **ओडिशा** (आठ) तथा **तमिलनाडू** (दो) लाभार्थियों ने बताया कि इं.आ.यो. घरों के निर्माण के दौरान ठेकेदारों को लगाया गया था।

9.6 घरों में सुविधाएं

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के अनुसार, घरों को मौसमी स्थितियों तथा पर्याप्त स्थान, रसोई घर, वायुसंचार, स्वच्छता सुविधाएं, धुंआरहित चूल्हा आदि प्रदान करने की आवश्यकता तथा सामुदायिक बोध, प्राथमिकताएं तथा सांस्कृतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लाभार्थियों की इच्छा के अनुसार डिजाईन किया जाना चाहिए था।

रसोई घर केवल 13,279 लाभार्थियों (44 प्रतिशत) ने बताया कि उनके घरों में रसोईघर की सुविधा उपलब्ध थी। **बिहार, झारखण्ड, नागालैण्ड** तथा **उत्तर प्रदेश** में रसोई घर की सुविधा केवल छः प्रतिशत अथवा कम में उपलब्ध थी। **असम** में किसी भी लाभार्थी ने रसोई घर की सुविधा की उपलब्धता का उत्तर नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त, **गोवा** (95 प्रतिशत), **महाराष्ट्र** (90 प्रतिशत) तथा **मिजोरम** (97 प्रतिशत) में अधिक लाभार्थियों ने उत्तर दिया कि उनके घरो में रसोई घर की सुविधा उपलब्ध थी।

धुंआरहित चूल्हा-केवल 4,822 लाभार्थियों (16 प्रतिशत) ने बताया कि उनके घरों में धुआंरहित चूल्हा उपलब्ध था। **अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू**

एवं कश्मीर, झारखण्ड, मणिपूर, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा **लक्षद्वीप** में यह सुविधा या तो उपलब्ध नहीं थी या फिर एक प्रतिशत से कम में उपलब्ध थी। दूसरी ओर धुंआरहित चूल्हा, **गोवा** (98 *प्रतिशत*), **महाराष्ट्र** (70 *प्रतिशत*) तथा **तमिलनाडू** (63 *प्रतिशत*) में अधिक संख्या में उपलब्ध था।

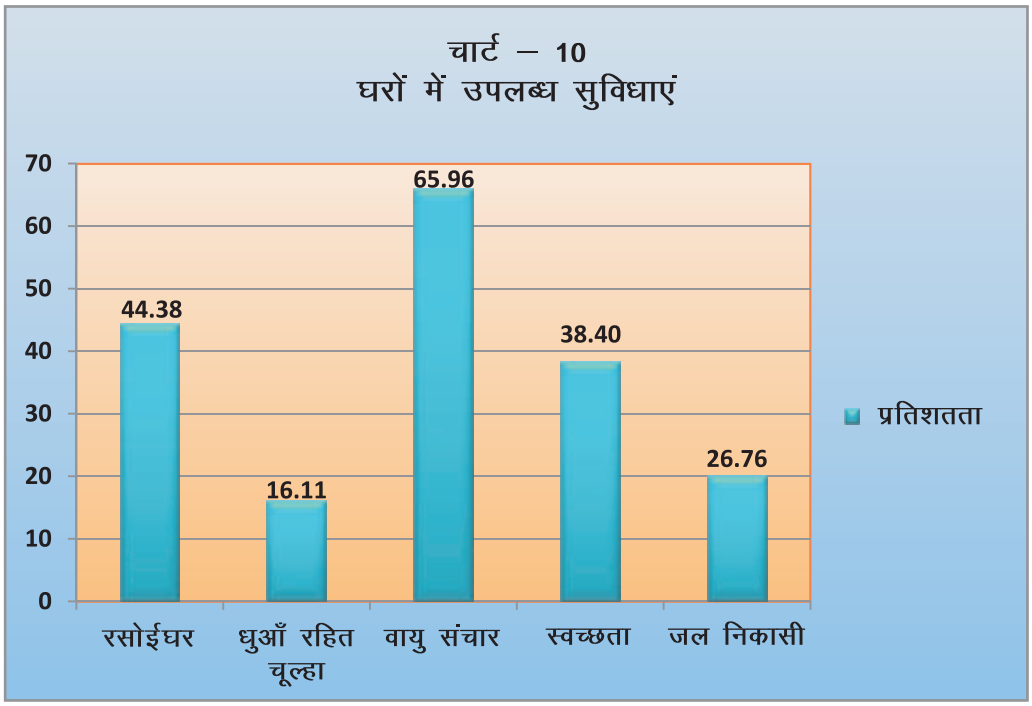
वायु संचार- केवल 19,738 लाभार्थियो (66 *प्रतिशत*) ने बताया कि उनके घरों में वायु संचार की सुविधा उपलब्ध थी। अरूणाचल प्रदेश (28 *प्रतिशत*), मणिपुर (4 *प्रतिशत*), नागालैण्ड (24 *प्रतिशत*), पंजाब (24 *प्रतिशत*) तथा दमन एवं दीव (8 *प्रतिशत*) में वायु संचार कम था।

स्वच्छता- केवल 11,543 लाभार्थियों (39 प्रतिशत) में बताया कि उनके घर में स्वच्छता की सुविधा थी। छः राज्यों। सं.शा.क्षे. अर्थात **बिहार, झारखण्ड, नागालैण्ड, ओडिशा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** तथा **दादरा एवं नागर हवेली** में परिस्थिति खराब थी जहां स्वस्छता की सुविधा 10 प्रतिशत से कम घरों में उपलब्ध थी।

दूसरी ओर **गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडू, उत्तराखण्ड** तथा **लक्षद्वीप** में लाभार्थियों के 52 से 92 *प्रतिशत* ने बताया कि उनके घरो में स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध थी।

जल निकासी- केवल 8,007 लाभार्थियों (27 *प्रतिशत*) ने बताया कि उनके घरों में जल निकासी उपलब्ध थी। **असम, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मणिपूर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, त्रिपूरा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव** तथा **लक्षद्वीप** में 10 प्रतिशत से कम लाभार्थियों ने उनके घरों में जल निकासी की अनुपलब्धता का उत्तर दिया।

घरों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की प्रतिशतता को **चार्ट-10** में दर्शाया गया है;



9.7 सरकार/गै.स.सं. द्वारा प्रदत्त विशेषज्ञ राय/सूचना

9.7.1 अभिनव सामग्री का उपयोग- केवल 2,360 लाभार्थियों (कुल लाभार्थियों का आठ प्रतिशत) ने बताया कि सरकार/गै.स.स. ने घर के निर्माण में अभिनव सामग्री के उपयोग पर विशेषज्ञ राय/सूचना प्रदान की गई थी। **आन्ध्र प्रदेश, छतीसगढ़, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल** तथा **दादरा एवं नागर हवेली** के सिवाय अधिकांश राज्यों/ सं.शा.क्षे. में किसी भी लाभार्थी ने उत्तर नहीं दिया था कि उन्होने अभिनव सामग्री के उपयोग पर विशेषज्ञ राय/सूचना प्राप्त की है। **दादरा एवं नागर हवेली** (100 *प्रतिशत*), **आन्ध्र प्रदेश** (90 *प्रतिशत*) तथा **त्रिपुरा** (70 *प्रतिशत*) में लाभार्थियों की अधिक संख्या ने उत्तर दिया कि सरकार/ गै.स.सं. ने इसके संबंध में विशेषज्ञ राय/सूचना प्रदान की थी।

9.7.2 निम्न लागत सामग्री के प्रापण पर- केवल 2,577 लाभार्थियों (कुल लाभार्थियों का नौ प्रतिशत) ने बताया कि सरकार/गै.स.सं. ने निम्न लागत सामग्री के प्रापण के संबध में विशेषज्ञ राय/सूचना प्रदान की थी। **आन्ध्र प्रदेश, छतीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडू, त्रिपूरा, पश्चिम बगांल, दादर एवं नागर हवेली** तथा **लक्षद्वीप** के सिवाय राज्यों

में किसी भी लाभार्थी ने यह नहीं बताया कि उन्होंने निम्न लागत सामग्री के प्रापण के संबंध में विशेषज्ञ राय/सूचना प्राप्त की थी।

आन्ध्र प्रदेश (कुल 660 लाभार्थियों का 93 *प्रतिशत*), **त्रिपुरा** (कुल 624 लाभार्थियों के 96 *प्रतिशत*) तथा **दादरा एवं नागर हवेली** (20 लाभार्थियों के 100 *प्रतिशत*) में 90 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों ने बताया कि उन्होने निम्न लागत सामग्री के प्रापण के संबध में विशेषज्ञ राय/सूचना प्राप्त की थी।

9.7.3 निर्माण डिजाईन के संबध में- केवल 3,267 लाभार्थियों (कुल लाभार्थियो का 11 प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि सरकार गै.स.सं. ने इं.आ.यो. के अंतर्गत घर के निर्माण डिजाईन के संबध में सूचना प्रदान की थी। **असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर**, **मिजोरम**, **नागालैंड**, **पंजाब**, **राजस्थान**, **उत्तर प्रदेश**, **उत्तराखण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** तथा **दमन एवं दीव** में किसी भी लाभार्थी ने उत्तर नहीं दिया था कि उन्होने इं.आ.यो. के घरों के निर्माण डिजाईन के संबंध में विशेषज्ञ राय/सूचना प्राप्त की थी।

दो राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. अर्थात **दादरा एवं नागर हवेली** (20 लाभार्थियों का 100 *प्रतिशत*), **आन्ध्र प्रदेश** (660 लाभार्थियों का 95 *प्रतिशत*) **तथा त्रिपुरा** (624 लाभार्थियों का 81 *प्रतिशत*) में अधिक लाभार्थियों ने उत्तर दिया कि उन्होने निर्माण डिजाईन के संबंध में सूचना/विशेषज्ञ राय प्राप्त की थी।

9.7.4 लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी- केवल 2,658 लाभार्थियों (नौ प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि उन्होने लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी के संबंध में सरकार/गै.स.सं. से सूचना/विशेषज्ञ से राय प्राप्त की थी। **आन्ध्र प्रदेश, छतीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादरा एवं नागर हवेली** तथा **लक्षद्वीप** के सिवाय राज्यो/सं.शा.क्षे. से किसी भी लाभार्थी ने लागत प्रभावी पर प्रौद्योगिकी के संबध में सूचना/विशेषज्ञ राय प्राप्त नहीं की थी। तथापि, **दादरा एवं नागर हवेली** (20 का 100 *प्रतिशत*), **त्रिपुरा** (624 का 96 *प्रतिशत*) तथा **आन्ध्र प्रदेश** (660 का 88 *प्रतिशत*) में

लाभार्थियों की अधिक संख्या ने इस प्रौद्योगिकी के संबंध में सरकार/गै.स.सं. से विशेषज्ञ राय प्राप्त की थी।

9.7.5 आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकी- केवल 2,483 लाभार्थियों (आठ प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि उन्होने आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकी के संबंध में सूचना/विशेषज्ञ राय प्राप्त की थी। **आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडू, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादर एवं नागर हवेली** तथा **लक्षद्वीप** के सिवाय अधिकांश राज्यों/सं.शा.क्षे. में किसी भी लाभार्थी ने इस प्रौद्योगिकी के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं की थी।

9.8 अभिसरण

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह सुनिश्चित किए जाने हेतु सभी प्रयास किए जाने थे कि प्रत्येक इं.आ.यो. के घर को पू.स्व.अ. के साथ अभिसरण में स्वच्छ शौचालय, रा.गां.ग्रा.वि.यो. के साथ समन्वय द्वारा बिजली तथा रा.ग्रा.ज.आ.का. के अंतर्गत कार्यो के अभिसरण के माध्यम से पेय जल प्रदान किया गया था।

इसके अतिरिक्त, जि.ग्रा.वि.अ. को जिले में संबंधित नोडल अभिकरण को प्रत्येक माह सभी इच्छुक लाभार्थियों के विवरण प्रस्तुत करने थे। जिससे कि लाभार्थी बीमा नीतियों के अंतर्गत उपलब्ध लाभों को प्राप्त करें।

9.8.1 पूर्ण स्वच्छता अभियान (पू.स्व.अ.) के साथ अभिसरण

केवल 1,844 (छः *प्रतिशत*) ने उत्तर दिया कि उन्होने पू.स्व.अ. के साथ अभिसरण में स्वच्छ शौचालय की सुविधा प्राप्त की। इसके अतिरिक्त, **अरूणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मिजोरम, नागालैण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव** तथा **लक्षद्वीप** से किसी भी लाभार्थी ने पू.स्व.अ. से सहायता की प्राप्ति का उत्तर नहीं दिया था। दो राज्यो अर्थात **त्रिपुरा** (33 *प्रतिशत*) तथा **महाराष्ट्र** (22 *प्रतिशत*) में लाभार्थियों की अधिक संख्या ने स्वच्छता सुविधाओं हेतु पू.स्व.अ. से सहायता प्राप्त की थी।

9.8.2 राजीव गांधी ग्रामीण विधुतीकरण योजना (रा.गां.ग्रा.वि.यो.) के साथ अभिसरण

केवल 4,187 लाभार्थियों (16 प्रतिशत) में उत्तर दिया कि उन्हे रा.गां.ग्रा.वि.यो. के साथ अभिसरण में उनके घरों में विजली कनेक्शन प्रदान किए गए थे। **अरूणाचल प्रदेश, छत्तीससगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपूर, नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नागर हवेली** तथा **दमन एवं दीव** में किसी भी लाभार्थी ने अथवा एक प्रतिशत से कम लाभार्थियों ने बिजली कनेक्शन हेतु रा.गां.ग्रा.वि.यो. से सहायता प्राप्त की। **मध्य प्रदेश** तथा **राजस्थान** में 57 तथा 51 प्रतिशत लाभार्थियों ने बिजली कनेक्शन हेतु रा.गां.ग्रा.वि.यो. से सहायता प्राप्त की।

9.8.3 राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (रा.ग्रा.ज.आ.का.) के साथ अभिसरण

केवल 2,246 लाभार्थियों (आठ प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि उन्होने पेय जल हेतु रा.ग्रा.ज.आ.का. से सहायता प्राप्त की थी। **अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मिजोरम, नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड़, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** तथा **दादरा एवं नागर हवेली** में किसी भी लाभार्थी ने अथवा एक *प्रतिशत* से कम लाभार्थियों ने उनके घरो पर पेय जल आपूर्ति हेतु रा.ग्रा.ज.आ.का. से सहायता की प्राप्ति का उत्तर दिया। शेष राज्यों/सं.शा.क्षे. की तुलना में **आन्ध्र प्रदेश** (32 *प्रतिशत*), **पंजाब** (35 *प्रतिशत*) **तथा राजस्थान** (32 *प्रतिशत*) में लाभार्थियो की अधिक संख्या ने रा.ग्रा.ज.आ.का. से सहायता प्राप्त की।

9.9 जी.बी.नि. से सहायता

केवल 701 लाभार्थियों (दो प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि उन्हे जी.बी.नि. की बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। 19 राज्यों/सं.शा.क्षे. अर्थात **अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मणिपूर, मिजोरम, नागालैण्ड, पजांब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव** तथा **लक्षद्वीप** में किसी भी लाभार्थी ने उन्हे जी.बी.नि. के अतंर्गत

शामिल किए जाने का उत्तर नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त **असम, गुजरात, मेघालय, तमिलनाडु** तथा **पश्चिम बंगाल** में एक प्रतिशत से कम में जी.बी.यो की बीमा योजना का लाभ उठाया था।

दूसरी ओर, **आन्ध्र प्रदेश** (15 प्रतिशत), **छत्तीसगढ़** (नौ प्रतिशत), **झारखण्ड** (छः प्रतिशत), **मध्य प्रदेश** (आठ प्रतिशत) तथा **महाराष्ट्र** (10 प्रतिशत) में स्थिति थोड़ी अच्छी थी।

बीमा योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का कम आवृतन दर्शाता है कि जि.ग्रा.वि.अ. बीमा योजनाओं से प्राप्त किए जाने वाले लाभों के संबध में लाभार्थियों के बीच जानकारी उत्पन्न करने में विफल था।

9.10 घर रूपरेखा प्रकार की गुणवत्ता तथा वांछनीय विशिष्टताएं

यह वांछनीय था कि घर में घरेलु कार्यों को करने हेतु पर्याप्त स्थान, एक बरामदा, सीढियां तथा वर्षा जल एकत्रण प्रणाली होनी चाहिए।

केवल 14,426 लाभार्थियों (48 प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि उनके घरों में बरामदा उपलब्ध था तथा 4,330 लाभार्थियों (15 प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि सीढियों का निर्माण किया गया था। तथापि, 1,229 लाभार्थियों (कुल लाभार्थियों का चार प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि उनके घरो में वर्षा जल एकत्रण सुविधा उपलब्ध थी। **अरूणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, महाराष्ट्र, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा दमन एवं दीव** में किसी भी लाभार्थी ने यह उत्तर नहीं दिया कि उनके घरों में वर्षा जल एकत्रण सुविधा उपलब्ध थी।

कुल 19,914 लाभार्थियों (67 प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि संबधित राज्य सरकार द्वारा भौगोलिक स्थिति अथवा अन्य प्रतिमानों को ध्यान में रखते हुए इं.आ.यो. के घर के निर्माण हेतु कोई विनिर्देश अधिसूचित नहीं किया गया था, केवल 4,016 लाभार्थियों (13 प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि उनके घरों का निर्माण सरकारी विनिर्देशों के अनुसार किया गया था तथा 5,360 लाभार्थियों (18 प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि उनके घरो का निर्माण विनिर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, छः राज्यों/सं.शा.क्षे. अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** में सभी लाभार्थियों ने उत्तर दिया कि राज्यों/सं.शा.क्षे. ने घर के निर्माण हेतु विनिर्देशों को अधिसूचित किया था परंतु इन राज्यों के 21 से 100 प्रतिशत लाभार्थियों ने उत्तर दिया कि उनके घरो का निर्माण विनिर्देशों के अनुसार नही किया गया था।

9.11 वासभूमि स्थलों हेतु योजना

केवल छः राज्यों अर्थात् **बिहार, छत्तीससगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान** तथा **पश्चिम बंगाल** में वासभूमि स्थल ग्रामीण ग.रे.नी. के परिवारों को प्रदान किए गए थे जैसा इन राज्यों में नमूना लाभार्थियों द्वारा सूचित किया गया था। सयुंक्त भौतिक निरीक्षण में इस योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या में **राजस्थान** में एक से **छत्तीससगढ़** में 113 तक भिन्न है।

केवल 246 लाभार्थियों (उपर्युक्त उल्लेखित छः राज्यो में 8,930 लाभार्थियों का तीन प्रतिशत) को घर के निर्माण हेतु वासभूमि स्थल प्रदान किए गए थे। **बिहार** तथा **राजस्थान** में, एक प्रतिशत से भी कम मामलों में लाभार्थियों को वासभूमि स्थल प्रदान किए गए थे।

शेष राज्यों/सं.शा.क्षे. में लेखापरीक्षा ने वासभूमि स्थल के अतंर्गत लाभार्थी नहीं पाए थे।

अध्याय 10: निष्कर्ष

इं.आ.यो. भारत सरकार (भा.स.) की एक मुख्य योजना है जिसे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहें बेघर ग.रे.नी. के परिवारों को घर प्रदान कराने हेतु प्राथमिक रूप से निर्दिष्ट किया गया है। इं.आ.यो. को ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) तथा जिला परिषदों (जि.प.)/जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (जि.ग्रा.वि.अ.) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। ग.रे.नी. सूची से ग्रा.पं. द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाना था तथा लाभार्थियों द्वारा स्वयं मकानों का निर्माण/सुधार किया जाना था। हमने इं.आ.यो. के कार्यान्वयन में विभिन्न कमियां तथा चूकें पायी थीं।

इं.आ.यो. के सफल कार्यान्वयन हेतु लाभार्थियों का पारदर्शी एवं निष्पक्ष चयन एक महत्वपूर्ण पहलू है। तथापि, हर जगह निर्धारित मानकों के अनुसार चयन प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया था। 14 राज्यों में मकानों की कमी का आकलन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अयोग्य लाभार्थियों का चयन किया गया था। कुछ राज्यों में, सूची को तैयार न किए जाने के कारण लाभार्थियों का चयन भी एक से अधिक बार हुआ था जिसका परिणाम अनियमित वित्तीय सहायता के रूप में हुआ था। योजना के मानकों के उल्लंघन में, छः राज्यों में परिवार के महिला सदस्य के नाम पर रिहायशी इकाई के आवंटन को प्राथमिकता नहीं दी गयी थी।

इं.आ.यो. के कार्यान्वयन के दौरान मकानों के समय पर पूरा होने तथा गुणवत्ता आधार को भी अनदेखा किया गया था। निर्माण गतिविधि में विवेकपूर्ण ढ़ंग से कार्य करने में प्राधिकारी विफल हुए तथा योजना के प्रावधानों के उल्लंघन में पांच राज्यों/सं.शा.क्षे. के आठ चयनित जिलों के 12 ब्लाकों में विभागीय या ठेकेदारों द्वारा ₹7.88 करोड़ की लागत पर मकानों का निर्माण हुआ था। नौ राज्यों के 48 चयनित जिलों में दो वर्षों से अधिक की अवधि बीत जाने के पश्चात् भी 61,293 मकान अपूर्ण रहे। निर्मित मकानों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित गुणवत्ता जांच/तकनीकी पर्यवेक्षण का भारी अभाव था। कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा 18 राज्यों/सं.शा.क्षे. में सुधार करने में या मजबूत, कम लागत वाले तथा आपदा प्रतिरोधी मकानों का निर्माण करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रयास नहीं किए गए थे।

अधिकतर राज्यों में, परिकल्पित रूप से अन्य योजनाओं के साथ गैर-अभिसरण के कारण इं.आ.यो लाभार्थी स्वच्छ पेयजल, मुफ्त बिजली कनेक्शन तथा स्वच्छ शौचालय से वंचित रह गए थे।

आवाससाफ्ट को पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं बनाया जा सका था जिसका परिणाम मंत्रालय द्वारा खराब मॉनीटरिंग के रूप में हुआ। खराब आंतरिक नियंत्रण तथा पुर्ननिरीक्षण की कमी ने मॉ.सू.प्र. में डॉटा की विश्वसनीयता तथा सत्यता को बहुत घटा दिया था।

रा.स्त.मॉ. द्वारा नियमित मॉनीटरिंग के गैर आवर्तन तथा उनकी रिपोर्टों पर अप्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है। 22 राज्यों/सं.शा.क्षे. में सामाजिक लेखापरीक्षा की शुरूआत अभी की जानी थी। 19 राज्यों/सं.शा.क्षे. में इं.आ.यो. के कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन करने के लिए मूल्यांकन अध्ययनों को संचालित नहीं किया गया था।

मंत्रालय द्वारा निधियों के अनुमोदन तथा निधियों को जारी किए जाने की प्रणाली में कमियां थीं। लेखापरीक्षा ने ऐसे उदाहरण पाए जहां मंत्रालय ने अपनी स्वयं की शर्तों के उल्लंघन में अनुदान जारी कर दिए थे। राज्य के अंश के कम एवं विलंबित रूप से जारी किए जाने, निधियों का दुर्विनियोजन तथा विपथन जिसे कि 2003 में योजना की पिछली लेखापरीक्षा में पाया गया था, वह इं.आ.यो. के कार्यान्वयन में भी मौजूद थे।

ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वासभूमि स्थल प्रदान करने की योजना, जिनके पास न तो कृषि भूमि थी न ही मकान के लिए जगह थी, अगस्त 2009 में प्रारम्भ की गई थी। योजना का 17 राज्यों/सं.शा.क्षे. में कार्यान्वयन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा राज्यों को वासभूमि स्थल योजना के अंतर्गत अतिरिक्त घरों के निर्माण हेतु जारी की गयी निधियां तो अप्रयुक्त रही थी उन्हें सामान्य इं.आ.यो. के अंतर्गत लाभार्थियों के घरों के निर्माण के प्रति विपथित कर दिया गया था।

योजना में बहुत सी कमियां अभी भी मौजूद हैं तथा इसकी जानकारी मंत्रालय को म.नि.ले.प. द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से दी गयी थीं। हालांकि, मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई, इन कमियों का निदान करने में अपर्याप्त थी।

2008-13 के दौरान ₹60,239 करोड़ के व्यय के बावजूद इं.आ.यो. देश में मकानों की कमी के अंतर को उल्लेखनीय रूप से कम नहीं कर सका है चूंकि XIवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत में घरों की कमी की समस्या का आंकलन अगली पंचवर्षीय योजना की शुरूआत के समय भी लगभग समान परिमाण तक ही बना रहा।

जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है, मंत्रालय को निदानात्मक कदम उठाने की और गड़बड़ियों को सुधारने की आवश्यकता है ताकि योजना के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके।

(सतीश लूम्बा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

नई दिल्ली
दिनांक : 2 दिसम्बर 2014

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 2 दिसम्बर 2014

अनुबंध

अनुबंध-2.1

नमूना चयन का सारांश

(पैराग्राफ 2.1.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.का नाम	जिला		ब्लॉक		ग्रा.पं.		संयुक्त भौतिक जांच के लिए गांव		संयुक्त भौतिक जांच के लिए लाभार्थी	
		योग	चयनित	कुल	चयनित	कुल	चयनित	कुल	चयनित	कुल	वास्तविक रूप से जांच की गई
1	आन्ध्र प्रदेश	22	02	103	08	151	55	106	79	5,945	660
2	अरूणाचल प्रदेश	16	04	26	08	123	40	121	69	981	412
3	असम	27	08	98	20	228	72	676	141	5,706	862
4	बिहार	38	10	136	30	459	138	744	253	31,973	1,647
5	छत्तीसगढ़	18	05	63	13	883	129	209	191	3,816	1,314
6	गोवा	02	02	12	04	66	22	42	28	2,877	265
7	गुजरात	26	07	73	17	1,307	170	208	191	10,252	2,008
8	हरियाणा	21	06	35	13	668	120	128	128	2,917	1,339
9	हिमाचल प्रदेश	12	04	24	08	285	71	533	139	375	382
10	जम्मू एवं कश्मीर	22	06	41	12	361	90	163	133	2,803	973
11	झारखण्ड	24	06	87	18	338	102	629	196	7,267	1,199

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.का नाम	जिला		ब्लॉक		ग्रा.पं.		संयुक्त भौतिक जांच के लिए गांव		संयुक्त भौतिक जांच के लिए लाभार्थी	
		योग	चयनित	कुल	चयनित	कुल	चयनित	कुल	चयनित	कुल	वास्तविक रूप से जांच की गई
12	कर्नाटक	30	08	45	16	404	119	600	252	7,963	1,258
13	केरल	14	04	41	11	68	25	419	50	1,204	318
14	मध्य प्रदेश	50	13	99	26	1,935	260	544	395	5,615	2,396
15	महाराष्ट्र	33	08	91	19	1,788	190	245	228	6,410	1,807
16	मणिपुर	09	04	21	08	560	69	257	98	2,072	816
17	मेघालय	07	04	27	08	435	74	213	144	1,462	540
18	मिजोरम	08	02	09	04	80	25	25	25	418	150
19	नागालैण्ड	11	03	14	06	183	60	60	60	7,587	695
20	ओडिशा	30	08	92	20	403	123	950	242	4,822[1]	1,293
21	पंजाब	20	06	33	12	1,018	120	122	122	1,305	611
22	राजस्थान	33	08	62	16	631	155	706	295	6,878	1,680
23	तमिलनाडु	31	08	98	22	793	168	1,003	321	2,912	1,546
24	त्रिपुरा	04	02	24	06	188	52	377	291	3,584	624

[1] 18 गावों से संबंधित कुल लाभर्थियों की संख्या उपलब्ध नहीं थी

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.का नाम	जिला		ब्लॉक		ग्रा.पं.		संयुक्त भौतिक जांच के लिए गांव		संयुक्त भौतिक जांच के लिए लाभार्थी	
		योग	चयनित	कुल	चयनित	कुल	चयनित	कुल	चयनित	कुल	वास्तविक रूप से जांच की गई
25	उत्तर प्रदेश	71	15	57	35	2,492	350	585	501	10,911	3,197
26	उत्तराखण्ड	13	05	36	10	695	100	218	115	4,314	1,149
27	पश्चिम बंगाल	18	05	77	15	150	45	600	90	3,687	600
28	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	03	02	06	04	37	11	34	20	354	127
29	दादर व नागर हवेली	01	01	01	01	11	02	12	04	104	20
30	दमन व द्वीप	02	01	01	01	10	01	03	01	25	12
31	लक्षद्वीप	01	01	01	01	10	02	02	02	275	23
कुल		**617**	**168**	**1,533**	**392**	**16,760**	**2,960**	**10,534**	**4,804**	**1,46,814**	**29,923**

अनुबंध-2.2
नमूना के ब्यौरे
(पैरा 2.1.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	जिलों के नाम	ब्लॉक के नाम	ग्रा.पं. के नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम*, गुंटुर*, अनुतपुर*, कुरनूल*, करीमनगर, खम्मन (दो)	भीम देवरा पाल्ले, गोल्लापाल्ले, मुथरम महादेवपुर, सिरिसिल्ला, अश्वपुरम, केनीजेरला, कुकुनूर, सत्तूपल्ली (आठ)	रामनगर, वंगर, कन्नरम, कोप्पुर, मणिक्यापुर, मल्लरम, इब्राहिम नगर, गुंजापडगु, चंदोली, बी.बी. राजपल्ली, अथमकुर, गोलापल्ली, सकांला, लोथूनूस, पोलारस, सताबमपल्ली, (पी.पी.), नालागुन्टा, मेनाजीपत, मूथराम, जिलापल्ली, कोरलाकुंटा, थंगल्लनल्ली, बदने पल्ले, जिल्लेलला, बस्वापुरम, बोनाला, मंडेपल्ली, कस्बेकलकुर, सरमपल्ली, रातचंद्रपुर, पेड्डुर, अम्मगरीपल्ली, अश्वपुरम, गोल्लागुदम, जग्गरम, मित्तगुदम, मौडीकुंता, चीना मुनगला, लिंगा गुदम, पेड्डा गोपथी, राम नरसैघा नगर, तनीकील्ली, थुम्मलपल्ली, पेडा मुनगाला, अमखरम, गोम्मू गुदम, मरे दुब्बका, तोंदीपक्का, उप्पेरू, विंजरम, बुग्गापडु, ककरलपल्ली, किस्तापुरम, नारायण पुरम, रूद्राक्षपल्ली, सदासिवनीपलम (55)
2.	अरूणाचल प्रदेश	लोहित, अंजाव, पपुम पारे, पश्चिम सियांग (चार)	तेजू, वाकरो, ह्यूलियांग, मंचल, बलिजान, कीमिन, पश्चिमी आलो, लिका बलि (आठ)	दंगलत, खोरालियांग,नया दंगलत, तफरागम-I तफरागम-II, तफरागम-III हूकिंग, कंजंग, वैखेटलिनाग-दुबरूमलियांग, ह्यूलियांग, सुपलंग जी.बी.सी., पंगुंग, क्वीबंग, बोरमाई, दरियाबिल, होलोंगी, जोटे, लंग्का, पोमा, रामघाट, तुबुंग दुर्पाजन, पुलकिमिन, बेने, दरका-I दरका-II, गुने बने, काबु-II, कुगी पोमसे, कुमी पोम्दे, पये, पोबदी, दीपा-I दुर्पई, जीपू,कुंटुर,लिपु-I, लिपु-II, लिरू-I, (40)
3.	असम	कर्बी अंगलोंन, कोकराझर, सोनीतपुर, शिवसागर, नगांव, बर्पेता, कचर, करीमगंज (आठ)	हावडाघाट, बोकाजन, काचुगांव, दोबीतोला, गमरू, चैदुआर, बाघमारा, अमगुरी, देमोव, पश्चिम कालीबोर, दोलोनघाट, जुगीलान, राहा, गोवर्धन, बजाली, कलैन, पलोनघाट, सिल्चर, पाथारकंडी, दुल्हावचेर्री (20)	हावडाघाट, लंधिन, सरूपथार, बैरली, बल्लीमरी, बुडाचारा, गुवावाड़ी, जारागुरी, गोलाडांगी, कचुगांव, काशियाबाड़ी, रैमोना, ब्कमपुर,मोदाती, पोलारागुडी,देबीतोला,, पांचमिले, डोलाबाड़ी, अमतला, मिस्सामड़ी, व्कुबाडी, हेलेम, गिंगिया, तिंसुती, अमगुडी, भयुनहाट, लालिमचापोरी, गोहैन फखुड़ी, महारानी, नाहट, नेमुगुड़ी, पालेंगी, रूपज्योति, राहधोला, रंगलियाल, हतिगांव, निज़ हातिचुंग, माजजाजोरी, बोर्पुखुड़ी, दीमारपुर, पब धोनीराम पणर, गोपालनगर, दीयालियाती, सल्मोड़ा, फुलागुडी, प्रमिला, कुमारगांव, पश्चिम होवली, उत्तर हवेली, बाघमारा, बंधासिधानी, बोर्भालुकी, वालीपाड़ा, मरीपुर,आनंदपुर, नित्यानंद पानबाड़ी, बुरूंगा, गोरे रिवतोर,जलालपुर, कलैन, कुरियारकुल, भुबनहिल, गंगानगर, मोहनखाल रम्मीनीकपुर, भाजंतीपुर, घुंगूर, कनकपूर, तुपखाना, बरीराम, जुरबाड़ी, देफाला, कनेबजार, मोयना, बिद्यानगर, लालचेड़ा, पटियाला, सिंगलाचेरा (72)
4.	बिहार	सारन, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, सुपौल, औरंगाबाद, भोजपुर, भागलपुर, लखीसराय, मधुबनी,	मधुबनी, पीपरासी, ठकराहा, बगहा-2, एकमा, लहलदपुर, नागरा, परेसा, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, बसंतपुर, प्रतापगंज, बारून, मंदनपुर, अजियागांव,	बरवा, मधुबनी, तमकुहा, डुमरी, भग्वदा, पीपरासी, जगीरहन, मोतीपुर, बैरागी, सोनवर्षा, बलेहवा मदनपुर, भरही, बकुली पचगवा, जमुनापुर, तरालिया, लक्ष्मीपुर रामपुरवा, मंगलपुर, औसनी, नौरगिया दादरी, असहनी, बलिया, देवपुरा, नवादा, पुचतीकलां, रामपुरबिंदलाल, दंदासपुर, कतेयान, अफौर, कोरेया, तुजारपुर, बहरमदर, बलीगांव, पंचरूखी, शंकरडीह, भदवदी, चंदवार मिलिक, दोहार, गांगी, लौचा, महेश बथना, बेशरबती, भोगदाबर, डलेलगांव, डुमरिया, मलिनगांव, रसिया, सुखुआडली, भगवानपुर, कुशार, परमानंदपुर, सतनपट्टी, उत्तरी भवानी पुर, चिलौनी उत्तरी, सुखनगर, बारून, काजीचक,

		समस्तीपुर (10)	बिहिया, शाहपुर, इस्माइलपुर, नौगछिया, रंगरा चौक, बरहिया, सूर्यगरहा, बिस्फी, जयनगर, लखनौर, फुलपरास, विभूतिपुर, मोहनपुर, पूसा, ताजपुर (30)	कंचनपुर, पौठू, टेंगर, वार, चेई नवादा, घोरीडीहरी, खीरीआवन, पीरवान, बरूना, चासी, नारायणपुर, पोसवा, पावना, गोदढ़ रूद्रनगर, ओसई, रानीसागर, तियार, भरौली, बिलौटी, गौरा, ईश्वरपुरा, परसौदा, शहजौली, इस्माइलपुर पूर्वी बिहटा, परबत्ता, ढोलबज्जा, नगरा, टिटरी, बैसी जहांगीरपुर, रंगरा, टींटन दियरा दक्षिण डुमरी, गंगासराय, खुटवा पूर्व, अरमा, चंदनपुरा, कसवा, खबराजपुर, मदनपुर, रामपुर, सलेमपुर पूर्व, ताजपुर बेलही, चहटा पूर्व, उत्तर खैरीवंका, उत्तरी नेहस रूपाली, दक्षिणी नेहास रूपौली, उत्तरी परसौनी, रथौस, सदुल्लापुर, पूर्वी बेलही, दक्षिण बेलहा, डोरवार , जयनगर बस्ती, कोरहिया, बलिया, कैथनिया, पूर्वी लखनौर, मैवी दक्षिण बेहत, बथनाहा, सैनी, सुगापट्टी, धनौजा, बिभूतिपुर पूर्व, चखाबीब, दक्षिण खास तभका, महिषी, दक्षिण महती, नरहन, सखमोहन, सिंहया बुजुर्ग उत्तर, तभका, बघरा, बिशनपुर बेरी, दक्षिण डुमरी, बिशनपुर बथुआ, चकलेवैनी, मोहम्मदपुर देवपर, थहरा, माधोपुरदिगरूआ, मुरादपुर बंगरा, रहीमबाद, रामपुर महेशपुर, शाहपुर बेधौनी (138)
5.	छत्तीसगढ़	कोरबा, दुर्ग, रापुर, सरगुजा, बस्तर (पांच)	कोरबा, पाली, गुंदरदेही, संजरी बालोद, छुरा, धरसिवा, फिगेश्वर, अंबिकापुर, लुंद्रा, मैनपात, रामचंद्रपुर, जगदलपुर, बकवंद (13)	अरसेना, बरपली, भेषमा, देवरमल, दोंदरो, जंबहर, मदनपुर, फुलसरी, सोलवा, तिलकेजा, खोतगांव, बकसही, चोढ़ा, धौराबंथा, कर्तली, मदनपुर, मंगमर, खैरदुबन, पटपरा, सेन्द्रीपल, सिरली दुदिया, कंदुल, खार्रा, खुरसुल, खोतगांव, खोतगांव, लिमोडा, महद, नहादा, परसदा पेंडारी, दरबारी नवागांव, हीरापुर, जगन्नाथपुर, खापरी, कोहनागटोला, निपानी, पर्रेगुदा, सकरा (जे), संकरा (के), तमोरा, अमेठी, देवरी, गदाघाट, गपादबरी, कड़कड़, खैरझिटी, लोहाझर, पेपरहाट्टा, रजनकट्टा, सोरीखुर्द, बहेसर, बनारसी, चरोदा, चिखाली, देवरी (अकोली), धरसोवा, दुमा, मनबस्ती, मनोहरा, दौंदेखुर्द, चौबेबंधा, कोपरा, कोसमखुटा, लचकेड़ा, लफंडी, पेरतेबा, पोखरा, रवेली, सेमहरतरा, सिधोरी, बकिरमा, चैताबाहर, कर्जी, माणिक प्रकाशपुर, मेंदरा खुर्द, नवपरकला, नवपरखुर्द, फतेहपुर, पोंडीकला, थोर, बांका कला, बारडीह, बर्गीडीह, डकाई, गंगोरी, जामडीह, लालमाटी, पडुली, सहांपुर, समेरपुर, बंदना, कमलेश्वरपुर, कटकल, कोत्कल, कुनिया, पैगा, पेडपतिया, समनिया, उदमकिला, दिंदो, दोलंगी, केवली, कृष्णनगर, नगरा, औरंगा, पलगी, पुरंधी, सनवल, तलकेश्वरपुर, हल्बकचोरा, चोखवड़ा, नगरनार, मदपाल, कुरंडी, अडवाल, धनपुंगी, बम्हनी, धुरगुदा, आमगुदा, झाडुगांव, सरगीपल, चिउरगांव, कर्पावंद, साओतपुर, बदलवंद, मूली, कावदावंद, किंजोली, राजनगर (129)
6.	गोवा	उत्तरी गोवा, दक्षिण गोवा (दो)	बिचोलिया, सत्तारी, कानाकोना, सेलसेट (चार)	लतम्बरसेम, मथेन-वैग्युनिम, मूलगांव, नारोआ, ओन मौलिग्नम, कोटरम, गुलेली, होंडा, पोरियम, कोला, पोइगुनिम, श्रीस्थल, एक्यूम-बैक्सो, कमरलीम, काना-बनौलिम, चंदोर, ड्रामापुर, लौटोलिम, मकजाना, नवलिम, वार्सा (22)
7.	गुजरात	आणंद, बनसकंठा, दाहोद, सूरत, बडोदरा, जूनागढ़, सुरेन्द्रनगर (सात)	आणंद, तारापुर, दांतवाड़ा, दीसा, पालनपुर, जालोद, लिमखेड़ा, संखेड़ा, कर्जन, दभोई, मंडवी, कमरेजj, भेसन, जूनागढ़, केसेद, चोटिला, सायला (17)	गमड़ी, जोड, कुंजराव, लभावेल, मेधवा गाना, रजुपुरा, रावलपुरा, सदनपुरा, वादोद, बलसन, आमिलिवारा, भंडेराज, बुधेज, इसनपुर, खाडा, खकसर, मोभा, मोराज, मोटाकालोदरा, अखोली, भखरमोती, भखरनानी, भंडोतरा, दांगिया, नंदोत्रा (बी.वी.), रामसिदा, सतसन, शेरगाध (ओ), वेलवास, भद्रा, दामा, धनपुरा, कांट, कुछवड़ा, लखनी, मनकपुरा, नेस्दा जुना, नेरदा नावा, ओधावा, देलावादा, कनोदर, लुनावा, मदाना (दंगिया), मोरिया, पतोसन, रामपुरा (कर्जा), रनवस, सेद्रासन, सेमोद्रा, अंवरपुरा, बोरसद, (चकलिया), दंतगढ़ (चकलिया), डुंगरी, गरादू, गुल्तोरा, हदमत खुंता, महदी, प्रतरपुरा, सरमरिया, अगरा (आर), बर्गोता, डुंगरी, कुंधा, लुखवाड़ा, मंदेर (आर.), मंगलमहदी, नाना अंबलिया, पल्ली, पिपलिया (आर.), अब्रामा, भादा, डुंगर, डुंगरा, कमरेज, कर्जन, कोस्मादा, कोस्मादी, नवीपर्दी, उंभेल, चोराम्बा, अरेथ, पूना, तरसदबर, सर्कुई, सलैया,

				बोरी, कलमकुआ, लखगम, नंदपुर, असोदोरा, भिलापुर, धोलार,करमल नादा, सथोड़, सिमलिया, सिरोला, तर्शाना, वनदरा, अभरा, फतेपुर, हटदर्वा, कोठिया, संदरना, सनियाद, संसरोद, सरिंग, सिमली, उमज, फलेपुर, मोदासर, पदवां, रतनपुर (के), रतनपुर (थ), सगवा, संखेदा, टिंबा, वनियाद्री, वस्ना, धोदवा, हदमीतिया विशन, चडाका, मैंदापारा/दुधादा, सततपाड़ा, करिया, खम्बलिया, धरीगुंदादी नवी, पिलिया तड़का पाटला पतवद, बिल्खा, चोकी, चोखदी, डुंगरपुर, इवनगर, खडिया, मजेवदी, नवगम, पलस्वा, पदरिया, बमंसा, भाट सिमरोली, चार, कनेरी, केवद्रा, खामिदाना, खिरसरा, मेस्वान, प्रांस्ली, रंगपुर, भीमगढ़, चोबारी, गुंडा जीवापर (आनंदपुर), कलासर, खखरवली, मोती मोलदी, नालियेरी, वडाली, जिंजुदा, छड़ियाली, धजला, धतरासला, गरमभड़ी, हदला, करदी, लिंबला,मोटा शाखपर, समतपर, विडिया (170)
8.	हरियाणा	करनाल, पंचकुला, सोनीपत, हिसार, महेन्द्रगढ़, पलवल (छः)	घरौंदा, निलोखड़ी, मोरनी, रायपुरानी, सोनीपत, मुंडलाना, हिसार-II, हांसी-II, उक्लाना, नारनौल, कनिना, पलवल, हथिन (13)	बल्हारा, गढ़ी भरल, बस्तरा, मलिकपुर, पनोरी, लालूपुरा, देरा संजय नगर, पीर बरोली, चौरा खालसा, मुंडीगढ़ी, डबरथला, सोहलोन, रायपुर रोशन, लल्यानी, जट्टपुरा, ख्वाजा अहमदपुर, दया नगर, पस्तना, सुल्तानपुर, दादुपुर, भोज पोंटा, दुदगढ़, बलदवाला, भोज जब्याल, थंदोग भोज टिपरा, थर्वा, बेहबलपुर, टबर, हरयोली, फिरोजपुर, मंडलई,गढ़ी खोटा, सुलतानपुर, मासूमपुर, मीरपुर, भटगांव, डुंगरान, जैनपुर, टिकोला, संदल कला, बदवस्नी, जाजी, मोहना, नगल खुर्द, देवरू, घड़ी हकीकत, मतंद, महमूदपुर मान, जवाहर, चतेहरा, मुंडलाना, धुराना, सिवांका, कोहला, हसनगढ़, इशापुर खेड़ी, सिस्वाला, बंदाहेड़ी, चौधरी वास कलवास, देवान, गवर, गोर्छी, बसरा, लुदास, मदर, शयम, बदला, थुराना, जीतपुरा, खंडा खेरी, उलगन, बस्स खुर्द बिजन, चितौन, कल्लेर मैनी, खैरी, लितानी, पब्रा, सनियाना, उक्लाना गांव, उक्लाना मंडी, धारसू, बस्कीरा रोड़, खोदमा, मोहम्द हमीदपुर, चिंदलिया, घटशेर, बमनवास, पत्तीकारा, थाना, नरहेरी, मोहस्नपुर, चेलावास, गहरा, भोजवास, बवनिया, झगरोली, मोरी, झिगवान, कक्राला, मुदायन, थंत्री, रसूलपुर, पृथाला, अलावलपुर, राजपुरा, जोहर खेडा, सुजवरी, घुघेरा, किसोरपुर, धातिर, मलई, हंचपुरी कला,गुरकसर, खोकियाका, मलुका, मदनाका, जरारी, धुरेंची, छैंरना, खेडली जीता (120)
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला, सिरमौर, हमीरपुर, लाहौल एवं स्पीती (चार)	नाहन, राजगढ़, चोपल, रोहरू, भोरंज, नदांऊ, किलोंग, काजा (आठ)	नाहन, नवीना, पल्लिओन, पन्नार, कथाशितला, बग्गर, बनेठी, चखली, कला अम्ब, किथारी, शाया सनौरा, कथली भरण, शिल्लंजी, टिक्कर, शलना, दिब्बर, भणत, बोहल तालिया, छोग ताली, बंडल कफला, बिज्मल, गौर्ली मरोग, झीणा, जुब्बली, जुरू शिलल, जोरना, मलत, नेरवा, धरोच, भम्नोली, भालून, बश्ला, हंसतरी, जगोथी, पुजारली-4, शील, टिक्कर, धलगांव, ब्रसली, करोहटा, नंदन, झर्लोग, कर्हा, संधरियां, अघर, अमरोह, धमरोल, गर्सर, बहंवीन, सपरोह, रंगस, ग्वालपवर, कश्मीर, मंघेली, गोऐस, बारा, बसरल, धनता, गहली, किलौंग, कर्दग, खंग्सर, मूलिता, मूरिंग, तंडी, शकोली, शंशा, धंकर, किब्बर, कुंगरी, सग्नम (71)
10.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू, बंदगम, कुलगम, पूंछ, राम्बन, कारगिल (छः)	अखनूर, मार्ह, बी.के. पोरा, खानसाहिब, पहलू, डी.एच.पोरा, सुरनकोहे, बलाकोटे, शकर चिक्तन, द्रास, बनीहाल, रामसू (12)	भलवल ब्रह्माना, भरदा कलां, चक किर्पालपुर, चौकी, धना जलारा, धोकजावीर,गुरा जागीर, कनेरी, क्वीयर, तर्गवाल, गजंसू, गंगो चक, गोल गुजराल, हलका, जस्वन, कल्याणपुर, मार्ह, पंजोर, दंगरपुरा, धरमबघ, कलिदर, केनिहानया, क्रालप्रा ए, कुथीपरा, पहरू ए, वदीपोरा, चेकशेरा, चिल्ल, दृगम, फचिल्ल,गुंद अली नायक, हर्दुपंजू, हरीवनी, खोसपोरा, कुमरू, वगेर,चंबगुंद, दर्दगुंद, लैसू, लम्मेर बी (हल्लन), पहलू, बदीझल्लन, बंगीवर्द, चिमार बी, डी.एच. पोरा ए डी.के.मार्ग बी, ड्रेग्डन, के.बी.पोरा बी, लोगोपोरा, रेंगीथ यर्खाबी, गुंथल, लोवर, गुंथलअपर, हरी बुद्ध अपर, हरी अपर,

				कलई, कल्लर कत्तल, लथूंग, मल्हन, पम्रोते, संगला लोवर, नकमजारी लोवर, धर्गलून लोवर, धर्गलून मध्य, कल्लर मोहरा, नकमजारी अपर, बोध कर्बू कुकशो, संजक, होल्लियल, कल्सर, मुश्कू, थरगम, चमलवास लोवर, बी. चंजलू, धूमीगम अपर ए, धूलिगम अपर बी, गुंदादिल्कोट ए, क्रवा, महू अपर, भोर्दर बी, धनमस्ता, फग्मुला होचक, खारी अपर बी, खारी लोवर, मलीगाम बी, नील पोगल अपर, सुजीमथाना (90)
11.	झारखंड	देवघर, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, रांची, गढ़वा, पलामू (छः)	देवघर, मधुपुर, गोड्डा सदर, ठाकुरगंग्ती, घाटशिला, गोराबंदा मंदार, नगरी, नामकुम, रातू, चिनिया, दंदई, गढ़वा सदर, नगर उंतरी, बिशरामपुर, चैनपुर, मोदिनी नगर, सदर लेरलीगंज (18)	बंसवडिलया, चितोलोढ़िया, गौरीपुर, कर्नीबाग, खोरीपनन, कोकरीबेक, मणिकपुर, नवाडीह, पिचरीबाद, धमनी, गरिया, जमुनी, मिस्राना, सप्तार, सिकटिया, बंका घाट, पहाड़पुर, घोरसंदा, जमनी पहाड़पुर, मोतिया, नूनबत्ता, पैरडीट, पंडाल, सैदापुर, बनियाडीट, चप्री, माल मंद्रो, फुलवाडिया, तेतरिया माल, बंकी, बरजूरी, भदुआ, घाटशिला, झंतीझरना, मौभंदर (पश्चिम), पावड़ा, अंगरपाड़ा, फारेस्ट ब्लॉक, बंझिला, महुआजरी, मंदरो, मूर्मा, सर्वा, टिगोरयांबतोली, बलालोंग, चिप्रा, देवरी, सपरोम, हहप, हर्दग, कुटियातु, लाली, लल्लखटंगा, रजौलातू, सोदाग, बाजपुर, हरहरी, पाली, रातु पूर्व, बेट्टा, चिनिया, डंडाई, झोटर, सोनीहारा, अचला, बीरबंधा, चिरौंजिया, दुबे मर्हटिया, महुलिया, ओबरा, रांका, गर्बधं, हलीवंता कला, कोलिझिकी, कुंबा खुर्द, नगर उंतारी, विसरामपुर, डंडला कलां, गुड़ी, टोलरा, उर्सला, बंदुआ, बेदमा बभनडीह, चैनपुर, महगवान, मझीगवान, नरसिंह पलास, नेऊरा, पतरिया खुर्द, रामगढ़, साहपुर (उत्तर), उत्तर बड़ाटोला, जोन्न , पोखराहाखुर्द, पोल्पोल्कला, दक्षिण रेदमा, हरतुआ, कुरैन पतारा, नौडिहा, पुर्णाडीह, रझारा (102)
12.	कर्नाटक	चिकमंगलूर, मंडया, चित्रदुर्गा, रामनगर, धारवाड़, गदग, गलुवर्गा, कोप्पला (आठ)	चिकमंगलूर, श्रृंगेरी, पंडवापुरा, श्रीरंगपट्टन, चित्रदुर्गा, मलकलमुरू, चन्नपट्टन, रामनगर, हुबली, कुंदगोल, गदग, नरगुंद, अफजलपुर, सेदम, गंगवधी, कोप्पल (16)	बेलगट्टा, चोलगट्टा, हीरेगुंटानूर, जनकोंडा, कलागेरे, कुनाबेवु, मदनयकनहल्ली, मेदेहल्ली, तुरूवनूर, यलगोदु, चिक्केरहल्ली ,कोनसागर, नेरनाहल्ली, अशोक सीद्दापुरा, तुमाकुर्लहल्ली, बनगा हल्ली, हरोकोदा, कोदाम्बल्ली, मलुरपतन, माट्टीकेरे, नीलासंद्रा, सोगला, सुल्लेरी, विरूपक्षीपुरा, येले थोतादहल्ली, बन्नीकूप्पे (के), दोद्दागंगवदी, हुलीकेरे, गुन्नूर, कैलांचा, कैंचनकुप्पे, मनचनयकना हल्ली, विभुतिकेरे, अंचतगेरी, छबी, हेबसुर, कोसीवाड़, रयनल, वरूर, बु. तर्लागत्ती, हीरेगुंजल, हीरेनर्थी, मलाली, रमनकोप्पा, शिरूर, येलीवाला, अदावीसोमापुर, असुंदी, बिंकादाकत्ती, येलिशिरूर, हुलाकोती, कुर्ताकोती, लक्कुंदी, सोरातुर, भीरानाहत्ती, हीरेकोप्पा, शिरोल, वासन, अनुर, भीरामदगी, चौदापुर, हसरगुंदगी, कर्जगी, मन्नूर,उद्चना, दुग्नूर, कनगद्दा, कुक्कुंदा, मल्खेडा, मोटकपल्ली, नीलहल्ली, यूद्गी, बेन्नूर, चिक्कमंडीनल, हेरूर, करादोना, करतगी, मरलनहल्ली, संगपुरा, सिद्दापुर, वेंकटगिरि, येरादोना, बंदीहर्लापुर, चिककबोम्मनल, हलगेरी, होसाल्ली, इंदरागी, कथर्की गुदलानुर, कोलुर, कुनीक्रेरी, ओजानहेल्ली, शिवपुर, अयुथी, दसरहल्ली, हीरेगौजा, कातिकेरे, कुदुवल्ली, मचेनहल्ली, मूगथीहल्ली, मुगुलावल्ली, थोगरीहुंकल, वस्थारे, अद्दागद्दे, नेम्मारू, विद्यारनयपुरा, बन्ननगदी, दोद्दाब्यादरहल्ली, हरवू, के वेट्टाहल्ली, कनगनमरदी, कतेरी, मनीकाना हल्ली, टी.एस. चतरा, बल्लेकेरे, दरसगुप्पे, हुल्लेकेरे, कोदियाला, मेलापुरा, पलहल्ली, थदगवदी (119)
13.	केरल	तिरूवनंतपुरम, अलप्पपुझा, मलप्पुरम, वयनद (चार)	अथियान्नूर, नेदुमंगद, वमनपुरम, हरीप्पद, मुथुकुलम, चंपाकुलम, मननतवदी, सुल्तान बतेरी, मंकदा, पेरूंपदप्पु, वंदूर (11)	कोत्तुकल, वेनगनूर, अरूवीक्करा, पनवूर, कल्लारा, नन्नीयोदे, पेरीगंमला, चेरूथना, करूवत्ता, त्रिक्कुन्नपुझा, चिंगोली, देवीकुलंगर, मुथुकलम, कैनाकरी, थकझी, योंदरनाडु, थिरून्वेल्ली, अम्बलवयल, सुल्तान बतरी, कूट्टीलंगदी, मंकदा, नन्नम्मुक्कु, वेलियांकोद, मंबद, पोरूर (25)

14.	मध्य प्रदेश	बालाघाट, बदवानी घर, दिंदोरी, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंडला, नरसिंहपुर, रैसेन, राजगढ़, शजापुर, उज्जैन (13)	बैहर, किरनपुर, बदवानी, सिंधवा, निसारपुर, सरदारपुर, दिंदोरी मेहदवनी, पानागर, पाटन, बहोरीबन्द, रीथी, हरसूद, खालवा, मंडला, निवास, गोटेगांव, करेली, सिलवानी, उदयपुरा, बइओरा, खिलचीपुर, अगर, नालखेडा, खचरोद, महीदपुर (26)	भलपुरी, कटंगी, लहंगकंटर, नवही, मेंडकी, कुगांव, जट्टा (आर.वाई.टी.), करवही, जैतपुरी (एफ), बिरवा, पिपलगांव, दहेगवदा, सेओनी, कोकना, कोस्ते, जन्वा, वारा, पोनी, मंगोली खुर्द, कोसामारा, भुराकुवा, सज्वनीखम, तलुंखुर्द, गोधन्या, सौंदुल, बेगलगांव, हन्नई, सजवनी, अम्ल्यापनी, सुस्तीखेदा, धवदी, हिंग्वा, हिंडली, कुमथाना, चिखली (श.), अंबवतर, किदियांबा, रजोनीमल (वंग्रम), कलदा, कमोद (च.), नवदपुरा, निसारपुर, कोथड़ा, अंबदा, दोगाव, बेदबल्या, खरजना, देशवल्या, भवरिया, सिसगांव, चलनी, हनुमन्तपदम पुरा, जलोना, बोला, सलवा, भेरूपदा, अमलिया, मोरगांव, उंडेली, अमझेरा, कैलवारा, पदरियामल, विदयपुर, केओलरी, सरंगपुर्पदरिया, अनखेडा, वटोंधा, नूनखन आर.वाई.टी, कनै संगव, बर्गई, बुलदमाला, मटयारी, कंहारी, भानपुर, झरगुदा, राधोपुर, हौबिसमाल, दुल्हारी, पयली, सर्सीमाल, बिल्पुरा, धरहर, खेरी, तिवारीखेड़ा, उरदावकाला, अमहानदुआ, पदरी, रिचाई, नगना, किवलारी, पौंदी (उड़ाना), बौंरिया, कैधारा, रामखिरिया, मेदही, ककडखेड़ा, थाणा, जुरीकला, मिलौदी, पौड़ी (चपरी), जुझारी, बरही, गौराह, पथरूदी (पीप), भेड़ा सलया (कुवा), सिहूदी बकल, किवलही, सलाया पियाशी, मोहत्रा, थनोरा, धनिया,नितरा, दांग/डोरा, बिरूहली, तिधाराखुर्दा, खेरा, पटोहा, धुगरा, भरतपुर, मोगल रैयत, पलनी मल, दो तखेदा रैयत, सेमल्या (एफ.वी.) पडल्या मल धावर्दी, मदनी, मीरपुर, खेड़ी, तिमरनी, तिगरिया, झिर्पा, जमुनिया आशापुर, फूलसागर, चतुओमर, मनदई, बनियातरा, पटपरसिंगारपुर, देवगांव, धुचरा, सल्हेदंदा, मोहगावचक, टिकरिया, मोहगांव, बहमनी मल, गुंडलई मल, कंजई, खोबी, सोंतश्वर, बेलखेदी मुआर, मेख, डोन, मगर्धा, नदिया,कुसिवाड़ा, बुधगांव, अमगांव बड़ा,रितकरर (कलां), जोवा, मचर्मो, बलनी, रामपुरा, बसदेही, कोदसा, सौताला, कंधरापुर, सम्नापुर,किनालपुर, पदरियाखुर्द, सेमराखस, उमरझिर, निगारी,अम्मवन,सिंगपुरी, उचेरा, सिमरिया खुर्द, डबरी,रेहली, बुधवदा, चौरस, गोर्धनपुरा, जेलपा, अगर, सलरिया खेड़ी, पडली गुसाई, बोर्दा, बदरी, कछोटिया, सतनखेड़ी, धमनिया (जोगी, छिपीपुरा, गोपालपुरा, बवदीखेडा, विसनिया, हिम्मतपुरा, नटराम, निपनियाबजनाथ, खकरी, गुंडीकलां, चचाखेडी, पचेती,नन्याखोदिहिर, चिकलीगोयल,पिपोली कलां, शिपगढ़, लदंवा, गुदरावन, धरोला, दमदम, कोहदिया, सिया, दपत्पुर, लसुदलियाकेल्वा, गुजरखेड़ी, बेर्चाखेडी, हतई, बिल्वनहया, बेदवां, बोर्खेदापितरामल, चपनेर, कनवस, चंदनवस्ला, बोर्दिया, दिवेल, झिरमिरा, नारायण खेडी, लसुदियांमसूर, कजीखेडी, लसुदियानहाटा, धनोलिया, आक्याजस्सा, झर्दा, नामखेडा, नल्सखेडा, धटियासैदस (260)
15.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, सोलापुर, बीद, नांदेड़, भंडारा, गोदिया, रत्नागिरि, ठाणे (आठ)	अकोला, रहटा, रहुरी, मधा, मलसीरस, बीद, पर्ली (वैजनाथ), अर्धापुर, हिमायतनगर, किंवत, भंडरा, लखंदपुर, गोरेगांव, सदक-अर्जुनी, चिपलुन, गुहगर, भिवंडी, कल्याण, शाहपुर (19)	पैथन, कलस बी.के., वीरगांव, धुमलवादी, तेरूंगन, वाकी, हीवरगांव, जचकवदी करंदी, रेडे, भगवती, कोल्हार, रंजनखोल, खंडकेवके, अदगांव, खुर्द पिपरी निर्मल, लोनी बी.के. रामपुरवदी, शिंगवे, तिस्गांव, बकलेश्वर, अमलनेर, लाख, बड़गांव नंदुर, ब्रहानी, पिंपलगांव, फुगीन, केसापुर, करजगांव, धमोरी बी.के. घोर्पदवड़ी, बोधिगांव, रनदीवेवदी, सोलांकरवदी, तुलसी, वडोली, बवी, खैरव, पिंपलखुटे, रंजनी, शिंदेवडी, फुटजावलगांव, मलशिरस, उम्बरे (बेलापुर), गोरदवदी, मांडवे, हनुमानवदी, दहीगांव, पुरनदवदे, धनोर, उम्बारे (दहीगांव), कोंदाभवी, कम्बी, सखरे बोरगांव, नागपुर (खु), वयबतवदी, लोनीघाट, अंधापुरी, पटोदा (बि), भटसंगवी, बालापुर, वारवती, तपोवन, हलम, सरफराजपुर, असवलंबा, भीलेगांव, दैथन (घाट), मंडेखेल, बदगांव, पंगरी, नथरा, अमराबादतंदा,देगांव (कु.),

				येदेगांव, खैरगांव, लोनी (बु), चेनापुर, पिंपलगांव, स्याहपुर, बमनी, शंगवी (खु.) दीघी, वतकली, सोनरी, कंडली ख., परा धारापुर, मंगरूल, सवना (जे.), कर्ला (पी.), दबदरी, भीषी, कंकी तंदा, मारेगांव ख., अप्पाराव, पेथ, धमनदारी, राजगढ़ तंदा, पारसराम नायक, तंदा, पंगरी, कनकवदी, बोधादी बी.के., दोदमजरी, मंदनगांव, बेरोदी, अम्बदी, वकेश्वर, सीरसघाट, मोहादुरा, थाणा, पीपरी, चिखली, दंबोविरेल्ली, पींपलगांव, सखरा, कुदेगांव, मुरमदी, लखदुर, सोनेगांव, पेंधारी, किर्माती, मुर्जा, पुरगांव, भदंगा कटंगी (बी), महासगांव, तिमेजरी, दाब्बा, गोंदेखारी, शहरवनी, कवलेवडा, चिल्हाती, रेंगेपर (पी.ए.) बहमनी (एस) ,पुतली, बहमनी (ख) कोकना (जे.ए.) राजगुदा, पंधरवनी (आर.ई.) खदीपर, सौदद, डल्ली, पिलवली टी. वेल्म्ब, कोकरे, कान्हें, मंडकी ख., कपसल, नई कोल्केवदी, केतकी, मर्गतम्हाणे खुर्द, करमबगावने, कुतरे, वेल्दुर, पटपनहाले, धोपवे, जमसुद, चिखली, पोमेंदी, अटुर, पन-ती- ह्वेली, तलवली, अंबेरे, गुंदावली, सापे, नींबवली, दुधनी, पयगांव, अलीमगर, खोनी, खलिंग, राहूर, सोनले, आने भिसोल, दहीसर, धरीवली, गोलवली, कंबा, कोले, नदगांव, नरीवली, पलसोली, वरात रोलवली, साणे, वाफे, गोर्धघर, शिरगांव, वशला, चिरलगांव लाहे, शील, सकुर्ली, सकरबाद (190)
16.	मणिपुर	पूर्वी इंफाल, थोबेल, चुराचंदपुर, सेनापति (चार)	पूर्वी इंफाल-I, पूर्वी इंफाल-II, थोबल, ककचिंग, तुइबुआंग, सैकोट, तदुबी, सैतु-गंफजोल (आठ)	हैगंन, खुर्नी चिरंगबम, लैकई खुरई नन्देईबम, लैकई, नीलाकुथी, पुखाव, सवोंबुंग, तखेल, तेल्लोऊ, चन सैजंग अंगथा, चनम संदरोक, कैरव, कियांगेई मुस्लिम अरप्ती, क्षैत्रीगांव पार्ट-II, टॉप चिंगथा, टॉप दुसरा, तुमुखोंग मोयरंगपुरेल, वंगबल, चैरेल, हियांगलम, लंगमेइदोंग,पल्लेल, सेकमैजिन पार्ट-II, सपम, टेकचम, तेथा, वंगबल, चैरेल, हियंगलम, लेंगमेइदोंग, पल्लेल, सेकमैजिन, तुईबोंग, डी फैलेन, कमदोऊ वेंग, के मोंगजंग, बी.पैचम, डी. वैसन, माता लंबुलानं, एन बोलजंग, तुइनोम, जाओलेन, सैकोट, मौलवैफई, न्युर्ते, सैदन, सैपुम, एम. ल्हाहवोम, सेहकेन, थिंगचोम, टुडथपी, एम. सीमोल, मरम मथक, पुदुनमई, काटोमेई, खंबुग करोंग, सोंग सोंग, मरम खुलक्पा, कथिनु, लैरोचिंग, राजौबा, मखन सेन्टर, मोटबुंग, वैनम लौंगा कोइरेंग, लोइकोत, नखुजंग, कंगचुप मखोम, खेंगजंग, खोखेंग, मखन,पी.मोल्डिंग (69)
17.	मेघालय	पूर्वी खासी पहाड़ी, पश्चिमी खासी पहाड़ी, पूर्वी गारो पहाड़ी, पश्चिमी गोरा पहाड़ी (चार)	मावकीन्रेव, पीनुर्सला, मवशीन्रूत, मावकीर्वत, रेसुबेलपाड़ा, सोंगसक, दालू, टिकरी किल्ला (आठ)	उम्बलई, मीनसंग, मावजतप, मावलली, खपमाव, ख्वाद, जोंगक्षा, मिल्लत, नोंगशकेन, उर्कशेव वाहपथव, नोंगजरी एलाका, वाहखेन, नोंक्वाई, मदन शतसंगी, पोरीयू, अचेंग, पोर्ला नोंगतराई, नोनसींरंग, मावतीरोंग, रोंगतोक, नोंगकरोंग, नोंगशिरम रोंगबेंग, शलंग ए., मावथेंगकुत, मावरप, डोमतीरोंग, समसीर डोमतील्लंग, तिएहतलियर, मावकाबैत, नोंगबाह रोंगबलांग, मावलंग वीर, फोटजौद, रंगबलंग सोहसिर, फर्माहियांग, गेनंग रभा, न्यू कंटोलगुरी, कंटारगरे, कटोंगरे, बोरो मायापारा, रोंग्गोप्गरे, समकलकगरे, थैरिकाकोन गारो, माओमरी, दोबा अपल, दोबू अचकपेक, बिजासिक सोंगमा, बोलमोरम अदप, अकरोक, वागोपगरे, कोंचिकोल, दगल अगा, नपक अपल, गोंगरंग, रेंगसिपाड़ा, अनंगपाड़ा, पोस्सेंगागरे, दिंगकाजोरा, बारोंगपाड़ा, दालूगांव, रेंगरामपाड़ा, चोंगनापाड़ा, कोइनाभोई, चंदापाड़ा, दबांग्गेरे, रोनी असिम, अंदालसिकगरे, टिकरीकिल्ला, वाटरेगरे, बोरोबकरा, अप्पर दमचिगा, ओल्ड कलापाड़ा, चिनाराम्गरे, मेगापडा (74)

18.	मिजोरम	आईजोल, चंफई (दो)	टलांग्नुअम, ऐबावक, चंफई, खावजाल (चार)	लेंगपुई, लुंगलेंग-I, समत्लंग, सिहमुई, ऐबवक, चमरींग, फल्कवन, मुइफंग, हूआलगोहमुन, केल्सी, नाहलान, एन. खावबंग, नगुर, वपर, दिल्कौन, केल्कंग, खवजौल-I, खावजौल-II, खावजौल-III, खावजौल-IV खावजौल-V मेलवुक, मुअल्कवी, तुइपुई, जोखावतर (25)
19.	नागालैण्ड	मोन, कोहिमा, दीमापुर (तीन)	तोबु, तिजीत, कोहिमा, चिएफोबोझौ, मेदिजफेमा, कुहुबोटो (छः)	बुमई, चंगलो, चंगलांगशु, तोबु, मानेयाक्शु, पेसाओ, शामन्यू, शेन्नयू, तम्कोंग योंगखाओ, लोआखों, लौखुन, लोंगलेम, लोंगतिंग, नेइतोंग, म्यांगटींग, जबोका, तेला, यंपन, तिजीट गांव, चैदमा मांडल, दजुलाकेमा, जोत्सोमा, खोनोमा, किरूफेमा बावे, कोहिमा गांव, मेंगुजौमा, मेजोमा, सेचुमा, सेचुमा (जुब्जा), नेरहेमा, नेरहेमा मॉडल, फेकेक्रीएमा बासा, सियहा फेसा, सैहमा तेयचुमा, त्सेईमेखुमा बावे, त्सेईसेमा बसा, टोउफे फेजौ, जैजो, अओ कशीराम, चेकिये, दारोगजन, दारोपथर, दीफुफर बी, काशीराम, नागायूनाइटेड, सामगुरी, सिर्हिमा, तोलुवी, हेनिवी, हेवीशे, एल होतोवी, नीहितो, ओल्ड शौबुआ, एस. होतोवी, सुहोई, तोकुघा, जेकिये, जेल्होझे (60)
20.	ओड़िशा	कटक, खुर्दा, गंजम, बालासोर, देवघर, नुआपाडा, संबलपुर, सुंदरगढ़ (आठ)	नियाली, सालेपुर, बरंग, जतनी, बोलागढ़, कबीसूर्यनगर, हिंजिलीकट, दीगापहंदी, चिकिती, नीलागिरि, रेमुना, बरकोटे, तिलेईबानी, कोमना, सीनपली, जमनकीरा, धनकौदा, राजगंगपुर, लहुनीपाड़ा, बरगांव (20)	जल्लरपुर, पहंगा, कृष्णाप्रसाद, पोखरीगांव, रानीओला, रतनपुर, तिहुदी, बलीसही, पिकोल, नंदोल, चंपती, बरीगोल, कटरपा, चंद्रदेईपुर, ओडासिंह, सुधाखंडा, रैसुनगुदा, हरीअंता, नगरी, सैसो, बेलगछिया, कुरूंगप्रधान, बेनापंजारी, चनाघर, गंगपड़ा, कंटिया अरीकामा, बदकुमारी, दलाई साही, फसीओदा, गोपालपुर, खंगुरिया, बोरासिंगी, गुदियाली, पैकजमुना, रीषिपुर, सीयालिया, सुबालया, भाबंधा, दारूभद्र, दयापल्ली, नंदिका, पोचीलीमा, साहापुर, बदादुमुला, विजयलक्ष्मी नारायणपुर, पदमानवपुर, बसुदेवपुर, सहदेबतीकरापाडा, खमरीगाम, चसनीमखंडी, नुआपाड़ा, कंपा नुआगम, रामचंद्रपुर, चंदापुर, गिरिसोला, पिथहटा, मतियाली, भनुरीयाबाद, अरबंधा, साजनागढ़, बरहमपुर, गराडीही, छत्रपुर, गुदुदा, सेरगढ़ निजामपुर, सरस्वतीपुर, मंगलपुर, बिरूअन, महाराजपुर, गनीपुर, बमपरदा, दंदसिंधा, दनरा, कल्ला, कंधल, कौंसीवहल, मध्यपुर, बनियाकिलिंदा, कंसर, परपोसी, तैंसर, तिलैबनी, जटगढ़ , सुंदबेदा, पेंडरावन, मुंडपाला, कुरूमपुरी, बुधिकोमना, लखना, नंगलबोद, मखपदर, गोरला, नुआपाड़ा, निलजी, करणबहाली, कुसुमजोरे, टिकिबा, जमनकिरा, बदरमा, धुदीपली, सरदा, भोजपुर, संकर्मा, ए.कटपल्ली, बसंतपुर, कर्दोला, गदमुंदा, कुनमुरू, मलीडीही, बुचुकापाडा, जराईकेला, कलैपोश, शशिकेला, दलैसेरा, रजमुंदा, हल्दीकुदार, बरंगकोछर, भोईपाली, इतमा, सहज बहल (123)

21.	पंजाब	नवां शहर, एस.ए.एस. नगर, पटियाला, तरण तारन, मनसा मुक्तसर, (छः)	और, बंगा, डेराबस्सी, मजरी, नोभा, समाना भीखीविंद, तरण तारन, भीखी, झुनीर, गिद्देरबहा, मलौत (12)	औड़, बेगोवाल, भारो माजरा, गेहल मजरी, कहलोन, कमम, कंग, मिर्जापुर, शेखुपुर, तलवंदी, सिबु, अनोखखल, बहर मजरा, बहुआ, धहन, गुज्जरपुर खुर्द, हेओन, खोतरन, मालू पोटा, नगरा, संधवान, बटोली, बिजनपुर, दीरे माजरा, फतेहपुर, कसौली, खेल्लन, पंडवाला, रानी माजरा, तर्रक, त्रिवेदी कैंप, भूप नगर, बूथगढ़, फतेहपुर, फतेहपुर तपरन, मंजरी, मलकपुर, परौल, सलेमपुर कलां, रौखुपुरा, शियामीपुर, अकालगढ़, बनेरा कलां चस्वल, गुनिके, खेरी जत्तन, ललौदा, रान्नो, शम्शपुर, टोंडखल, रामगढ़ बी. एस.127, अस्सरपुर, बहमना, बूटा सिंह वाला, धैंथल, गजेवस, घंगरोली, कदराबाद, रामपुर पर्तन, सहजपुरा, खुर्द, उगोके, अबदी भगवान पुरा, बसर्के, बेगेपुर, चुंग, दोदे, कजीचक, कलसियन, खुर्द, खलरा, नरली, संदपुरा, बथ लकन, भुल्लर, झमल, खाम, झमल पुख्ता, ममंके खुर्द, मुस्से खुर्द, नूरपुर, पदरी खुर्द, रशियाना, स्वर्ग पुरी, अकलिया, अहला कलां, बीर खुर्द, बुर्ज झमर, जोगा, खीवा खुर्द, मट्टी, मौजी कलां, मोहर सिंह वाला,फाफरे भाई के, बाजेवाला,बुर्ज भलैके, चचोहर, दसौंदिया, कोएरवाला, माखे वाला, नंदगढ़ पेरोन, रायपुर, तंदिया, अमनगढ़, बटर बखुहा, बटर, शरियां, दुहेवाला, काओनी, कोठे दशमेरा नगर, कोठे हजुरे वाला, कोठे केसर सिंह वाला शैक, धरजवाला, अलमवाला, बोदीवाला, खड़क सिंह, बुर्ज सिधवां, चक उधम सिंह, जंद वाला चरत सिंह, खाने के ढाब, किंगरा, कोलियन्नवली, खरियान, सरवां बोदला (120)
22.	राजस्थान	बीकानेर, पाली, भिलवाड़ा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, सिकर, बूंदी, करूली (आठ)	बीकानेर, दूनगढ़, बाली, जैतरन, असिंद, जहाजपुर, बदगांव, गिरवा, अनूपगढ़, घदसना, दाता रामगढ़, धोढ, बूंदी, हिंडोली, हिंदाअन, करौली, (16)	अम्बसर, जलवली, कटरियासर, किल्छू, देवदन, कोलासर, ललमदेसर, नोरंग देसर, रमसर, रिदमलसर पुरोहितन, अदसर, बीग्गा, दुसर्ना पंडरीकजी, कितासर भटिया, रीरी, शेरूना, सोनियासर मिथिया, उपनी, अमलिया, भीमणा, दूदनी, कूरन, कोतबलियां, कोठार, माल्नू, मुंदारा, नाना, शिवतलाव, अगेवा, बेर कलां, दीगरना, कनेचा रणवतन, कनवलिया कलां, केकिनदारा, निमज, पिपलिया खुर्द, फूलमल, टूंकरा, अकर्सदा, बोरेला, गंगलस, कलियास, कंबलास, कर्जलिया, नीमबहेरा, परसोली, पटन, तितोली, अमलदा, बेई, ढोर, गुढ़ा, इंतुंदा, जमोली, पंदेर, रावत खेडा, रोपन, ऊंचा, अंबेरी, धर, कदिया, कदमल, कैलाशपुरी, लखवली, लोयरा, मदर, अलसीगढ़ भसेरा, कलां, चंस्दा, जगत जवर, कलखास, मतून, परमदा, सकरोदा, वली, 1 एल.एम.एम. (बंदाकलोनी), 2 जी.बी.-ए, 28 जी.बी., 4 बी.एल.डी., 42 जी.बी., 48 जी.बी. (रेडबग्गी), 65, पी.बी., 72 जी.बी. 78 जी.बी., 4 के.एस. (बंदा) (सिरजसर), 1 एम.एल.के.सी, 13 डी.ओ.एल. 19 जी.डी., 2 एम.एल.डी.-ए, 20 एल.एम., 22 आर.जे.डी. 5 पी.एस.डी. 6 जेड.डब्ल्यू.एम., 7 के.एन.डी., 2 आर.के.एम., अलोदा, दसरोली, गनोरी, खंडेलसर, खाटू श्यामजी, खूड, मंडा (सुरेरा), मुदियावस, पचर, सुरेरा, ऊनोखू, ढोद, जर्ठी, कुदान, लोसल हवेटी, मंडवासस, 9पेपा, रसीदपुरा, संवलोदापुरोफितन, सिंगरावत, अजेता, धनतरी, गुमामपुरा, कलपुडिया, खटकर, मतूंदा, नयागांव, नीम का खेड़ा, उलेरा, अकोदा, छतरगंज, दतूंगा, हिडोली, कछोला, खीन्या, पगरा, रोनीजा, रोसंदा, विजयगढ़, अलीपुरा, गवनरी, जतवड़ा, खेड़ा, खेर्ली, गूजर, क्यर्दा खुर्द,पालनपुर, रेवई, शेरपुर, वई जत्त, अटेवा, गुर्ला, कर्सई, कोटा (एम), कोटा छबर, लौहरा, परीता, रामपुर, रतियापुरा, तुलसीपुरा (155)
23.	तमिलनाडु	कुड्डालोर, त्रिचिरापल्ली,	उप्पिलियापुरम, तिरूवेंबुर, तुरैयुर, कट्टुमन्नारकोयल, विरूधाचलम,	अलगपुरी, वैरीचेत्तिपलयम, वेंकटाचलपुरम, थलुगई, सोबनापुरम, नटराजपुरम, कुवलकुडी, किलियुर, कंथालुर, सुरियर, नवलपट्टू, टी. रैंगमांदपुरम, कीरंबुर, कन्नुर, मरूवथुर, वेंगटेसपुरम, नगलपुरम, नरसिंगपुरम,

		कांचीपुरम, तिरूवन्नमलई, रामनाथपुरम, तुतीकोरिन, नीलगिरी, तिरूपुर (आठ)	कम्मपुरम, कट्टंलातुर, उथिरमेरूर, कुनराथुर, वेंबक्कम, पेरानमल्लुर, तिरूवन्नमलाई, तेल्लर, रामनाथपुरम, मंदपम, तिरूचेदुर, श्रीवैकुंदम, कोठागिरि, कूनुर, तिरूप्पुर, पल्लदम, मूलानुर (22)	सोक्कानदपुरम, सैल्लीपलपम, मदुरापुरी, मेलपुलियांकुडी, इंचांपूंदी, रेद्दीयुर, कोल्लुमेदु, अयंगुडी, कुरूंगुडी, तीतमपट्टु, करूणकरनाल्लुर, चेतीथंगल, श्रीयाधीवरगनाल्लुर, नरूमनन, वीसालूर, सेंबलकुरीची, वेन्नकुडिकडु, सथुकुदल मेलपथी, एम. पत्ती, तोत्तीकुप्पम, करूवेपीलनकुरीची, अलादीख् कुप्पनाथम, यू. मंगलम, सी. कीरानूर, मरूगुर, देवनगुडी, वदक्कु वेल्लोर, इरूप्पुकुरीची, मेलपथी, वी.कुमारमंगलम, कोल्लीरूप्पु, टी. पवनझंगुदी, वीरापुरम, वल्लम, पेरियापोथेरी, अप्पुर, कुन्नावक्कम, उनामंचेरी, पेरूमत्तुनाल्लुर, करानैपुदुचेरी, तीम्मवरम, कलबोय, अन्नाधपुर, अम्मैयाप्पानाल्लुर, रवतनल्लुर, केलियांपूंदी, कवितंदलम, सलवक्कम, तिरूवनैकोइल, सिरूपिनायुर, पिनायुर, अदवपक्कम, एरूमैयुर, परानीपुतूर, कोलपक्कम, तंदलम, ओरातूर, सोमंगलम, कोल्लाचेरी, वरदराजपुरम, सेरापनंचेरी, नदुवीरापत्तू, पेरूनमंथंगल, मोरानम, सत्तूवंथगस, मूंजुरपत्तु, बदमनपक्कम, मांगल, उक्कंपेरूंपक्कम, नेमिली, कीलनयंपलम, अझिंजलपत्तु, मदम, मरक्कुनम, एरूंबुर, इमापुरम, नैंदुंगुनम, मेलानुर, सोलवरम, अनैबोगी, नायाणमंगलम, सेम्ममबदी, अननदल, सो. किल्नावुपत्तु, इसुकली कत्तेरी, सु. वलावेती, टी. वलावेती, बैरैयुर, पनैयुर, सु. पप्पांबदी, नचनंदल, सु. अंदापत्तु, मझैयुरकंदावराती, मीसानाल्लुर, सीयामंगलम, पोन्नूर, रामसमुद्रम, सथियावदी, मेलपथी, कुथमपत्तु, अरूनथोदु, देवीफ्तीनम, अथियुथु, चियरकोट्टई, अंचुदनवयल, नरनामंगलम, सक्कराक्कोत्ताई, इलामनूर, पुथैंधल, पनैकुलम, कुसवंकुदी, नोचियुरानी, पीराप्पंवलसै, कोरावल्ली, पुदुमदम, अलगंकुलम, मरैकपत्तीम, कयामोझी, वीरामनीक्कम, मेला पुदुक्कुडी, मारांगलम, सिरूतोंदनल्लुर, वलवल्लन, श्रीपरंगुसनल्लुर, मंजलनीरकयल, थोलाप्पन, पन्नई, मुक्कनी, पलयानकयल, उमरीकदु, केनगराई, नदुहट्टी, देनाद, हुब्बथलई, बेस्ती, एत्तीवीरंपलयम, मेर्कपथी, मुदालीपलयम, वल्लीपुरम, आरूमुथंपलयम, करदीववी, पूमालुर, सुक्कमपलयम, के. कृष्णपुरम, चितबलम, थुरंबदी, कुमारपलयम, एरासीनंपलयम, पेरामियम (168)
24.	त्रिपुरा	पश्चिमी त्रिपुरा, उत्तरी त्रिपुरा (दो)	विशालगढ़, जंपुईजला, खोवई, मंडवी, दस्दा, पानीसागर (छः)	अमतली, चंपामुरा, चंद्रनगर, गजरिया, कृष्ण किशोरनगर, मध्य लक्ष्मीबिल, पदमानगर, पथलिया, प्रभुरामपुर, रघुनाथपुर, अमरेंद्रनगर, गोलीरैबरी, कलैबरी, केन्दैचीरा, पेकुअर्जला, पूर्वा टकर्जला, उजन घनीयामारा, उजन पथलियाघाट, बराबिल, जंबुरा, लक्ष्मी नारायणपुर, पश्चिम छेबरी, पश्चिम गंकी, राधाचरण नगर, सेपैहौर, उत्तर सिंगीचीरा, अशीघोर, विश्रामबाड़ी, दक्षिण शिबनगर, दीबंधु नगर, काठीरामबड़ी, खम्थींगबाड़ी, पूर्व दीनबंधुनगर, आनंदसागर, दक्षिण लालजुरी, जमरैपाड़ा, मनू चैलेंग्ता, शांतिपुर, शिबनगर, सुभाषनगर, उत्तर दसदा, उत्तर तुईचमा, अग्निपासा, चंद्र हलम पाड़ा, दुपिरबोंद, हूपलोंग, नोआगंग, पश्चिम तिलथई, रामनगर, दक्षिण गंगानगर, तंगीबाड़ी जैथंग (52)
25.	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर, देवरिया, गोंडा, कुशीनगर, महराजगंज, वाराणसी, बदायूं,	सुमेरपुर, मौधा, मौरनीपुर, बंगरा, ऐरायन, हथगम, खजुहा, गोसाईगंज, माल, गजरौला, अमरोहा, कर्हाल, किशनी,	बरूआ, चंद्रपुरवा बुजुर्गा, इंगोहटा, मवैजर, मोराकंदेर, सीनमौदी, टेढ़ा, अमीर्ता, बरदाहा सहजना, कुंदौरा, अर्ता, भुलासी, बीगहना, एचौली, कम्हंरिया, लारौंध, लेवा, मदरपुर, पीपरोंधा, रोहरी, अक्सेव, बेरवई, भदरबारा, चुरारा, घडवा, खंडर्का, खकोरा, खराकमफ, स्यबनी खुर्द, मंडवा, मुहम्मदपुरगोटी, उमरपुर, गौती, नक्सरा, रसूलपुर, भंदरा, अफोई, बघौली, बहेरासदत, दयालपुर, कही, अब्दुल्लापुर, बदहा, बैगांव, इश्कपुर, केश्वपुर, मल्हैया,

		ज्योतिबा फुले नगर, मैनपुरी, मथुरा, रामपुर, हमीरपुर, झांसी, फतेहपुर, लखनऊ (15)	नौहझील, राया, अंबियापुर, मियाओं, वजीरगंज, मिलक, स्वार, अकबरपुर, टांडा, घुघली, लक्ष्मीपुर, हाटा, सेवरही, मोतीचक, भागलपुर, भटनी, सलेमपुर, छपिया, झंझारी, तरब गंज, पींडरा, अराजीलाइंस (35)	किशोयी, कोटला, पत्तीशाह, सिथौरा, यौहन, अजमतपुर, बरेथाबुजुर्ग, हिम्मतपुर, जफररगंज, जमरौली नौहरी, तपनी, बरदरा, परादान, धौरहरा, अदमपुर मितौली, बजूपुर, बककस, गोमी खेड़ा, काजी खेडा, कपेरा मदरपुर, कासीमपुर, पहाड़ नगर टिकरिया, सेमरापीतपुर, सुरियामौ अंतगढ़ी, भानुपुर, चंदवाड़ा, गौदवा, बरौकी, कोलवा भनौरा, मुदियारा, रहीमापुर खालसा, सलेमपुर गोंसाई, याकूबपुर अगहापुर, अफजलपुर लूट, भगवानपुर भूर, लखमिया, अदलपुर संदू, बादशाहपुर, दाउद सराय, गलीब्बरा, हादीपुर कला, कायमपुर करारनगर, नजरपुर खुर्द, रसूलपुर गोंधी, अव्वालपुर, नौगवांतागा, अहलादपुर, भतोहा, भवानीपुर, गदांपुर, खेड़ा, तखरौ, मोहब्बतपुर, सरसैमंसूपुर, मोहम्मदपुरनगरिया, नगलालाजत, जवापुर, बुधौली, सिंहपुर कुतुपुर, कुरसंदा, लैगांव, अलीपुर, केशोपुर, चौराइपुर, घुटरामेशोमपुर, सकरा, मीरपुर, मिथौली, सेउपट्टी, सुल्तानपट्टी, अहमदपुर, खाजपुर, भलई, बेरा, मोइद्दीनपुर, छीनपराय, अचरूलधोरा, लोहवान, लालपुर, महावन, ककरारी, सुर्रका, भानारपुर बसैला, शेरनी, बीरबल, चौराहंसी, मनीलाबालू, अगोल, बानबेहल, बंसबोरोलिया, धदुमर, हैदलपुर, मोहमदगंज, मुसेपुर, नगरझुना, साहसपुर, शाहबाजपुर, आनंदपुर, बेलाहारी, बिडिया दादा, देवरिया असगुना, नवींगज, ककराला, टाउन बाहर, गोटरापट्टी वुकुट हल्ली, कोदागुजर, रूपमई, कटिया, मनवा, रोटा, दुगो, रूपपुरा, गरगैया, सुरसेना, निजामपुर, सहवार खेडा, अगई, कर्कटपुर, बथुरा, दुगनपुर, दुलीचंदपुर, खाता चिंतामम, मुबारकपुर, पशुपुरा, राजदुरा, तिरिया, विष्णु, कृपा पांडेय, भवरकी, धीरजनगर, डिलारी, कुम्हरिया कला, कुंवरपुर ननकर, मुवाना, राजपुरा, टांडा, सेहरिया जवाहर, वहादुर का माजरा, बिहारी नगर, शहजाद नगर, अमर्तल, बहलोलपुर, दौडपुर, दुखहर परमरूदैन, लालापुर, लोधीपुर, पलयी कल्याणपुर, रसूलपुर दियारा, सतरोही, विश्रामपुर, अशरफपुर, अर्सबन, डाडी, दुहिया, नसरूल्लापुर, करमपुर, बरसावन, सद्दरपुर, पकोलिया, अशोपुर, फत्तेपुर, बसंतपुर, बेलवतीकर, भुवाना, गंगरई, करमही, करौता, उर्फ निबुड्रया, खानपुर, पकडियार विशुनपुर, पौहरिया, अहिरौली, बहोरपुर, बडहरा, बरगवदा बिष्णुपुर, एकसरवा, करैलिया, करैला अजगरहा, करम हवा खुर्द नैकोट, सुरपर, सोनवल, अर्हिरौली, राजा, बरणा खुर्द, बतरौली, गौनार, कुरमौता, ललीपर, मदराहा, रामपुरमिसरी, सोहसा पट्टी गौसी, पारसखंड, अहिरौली डान, जगदीशपुर, बसडीला खुर्द, गणहिया पाठक, बसडीला गुनकर, पथरवा, पकरियार पुरबपट्टी, जबहीदयाल, सुमहीसंतपट्टी, जमसदीआया, बेलवा सुदामा, लक्षमीपुर, फरदाहा, बरवा बेंदुपर, अजीज नगर, पुरैनी, मठिया उर्फ अकतहा, मु. ममैम सिकतिया, सिकता, मथोली, अदिला, बलिया उत्तर, भागलपुर, धकपुरा, गोपाबपर, कुंडावलहारी, कुदावलतारा, मेल, रेवाली, तेलिया कला, अहिरौली, बांसघाटी, बेहरादबर, दनौर, जिगनामित्रा, मिशरौली दीक्षित, मोतीपुर, भुआल, मोतीपुर टिकैत, रूपई, सथियावन, गौरीठाकुर, धनगढ़ा, बंजरिया, बनराही, अहरौलीलाला, तिलोली उर्फ देहरी, सिसवा पांडेय, मुजुरी खुर्द, गोपालपुर ,धुसरी, घनश्यामपुर ग्रांट, अग्यामाफी, खमरियाबुजुर्ग, बीरापुर, बौहन, पतिजिया खुर्द टीकर, तांबेपुर खपरीपाड़ा, भमैचा उम्मेदजोत, झंझरी, गौरावा कनूनगो, मथुराचौबे, भगहर बुलंद, सरैयां माफी, जनकीनगर, जमदारा, वमनी कानूनगो, किंधौरा, लक्ष्मणपुर, मनहना, सोझिया, सिंचाचंदा, अकबरपुर, ब्योदा उपरहर, बौरिहा, दुफेदिया, जमथा, सराय, रमैपत्ती, देवजी, पिंडरै,

				धोघारी, गरथमा, खड़गपुर, बसंतपुर, बरवां, अहरक, बरैनीकला, भटसर, धोलापुर, दींदासपुर, खोचवान, कोरौती, नरसरा, रखौना, सरवनपुर, सिहोरवा (एन.) (350)
26.	उत्तराखण्ड	देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर (पांच)	रायपुर, सहसपुर, देवप्रयाग, जौनपुर, नरसन, रूड़की, हल्दवानी, रामनगर, जसपुर, रूद्रपुर (10)	बदरीपुर, दवारा, लदपुर, मेहूवाला, मोथारोवाला, नाथनपुरा, रायपुर सिल्ला, सिंधवाल गांव, तलई, अरकेदिया ग्राटं, अटकफारम, चरबा, ढ़ाकी, पूर्वी हेाप टाउन, गल्जबदी, कंडोली, करवरी ग्रांट, लक्ष्मीपुर, पालियों नाथुवाला, बागी, बमना, ददुवा, धुंगी, गोसिल, जाखेद, कंडी बगंदी, महद, पुजार गांव, त्यादगांव, बैट, भटवारी, डकरोला, गैद, कोट, ललोटना, मरोद, मथलौन, परोदी, संदुल, भगवानपुर चंदनपुर, बुदपुर जट, गधारोना उर्फ राजपुर, हरजोली जट, कुर्दी, लिब्बरहेदी, नगला इमरती, शेरपुर खेलमौ, टांडा भनेड़ा, टिकोला कलां, बेलदा, डेलना, माधोपुर हजरतपुर, मेहवाद कलां, मिर्जापुर मुस्तफाबाद, नंगला कुब्दा, पदली गुर्जर, पनियाला चंदापुर, सफरपुर, तांशीपुर, बछीनगर, बसंतपुर, देबलचौड, देवला तल्ला, जगतपुर, खनवल कतां, कुंवरपुर, कुरिया गांव, लमचौड खस, सीतापुर, बैदाझल, बैलपड़ाव, चंद्र नगर, चिल्किया, गांधीनगर, कांडला, कनिया, टांडा मल्लू, थारी, उदयपुरी, बंदोबस्ती, अंगदपुर, बैलजडी, बसई इस्लामनगर, भरतपुर, गदीनेगी, हरियावाला, खेडालक्ष्मीपुर, किलावली, पतरामपुर, रामनगरवन, आनंदपुर, भंगा, भुरा रानी, देवरिया, ,खुरपिया, खुरैय्या, महाराजपुर, रामेश्वरपुर, सुतैया, शाहदौरा (100)
27.	पश्चिम बंगाल	हावड़ा, नदिया, बीरभूम, कूच विहार, मालदा, (पांच)	बल्ली जगछा, श्यामपुर-II, आमता-I, छपरा, टेहट्टा-II, कालीगंज, बोलपुर श्रीनिकेतन, सिउरी-I, मयूरेश्वर-II, सिउरी-II, तुफंगंग-II,, कूच विहार-II चंचोल-I, गजोले, हरिचंद्रपुर-II (15)	बाली, चकपाड़ा आनंदनगर, बछरी, दीहीमंडलघाट-II, आमता, कानपुर, खडदह, उदंग-II छपरा-I, बृतिहूदा, बगवोडिया हतीसला-II, बर्निया, साहेबनगर, कालीगंज, जुरनपुर, मटियारी, गोबरा, राजारामपुरा, गोरेक्षेत्र, कसबा, सियानमलुक, सिंधी, भुरकुना, खटंगा, दसपलसा, मयूरेश्वर, अविनाशपुर, दोमदोमा, रामपुर-I, रामपुर-II, शलबरी-II , बडारंगरस, खगरबरी, मधुपर, टकागाछ राजारहाट, भगवानपुर, मटिहरपुर, गजोले-I, पंडुआ, देवतला, बाबूपुर,माझरा, दौलतनगर, मशलदाह, भलुका (45)
28.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	उत्तर एवं मध्य अण्डमान, दक्षिण अण्डमान (दो)	दीगलीपुर, मयाबुंदर, लिटल अंडमान, प्रोथरापुर, (चार)	दीगलीपुर, किशोरीनगर, लक्ष्मीपुर, शिवपुर, सीतानगर, मयाबुंदर, रामपुर, आर.के. पुर, बोओदनाबाद, गोविंदनगर, नील केन्द्र (11)
29.	दादर एवं नागर हवेली	दादर एवं नागर हवेली (एक)	सिल्वासा (एक)	खानवेल, दपड़ा (दो)
30.	दमन एवं द्वीप	दमन (एक)	नानी दमन (एक)	वरकुंड (एक)
31.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप (एक)	कवारती (एक)	अगती, कवारती (दो)

*स्वतंत्र तेलंगना राज्य की घोषणा के कारण नागरिक उपद्रवों के कारण जिलों का लेखा परीक्षण नहीं हुआ।

अनुबंध-3.1

स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूचियां

(पैराग्राफ 3.2.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्ति
1.	अरूणाचल प्रदेश	ग.रे.नी. के परिवारों के लिए स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षासूची बनाई जाती थी। हालांकि, इसे तैयार करने का आधार अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.जा. एवं अन्य परिवार होते है।
2.	असम	दो चयनित जिलों करीमगज (दुल्लावचेड़ा, पठेरकंदी) एवं शिवसागर, (अमगुरी, दिमॉव) के चार ब्लॉकों में, 208[1] लाभार्थियों का नाम एवं पता स्थायी प्रतीक्षासूची में दो बार आया था। पांच चयनित जिलों (कचर, करबी अंगलाँग, करीमगंज, कोकराझार, सोनीत्पुर) के 177 ग्रा.पं. में अ.जा./अ.ज.जा. एवं गैर-अ.जा/अ.ज.जा. के लिए अलग प्रतीक्षा सूचियां तैयार नहीं की गयी थीं।
3.	बिहार	तीन चयनित जिलों (भोजपुर, किशनगंज, समस्तीपुर) में ग.रे.नी. की सूचियों को स्थायी प्रतीक्षा सूचियां माना गया था तथा अन्य सात चयनित जिलों में स्थायी प्रतीक्षा सूचियां तैयार की गयी थीं।
4.	छत्तीसगढ़	ब्लॉक छुरा के ग्रा.पं. करकरा में, शेष 30 लाभार्थियों के लाभ के लिए 223 लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची में से 193 लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए थे।
5.	गोवा	दो चयनित जिलों में 22 ग्रा.पं. में से 16 स्थायी प्रतीक्षा सूचियां तैयार नहीं की गई थीं।
6.	हरियाणा	छः चयनित जिलों में से केवल जिला सोनीपत ने अ.जा./अ.ज.जा. एवं गैर अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों के लिए अलग प्रतीक्षा सूचियाँ तैयार की गई थीं।
7.	झारखंड	छः चयनित जिलों में से दो जिलों (गढ़वा, देवघर) में स्थायी प्रतीक्षा सूचियां तैयार नहीं की गई थी तथा लाभार्थियों का चयन सीधे ग.रे.नी. की सूची से किया गया था। अन्य चार चयनित जिलों (गोड्डा, पूर्व सिंहभूम, पलामू, राँची) में, स्थायी प्रतीक्षा सूचियां जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा प्रदान की गयी थीं और इन्हें ग्रा.पं. द्वारा तैयार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, चार चयनित ब्लॉकों[2] में प्रतीक्षा सूची में कई विभिन्नताएं नोट की गयी थीं, अर्थात् लाभार्थी के पिता/पति के नामों का उल्लेख न किया जाना, सामान्य लाभार्थी को अ.जा./अ.ज.जा. प्रतीक्षा सूची में शामिल करना, ग.रे.नी. अंकों का उल्लेख न किया जाना आदि। इसके अतिरिक्त, जिला राँची में चार चयनित ब्लॉकों (नामकुम, नगरी, मंदार, रातु) में दोनों अ.जा./अ.ज.जा. एवं गैर-अ.जा/अ.ज.जा. के लिए संयुक्त प्रतीक्षा सूचियां तैयार की गयी थीं।
8.	केरल	मनकडा एवं अथियानूर ब्लॉकों में ग्रा.पं. में 2010-11 तक स्थायी प्रतीक्षा सूचियां तैयार की गयी थीं। शेष चयनित ब्लॉकों/ग्रा.पं. ने कोई स्थायी सूची तैयार नही की थीं।
9.	मध्य प्रदेश	तीन चयनित जिलों (बरवानी, डिंडोरी, उज्जैन) में 19 ग्रा.पं. में स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूचियां तैयार नहीं की गयी थी।
10.	ओडिशा	जिला संबलपुर में केवल 2009-10 तक ही स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की गई थी। इसने 2010-

[1] अमगुरी (6), दिमॉव (73), दुल्लावचेड़ा (117) एवं पठेरकंदी (12)

[2] गोड्डा सदर, ठाकुरगंगती, घाटशीला एवं गुराबंदा ब्लॉक

		11 से 2014-15 के अगले पांच वर्षों के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की थी। चार चयनित जिलों (कटक, देवगढ़, बालासोर, सुंदरगढ़) ने कभी स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की थी आठ चयनित जिलों के 20 पं.स. में छः पंचायत समितियों[3] (पं.स) में अ.जा./अ.ज.जा. एवं गैर अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के लिए अलग स्थायी प्रतीक्षा सूचियां तैयार नहीं की गयी थीं तथा दोनों श्रेणियों के लिए एक प्रतीक्षा सूची तैयार की गई थी।
11.	उत्तराखण्ड	पांच चयनित जिलों में से, केवल दो जिलों उधम सिंह नगर एवं नैनीताल ने अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्यों के लिए अलग प्रतीक्षा सूचियां तैयार की थीं।

[3] चिकीती (गंजम), कोमना (नुआपाड़ा), बोलगढ़, जटनी (खुर्दा), बरकोट, तिलेबानी (देवगढ़)

अनुबंध-3.2

लाभार्थियों का चयन

(पैराग्राफ 3.3.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	2008-13 की अवधि के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के लाभार्थियों का चयन तीन से लेकर 48 प्रतिशत तक था। इं.आ.यो. दिशानिर्देशों, अर्थात् 2008-09 (172 प्रतिशत, 2009-10) (104 प्रतिशत), 2011-12 (109 प्रतिशत) के प्रावधानों से अधिक में गैर-अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों का चयन हुआ था। शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का चयन 0 से लकेर 2.54 प्रतिशत तक था।
2.	असम	6,80,704 मकानों में से 3,79,409 मकानों अर्थात् 56 प्रतिशत अ.जा./अ.ज.जा. के परिवारों को आबंटित किए गए थे।
3.	छत्तीसगढ़	चयनित जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति 15 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के प्रति एक से पांच प्रतिशत तक थी। शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का चयन 0.3 से लेकर 1.09 प्रतिशत तक किया गया था।
4.	गुजरात	भौतिक लक्ष्यों के संदर्भ में चयनित जिलों अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों की प्रतिशतता दो प्रतिशत (आनन्द) एवं 56 प्रतिशत (बनसकंठा) थी। भौतिक लक्ष्यों के संदर्भ में तीन चयनित जिलों में अल्पसंख्यक लाभार्थियों का चयन दाहोद एवं सूरत में शून्य प्रतिशत, जूनागढ़ में 12 प्रतिशत था। चयनित जिलों में भौतिक लक्ष्यों के संदर्भ में शारीरिक एवं मानसिक रूप से विक्लांग व्यक्तियों का चयन 0 से लेकर 2 प्रतिशत तक हुआ था।
5.	हिमाचल प्रदेश	अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को मकानों का आबंटन संतोषजनक था तथा 2008-13 के दौरान 55 से लेकर 61 प्रतिशत के बीच था। तीन चयनित जिलों में अल्पसंख्यकों का चयन तीन से नौ प्रतिशत तक था। शारीरिक एंव मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का चयन दो प्रतिशत तक था।
6.	कर्नाटक	छ: चयनित जिलों में अ.जा./अ.ज.जा. के लाभ 40 से लेकर 59 प्रतिशत के बीच थे तथा दो चयनित जिलों चित्रदुर्ग (2011-12, 2012-13) तथा गुलबर्ग (2008-09),

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्ति
		में यह इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार था। जिलों गडग (2008-13,) गुलबर्ग 2012-13) तथा कोप्पल (2009-10 एवं 2011-12) जिलों को छोड़कर जहाँ यह 15 प्रतिशत था चयनित जिलों में अल्पसंख्यकों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन पांच से लेकर 14 प्रतिशत तक था।
7.	केरल	1.52 लाख नए मकानों के प्रति, अ.जा./अ.ज.जा. के परिवारों को केवल 1.32 लाख (52 प्रतिशत) मकान आवंटित किए गए थे। सुधार के अंतर्गत 50 प्रतिशत की प्राप्ति हुई थी। 7,617 (तीन प्रतिशत) के प्रति केवल 5,166 (2.03 प्रतिशत) शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तिओं का चयन किया गया था।
8.	मध्य प्रदेश	सभी चयनित जिलों में इं.आ.यो. के अंतर्गत लक्षित 1,18,437 (60 प्रतिशत) के प्रति अ.जा./अ.ज.जा. के परिवारों को केवल 80,969 (41 प्रतिशत) मकान आवंटित किए गए थे।
9.	मिजोरम	गैर-अ.जा/अ.ज.जा. लाभार्थियों में से किसी लाभार्थी का चयन नहीं किया गया था, जबकि राज्य में गैर-अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थी कुल जनसंख्या के 5.51 प्रतिशत का गठन करते थे।
10.	पंजाब	छः जिलों में से पांच जिलों (मुक्तसर, नवाँशहर, सास नगर, पटियाला, तरन तारन) में इं.आ.यो. के अंतर्गत लाभार्थियों की विशेष जातियों को लाभ मिला या नहीं का पता लगाने के लिए अभिलेखों का अनुसरण नहीं किया गया था।
11.	राजस्थान	आठ चयनित जिलों में से, 3 जिलों (बिकानेर, बुंदी, सिकर) में, अ.जा./अ.ज.जा. के लाभार्थियों को मकानों का आबंटन 42 से लकेर 55 प्रतिशत के बीच किया गया था। दो चयनित जिलों (बिकानेर, करौली) में, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का 0.46 से लेकर 2.56 प्रतिशत के बीच था।
12.	त्रिपुरा	दो चयनित जिलों उत्तर त्रिपुरा (दसडा) एवं पश्चिम त्रिपुरा (बिसालगढ़, खोवाई) के तीन ब्लॉकों में अ.जा./अ.ज.जा. को 34 से लेकर 58 प्रतिशत मकानों का आवंटन किया गया था। जिला पश्चिम त्रिपुरा के ब्लॉक जमपुईजाल में 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान अ.ज.जा. परिवारों को 100 प्रतिशत मकान आवंटित किए गए थे (334 एवं 712 मकान) तथा अन्य समूहों को कोई मकान आवंटित नहीं किया

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्ति
		गया था। 2011-12 और 2012-13 के दौरान, जिला पश्चिम त्रिपुरा के ब्लॉक जमपुईजल में अल्पसंख्यक समूह को 13,48 मकान (क्रमश: 20 एवं 28) आवंटित किए गए थे। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान अल्पसंख्यक लाभार्थी प्रतीक्षा में थे तथा यद्यपि उनके नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में होने के बावजूद उन्हें कोई मकान आवंटित नहीं किया गया था।
13.	उत्तराखंड	अ.जा./अ.ज.जा. को मकानों का आवंटन 31 से 59 प्रतिशत तक किया गया था।

अनुबंध-3.3

गैर - ग.रे.नी. के लाभार्थियों का चयन

(पैराग्राफ 3.3.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	गैर-ग.रे.नी. के लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	6	10	17	4.06
2.	असम	1	11	26 (वी.डी.सी.)	27,625	6,216
3.	छत्तीसगढ़	1	1	1	2	0.07
4.	हरियाणा	2	2	5	27	11.30
5.	जम्मू व कश्मीर	6	12	361	6,423	1,779.55
6.	झारखण्ड	2	7	44	593	187.18
7.	कर्नाटक	1	1	2	3	1.05
8.	मध्य प्रदेश	4	आं.उ.न.[1]	आं.उ.न.	4	7.35
9.	मेघालय	4	8	74	396	181.26
10.	ओडिशा	3	7	16	104	27.10
11.	पंजाब	3	5	106	1,129	351.18
12.	उत्तर प्रदेश	5	7	25	428	149.80
	कुल	**34**	**67**	**670**	**36,751**	**8,915.90**

[1] आंकड़ा उपलब्ध नहीं।

अनुबंध-3.4

प्रतीक्षासूची को ध्यान में न रखते हुए लाभार्थियों का चयन

(पैराग्राफ 3.3.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	लाभार्थियों की संख्या	टिप्पणी
1.	बिहार	4	6	13	82	प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठता को ध्यान में न रखते हुए सहायता दी गई थी।
2.	मध्य प्रदेश	7	14	52	551	प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठता को ध्यान में न रखते हुए सहायता दी गई थी।
3.	मेघालय	4	8	74	आं.उ.न.[2]	प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठता को ध्यान में न रखते हुए सहायता दी गई थी।
4.	मिजोरम	2	4	25	345	प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठता को ध्यान में न रखते हुए सहायता दी गई थी।
5.	राजस्थान	4	आं.उ.न.	आं.उ.न.	आं.उ.न.	प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठता को ध्यान में न रखते हुए सहायता दी गई थी।
6.	त्रिपुरा	2	6	52	3,584	प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठता को ध्यान में न रखते हुए सहायता दी गई थी।
7.	उत्तर प्रदेश	1	1	6	71	प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठता को ध्यान में न रखते हुए सहायता दी गई थी।

[2] आंकड़ा उपलब्ध नहीं।

8.	उत्तराखण्ड	1	2	आं.उ.न.	73	प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठता को ध्यान में न रखते हुए सहायता दी गई थी।
9.	पश्चिम बंगाल	3	5	13	53	कूच बिहार (17 लाभार्थियों को ₹5.95 लाख के भुगतान सहित), बीरभूम (पांच लाभार्थियों को ₹1.75 लाख के भुगतान सहित) तथा मालदा (26 लाभार्थियों को ₹9.01 लाख के भुगतान सहित के 5 ग्रा.पं.[6] ने स्थायी सूची में क्रम का पालन नहीं किया था
10.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1	1	1	37	प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठता को ध्यान में न रखते हुए सहायता की गई थी।
	कुल	**29**	**47**	**236**	**4,796**	

[6] रामपुर-II, रामपुर-I, खागराबरी, बारारंगरस, मधुपुर

अनुबंध-3.5

महिला सदस्यों को मकानों का आवंटन

(पैराग्राफ 3.4.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	अभ्युक्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	जिला खाम्माम में 1,80,801 मकानों में से 4,763 (तीन प्रतिशत) तथा जिला करीम नगर में 51,107 मकानों में से 567 (एक प्रतिशत) पुरूष सदस्यों को आवंटित किए गए थे।
2.	असम	जिला कर्बी अंग्लॉग में दो ब्लॉकों (हॉवराघाट, बोकाजन) में क्रमश: 4,675 (93 प्रतिशत) और 3,774 (87 प्रतिशत) पुरूष सदस्यों को मकान आवंटित किए गए थे। ग.रे.नी. की सूचियों/स्थायी प्रतीक्षासूची में परिवारों के विवरणों की गैर-उपलब्धता के कारण शेष चयनित ब्लॉकों की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका था।
3.	छत्तीसगढ़	चयनित जिलों में, पुरूष सदस्यों को 77 प्रतिशत आवंटन किया गया था।
4.	गोवा	उत्तर गोवा जिला में, पुरूष सदस्यों को आवंटन किया गया था।
5.	हरियाणा	13 चयनित ब्लॉकों में, 11,032 मकानों में से 1,929 (17 प्रतिशत) पुरूष सदस्यों को आवंटित किया गया था तथा ₹7.01 करोड़ की सहायता प्रदान की गई थी।
6.	हिमाचल प्रदेश	382 लाभार्थियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान ग.रे.नी. के परिवारों के पुरूष सदस्यों को मकान (48 प्रतिशत) आवंटित कर दिए गए थे।
7.	जम्मू व कश्मीर	12 चयनित ब्लॉकों में, महिला सदस्यों के नाम में कोई औपचारिक संस्वीकृति/आवंटन आदेश जारी नहीं किए थे तथा पुरूष सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।
8.	कर्नाटक	1,74,451 मकानों में से, 6,237 (चार प्रतिशत) मकान पुरूष सदस्यों को आवंटित किए गए थे। 6,063 मामलों में लेखापरीक्षा में नमूना परीक्षित किए गए फाइल में कोई शीर्षक विलेख नहीं रखे गये थे तथा 1,347 मामलों में कोई खाता सार नहीं थे। इन दस्तावेजों की अनुपलब्धता में, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर पायी कि क्या मकानों का स्वामित्व महिला सदस्यों को वास्तव में आवंटित किया गया था।
9.	केरल	तीन चयनित जिलों (हरीप्पाड, मुथुकुलम, अथियानुर) में 291 (4.1 प्रतिशत) पुरूष सदस्यों को मकानों को आवंटन किया गया था।
10.	महाराष्ट्र	आठ चयनित जिलों में पुरूष सदस्यों के नाम में मकानों का आवंटन 73 से लेकर 99 प्रतिशत के बीच किया गया था।
11.	मिजोरम	परिवार के पुरूष सदस्यों को नवनिर्मित मकान छ: प्रतिशत (824) तथा सुधार किए गए मकान आठ प्रतिशत (538) आवंटित किए गए थे।

12.	नागालैण्ड	68,805 इं.आ.यो. के मकानों में से, महिला सदस्यों को केवल 806 (एक प्रतिशत) मकान आवंटित किए गए थे।
13.	त्रिपुरा	624 लाभार्थियों के संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में पता चला कि 339 मकान महिला सदस्यों (54 प्रतिशत) के नाम पर आवंटित किए गए थे जबकि 285 मकान परिवार के पुरूष सदस्यों को आवंटित किए गए थे, जबकि प्रत्येक परिवार में महिला सदस्य मौजूद थीं।
14.	उत्तराखण्ड	1,149 इं.आ.यो. के मकानों के संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में पता चला कि इन मकानों में से 947 (82 प्रतिशत) को महिला सदस्यों के नाम में आवंटित किया गया था तथा शेष, 202 मकान पुरूष सदस्यों को आवंटित किए गए थे। पुरूष सदस्यों को आवंटित 202 मकानों में से 117 परिवारों में व्यस्क महिला सदस्य मौजूद थी।
15.	दमन एवं दीव	दमन में 60 मकानों में से, परिवार के पुरूष सदस्यों को 24 (40 प्रतिशत) मकान आवंटित किए गए थे तथा उन्हें ₹10 लाख की राशि का भुगतान किया गया था।

अनुबंध-3.6

मकानों के आवंटन में अन्य अनियमितताएं

(पैराग्राफ 3.4.2 के संदर्भ में)

एक पहचान पत्र का उपयोग करके इं.आ.यो. तथा अन्य योजना के अंतर्गत मकान का आवंटन

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	टिप्पणी
1.	असम	2	10	34	46	16.05	अल्पसंख्यकों के लिए 2008-13 के दौरान उसी या बाद के वर्षों में एक परिवार का प.प. का उपयोग करते हुए जिला नागाँव के चार[7] ब्लॉकों में 15 लाभार्थियों तथा जिला बरपेटा के छ:[8] ब्लॉकों को इं.आ.यो. (सामान्य) तथा बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (व.क्षे.वि.का.) के अंतर्गत क्रमश: ₹4.04 लाख तथा ₹12.01 लाख का कुल अधिक व्यय करके मकान आवंटित किए गए थे।
2.	हरियाणा	3	3	10	15	5.45	तीन[9] ब्लॉकों में, इ.आ.यो. तथा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित राज्य आवास योजना के अंतर्गत 15 लाभार्थियों ने लाभ उठाया तथा इं.आ.यो. के अंतर्गत उन्हें ₹5.45 लाख की वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई थी।

[7] पश्चिम कालियाबोर (10) जुगीजन (2), डोलीघाट (2) तथा राहा (1)

[8] भवानीपुर (2), चेंगा (1) मंदिया (18), पाकाबेतबारी (1), रूपोसी (6) तथा सारूखेतरी (3)

[9] कनीना, पलवल तथा सोनीपत

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	टिप्पणी
3.	झारखण्ड	2	5	12	19	7.51	2008-11 के दौरान इं.आ.यो. तथा सिद्धु-कान्हु आवास योजना[10] में दो चयनित जिलों गढ़वा (चिनिया, डानडाई, सदर), पूर्व सिंधभूम (घाटशिला, गुराबंदा) के पांचब्लॉकों में 19 परिवारों को 45 मकान आवंटित किए गए थे। 26 अतिरिक्त परिवारों के आवंटन के परिणामस्वरूप ₹7.51 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।
4.	कर्नाटक	1	1	1	1	0.35	ग्रा.पं. मंचनायकनाहल्ली में, एक लाभार्थी को इं.आ.यो. तथा अम्बेडकर राज्य आवास योजना दोनों के अंतर्गत 0.35 लाख की सहायता प्रदान की गई थीं।
5.	उत्तराखंड	3	14	37	45	17.57	तीन चयनित जिलों[11] में, उन लाभार्थियों को 45 इं.आ.यो. के मकान[12] आवंटित किए गए थे जिन्हें पहले से ही दीन दयाल उपाध्याय तथा अटल आवास योजनाओं द्वारा लाभ हुआ था।
	कुल	**11**	**33**	**94**	**126**	**46.93**	

[10] सिद्धु-कान्हु आवास योजना विभाग, झारखंड सरकार द्वारा इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही एक राज्य प्रायोजित योजना है

[11] नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून

[12] नैनीताल : 08, हरिद्वार : 13 देहरादून : 24

अनुबंध-4.1

ठेकेदारों द्वारा या विभागीय रूप से निर्मित इं.आ.यो. के मकान

(पैराग्राफ 4.3 के संदर्भ में)

राज्य/सं.शा.क्षे.	जिला	ब्लॉक	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	टिप्पणी
असम	01 (कारबी एगंलांग)	01 (हावराघाट)	1,045	311.00	सामग्री का प्रापण तथा मजदूरों को कार्य में लगाने के लिए ब्लॉक द्वारा राशि का व्यय किया गया था। विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि दिशानिर्देशों की देर से प्राप्ति तथा लाभार्थियों के खाते न खोले जाने के कारण निर्माण कार्यों को मुख्यत: ब्लॉक स्तर पर किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी अन्य ब्लॉक ने अपने स्तर पर मकानों का निर्माण नहीं किया था।
	01 (शिवसागर)	03[1]	--	52.29	सामग्री के प्रापण के लिए ब्लॉकों द्वारा राशि का व्यय किया गया था। उसी के प्रापण एवं उपयोगिता से संबंधित अभिलेखों को मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया था।
कर्नाटक	01 (कोप्पल)	01 (गंगावठी)	--	38.83	इं.आ.यो. के अंतर्गत मकानों के निर्माण हेतु कनिष्ठ अभियंताओं (क.अ.) को राशि का भुगतान किया गया था। हालांकि, मकानों के निर्मित होने तथा लाभार्थियों को दिए जाने से संबंधित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। उत्तर में, विभाग ने बताया कि कनिष्ठ अभियंताओं/ग्रा.पं. अधिकारियों ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे।
केरल	01	01	04	1.94	ब्लॉक मननथावडी (जिला वयनाड) के ग्रा.पं. थोंडरनाडु में इं.आ.यो. के निर्माण में ठेकेदारों की भागीदारी थी1
महाराष्ट्र	02	02	34	19.08	ग्रा.पं. नवीन कोलकेवडी, ब्लॉक चिपलुन, जिला रत्नागिरी, (पांच मामले) तथा ब्लॉक सड़क अरजुनी, जिला गोंडिंया (29 मामले) में इं.आ.यो. के मकानों के निर्माण में ठेकेदार शामिल थे।

[1] (i)सोनारी- ₹ 44.65लाख (ii) गौरीसागर- ₹7.43 लाख तथा (iii) अमगुरी- ₹0.21 लाख

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	02	04	2,188	365.32	2010-11 तक जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा सामान के क्रय हेतु भुगतान सीधे ठेकेदारों के खाते में किया गया था। उत्तर में, जि.ग्रा.वि.अ. ने बताया कि ऐसे भुगतान रोक दिए गए हैं तथा दिशानिर्देशों को सख्ती से पालन को सुनिश्चित करने के लिए मामले की समीक्षा की जाएगी।
कुल	**08**	**12**		**788.46**	

अनुबंध-4.2

इं.आ.यो. अधिकारियों/कर्मचारियों/बढ़ईयों/मिस्त्रियों को प्रशिक्षण न दिया जाना तथा कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन न किया जाना

(पैराग्राफ 4.7.1 & 4.7.2 के सदर्भ में)

राज्य/सं.शा.क्षे.	अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया		बढ़ईयों/मिस्त्रियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया		आयोजित न की गई कार्यशालाएं/संगोष्ठियां	
	जिला	ब्लॉक	जिला	ब्लॉक	जिला	ब्लॉक
आन्ध्र प्रदेश	01	04	01	04	--	--
असम	08	20	08	20	--	--
अरूणाचल प्रदेश	4	8	4	8	--	--
बिहार	09	28	10	30	08	24
छत्तीसगढ़	05	12	05	12	05	12
गोवा	02	04	02	04	--	--
गुजरात	07	17	07	17	07	17
हरियाणा	06	13	06	13	--	--
हिमाचल प्रदेश	04	08	04	08	--	--
जम्मू व कश्मीर	06	12	06	12	--	--
झारखण्ड	06	18	--	--	--	--
कर्नाटक	08	16	08	16	08	16
केरल	04	11	--	--	--	--
मध्य प्रदेश	13	26	--	--	13	26
महाराष्ट्र	08	19	08	19	08	18
मणिपुर	04	08	04	08	--	--
मेघालय	04	08	04	08	04	08
मिजोरम	02	04	02	04	02	04
नागालैण्ड	03	06	03	06	--	--
ओडिशा	08	20	08	20	--	--
राजस्थान	08	16	08	16	--	--

उत्तर प्रदेश	15	35	15	35	15	35
उत्तराखण्ड	05	10	05	10	--	--
पश्चिम बंगाल	05	13	05	11	05	12
अण्डमान व निकोबार	02	04	02	04	02	04
लक्षद्वीप	01	01	--	--	--	--
कुल	**148**	**341**	**125**	**285**	**77**	**176**

अनुबंध-4.3

गुणवत्ता निरीक्षण/तकनीकी पर्यवेक्षण को संचालित न किया जाना

(पैराग्राफ 4.8 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/स.शा.क्षे.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	अभ्युक्ति
1.	बिहार	09	27	117	इं.आ.यो. के मकानों के निर्माण हेतु किसी प्रकार के तकनीकी पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने कोई पहल नहीं की थी। इसके कारणवश खराब गुणवत्ता तथा असुरक्षित मकानों का निर्माण हुआ था।
2.	गोवा	02	04	22	मकानों की गुणवत्ता के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण प्रदान नहीं किया गया था।
3.	गुजरात	07	17	170	सभी चयनित जिलों में किसी भी लाभार्थी को तकनीकी पर्यवेक्षण प्रदान नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्राधिकारियों द्वारा निर्माण की गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं किया था।
4.	हरियाणा	06	13	120	मकानों की गुणवत्ता के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण प्रदान नहीं किया गया था।
5.	झारखण्ड	06	18	102	तकनीकी पर्यवेक्षण की कमी के कारण इं.आ.यो. के मकानों के घटिया निर्माण से इंकार नहीं किया जा सकता है।
6.	कर्नाटक	08	16	119	तकनीकी पर्यवेक्षण प्रदान नहीं किया गया था तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था।
7.	मध्य प्रदेश	10	20	200	लाभार्थियों को कोई तकनीकी पर्यवेक्षण प्रदान नहीं किया गया था जबकि मकान का निर्माण नींव या लिंटल स्तर पर होना था।

क्र.सं.	राज्य/स.शा.क्षे.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	अभ्युक्ति
8.	नागालैण्ड	03	06	60	विभाग के उत्तर के अनुसार (सितम्बर 2013) इं.आ.यो. के मकान का निर्माण का पर्यवेक्षण समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता था। हालांकि, इस कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, साक्षात्कार के दौरान चयनित लाभार्थियों ने बताया कि इं.आ.यो. के मकान के निर्माण पर्यवेक्षण हेतु कोई विभागीय अधिकारी नहीं आया था।
9.	ओडिशा	08	20	123	संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किसी भी स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किसी गुणवत्ता निरीक्षण का संचालन नहीं किया गया था। तकनीकी पर्यवेक्षण न किए जाने के कारण अधिकतर इं.आ.यो. के मकान पक्के नहीं थे तथा पत्थर, मिट्टी तथा टाइल/अजबेस्टो के बने हुए पारंपरिक मकान थे जो कि मौसम प्रतिरोधी नहीं थे।
10.	राजस्थान	08	16	155	राज्य सरकार ने बताया (मई 2013) कि तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु मानकों को निर्धारित नहीं किया गया था।
11.	उत्तर प्रदेश	15	35	321	इं.आ.यो. मकानों की गुणवत्ता को सुनिश्चित तथा निरीक्षित करने के लिए 15 चयनित जिलों में कोई निरीक्षण नहीं हुए थे। राज्य/जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षणों की कोई सूची राज्य सरकार ने निर्धारित नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप इं.आ.यो. के अंतर्गत निर्मित मकान मजबूती

क्र.सं.	राज्य/स.शा.क्षे.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	अभ्युक्ति
					तथा मौसम एवं अन्य प्राकृतिक/मानव निर्मित परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधी नहीं थे।
12.	उत्तराखण्ड	05	10	100	कोई गुणवत्ता निरीक्षण नहीं किया गया था।
13.	पश्चिम बंगाल	04	12	30	कोई तकनीकी पर्यवेक्षण प्रदान नहीं किया गया था तथा किसी प्रकार की तकनीकी जानकारी के बिना लाभार्थियों ने अपने मकानों का निर्माण किया था जिसके कारणवश मकानों की गुणवत्ता खराब थी।
	कुल	**91**	**214**	**1,639**	

अनुबंध-5.1

विभिन्न कारणों से केन्द्रीय अंश के निर्गम नहीं होने के राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरे

(पैराग्राफ 5.3 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09 से 2012-13				कुल	राज्य अंश का कम निर्गम	कुल योग
		निधियों का अतिरिक्त अग्रनयन (अनुबंध 5.1.1.)	राज्य अंश का कम निर्गम (अनु.5.1.2)	प्रस्तावों की विलम्बित प्राप्ति (अनु.5.1.3)	अन्य/विविध [अनु.-5.1.4]			
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	9237.60	9237.60	3079.20	12316.80
2.	अरूणाचल प्रदेश	179.23	258.33	7.48	27.67	472.71	52.52	525.23
3.	असम	15185.27	9954.18	1175.67	117.93	26433.05	8811.02	35244.07
4.	बिहार	60822.59	4020.92	33.6	29129.24	94006.35	31335.45	125341.80
5.	छत्तीसगढ़	659.86	37.95	0.00	110.51	808.32	269.44	1077.760
6.	गोवा	134.18	72.25	0.00	0.00	206.43	68.81	275.24
7.	गुजरात	13404.76	919.75	0.00	123.7	14448.21	4816.07	19264.28
8.	हरियाणा	166.07	2.75	0.00	0.00	168.82	56.27	225.09
9.	हिमाचल प्रदेश	212.14	12.09	0.00	2.83	227.06	75.69	302.75
10.	जम्मू एवं कश्मीर	829.53	1818.33	207.37	0.00	2855.23	951.74	3806.97
11.	झारखण्ड	8405.4	1479.33	1866.49	84.39	11835.61	3945.20	15780.81
12.	कर्नाटक	4699.22	152.55	2288.85	4241.4	11382.02	3794.01	15176.03
13.	केरल	1750.19	56.53	0.00	2370.45	4177.17	1392.39	5569.56
14.	मध्य प्रदेश	[illegible]	509.19	179.94	418.9	2897.74	965.91	3863.65
15.	महाराष्ट्र	933.6	16.06	119.12	1952.45	3021.23	1007.08	4028.31
16.	मणिपुर	129.38	399.06	150.80	0.21	679.45	75.49	754.94
17.	मेघालय	1133.08	478.29	0.00	0.00	1611.37	179.04	1790.41
18.	मिजोरम	0.00	83.13	80.41	12.16	175.7	19.52	195.22
19.	नागालैण्ड	20.51	282.30	0.00	0.00	302.81	33.65	336.46
20.	ओडिशा	11613.13	905.30	0.00	3452.58	15971.01	5323.67	21294.68
21.	पंजाब	1149.60	1929.73	147.39	0.00	3226.72	1075.57	4302.29

क्र.सं.	राज्य	2008-09 से 2012-13				कुल	राज्य अंश का कम निर्गम	कुल योग
		निधियों का अतिरिक्त अग्रनयन (अनुबंध 5.1.1.)	राज्य अंश का कम निर्गम (अनु.5.1.2)	प्रस्तावों की विलम्बित प्राप्ति (अनु.5.1.3)	अन्य/विविध [अनु.-5.1.4]			
22.	**राजस्थान**	2250.15	136.94	0.00	1097.06	3484.15	1161.38	4645.53
23.	**तमिलनाडु**	402.75	0.03	0.00	456.24	859.02	286.34	1145.36
24.	**त्रिपुरा**	0.00	538.22	0.00	0.00	538.22	179.41	717.63
25.	**उत्तराखण्ड**	357.95	408.67	11.83	189.47	967.92	322.64	1290.56
26.	**उत्तर प्रदेश**	3214.35	379.61	0.00	658.10	4252.06	1417.35	5669.41
27.	**पश्चिम बंगाल**	26911.55	304.05	3616.46	106.05	30938.11	10312.70	41250.81
	योग	**156354.20**	**25155.54**	**9885.41**	**53788.94**	**245184.09**	**81007.56**	**326191.65**

अनुबंध-5.1.1

निधि के अतिरिक्त अग्रनयन के कारण केन्द्रीय अंश के निर्गम नहीं होने के राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरे

(अनु. 5.1 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	निधि का अतिरिक्त आग्रनयन					कुल
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	169.56	0.00	0.00	0.00	9.67	179.23
3.	असम	1004.59	3076.14	4787.92	1034.21	5282.41	15185.27
4.	बिहार	40.57	18600.17	19700.68	5252.24	17228.93	60822.59
5.	छत्तीसगढ़	252.44	0.00	151.69	0.00	255.73	659.86
6.	गोवा	35.77	0.00	98.41	0.00	0.00	134.18
7.	गुजरात	1596.68	2031.07	3087.31	2505.24	4184.46	13404.76
8.	हरियाणा	32.96	0.00	0.00	24.04	109.07	166.07
9.	हिमाचल प्रदेश	29.48	101.33	14.10	24.11	43.12	212.14
10.	जम्मू एवं कश्मीर	81.45	191.56	0.92	306.30	249.30	829.53
11.	झारखण्ड	1391.10	1622.08	1362.08	1045.90	2984.24	8405.4
12.	कर्नाटक	1214.53	0.00	0.00	392.28	3092.41	4699.22
13.	केरल	9.04	0.00	0.00	0.00	1741.15	1750.19
14.	मध्य प्रदेश	89.18	16.17	223.64	708.33	752.39	1789.71
15.	महाराष्ट्र	743.36	127.89	0.00	0.00	62.35	933.6
16.	मणिपुर	19.18	65.31	0.00	44.89	0.00	129.38
17.	मेघालय	128.24	497.34	354.46	20.36	132.68	1133.08
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51
20.	ओडिशा	801.48	3621.91	2084.79	3388.06	1716.89	11613.13
21.	पंजाब	275.61	119.98	427.95	326.06	0.00	1149.6
22.	राजस्थान	107.55	484.35	46.85	24.52	1586.88	2250.15
23.	तमिलनाडु	75.51	0.00	0.00	183.80	143.44	402.75
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तराखण्ड	1.28	0.00	0.00	26.20	330.47	357.95
26.	उत्तर प्रदेश	151.21	68.13	0.00	12.87	2982.14	3214.35
27.	पश्चिम बंगाल	4533.23	1375.89	5339.69	0.00	15662.74	26911.55
	योग	**12804.51**	**31999.32**	**37680.49**	**15319.41**	**58550.47**	**156354.20**

अनुबंध-5.1.2

राज्य अंश के कम निर्गम के कारण केन्द्रीय अंश के गैर-निर्गम के राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरे

(अनुबंध 5.1 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	राज्य अंश का कम निर्गम					कुल
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	166.35	19.01	0.00	0.00	72.97	258.33
3.	असम	1995.49	6263.54	1695.15	0.00	0.00	9954.18
4.	बिहार	1112.18	573.56	0.00	2123.09	212.09	4020.92
5.	छत्तीसगढ़	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00	37.95
6.	गोवा	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	72.25
7.	गुजरात	0.00	879.26	36.90	3.59	0.00	919.75
8.	हरियाणा	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	9.26	0.00	2.83	0.00	12.09
10.	जम्मू एवं कश्मीर	427.27	480.43	544.42	309.01	57.20	1818.33
11.	झारखण्ड	124.40	951.10	65.23	338.60	0.00	1479.33
12.	कर्नाटक	51.01	0.00	0.00	101.54	0.00	152.55
13.	केरल	17.14	39.39	0.00	0.00	0.00	56.53
14.	मध्य प्रदेश	0.03	22.85	4.84	76.15	405.32	509.19
15.	महाराष्ट्र	0.00	11.11	0.00	4.95	0.00	16.06
16.	मणिपुर	13.13	204.48	0.00	73.51	107.94	399.06
17.	मेघालय	0.00	473.74	4.55	0.00	0.00	478.29
18.	मिजोरम	57.95	15.98	9.20	0.00	0.00	83.13
19.	नागालैण्ड	131.33	150.97	0.00	0.00	0.00	282.30
20.	ओडिशा	380.75	95.10	0.00	401.01	28.44	905.30
21.	पंजाब	52.26	1157.34	653.85	66.28	0.00	1929.730
22.	राजस्थान	33.66	90.13	0.00	0.00	13.15	136.94
23.	तमिलनाडु	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
24.	त्रिपुरा	363.86	174.36	0.00	0.00	0.00	538.22
25.	उत्तराखण्ड	0.00	11.98	396.69	0.00	0.00	408.67
26.	उत्तर प्रदेश	71.81	19.64	85.77	129.76	72.63	379.61
27.	पश्चिम बंगाल	0.01	304.04	0.00	0.00	0.00	304.05
	योग	**5070.88**	**11988.00**	**3496.60**	**3630.32**	**969.74**	**25155.54**

अनुबंध-5.1.3

प्रस्ताव की विलंबित प्राप्ति के कारण केन्द्रीय अंश के गैर-निर्गम के राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरे

(अनुबंध 5.1 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	प्रस्तावों की विलंबित प्राप्ति					कुल
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	7.48	0.00	0.00	7.48
3.	असम	0.00	0.00	1175.67	0.00	0.00	1175.67
4.	बिहार	0.00	0.000	0.00	0.00	33.60	33.60
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	90.53	0.00	116.84	207.37
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	1866.49	0.00	0.00	1866.49
12.	कर्नाटक	0.00	0.000	0.00	2288.85	0.00	2288.85
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	179.94	0.00	0.00	179.94
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	119.12	0.00	0.00	119.12
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	150.80	0.00	150.80
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	80.41	80.41
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	ओडिशा	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	37.94	109.45	0.00	0.00	147.39
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83	11.83
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	3616.46	0.00	0.00	3616.46
	योग	**0.0**	**37.94**	**7165.14**	**2439.65**	**242.68**	**9885.41**

अनुबंध-5.1.4

अन्य विविध कारणों से केन्द्रीय अंश के गैर-निर्गम के राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरे

(अनुबंध 5.1 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	अन्य विविध कारण					कुल
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	9237.60	9237.60
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	27.67	0.00	0.00	27.67
3.	असम	0.00	0.00	117.93	0.00	0.00	117.93
4.	बिहार	7155.30	81.11	796.54	5429.97	15666.33	29129.24
5.	छत्तीसगढ़	0.00	14.78	0.00	70.93	24.81	110.51
6.	गोवा	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	8.24	46.88	0.00	0.00	68.58	123.70
8.	हरियाणा	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	1.10	0.00	1.73	0.00	2.83
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	84.39	0.00	84.39
12.	कर्नाटक	18.75	0.00	0.00	519.35	3703.30	4241.40
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	2370.45	2370.45
14.	मध्य प्रदेश	18.75	0.00	175.32	7.78	217.06	418.90
15.	महाराष्ट्र	341.09	7.30	44.49	241.00	1318.58	1952.45
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	12.16	12.16
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	ओडिशा	869.47	1554.00	49.96	960.30	18.85	3452.58
21.	पंजाब	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	73.89	9.75	82.63	556.98	373.81	1097.06
23.	तमिलनाडु	325.82	0.00	0.00	21.35	109.07	456.24
24.	त्रिपुरा	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	189.23	0.24	0.00	189.47
26.	उत्तर प्रदेश	11.90	45.94	21.70	192.55	386.01	658.10
27.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	85.31	20.74	0.00	106.05
	योग	**8823.21**	**1760.86**	**1590.78**	**8107.52**	**33506.61**	**53788.94**

अनुबंध-5.2

मंत्रालय द्वारा निधियों का अधिक निर्गम

(पैराग्राफ 5.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	जिला/राज्य	वर्ष	अधिक निर्गम (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
1.	**बारपेट/असम**	2009-10	13.29	जिले ने 2009-10 हेतु दूसरी किश्त का दावा करने के लिए वर्ष 2008-09 के लिए लेखापरीक्षित अव्ययित शेष को ₹3.07 करोड के रूप में सूचित किया था। इस सूचित अव्ययित शेष के आधार पर मंत्रालय ने जिले को ₹13.29 करोड़ जारी किए (जनवरी 2010)। तथापि, जिले ने 2009-10 हेतु अपने लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते समय (दिसम्बर 2010) 2008-09 के लेखापरीक्षित अंत शेष को ₹23.07 करोड़ तक (पूर्व में सूचित ₹3.07 करोड़ की बजाए) संशोधित किया। यदि जिले ने ₹23.07 करोड़ का सही अव्ययित शेष सूचित किया होता तो वह ₹13.29 करोड़ की दूसरी किश्त योग्य नहीं था। यह तथ्य मंत्रालय के संज्ञान में भी नहीं था।
2.	**कर्बी एंगलोंग/असम**	2011-12	20.60	दूसरी किश्त जारी करते समय जिले के पास उपलब्ध के 10 प्रतिशत से अधिक में अथशेष को काटा जाना चाहिए। तथापि, मंत्रालय द्वारा उस जिले के मामले में इस शर्त से छूट प्रदान की गई थी जिसने संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक उपलब्ध निधियों के कम से कम 75 प्रतिशत का व्यय सूचित किया गया था। जिले ने 31 दिसम्बर 2011 को उपलब्ध निधियों का केवल 61.88 प्रतिशत उपयोग सूचित किया था। 1 अप्रैल 2011 को ₹29 करोड़ का अथशेष सूचित किया गया था जबकि दूसरी किश्त देय केवल ₹20.60 करोड़ थी। इसलिए, दूसरी किश्त जारी नहीं की गई थी। असम सरकार के अनुरोध पर मंत्रालय ने फरवरी 2012 तक निधियों के 75 प्रतिशत उपयोग की छूट प्रदान की तथा अव्ययित शेष के अधिक अग्रनयन के कारण कटौती लगाई। जिले को इन शर्तों कि (i) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य अंश का निगर्म, (ii) वापस की गई राशि का वर्तमान वर्ष के दौरान उपयोग किया जाना था तथा (iii) प्रोत्साहन विशिष्ट पैकेज आदि के संबंध में कोई उपयोग प्रमाण पत्र/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लंबित नहीं थी, से आगे छूट अनुमत की गई थी।

क्र.सं.	जिला/राज्य	वर्ष	अधिक निर्गम (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
				29 फरवरी 2012 को, जिले ने ₹52.47 करोड़ की उपलब्ध निधियों का 39.38 करोड़ (75 प्रतिशत) का व्यय सूचित किया तथा इसलिए मंत्रालय ने 29 मार्च 2012 को जिले को ₹20.60 करोड़ की दूसरी किश्त वापस की। लेखापरीक्षा ने पाया कि जिले ने 2011-12 के दौरान ₹1.13 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया; फिर भी न तो जिले ने 29 फरवरी 2012 को उपलब्ध निधियों में ब्याज घटक को शामिल किया गया था और न ही मंत्रालय ने इस पर विचार किया था। अगर उपलब्ध निधियों में ब्याज को शामिल किया गया होता तो जिला दूसरी किश्त का पात्र नहीं था। इस प्रकार, ₹20.60 करोड़ का निर्गम अनियमित था।
3.	**नागॉव/असम**	2008-09, 2009-10 एवं 2010-11	64.38	जिले ने दूसरी ने किश्त का दावा करते समय वास्तविक 44.53, 53.97 तथा 57.36 प्रतिशत से 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान व्यय को क्रमश: 85.39, 95.17 तथा 92.53 प्रतिशत तक बढ़ाया था। इस प्रकार जिले को अनियमित प्रकार से ₹64.38 करोड़ जारी किए गए थे।
4.	**सोनितपुर/असम**	2011-12	5.99	जिले को निधियों के अधिक अग्रनयन के कारण ₹5.99 करोड़ की कटौती करने के पश्चात दूसरी किश्त के रूप में ₹17.50 करोड़ जारी किए थे क्योंकि उपयोग 75 प्रतिशत से कम था। 28 फरवरी 2012 को, जिले ने 76 प्रतिशत निधियों को उपयोग बताया तथा मंत्रालय ने ₹5.99 करोड़ जारी किए (मार्च 2012) तथापि, लेखापरीक्षा ने पायाकि जिले ने 76 प्रतिशत व्यय का दावा करते समय इ.आ.यो. निधियों (₹0.97 करोड़) पर प्राप्त ब्याज तथा विविध आय को शामिल नहीं किया था। अगर निधियों की कुल उपलब्धता में ब्याज तथा विविध आय को शामिल किया गया होता तो जिला ₹5.99 करोड़ का पात्र नहीं था।

क्र.सं.	जिला/राज्य	वर्ष	अधिक निर्गम (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
5.	**शोलापुर/महाराष्ट्र**	2010-11, 2011-12 एवं 2012-13	58.88	जिले को दूसरी किश्त के रूप में ₹19.68 करोड़ (2010-11) जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि जिले ने दूसरी किश्त का दावा करते समय 2010-11 के दौरान व्यय के रूप में ₹49.17 करोड़ के पिछले वर्ष के अमुक्त चैको का दावा किया था तथा इसे 2010-11 के अथ शेष में भी शामिल किया था जिसे पहले ही 2009-10 हेतु व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। इस प्रकार, जिले ने व्यय को 53.38 से 90.12 प्रतिशत तक बढ़ाया। इसका परिणाम 19.68 करोड़ के अनियमित निर्गम में हुआ। इसी प्रकार, 2011-12 के दौरान जिले ने 2011-12 के दौरान व्यय के रूप में ₹42.74 करोड़ के पिछले वर्ष के अमुक्त चैको का दावा करके व्यय को 66.39 प्रतिशत के वास्तविक व्यय से 76.25 प्रतिशत तक बढ़ाया। इस प्रकार, जिले को अनियमित प्रकार से ₹19.23 करोड़ का निर्गम (फरवरी 2012) किया गया था। 2012-13 के लिए भी जिले को फरवरी तथा मार्च 2013 में ₹19.97 करोड़ जारी किए गए थे। जिले ने 2012-13 के दौरान व्यय के रूप में ₹9.69 करोड़ के पिछले वर्ष के अमुक्त चैकों का दावा किया था तथा इसे 2012-13 के अथ शेष में भी शामिल किया गया था जिसे 2011-12 के लिए व्यय के रूप में पहले ही दर्ज किया गया था। यह भी पाया गया था कि 1 अप्रैल 2012 के अथशेष को 2011-12 के दौरान प्राप्त राज्य अंश को घटाकर ₹19.30 करोड़ तक कम किया गया था जबकि इसका राज्य द्वारा जिले को सहयोग दिया गया था। 2012-13 के लिए भी राज्य अंश को ₹8.06 करोड़ तक घटाया गया था जबकि राज्य द्वारा जिले को सहयोग दिया गया था इसने गलत प्रकार से 68.04 से 99.22 प्रतिशत तक व्यय की प्रतिशतता को बढ़ाया। मंत्रालय द्वारा बढ़ाए गए व्यय की स्वीकृति के कारण ₹23.24 करोड़ के अव्ययित शेष के अधिक अग्रनयन को प्रभावित नहीं किया जा सका। इस प्रकार, जिला ₹19.97 करोड़ की दूसरी किश्त का पात्र नहीं था फिर भी जिसे जारी किया गया था।
	कुल		**163.14**	

अनुबंध-5.3.1

राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा उपलब्ध कराए गए 2008-09 हेतु इं.आ.यो. के अंतर्गत वित्तीय स्थिति

(पैराग्राफ 5.5 के संदर्भ)

(₹ लाख में)

राज्य/सं.शा. क्षे.	1.04.2008 को अथशेष	प्राप्त केन्द्रीय अंश	प्राप्त राज्य अंश	विविध प्राप्ति	कुल	व्यय	31.03.2009 को अंत शेष
आन्ध्र प्रदेश	31.13	693.47	125.00	0	849.60	899.38	-49.78
अरूणाचल प्रदेश	15.46	33.58	9.37	0	58.41	37.86	20.55
असम	39.09	561.79	195.13	15.76	811.77	610.81	200.96
बिहार	1080.68	2129.75	507.46	82.61	3800.5	1810.80	1989.70
छत्तीसगढ़	2.35	76.40	24.57	0.81	104.13	100.21	3.92
गोवा	1.31	2.89	0.78	0.05	5.03	4.25	0.78
गुजरात	60.73	365.70	89.68	6.73	522.84	339.12	183.72
हरियाणा	1.18	50.33	16.79	0.32	68.62	50.05	18.57
हिमाचल प्रदेश	1.93	18.54	5.15	0.33	25.95	21.44	4.51
जम्मू एवं कश्मीर	4.00	49.41	14.11	0.18	67.70	53.54	14.16
झारखण्ड	47.27	190.01	44.50	0	281.78	180.06	101.72
कर्नाटक	133.24	309.90	107.03	5.25	555.42	206.08	349.34
केरल	7.12	156.56	50.09	2.33	216.10	151.91	64.19
मध्य प्रदेश	4.54	234.36	75.01	0.30	314.21	289.00	25.21
महाराष्ट्र	48.96	445.09	164.53	15.62	674.20	587.02	87.18
मणिपुर	1.68	13.67	2.09	0.17	17.61	10.50	7.11
मेघालय	1.79	21.70	6.94	0.08	30.51	26.43	4.08
मिजोरम	0.10	11.81	2.49	0.04	14.44	14.33	0.11
नागालैण्ड	0.83	40.05	6.28	0.03	47.19	45.25	1.94
ओडिशा	43.12	425.58	66.64	2.46	537.80	251.99	285.81
पंजाब	4.30	54.12	10.01	0.37	68.80	46.39	22.41
राजस्थान	22.28	181.31	89.70	0.93	294.22	176.92	117.30
तमिलनाडु	17.29	245.46	123.06	1.14	386.95	376.00	10.95

राज्य/सं.शा. क्षे.	1.04.2008 को अथशेष	प्राप्त केन्द्रीय अंश	प्राप्त राज्य अंश	विविध प्राप्ति	कुल	व्यय	31.03.2009 को अंत शेष
त्रिपुरा	1.64	61.82	10.17	0.13	73.76	69.42	4.34
उत्तराखण्ड	8.98	48.87	15.99	0.72	74.56	40.93	33.63
उत्तर प्रदेश	79.88	957.13	223.96	9.14	1270.11	1072.19	197.92
पश्चिम बंगाल	159.88	572.28	130.80	5.36	868.32	434.64	433.68
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2.92	0.91	0	0.07	3.90	0.74	3.16
दादर एवं नागर हवेली	0.37	0.53	0	0.01	0.91	0.33	0.58
दमन एवं दीव	0.02	0	0	0	0.02	0.01	0.01
लक्षद्वीप	0	0.41	0	0.10	0.51	0.33	0.18
कुल	**1824.07**	**7953.43**	**2117.33**	**151.04**	**12045.87**	**7907.93**	**4137.94**

अनुबंध-5.3.2

राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा उपलब्ध कराए गए 2009-10 हेतु इ.आ.यो. के अंतर्गत वित्तीय स्थिति

(पैराग्राफ 5.5 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

राज्य/ स.शा.क्षे.	1.04.2008 को अथशेष	प्राप्त केन्द्रीय अंश	प्राप्त राज्य अंश	विविध प्राप्ति	कुल	व्यय	31.03.2009 को अंत शेष
आन्ध्र प्रदेश	-49.78	990.85	388.53	0	1329.60	1307.96	21.64
अरूणाचल प्रदेश	20.55	16.56	0	0	37.11	36.51	0.6
असम	200.96	536.80	162.03	18.82	918.61	744.83	173.78
बिहार	1989.70	1869.42	632.75	102.68	4594.55	2657.08	1937.47
छत्तीसगढ़	3.92	117.54	49.14	1.11	171.71	189.18	-17.47
गोवा	0.78	4.67	3.00	0.45	8.90	5.77	3.13
गुजरात	183.72	409.19	159.42	58.45	810.78	552.34	258.43
हरियाणा	18.57	52.26	17.42	0.88	89.13	80.78	8.35
हिमाचल प्रदेश	4.51	17.53	7.39	1.15	30.58	28.17	2.41
जम्मू एवं कश्मीर	14.16	65.46	24.34	0.29	104.25	90.47	13.78
झारखण्ड	101.72	389.97	134.86	0	626.55	401.61	224.94
कर्नाटक	349.34	294.29	149.31	8.03	800.97	532.51	268.46
केरल	64.19	162.62	54.40	2.16	283.37	212.57	70.80
मध्य प्रदेश	25.21	240.86	84.72	0.80	351.59	321.06	30.53
महाराष्ट्र	87.18	464.93	769.14	22.52	1343.77	1169.21	174.56
मणिपुर	7.11	20.45	4.10	0.46	32.12	26.80	5.32
मेघालय	4.08	35.21	3.67	0.14	43.10	38.54	4.56
मिजोरम	0.11	12.19	1.35	0.08	13.73	13.69	0.04
नागालैण्ड	1.94	28.63	1.72	0.29	32.58	31.39	1.19
ओडिशा	285.81	423.20	210.76	38.13	957.90	682.59	275.31
पंजाब	22.41	49.50	21.48	3.10	96.49	76.43	20.06
राजस्थान	117.30	205.66	114.21	9.22	446.39	283.41	162.98
तमिलनाडु	10.95	337.33	271.98	3.70	623.96	601.89	22.07

राज्य/ स.शा.क्षे.	1.04.2008 को अथशेष	प्राप्त केन्द्रीय अंश	प्राप्त राज्य अंश	विविध प्राप्ति	कुल	व्यय	31.03.2009 को अंत शेष
त्रिपुरा	4.34	63.17	7.17	0.16	74.84	63.26	11.58
उत्तराखण्ड	33.63	50.39	13.38	4.51	101.91	78.28	23.63
उत्तर प्रदेश	200.23[1]	1018.33	431.23	19.32	1669.11	1469.07	200.04
पश्चिम बंगाल	433.68	619.38	243.69	11.28	1308.03	884.79	423.24
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3.16	1.00	0	0.10	4.26	1.67	2.59
दादर एवं नागर हवेली	0.58	0.80	0	0.02	1.40	1.24	0.16
दमन एवं दीव	0.01	0	0	0.04	0.05	0.05	0
लक्षद्वीप	0.18	0.62	0	0.19	0.99	0.62	0.37
कुल	**4140.25**	**8498.81**	**3961.2**	**308.08**	**16908.33**	**12583.77**	**4324.55**

[1] इसकं अंतर्गत जिला बदायूँ द्वारा 2008-09 के संबंध 229;92 लाख जो 2009-10 में प्राप्त किये गये और 1.75 लाख का अंतर जिला कासगंज में दर्शित हुए।

अनुबंध-5.3.3

राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा प्रदत्त 2010-11 हेतु इं.आ.यो. के अंतर्गत वित्तीय स्थिति

(पैराग्राफ 5.5 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

राज्य/ सं.शा.क्षे.	1.04.2010 के अथशेष	प्राप्त केन्द्रीय अंश	प्राप्त राज्य अंश	विविध प्राप्ति	कुल	व्यय	31.03.2011 को अंत शेष
आन्ध्र प्रदेश	21.64	873.66	291.64	0	1186.94	1148.92	38.02
अरूणाचल प्रदेश	0.6	39.19	0.44	0	40.23	38.22	2.01
असम	173.78	685.78	242.33	21.60	1123.49	823.46	300.03
बिहार	1937.47	2008.37	760.99	98.80	4805.63	2450.00	2355.63
छत्तीसगढ़	-17.47	132.00	39.86	3.90	158.29	174.69	-16.40
गोवा	3.13	5.17	2.15	0.51	10.96	8.05	2.91
गुजरात	258.44	608.19	190.47	119.29	1176.39	756.89	419.50
हरियाणा	8.35	59.75	19.92	0.68	88.70	78.70	10.00
हिमाचल प्रदेश	2.41	22.45	7.61	0.71	33.18	30.74	2.44
जम्मू एवं कश्मीर	13.78	70.88	20.08	0.69	105.43	89.60	15.83
झारखण्ड	224.94	558.64	173.94	0	957.52	713.58	243.94
कर्नाटक	268.46	334.31	160.97	11.88	775.62	304.62	471.00
केरल	70.80	185.91	61.97	0.29	318.97	233.12	85.85
मध्य प्रदेश	30.53	440.36	152.80	2.74	626.43	331.70	294.73
महाराष्ट्र	174.56	525.31	532.81	55.16	1287.84	1060.59	227.25
मणिपुर	**5.32**	20.04	3.11	0.42	28.89	24.04	4.85
मेघालय	4.56	50.56	5.90	0.30	61.32	57.79	3.53
मिजोरम	0.04	13.00	1.72	0.07	14.83	14.77	0.06
नागालैण्ड	1.19	48.88	6.47	0.09	56.63	52.37	4.26
ओडिशा	275.31	476.63	130.00	1.62	883.56	691.02	192.54
पंजाब	20.06	77.69	21.48	7.54	126.77	77.79	48.98
राजस्थान	162.98	373.68	176.43	6.05	719.14	309.72	409.42
तमिलनाडु	22.07	353.77	254.06	2.27	632.17	584.28	47.89

राज्य/ सं.शा.क्षे.	1.04.2010 के अथशेष	प्राप्त केन्द्रीय अंश	प्राप्त राज्य अंश	विविध प्राप्ति	कुल	व्यय	31.03.2011 को अंत शेष
त्रिपुरा	11.58	104.41	9.16	0.30	125.45	91.55	33.90
उत्तराखण्ड	23.63	51.83	20.08	1.56	97.10	80.62	16.48
उत्तर प्रदेश	200.28[2]	1163.19	338.84	18.85	1721.16	1486.88	234.28
पश्चिम बंगाल	423.24	593.49	197.92	10.56	1225.21	751.72	473.49
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2.59	1.49	0	0.09	4.17	2.35	1.82
दादर एवं नागर हवेली	0.16	0.92	0	0.02	1.10	0.41	0.69
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0.37	0	0	0.04	0.41	0.25	0.16
कुल	**4324.80**	**9879.55**	**3823.15**	**366.03**	**18393.53**	**12468.44**	**5925.09**

[2] इसमें जिला बलरामपुर में उसके ब्लॉकों में पड़े हुए ₹24 लाख शामिल थे।

अनुबंध-5.3.4

राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा प्रदत्त 2011-12 हेतु इं.आ.यो. के अंतर्गत वित्तीय स्थिति

(पैराग्राफ 5.5 के संदर्भ में)

(₹लाख में)

राज्य/ सं.शा.क्षे.	1.04.2010 के अथशेष	प्राप्त केन्द्रीय अंश	प्राप्त राज्य अंश	विविध प्राप्ति	कुल	व्यय	31.03.2011 को अंत शेष
आन्ध्र प्रदेश	38.02	892.37	281.83	0	1212.22	1113.01	99.21
अरूणाचल प्रदेश	2.01	28.58	11.16	0	41.75	40.86	0.89
असम	300.03	594.01	150.85	19.39	1064.28	909.21	155.07
बिहार	2355.63	2278.82	709.12	119.96	5463.53	3177.98	2285.55
छत्तीसगढ़	-16.40	130.97	52.18	1.37	168.12	185.57	-17.45
गोवा	2.91	5.22	6.50	0.78	15.41	12.63	2.78
गुजरात	419.50	384.34	125.31	105.66	1034.81	554.17	480.64
हरियाणा	10.00	58.12	19.37	0.88	88.37	80.61	7.76
हिमाचल प्रदेश	2.44	20.30	6.78	0.47	29.99	27.24	2.75
जम्मू एवं कश्मीर	15.83	57.96	23.45	0.59	97.83	82.39	15.44
झारखण्ड	243.94	207.25	82.30	0	533.49	511.37	22.12
कर्नाटक	471.00	248.96	110.00	11.55	841.51	317.30	524.21
केरल	85.85	181.60	58.22	1.04	326.71	264.20	62.51
मध्य प्रदेश	294.73	404.29	128.63	5.62	833.27	624.89	208.38
महाराष्ट्र	227.25	505.23	448.14	98.84	1279.46	1061.53	217.93
मणिपुर	4.85	29.57	1.38	0.44	36.24	36.37	-0.13
मेघालय	3.53	58.25	5.35	0.47	67.60	63.76	3.84
मिजोरम	0.06	11.09	1.47	0.10	12.72	12.62	0.10
नागालैण्ड	4.26	42.26	3.03	0.15	49.70	46.70	3.00
ओडिशा	192.54	447.20	152.20	40.55	832.49	634.01	198.48
पंजाब	48.98	23.98	11.67	8.87	93.50	53.94	39.56
राजस्थान	409.42	415.91	179.73	16.91	1021.97	489.68	532.29
तमिलनाडु	47.89	353.42	349.04	4.83	755.18	679.29	75.89

राज्य/ सं.शा.क्षे.	1.04.2010 के अथशेष	प्राप्त केन्द्रीय अंश	प्राप्त राज्य अंश	विविध प्राप्ति	कुल	व्यय	31.03.2011 को अंत शेष
त्रिपुरा	33.90	108.27	15.14	0.42	157.73	127.18	30.55
उत्तराखण्ड	16.48	58.21	19.63	0.65	94.97	76.38	18.59
उत्तर प्रदेश	234.28	1136.88	416.44	22.68	1810.28	1504.43	305.85
पश्चिम बंगाल	473.49	648.83	211.60	40.67	1374.59	897.18	477.41
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1.82	0.98	0	0.04	2.84	2.47	0.37
दादर एवं नागर हवेली	0.69	0	0	0.04	0.73	0.66	0.07
दमन एवं दीव	0	0.41	0	0	0.41	0.19	0.22
लक्षद्वीप	0.16	0.71	0	0.02	0.89	0.35	0.54
कुल	**5925.09**	**9333.99**	**3580.52**	**502.99**	**19342.59**	**13588.17**	**5754.42**

अनुबंध-5.3.5

राज्यों/सं.शाक्षे. द्वारा प्रदत्त 2012-13 हेतु इं.आ.यो. के अंतर्गत वित्तीय स्थिति

(पैराग्राफ 5.5 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

राज्य/ सं.शा.क्षे.	1.04.2012 को अथशेष	प्राप्त केन्द्रीय अंश	प्राप्त राज्य अंश	विविध प्राप्ति	कुल	व्यय	31.03.2013 को अंत शेष
आन्ध्र प्रदेश	99.21	846.79	174.14	0	1120.14	1132.53	-12.39
अरूणाचल प्रदेश	0.89	42.43	7.36	0	50.68	48.86	1.82
असम	155.07	543.30	177.11	9.77	885.25	747.81	137.44
बिहार	2285.55	1825.32	754.00	206.01	5070.88	3390.29	1680.59
छत्तीसगढ़	-17.45	291.99	97.28	2.93	374.75	366.07	8.68
गोवा	2.78	5.14	1.66	0.44	10.02	7.02	3.00
गुजरात	480.64	215.82	79.59	37.90	813.95	428.07	385.88
हरियाणा	7.76	66.00	21.00	0.77	95.53	80.27	15.26
हिमाचल प्रदेश	2.75	21.51	7.25	0.28	31.79	31.00	0.79
जम्मू एवं कश्मीर	15.44	55.78	20.42	0.47	92.11	78.37	13.74
झारखण्ड	22.12	259.71	87.71	0	369.54	434.20	-64.66
कर्नाटक	524.21	276.64	220.34	75.42	1096.61	798.16	298.45
केरल	62.51	153.44	53.02	37.41	306.38	218.31	88.07
मध्य प्रदेश	208.38	382.47	145.40	7.55	743.80	417.49	326.31
महाराष्ट्र	217.93	552.46	536.25	46.77	1353.41	852.73	500.68
मणिपुर	-0.13	17.89	2.68	2.30	22.74	19.78	2.96
मेघालय	3.84	54.47	5.05	0.58	63.94	52.16	11.78
मिजोरम	0.10	10.80	1.25	0.10	12.25	12.22	0.03
नागालैण्ड	3.00	36.42	2.02	0	41.44	38.49	2.95
ओडिशा	198.48	477.27	189.73	6.85	872.33	718.32	154.01
पंजाब	39.56	6.59	1.90	6.75	54.80	18.83	35.97
राजस्थान	532.29	270.84	104.73	0	907.86	433.13	474.73
तमिलनाडु	75.89	382.81	396.71	2.83	858.24	761.20	97.04

राज्य/ सं.शा.क्षे.	1.04.2012 को अथशेष	प्राप्त केन्द्रीय अंश	प्राप्त राज्य अंश	विविध प्राप्ति	कुल	व्यय	31.03.2013 को अंत शेष
त्रिपुरा	30.55	58.02	5.29	0.84	94.70	72.79	21.91
उत्तराखण्ड	18.59	43.01	14.18	1.17	76.95	60.21	16.74
उत्तर प्रदेश	305.85	935.65	294.60	22.41	1558.51	1089.61	468.90
पश्चिम बंगाल	477.41	460.24	169.11	19.40	1126.16	873.93	252.23
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.37	7.92	0	0.10	8.39	1.69	6.70
दादर एवं नागर हवेली	0.07	0.90	0	0.04	1.01	0.21	0.80
दमन एवं दीव	0.22	0	0	0.01	0.23	0.01	0.22
लक्षद्वीप	0.54	0	0	0.01	0.55	0.35	0.20
कुल	**5754.42**	**8301.63**	**3569.78**	**489.11**	**18114.94**	**13184.11**	**4930.83**

अनुबंध-5.3.6

मंत्रालय एवं राज्य/सं.शा.क्षे.के दिये गये आंकड़ों के मध्य अंतर

(पैराग्राफ 5.5 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			कुल		
	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर
आन्ध्र प्रदेश	820.83	693.47	127.36	856.29	990.85	-134.56	873.66	873.66	0.00	892.37	892.37	0.00	842.44	846.79	-4.35	4285.59	4297.14	-11.55
अरूणाचल प्रदेश	34.83	33.58	1.25	33.37	16.56	16.81	37.84	39.19	-1.35	31.98	28.58	3.40	33.27	42.43	-9.16	171.29	160.34	10.95
असम	683.53	561.79	121.74	667.37	536.8	130.57	710.32	685.78	24.54	767.68	594.01	173.67	573.49	543.3	30.19	3402.39	2921.68	480.71
बिहार	2397.82	2129.75	268.07	2008.55	1869.42	139.13	2260.59	2008.37	252.22	2176.91	2278.82	-101.91	1718.17	1825.32	-107.15	10562.04	10111.68	450.36
छत्तीसगढ़	158.49	76.4	82.09	162.8	117.54	45.26	132.8	132	0.80	253.87	130.97	122.90	167.8	291.99	-124.19	875.76	748.90	126.86
गोवा	2.89	2.89	0.00	4.67	4.67	0.00	5.17	5.17	0.00	5.45	5.22	0.23	4.9	5.14	-0.24	23.08	23.09	-0.01
गुजरात	358.38	365.7	-7.32	415.75	409.19	6.56	519.35	608.19	-88.84	380.69	384.34	-3.65	208.14	215.82	-7.68	1882.31	1983.24	-100.93
हरियाणा	50.31	50.33	-0.02	52.45	52.26	0.19	59.75	59.75	0.00	60.45	58.12	2.33	63.58	66	-2.42	286.54	286.46	0.08
हिमाचल प्रदेश	18.06	18.54	-0.48	18.64	17.53	1.11	21.43	22.45	-1.02	21.19	20.3	0.89	21.79	21.51	0.28	101.11	100.33	0.78
जम्मू एवं कश्मीर	71.29	49.41	21.88	57.25	65.46	-8.21	66.43	70.88	-4.45	58.3	57.96	0.34	57.75	55.78	1.97	311.02	299.49	11.53
झारखण्ड	296.92	190.01	106.91	301.6	389.97	-88.37	558.64	558.64	0.00	218.17	207.25	10.92	257.08	259.71	-2.63	1632.41	1605.58	26.83
कर्नाटक	282.09	309.9	-27.81	302.27	294.29	7.98	387.98	334.31	53.67	298.96	248.96	50.00	207.88	276.64	-68.76	1479.18	1464.10	15.08
केरल	156.56	156.56	0.00	162.62	162.62	0.00	185.91	185.91	0.00	189.65	181.6	8.05	145.4	153.44	-8.04	840.14	840.13	0.01
मध्य प्रदेश	234.36	234.36	0.00	240.86	240.86	0.00	442.23	440.36	1.87	435.88	404.29	31.59	392.33	382.47	9.86	1745.66	1702.34	43.32
महाराष्ट्र	470.24	445.09	25.15	474.43	464.93	9.50	523.14	525.31	-2.17	538.82	505.23	33.59	513.07	552.46	-39.39	2519.70	2493.02	26.68
मणिपुर	16.4	13.67	2.73	20.66	20.45	0.21	25.41	20.04	5.37	23.63	29.57	-5.94	21.38	17.89	3.49	107.48	101.62	5.86
मेघालय	21.38	21.7	-0.32	37.83	35.21	2.62	55.72	50.56	5.16	55.13	58.25	-3.12	48.95	54.47	-5.52	219.01	220.19	-1.18
मिजोरम	12.51	11.81	0.70	12.68	12.19	0.49	13.36	13	0.36	11.09	11.09	0.00	10.8	10.8	0.00	60.44	58.89	1.55

राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			कुल		
	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर
नागालैण्ड	39.59	40.05	-0.46	39.96	28.63	11.33	44.56	48.88	-4.32	34.42	42.26	-7.84	36.42	36.42	0.00	194.95	196.24	-1.29
ओडिशा	460.82	425.58	35.24	460.27	423.2	37.07	475.74	476.63	-0.89	627.31	447.2	180.11	468	477.27	-9.27	2492.14	2249.88	242.26
पंजाब	62.04	54.12	7.92	64.63	49.5	15.13	63.59	77.69	-14.10	21.75	23.98	-2.23	6.59	6.59	0.00	218.60	211.88	6.72
राजस्थान	181.11	181.31	-0.20	188.7	205.66	-16.96	374.23	373.68	0.55	394.73	415.91	-21.18	262.11	270.84	-8.73	1400.88	1447.40	-46.52
तमिलनाडु	294.14	245.46	48.68	305.47	337.33	-31.86	348.01	353.77	-5.76	351.73	353.42	-1.69	369.57	382.81	-13.24	1668.92	1672.79	-3.87
त्रिपुरा	66.97	61.82	5.15	63.69	63.17	0.52	108.27	104.41	3.86	115.31	108.27	7.04	61.86	58.02	3.84	416.10	395.69	20.41
उत्तराखण्ड	48.57	48.87	-0.30	50.45	50.39	0.06	53.95	51.83	2.12	58.27	58.21	0.06	40.81	43.01	-2.20	252.05	252.31	-0.26
उत्तर प्रदेश	975.69	957.13	18.56	1014.8	1018.33	-3.53	1149.9	1163.19	-13.29	1158.06	1136.88	21.18	877.74	935.65	-57.91	5176.19	5211.18	-34.99
पश्चिम बंगाल	572.12	572.28	-0.16	607.27	619.38	-12.11	630.14	593.49	36.65	676.08	648.83	27.25	436.31	460.24	-23.93	2921.92	2894.22	27.70
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.93	0.91	0.02	0.98	1	-0.02	0.77	1.49	-0.72	0.98	0.98	0.00	7.92	7.92	0.00	11.58	12.30	-0.72
दादर एवं नागर हवेली	0.53	0.53	0.00	0.8	0.8	0.00	0.92	0.92	0.00	0.9	0	0.90	0	0.9	-0.90	3.15	3.15	0.00
दमन एवं दीव	0	0	0.00	0	0	0.00	0.41	0	0.41	0	0.41	-0.41	0	0	0.00	0.41	0.41	0.00
लक्षद्वीप	0.6	0.41	0.19	0.62	0.62	0.00	0.71	0	0.71	0	0.71	-0.71	0	0	0.00	1.93	1.74	0.19
कुल	**8790.00**	**7953.43**	**836.57**	**8627.73**	**8498.81**	**128.92**	**10130.93**	**9879.55**	**251.38**	**9859.76**	**9333.99**	**525.77**	**7855.55**	**8301.63**	**-446.08**	**45263.97**	**43967.41**	**1296.56**

अनुबंध-5.3.7

मंत्रालय एवं राज्य/सं.शा.क्षे. के व्यय आंकडों के मध्य अंतर

(पैराग्राफ 5.5 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

ज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			कुल		
	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर
आन्ध्र प्रदेश	899.38	899.38	0.00	1307.96	1307.96	0.00	1134.81	1148.92	-14.11	1113.01	1113.01	0.00	1132.53	1132.53	0.00	5587.69	5601.80	-14.11
अरूणाचल प्रदेश	28.35	37.86	-9.51	24.01	36.51	-12.50	38.22	38.22	0.00	5.80	40.86	-35.06	6.90	48.86	-41.96	103.28	202.31	-99.03
असम	627.04	610.81	16.23	863.55	744.83	118.72	933.32	823.46	109.86	915.74	909.21	6.53	667.70	747.81	-80.11	4007.35	3836.12	171.23
बिहार	2154.36	1810.80	343.56	2995.94	2657.08	338.86	3324.84	2450.00	874.84	2738.58	3177.98	-439.40	2973.19	3390.29	-417.10	14186.91	13486.15	700.76
छत्तीसगढ़	107.33	100.21	7.12	322.05	189.18	132.87	196.31	174.69	21.62	346.24	185.57	160.67	307.87	366.07	-58.20	1279.80	1015.72	264.08
गोवा	3.98	4.25	-0.27	5.43	5.77	-0.34	8.04	8.05	-0.01	11.84	12.63	-0.79	5.72	7.02	-1.30	35.01	37.72	-2.71
गुजरात	338.37	339.12	-0.75	567.96	552.34	15.62	692.77	756.89	-64.12	578.85	554.17	24.68	433.95	428.07	5.88	2611.90	2630.59	-18.69
हरियाणा	53.57	50.05	3.52	84.53	80.78	3.75	82.26	78.70	3.56	81.63	80.61	1.02	68.40	80.27	-11.87	370.39	370.41	-0.02
हिमाचल प्रदेश	23.30	21.44	1.86	30.56	28.17	2.39	29.25	30.74	-1.49	27.65	27.24	0.41	30.64	31.00	-0.36	141.40	138.59	2.81
जम्मू एवं कश्मीर	39.39	53.54	-14.15	59.68	90.47	-30.79	53.76	89.60	-35.84	25.91	82.39	-56.48	24.64	78.37	-53.73	203.38	394.37	-190.99
झारखण्ड	163.80	180.06	-16.26	359.98	401.61	-41.63	693.57	713.58	-20.01	515.99	511.37	4.62	409.30	434.20	-24.90	2142.64	2240.82	-98.18
कर्नाटक	217.84	206.08	11.76	536.34	532.51	3.83	482.49	304.62	177.87	302.67	317.30	-14.63	804.38	798.16	6.22	2343.72	2158.67	185.05
केरल	151.91	151.91	0.00	212.57	212.57	0.00	237.59	233.12	4.47	264.18	264.20	-0.02	220.82	218.31	2.51	1087.07	1080.11	6.96
मध्य प्रदेश	408.30	289.00	119.30	339.54	321.06	18.48	324.18	331.70	-7.52	682.48	624.89	57.59	388.73	417.49	-28.76	2143.23	1984.14	159.09
महाराष्ट्र	545.59	587.02	-41.43	1285.89	1169.21	116.68	1059.35	1060.59	-1.24	904.94	1061.53	-156.59	1082.78	852.73	230.05	4878.55	4731.08	147.47
मणिपुर	4.25	10.50	-6.25	16.84	26.80	-9.96	14.50	24.04	-9.54	15.59	36.37	-20.78	13.52	19.78	-6.26	64.70	117.49	-52.79

ज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			कुल		
	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर
मेघालय	26.43	26.43	0.00	38.54	38.54	0.00	54.05	57.79	-3.74	70.73	63.76	6.97	52.16	52.16	0.00	241.91	238.68	3.23
मिजोरम	15.29	14.33	0.96	14.22	13.69	0.53	13.40	14.77	-1.37	12.61	12.62	-0.01	9.90	12.22	-2.32	65.42	67.63	-2.21
नागालैण्ड	54.99	45.25	9.74	30.39	31.39	-1.00	50.81	52.37	-1.56	47.40	46.70	0.70	0.00	38.49	-38.49	183.59	214.20	-30.61
ओडिशा	257.09	251.99	5.10	768.84	682.59	86.25	691.02	691.02	0.00	628.88	634.01	-5.13	774.54	718.32	56.22	3120.37	2977.93	142.44
पंजाब	44.30	46.39	-2.09	77.83	76.43	1.40	76.41	77.79	-1.38	62.74	53.94	8.80	18.83	18.83	0.00	280.11	273.38	6.73
राजस्थान	204.54	176.92	27.62	298.67	283.41	15.26	376.43	309.72	66.71	604.49	489.68	114.81	456.20	433.13	23.07	1940.33	1692.86	247.47
तमिलनाडु	339.43	376.00	-36.57	444.87	601.89	-157.02	440.72	584.28	-143.56	453.54	679.29	-225.75	381.45	761.20	-379.75	2060.01	3002.66	-942.65
त्रिपुरा	63.44	69.42	-5.98	38.19	63.26	-25.07	86.22	91.55	-5.33	149.27	127.18	22.09	0.00	72.79	-72.79	337.12	424.20	-87.08
उत्तराखण्ड	42.43	40.93	1.50	78.28	78.28	0.00	80.62	80.62	0.00	74.44	76.38	-1.94	60.19	60.21	-0.02	335.96	336.42	-0.46
उत्तर प्रदेश	1070.97	1072.19	-1.22	1587.70	1469.07	118.63	1478.33	1486.88	-8.55	1424.35	1504.43	-80.08	1011.03	1089.61	-78.58	6572.38	6622.18	-49.80
पश्चिम बंगाल	453.95	434.64	19.31	891.64	884.79	6.85	796.83	751.72	45.11	854.05	897.18	-43.13	793.49	873.93	-80.44	3789.96	3842.26	-52.30
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.74	0.74	0.00	1.67	1.67	0.00	2.35	2.35	0.00	2.47	2.47	0.00	72.58	1.69	70.89	79.81	8.92	70.89
दादर एवं नागर हवेली	0.17	0.33	-0.16	0.00	1.24	-1.24	0.00	0.41	-0.41	0.00	0.66	-0.66	0.00	0.21	-0.21	0.17	2.85	-2.68
दमन एवं दीव	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.05	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	-0.19	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.26	-0.26

ज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			कुल		
	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर
लक्षद्वीप	0.74	0.33	0.41	0.57	0.62	-0.05	0.00	0.25	-0.25	0.00	0.35	-0.35	0.00	0.35	-0.35	1.31	1.90	-0.59
कुल	**8341.27**	**7907.93**	**433.34**	**13284.24**	**12583.77**	**700.47**	**13452.45**	**12468.44**	**984.01**	**12916.07**	**13588.17**	**-672.10**	**12201.44**	**13184.11**	**-982.67**	**60195.47**	**59732.42**	**463.05**

अनुबंध 5.4

राज्य अंश का कम निर्गम

(पैराग्राफ 5.8 के सदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य के नाम	देय राज्य अंश	जारी राज्य अंश	कम निर्गम
1.	**आन्ध्र प्रदेश**	1463.17	1261.13	202.04
2.	**अरूणाचल प्रदेश**	-	-	1.13
3.	**असम**	425.70	406.71	18.99
4.	हरियाणा	21.22	20.23	0.99
5.	जम्मू एवं कश्मीर[3]	28.07	23.54	4.53
6.	झारखण्ड	535.19	523.30	11.89
7.	मणिपुर	18.40	13.36	5.03
8.	नागालैण्ड (2012-13 के लिए ही)	4.05	0	4.05
9.	पंजाब	70.63	66.54	4.09
10.	त्रिपुरा	2.99	0.87	2.12
11.	उत्तराखण्ड	84.11	83.26	0.85
	कुल			**255.71**

[3] छः चयनित जिलों में से पांच (बडगाम, जम्मू, कुलग्राम, पूंछ एवं रामबान)

अनुबंध-5.5

राज्य हिस्सेदारी के विमोचन में विलंब

(पैराग्राफ 5.9 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	दिनों में विलंब
1.	आन्ध्र प्रदेश	6 से 363
2.	असम	365 से 730
3.	बिहार	1 से 305
4.	छत्तीसगढ़	2 से 744
5.	गोवा	3 से 140
6.	गुजरात	1 से 187
7.	हरियाणा	20 से 67
8.	झारखण्ड	2 से 239
9.	कर्नाटक	18 से 237
10.	केरल	10 से 215
11.	मणिपुर	31 से 338
12.	मेघालय	60 से 210
13.	मिजोरम	11 से 279
14.	ओडिशा	20 से 307
15.	राजस्थान	4 से 602
16.	त्रिपुरा	7 से 253
17.	उत्तर प्रदेश	2 से 337
18.	उत्तराखण्ड (चयनित जिला)	2 से 266
19.	पश्चिम बंगाल	24 से 160

अनुबंध-5.6.1

निधियों का विपथन

(पैरा के 5.14 संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्रों/ योजनाएं जिनके लिए निधियों का विपथन हुआ	राशि (₹ करोड में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	खम्मम जिले में रियासती स्थल निधियों पर ₹0.03 करोड़ राशि के ब्याज को योजना के अंतर्गत विविध प्राप्तियों के रूप में लेने के बजाय फेसिंग के प्रति एवं जिला कलक्टर के कार्यालय में विद्युतीय संस्थान उपलब्ध कराने के लिए विपथित (नवम्बर 2011) किया गया था।	0.03
2.	असम	आठ चयनित जिलों मे, ₹0.16 करोड़ की इं.आ.यो. निधियाँ विभिन्न प्रयोजनों यथा मनरेगस, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), जनगणना पर प्रशिक्षण, कार्यालय भवन के नवीकरण आदि के लिए विपथित हुई थीं।	0.16
3.	छत्तीसगढ़	1 जि.पं. रामचन्द्रपुर ने ₹0.65 करोड़ मनरेगस को विपथित किया था, हाँलांकि इसकी आपूर्ति 48 से लेकर 260 दिनों तक की अवधि के पश्चात कर दी गयी थी। 2 जि.प. पाली, (जिला कोरबा), ने ₹0.37 करोड़ की राशि 2006 - 2009 के दौरान स्व.ग्रा.स्व.यो. को विपथित किया था।	0.65 0.37
4.	गुजरात	जि.ग्रा.वि.प्रा. जूनागढ़ ने इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹0.65 करोड़ मनरेगस को विपथित किया था। हालाँकि विपथित राशि को इं.आ.यो. खाते में 10 से 105 दिनों के पश्चात् उपलब्ध करा दिया गया था।	15.90
5.	झारखण्ड	1. जि.ग्रा.वि.प्रा., रांची ने ₹0.28 करोड़ बीरसा आवास योजना के व्यय को पूरा करने के लिए विपथित किया था, जिसमें से रू. 0.18 करोड़ की आपूर्ति अभी की जानी थी। 2 जि.ग्रा.वि.प्रा., पूर्वी सिंहभूमि ने ₹0.12 करोड़ की राशि वी.पी.एल. सर्वेक्षण कार्य हेतु 2008-09 के दौरान विपथित की थी।	0.28 0.12
6.	केरल	गरीबी उन्मूलन इकाई (ग.उ.इ.) मलप्पुरम ने ₹450 करोड़ रियासती योजना से मनरेगस को विपथित किया था परंतु बाद मे इसे इं.आ.यों. में उपलब्ध करा दिया गया था।	4.50
7.	मध्य प्रदेश	ग्रा.पं. (दिंदोरी जिले के अंतर्गत महदवानी ब्लॉक) में ₹0.02 करोड़ की	0.02

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्रों/ योजनाएं जिनके लिए निधियों का विपथन हुआ	राशि (₹ करोड में)
		राशि विद्यालय भवन के निर्माण हेतु प्रयुक्त की गयी थी।	
8.	ओडिशा	1. आठ जिलों के 10 ब्लॉकों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घटित हुआ कि ₹6.15 करोड़ के इं.आ.यो. निधि का विपथन 2008-13 के दौरान अन्य योजनाओं यथा मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन (वृ.पे.) आदि के लिए किया गया था जिसे अगस्त 2013 तक उपलब्ध नहीं कराया गया था। 2. थाना धनकौड़ा (जिला सम्बलपुर) में इं.आ.यो. निधियों से सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु ₹0.31 करोड़ का अप्राधिकृत व्यय किया गया।	6.15 0.31
9.	पंजाब	समना (पटियाला जिला) एवं मजरी ब्लॉक (एस.ए.एस. नगर जिला) के बी.डी.पी.ओ. ने ₹0.05 करोड़ का अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं, यथा ग्रा.वि.नि. एवं बारहवें वित्त आयोग में विपथन किया था।	0.05
10.	राजस्थान	1. जि.प. (आर. डी. सेल), करौली ने ₹0.48 करोड़ का अनुसूचित जाति अतिरिक्त योजना में 2009-12 के दौरान अनियमित रूप से विपथन किया था। तथापि, इन निधियों को बाद में इं.आ.यो. खाते में उपलब्ध (मार्च 2012 एवं मार्च 2013) करा दिया गया था। 2. जि.प. (आर. डी. सेल), उदयपुर ने प्रशासनिक अध्यक्ष को 2008-13 के दौरान ₹0.85 करोड़ का विपथन किया था। जिसमें से, ₹0.74 करोड़ को 87 से लेकर 261 दिनों के बाद उपलब्ध कराया गया था। ₹0.11 करोड़ की शेष राशि, जिसे अप्रैल 2011 में अंतरित किया गया था, की लेखापरीक्षा को अवधि तक वापस नहीं किया गया था।	0.48 0.85
11.	तमिलनाडु	1. जि.ग्रा.वि.प्रा., तिरूवन्नमलाई ने अगस्त 2011 के दौरान मनरेगस को ₹4.00 करोड़ की राशि विपथित की थी और उसे उसी माह में उपलब्ध करा दिया था। 2. प्र.वि.अ., पल्लडम (तिरूपुर जिला) ने अन्य योजना खाताओं यथा, ग्रामीण अवसंरचना योजना (ग्रा.अ.यो.) एवं तमिलनाडु ग्राम अधिवास सुधार योजना (त.ग्रा.अ.सु.यो.), में ₹0.39 करोड़ का विपथन अक्तूबर 2010 एवं फरवरी 2013 के मध्य किया था। ₹0.39 करोड़ की विपथित	4.00 0.39

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्रों/ योजनाएं जिनके लिए निधियों का विपथन हुआ	राशि (₹ करोड में)
		निधि को लेखापरीक्षा की तिथि तक इं.आ.यो. खाते में उपलब्ध नहीं कराया गया था।	
12.	त्रिपुरा	कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण विकास प्रभाग ने, दुकली एवं हजमारा के प्र.वि.अ. से जुलाई 2010 एवं जनवरी 2011 के दौरान इं. आ. यो. भंडार सामग्रियों के क्रय हेतु ₹0.28 करोड़ प्राप्त किया। उसे हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यालय भवन, इंद्रनगर, हजमारा के शंखोला बाँस हस्तशिल्प एवं विद्यासागर बाजार में बाजार स्टॉल के निर्माण के अनुरक्षण/नवीकरण के प्रति विपथित किया गया था।	0.28
13.	उत्तराखंड	चार जि.ग्रा.वि.प्रा. (हरिद्वार, देहरादून, यू.एस.नगर एवं नैनीताल) में ₹1.75 करोड़ की अन्य योजनाओं/मदों मुख्यतः आकस्मिकता, कार्यालय व्यय एवं स्थापना जैसे में विपथित किया गया था, जिसमें से, ₹0.52 करोड़ लेखापरीक्षा की तिथि तक असमायोजित पड़े रहे।	1.75
14.	अं. एवं नि. द्वीपसमूह	जि.ग्रा.वि.प्रा., दक्षिण अण्डमान ने इं. आ. यो. खाते से ₹0.70 करोड़ (जून 2010) मनरेगस में हस्तांतरित किया था। इसे अगस्त 2010 में इं. आ. यो. खाते में वापस हस्तांतरित कर दिया गया था।	0.70
15.	लक्षद्वीप	परियोजना अधिकारी, आर. डी. सेल, कवरती ने 2008-09 के दौरान ₹0.13 करोड़ (₹0.10 करोड़ जि.ग्रा.वि.प्रा. को, ₹0.02 करोड़ स्व.ग्रा.स्व.यो. को एवं ₹0.01 करोड़ एस.जी.आर.वाई. को) का विपथन किया था। जहाँ, जि.ग्रा.वि.प्रा. को विपथित ₹0.10 करोड़ उसी वर्ष वापस प्राप्त हो गया, ₹0.03 करोड़ को लेखापरीक्षा की तिथि तक उपलब्ध नहीं किया जा सका था।	0.13
			37.12

अनुबंध-5.6.2

गैर - अनुमेय मदों पर व्यय

(पैरा 5.14 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अभ्युक्ति	राशि (₹ करोड़ में)
1.	अरूणाचल प्रदेश	लाभार्थियों को स्वयं प्रबंध करके घरों का निर्माण करना था। पश्चिम सियांग जिले में, लाभार्थियों को ₹0.15 करोड़ भी अपने घरों के निर्माण के लिए पारिश्रमिक के रूप में 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान इं. आ. यो. के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सहायता के अतिरिक्त दी गयी थी, जो इं.आ.यो. दिशा-निर्देशों के प्रवधानों का उल्लंघन था।	0.15
		2008-09 हेतु जि.ग्रा.वि.प्रा पपुम्पारे के वार्षिक खाते के अनुसार, विविध भुगतानों और इं.आ.यो. के अंतर्गत कार्यालय लेखा-सामग्री पर व्यय हेतु ₹0.06 करोड़ खर्च किया था।	0.06
2.	असम	आठ चयनित जिलों (नगांव, बर्पेता, कचर, करीमगंज, कोकराझार, सोनीतपुर, करबी अंगलोंग एवं शिवसागर) के अंतर्गत 68 विकास ब्लॉकों में, ₹1.36 करोड़ 2008-13 के दौरान आकस्मिकता/प्रशासनिक एवं मॉनिटरिंग प्रयोजनों पर व्यय किया गया था।	1.36
3.	बिहार	पाँच चयनित जिलों (औरंगाबाद, भोजपुर, समस्तीपुर, सुपौल एवं पश्चिम चंपारण) में, ₹0.35 करोड़ दीवार पेंटिंग, आकस्मिकता, बैंक शुल्क, बी.पी.एल. सूची बनाने आदि पर प्रयुक्त किया गया था।	0.35
4.	छत्तीसगढ़	जि.प. धारसिवा (रायपुर), जि.प. जगदलपुर एवं जि.प. पाली (कोरबा) में, इं.आ.यो. निधियों से लेखा-सामग्री, फोटो कॉपी कराने एवं अन्य विविध मदों पर ₹0.03 करोड़ का व्यय किया गया था।	0.03
6.	गुजरात	सुरेन्द्रनगर जिले के अंतर्गत चार ब्लॉक (चोटिला- ₹0.20 लाख, लिमखेड़ा - ₹1.86 लाख, सायला - ₹0.66 लाख	0.24

		एवं जालोद - ₹14.97 लाख) एवं बडोदरा जिले के अंतर्गत एक ब्लॉक (कर्जन - ₹1.00 लाख), दो ब्लॉक (दांतेवाडा - ₹0.63 लाख एवं दीसा - ₹1.50 लाख) एवं जि.ग्रा.वि.प्रा. सुरेन्द्रनगर (₹3.18 लाख) ने आकस्मिकता/कार्यालय व्ययों पर खर्च किया था।	
7.	जम्मू एवं कश्मीर	तीन ब्लॉकों (द्रास, बी.के.पोरा एवं रामसू) ने प्रशासनिक प्रभारों पर इं.आ.यो. निधियों से ₹0.01 करोड़ की राशि खर्च की थी।	0.01
कुल			**2.20**

अनुबंध-5.7

निधियों के संदिग्ध/पुष्ट दुर्विनियोजन

(पैरा 5.16 के संदर्भ में)

क्र. स.	राज्य	अभ्युक्ति	राशि (₹ करोड़ में)
		पुष्ट दुर्विनियोजन के मामले	
1.	असम (i)	बलीजाना ब्लॉक (गोलपारा जिला) के कनिष्ठ अभियंता (क.अ.) ने वर्ष 2011-12 में 51 इं.आ.यो. घरों के निर्माण हेतु संस्वीकृत ₹0.24 करोड़ निकाला था और लाभार्थियों को केवल ₹0.13 करोड़ ही अदा किया था। संबंधित क.अ.ने.न तो कथित 51 घरों का निर्माण-कार्य पूरा किया और न ही शेष राशि लौटायी जो ₹0.11 करोड़ के इं.आ.यो. निधियों के क.अ. द्वारा दुर्विनियोजन में परिणत हुआ था। असम सरकार के पी. एण्ड आ.डी. विभाग ने क.अ. के खिलाफ विभागीय प्रक्रिया (वि.प्र.) शुरू की थी जिसका अब तक कोई परिणाम नहीं आया है।	0.11
	(ii)	पी.डी., जि.ग्रा.वि.प्रा. करबी अंगलोंग द्वारा एक जाँच के दौरान संस्वीकृत 133 घरों के संबंध में यह देखा गया था कि (क) 60 इं.आ.यो. घरों का निर्माण ही नहीं हुआ (₹0.20 करोड़) (21 घरों के अधूरे निर्माण के अलावा), (ख) 12 कल्पित लाभार्थियों को भुगतान (₹0.04 करोड़) एवं (ग) 15 लाभार्थियों को घरों का दुहरा आबंटन (₹0.05 करोड़) हुआ था जो हावड़ा घाट ब्लॉक में निम्नतम ₹0.29 करोड़ के स्पष्ट दुर्विनियोजन में प्रतिफलित हुआ।	0.29
	(iii)	कनिष्ठ अभियंता (लाभार्थियों के साथ संयुक्त खाता धारक) ने तीन ग्रा.पं. (लोंगजुप, निज-कामपुर एवं कोंड़ली) में 64 इं.आ.यो. घरों के निर्माण हेतु जारी ₹0.30 करोड़ में से ₹0.15 करोड़ का दुर्विनियोजन 2008-09 से 2011-12 के दौरान किया था। ब्लॉ.वि.अ., कथियाटली (नगांव जिला) द्वारा दायर प्र.सू.रि. के अनुसार सभी घर अधूरे पड़े थे। क.अ. लेखापरीक्षा कि तिथि तक फरार था।	0.15
	(iv)	ब्लॉ.वि.अ., मंडिया ब्लॉक (बर्पेता जिला) ने सितम्बर 2009 से फरवरी 2010 के दौरान 12 सेल्फ चैक जारी करके बैंक से आहरित कर (283 घरों के प्रति आबंटित एवं जारी) ₹1.09 करोड़ का दुर्विनियोजन किया था। सारी धनराशि न तो रोकड़ बही में दर्ज की गयी थी और न ही उसे लाभार्थियों को जारी किया गया था। अभिलेखों के अनुसार, ब्लॉ.वि.अ. ने मार्च 2008	1.75

		से सितम्बर 2009 के दौरान विकास ब्लॉक जलेश्वर (गोआलपाड़ा जिला) में अपनी पूर्व नियुक्ति के दौरान ₹0.66 करोड़ का दुर्विनियोजन भी किया था। मामला राज्य सी.आई.डी. के पास जाँच के अधीन है। बलॉ.वि.अ. का दिसंबर 2012 में देहांत हो गया था जिससे धनराशि की वसूली का कोई उपाय नहीं रहा। यह वित्तीय प्रबंधन में नियंत्रण की अनुपस्थिति दर्शाता है।	
	(v)	ग्रा.पं. आजाद (बर्पेता जिले के अंतर्गत ब्लॉक गुमाफुलबाड़ी) में ₹0.04 करोड़ (नौ लाभार्थियों के संबंध में) का 2010-11 के दौरान ग्रा.पं. अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा दुर्विनियोजन हुआ था। पूरी धनराशि बैंक से निकाली गयी थी परंतु वह न तो लाभार्थियों तक उनके घरों के निर्माण के लिए पहुँची और न ही ग्रा.पं. के रोकड़ बही में दर्ज की गयी। इस संबंध में बर्पेता पुलिस स्टेशन मे ग्रा.पं. के अध्यक्ष एवं सचिव के विरूद्ध निधियों के कपटपूर्ण आहरण के लिए एक प्राथमिकी दायर (दिसंबर 2010) की गयी थी। पुलिस जाँच का परिणाम लेखापरीक्षा की तिथि तक प्रतीक्षित था।	0.04
	(vi)	ग्रा.पं. राजापाड़ा (कामरूप जिले के अंतर्गत चयनी बरदुआर ब्लॉक) के सचिव ने 56 घरों के निर्माण हेतु मार्च 2008 में जारी ₹0.14 करोड़ का दुर्विनियोजन किया था क्योंकि कोई घर नहीं बना था। 42 घरों के लिए ₹0.09 करोड़ भी जारी किये गये थे, जिसमें से केवल चार घरों का प्लिंथ स्तर तक ही निर्माण हुआ था और शेष घरों के लिए छड़, सीमेंट एवं सी.जी.आई. चादरें जैसी कुछ सामग्री यद्यपि अधिप्राप्त की गयी थी, निर्माण शुरु नहीं हुए थे और सामग्रियां बुरी स्थिति में पड़ी हुई थीं। ग्रा.पं. सचिव को ब्लॉ.वि.अ. द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट के अनुसार दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। मु.का.अ., जिला परिषद ने उनके विरूद्ध आरोपों का मसौदा तैयार किया (अगस्त 2009) और ग्रा.पं. सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आरोपों के निर्मित मसौदे के अनुसार, ग्रा.पं. सचिव को ₹0.08 करोड़ की दूसरी राशि भी प्रदान की गयी थी परंतु उनके द्वारा एक भी घर का निर्माण नहीं कराया गया था।	0.22
	(vii)	बोकाजन ब्लॉक के तहत सरूपथार निर्वाचन-क्षेत्र के करबी अंगलोंग स्वायत्त परिषद के एक सदस्य की शिकायत के आधार पर, प्र.नि., जि.ग्रा.वि.प्रा., करबी अंगलोंग एवं ब्लॉ.वि.अ., ब्लॉक बोकाजन ने जाँच करवाई और पाया कि कनिष्ठ अभियंता द्वारा 77 लाभार्थियों को इं.आ.यो. के लाभ से वंचित करते हुए ₹0.14 करोड़ का दुर्विनियोजन किया गया था।	0.14

	(viii)	करबी अंगलोंग जिले के लोंगसोमेपी ब्लॉक में 2011-12 के दौरान 11 नकली लाभार्थियों के प्रति ₹0.05 करोड़ का दुर्विनियोजन हुआ था जिसमें से छः लाभार्थी सरकारी सेवा में थे।	0.05
	(ix)	करबी अंगलोंग जिले के लुंबाजोंग ब्लॉक में ₹0.04 करोड़ राशि के निधियों का दुर्विनियोजन हुआ था। प्र.नि., जि.ग्रा.वि.प्रा. ने 16 मामलों (57 मामलों में से) के संबंध में की गई कराये गये जाँच में पाया कि आठ घरों का निर्माण नहीं हुआ था, दो लाभार्थियों का अता-पता नहीं था और दो लाभार्थियों के घर अधूरे पड़े थे।	0.04
	(x)	करबी अंगलोंग जिले के रोंगखंग ब्लॉक में छः ग्राम प्रधानों की सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, छः क.अ. द्वारा 2003-08 के दौरान 100 अस्तित्व-हीन लाभार्थियों को निधियों के हस्तांतरण के प्रति ₹0.25 करोड़ का दुर्विनियोजन हुआ था। प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी थी। राष्ट्रीय स्तर के निरीक्षक ने जिला/ब्लॉक का मामले की जाँच हेतु दौरा (फरवरी 2010) किया; हालाँकि जाँच दो वर्ष पूर्व हुई थी परंतु जिला प्राधिकरण/राज्य सरकार को कोई जाँच रिपोर्ट अग्रेषित नहीं की गयी थी।	0.25
	(xi)	सिलचर ब्लॉक (कचार जिला) में प्रत्यक्ष सत्यापन एवं आगे जाँच (जून से अगस्त 2012) में पाया गया कि ब्लॉ.वि.अ. ने क.अ. के प्रश्रय में ₹0.64 करोड़ का दुर्विनियोजन किया था। 2005-06 के दौरान निर्मित होने वाले 327 घरों के प्रति, 165 घरों का अता-पता नहीं था और 86 घर अधूरे थे। पी. एवं आर.डी. असम के आयुक्त ने ब्लॉ.वि.अ. को सेवा से हटा दिया और ब्लॉ.वि.अ. एवं क.अ. दोनों में से प्रत्येक से दुर्विनियोजन राशि के 50 प्रतिशत की वसूली का आदेश दिया। लेखापरीक्षा की तिथि तक वसूली नहीं हो सकी थी।	0.64
	(xii)	ब्लॉ.वि.अ. द्वारा जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत पुरहुरिया (करीमगंज जिले के अंतर्गत उत्तरी करीमगंज ब्लॉक) के सचिव ने 33 लाभार्थियों के लिए वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 हेतु जारी ₹0.08 करोड़ में से जनवरी 2010 में ₹0.07 करोड़ का दुर्विनियोजन किया था। संबंधित ग्रा.पं. सचिव को पी. एंण्ड आर.डी., असम के आयुक्त द्वारा जून 2010 में निलंबन के अंतर्गत रखा गया था। विभागीय प्रक्रिया का परिणाम प्रतीक्षित था।	0.07

	(xiii)	लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे के अंत शेष एवं 31 मार्च 2009 को प्रा.नि., जि.ग्रा.वि.प्रा., शिवसागर द्वारा अनुरक्षित रोकड़ बही के मध्य ₹0.03 करोड़ का अंतर था। विसंगतियों पर सुमेलन करते समय नजर गयी और लेखापरीक्षकों ने व्यतिरेकी राशि को उचंत खाते में रखा था। बैंक ने सूचना दी थी कि व्यतिरे की राशि को 2001-02 के दौरान 16 चैकों के माध्यम से आहरित किया गया था। प्र.नि., जि.ग्रा.वि.प्रा., शिवसागर ने ऐसे चैकों को जारी करने इनकार किया और बैंक के खिलाफ पी. एण्ड आर.डी., असम के आयुक्त को सूचित करते हुए प्राथमिकी (2005 में) दायर कर दी। पुलिस जाँच का परिणाम लेखापरीक्षा की तिथि तक प्रतीक्षित था।	0.03
2.	बिहार (xiv)	हसनपुर ब्लॉक (समस्तीपुर जिला) में 2006-07 के दौरान नाजिर एवं ब्लॉ.वि.अ. द्वारा ₹1.03 करोड़ की राशि का दुर्विनियोजन हुआ था। एक प्राथमिकी दर्ज (अगस्त 2011) की गयी थी और दुर्विनियोजित धनराशि की वसूली हेतु प्रमाणपत्र मामला[4] दायर किया गया था। लेखापरीक्षा की तिथि तक धनराशि की वसूली होनी शेष है।	1.03
3.	झारखंड़ (xv)	मधुपुर ब्लॉक (देवघर जिला) में ₹0.10 करोड़ की राशि मार्च एवं जून 2009 के मध्य इलाहाबाद बैंक, सपतर से सहायक, मुख्य सहायक एवं ब्लॉक विकास अधिकारी के जाली हस्ताक्षर दर्ज करके कपटपूर्ण तरीके से निकाली गयी थी। बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत 164 परामर्शों में से, 36 परामर्श जाली पाये गये थे। 98 लाभार्थियों एवं इलाहाबाद बैंक के तीन कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। ब्लॉ.वि.अ. ने सूचित किया था कि वसूली कर ली गयी है और मामला सिविल न्यायालय, मधुपुर में निर्णय हेतु लंबित है।	0.10
		संदिग्ध दुर्विनियोजन के मामले	
1.	असम (i)	हावड़ाघाट एवं बोकाजन (करबी अंगलोंग जिला) ब्लॉकों के ब्लॉ.वि.अ. के रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2009-10, 2011-12 एवं 2012-13 हेतु 137 लाभार्थियों से संबंधित ₹0.54 करोड़ और वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2011-12 हेतु 79 लाभार्थियों से संबंधित ₹0.24 करोड़ लाभार्थियों के वैयक्तिक खाते में हस्तांतरित किये गये थे। ब्लॉकों द्वारा निर्मित और व्यक्तिगत खातों के साथ बैंक को प्रेषित परामर्श पर्चियों के पुनर्निरीक्षण से, हालाँकि, उजागर हुआ कि कथित राशि वास्तव में क्रमशः 68 एवं 39	0.40

[4]सर्टीफिकेट मामले का आशय राज्य लोक मांग वसूली अधिनियम, 1940 के अंतर्गत वसूली मामला से है।

		बैंक खातों को हस्तांतरित की गयी थीं। बैंक खातों की संख्या से लाभार्थियों की संख्या में अंतर अनेक मामलों में एक ही बैंक खाते के प्रति दो या अधिक लाभार्थियों को प्रदर्शित करने के कारण होनी पायी गयी थी। शेष कल्पित 69 एवं 40 खाताओं से संबंधित क्रमशः ₹0.28 करोड़ एवं ₹0.12 करोड़ की जारी की गयी धनराशि का कोई पता नहीं लगाया जा सका और इस प्रकार उक्त राशि के दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता है।	
2.	जम्मू एवं कश्मीर (ii)	ब्लॉ.वि.अ., माई ने वर्ष 2010-11 हेतु रोकड़ बही में ₹0.29 करोड़ व्यय के रूप में, किसी समर्थक प्रविष्टियों एवं जिन्हें धनराशि का भुगतान किया गया उन अभिकरणों के विवरण के बिना दिखाया था। इसके अलावा मार्च 2010 में ₹0.15 करोड़ खजाने से राज्य अंश के रूप में इं.आ.यो. के लिए आहरित किया गया था जिसे रोकड़ बही में हस्तांतरित किया हुआ दिखाया गया था। सहायक अभिलेखों के साथ रोकड़ बही को लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अभाव में, ₹0.44 करोड़ के दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता।	0.44
3.	झारखंड़ (iii)	जि.ग्रा.वि.प्रा., गढ़वा के सनदी लेखाकार रिपोर्ट के अनुसार रू. 0.04 करोड़ की राशि 2008-09 से पूर्व, मंडल अधिकारी (मं.अ.), नगरूटारी को उपलब्ध करायी गयी थी। धनराशि को जि.ग्रा.वि.प्रा. के लेखापरीक्षित रिपोर्ट के अंत शेष में 2011-12 तक दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा में इस बाबत प्रश्न उठाने पर, संबंधित मंडल अधिकारी ने उपरोक्त निधि की प्रत्यक्ष उपलब्धता के बारे में अज्ञान प्रकट किया, जबकि धनराशि रोकड़ बही में दर्शायी गयी थी। हालाँकि लेखापरीक्षा को मं.अ. द्वारा प्रदान किये गये इं.आ.यो. के बैंक खाते कथित राशि को नहीं दर्शाते थे। अतः ₹0.04 करोड़ के दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता है।	0.04
	(iv)	दो जि.ग्रा.वि.प्रा. (रांची एवं गढ़वा) के 2008-09 की अवधि के दौरान सनदी लेखाकार रिपोर्ट के अनुसार, 31.03.2009 को प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में अंत शेष (अं.शे.) ₹14.36 करोड़ था। तथापि, जि.ग्रा.वि.प्रा. के 2009-10 की अवधि हेतु लेखापरीक्षित प्रतिवेदन में 01.04.2009 को लिये गये अंत शेष में वही धनराशि घट गयी थी और ₹0.14 करोड़ के अंतर के साथ ₹14.22 करोड़ दर्शायी गयी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि रांची जि.ग्रा.वि.प्रा. में ₹0.06 करोड़ मंडल अधिकारी मुरहु के नाम पर था जिसे अं.शे. से 2009-10 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा रिपोर्ट बनाते वक्त बगैर कारण बताए हटा दिया गया था। जि.ग्रा.वि.प्रा. गढ़वा में ₹0.06 करोड़ की धनराशि को हटाने से संबंधित कोई कारण नहीं दिया गया था। इसलिए ₹0.14 करोड़ के दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता है।	0.14

	(v)	दो ब्लॉकों (पलामू जिले का विश्रामपुर एवं रांची जिला का रातू) में 10 अभिकरणों को जून 2008 एवं सितंबर 2012 के मध्य शौचालय, धुआँरहित चूल्हा (उन्नत चूल्हा) एवं इं.आ.यो. लोगों के लिए पत्थर की प्लेटों के निर्माण हेतु ₹0.21 करोड़ प्रदान किया गया था। तथापि, निर्माण-कार्य के वास्तविक कार्यान्वयन के समर्थन में लेखापरीक्षा को अभिकरणों के चयन, वाउचर, संबंधित फाइलों से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था। परिणामस्वरुप, ₹0.21 करोड़ के दुर्विनियोजन को खारिज नहीं किया जा सकता है।	0.21
	(vi)	मधुपुर ब्लॉक में, ₹0.10 करोड़ की धनराशि दो निजी अभिकरणों को फरवरी 2009 एवं जनवरी 2011 के मध्य इं.आ.यो. लोगों के लिए पत्थर की प्लेट और उन्नत चुल्हा खरीदने के लिए अदा की गयी थी। हालाँकि, निर्माण कार्य के वास्तविक कार्यान्वयन के समर्थन में लेखापरीक्षा को अभिकरणों के चयन, वाउचरों, संबंधित फाइलों से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। परिणामस्वरुप ₹0.10 करोड़ के दुर्विनियोजन को खारिज नहीं किया जा सकता है।	0.10
4.	कर्नाटक (vii)	गुलबर्गा में तीन ग्रा.पं. और रामनगर जिले में एक ग्रा.पं. में, ₹0.02 करोड़ की धनराशि सेल्फ चैक से मई 2008 से मार्च 2011 तक लाभार्थियों के खातों में जमा करने की बजाए आहरित की गयी थी। अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि धनराशि लाभार्थियों को संवितरित की गयी थी या नहीं।	0.02
	(viii)	ग्रा.पं. हरोकोप्पा और तालुक चन्नपटन रामनगर जिले के पंचायत विकास अधिकारियों ने व्यवसाय सेवा सहकारी संघ नियमिता बैंक, सोगला में बचत बैंक खाते वाले इं.आ.यो. लाभार्थियों को ₹2.15 करोड़ की धनराशि के चैक जारी (2008-13) किये थे। हालाँकि ग्रा.पं. के पास बुकों से यह देखा गया था कि ₹28.93 लाख राशि के चैक लाभार्थियों को देने की बजाय चन्नपटन के पोस्ट मास्टर के खाते में जमा किये गये थे। डाक घर के अभिलेखों के पुनः जाँच करने पर, यह पाया गया था कि 38 इं.आ.यो. लाभार्थियों से संबंधित ₹9.10 लाख की राशि चार व्यक्तियों को दी गयी थी जो इं.आ.यो. लाभार्थी नहीं थे। ₹19.83 लाख की शेष राशि के लिए पोस्ट मास्टर से ब्यौरे प्रतीक्षित थे। इस प्रकार, योग्य लाभार्थियों को धनराशि प्रदान करने का मामला संदेहजनक था और इन लेन-देनों में दुर्विनियोजन की आशंका थी।	0.09

5.	मणिपुर (ix)	लेखापरीक्षा ने 5,865 वास्तविक अदाता प्राप्तियों (वा.दे.प्रा.) की जाँच की थी जिसके माध्यम से 3,921 व्यक्तियों को ₹9.21 करोड़ अदा किया गया था और इनकी अनुमोदित लाभार्थी सूची के साथ तुलना की गयी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹2.86 करोड़ प्राप्त करने वाले 1,124 आदाताओं को अनुमोदित इं.आ.यो. लाभार्थी सूची में प्रदर्शित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में यह पाया गया था कि पाँच लाभार्थियों, जिन्हें ₹0.02 करोड़ की धनराशि (अभिलेखों के अनुसार) जारी की गयी थी, ने बताया कि उन्होंने इं.आ.यो. से कोई सहायता प्राप्त नहीं की थी। आगे, चार ब्लॉकों (ककचिंग, सैकोट, तदुबी एवं थौबल) में, 21 लाभार्थियों, जिन्हें ₹7.64 लाख संस्वीकृत हुआ था, उनका संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में पता नहीं लगाया जा सका।	2.86
	(x)	जि.ग्रा.वि.प्रा. इंफाल पूर्व ने 2009-13 के दौरान तीन संस्थाओं से ₹3.09 करोड़ के सी.जी.आई. चादरों के 9,961 गट्ठरों का केन्द्रीकृत प्रापण किया था। संस्थाओं को पूरी राशि अग्रिम में आपूर्ति करने के लिए किसी समय-सीमा के निर्धारण के बगैर कर दिया गया था। सामग्री प्राप्ति के मॉनीटरिंग, हेतु एवं लाभार्थियों के मुद्दों की निगरानी हेतु स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, ये सी.जी.आई. चादरें जिन्हें जारी की गयी थीं उन लाभार्थियों की सूची भी उपलब्ध नहीं थी। आगे, 2009-10 एवं 2011-12 के दौरान, 4,060 गट्ठरों की आवश्यकता के प्रति, जि.ग्रा.वि.प्रा. ने 8,126 गट्ठरों का प्रापण किया था। अतः ₹1.23 करोड़ मूल्य के सी.जी.आई. चादरों के 4,066 गट्ठरों का अतिरिक्त प्रापण हुआ था। अतिरिक्त प्रापण के बावजूद, संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में यह देखा गया था कि 192 लाभार्थियों ने उत्तर दिया कि उन्होंने कोई सी.जी.आई. चादर प्राप्त नहीं की थी। अतः, वास्तविक आवश्यकता से अतिरिक्तता में अधिप्राप्त मात्राओं के दुर्विनियोजन को खारिज नहीं किया जा सकता। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के जवाब में, विभाग 9,961 सी.जी.आई. चादरों के गट्ठरों में से केवल 4,137 गट्ठरों का ही हिसाब कर सका, जिन्हें 1,277 लाभार्थियों को जारी किया गया था। यह भी देखा गया था कि 509 लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में ₹1.02 करोड़ के भुगतान के प्रति, उनके द्वारा प्राप्त की गयी सी.जी.आई. चादरें केवल ₹66.17 लाख के मूल्य की थीं।	1.23

6.	नागालैण्ड (xi)	11 जिलों के वार्षिक लेखे के अनुसार, रू. 214.21 करोड़ का व्यय सी.जी.आई. चादरों के प्रापण पर 2008-13 के दौरान किया गया था। तथापि, वास्तविक सी.जी.आई. चादर प्रापण अभिलेखों (जिले-वार आबंटन, आपूर्ति आदेशों, गोदाम प्राप्तियां आदि) की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इस अवधि में विभाग ने केवल ₹211.77 करोड़ के कुल लागत पर 4,38,268 गट्ठरों का प्रापण किया था। इस प्रकार व्यय के आंकडे की अधिकबयानी हुई थी जो ₹2.37 करोड़ के संदिग्ध दुर्विनियोजन को दर्शाता है।	2.37
7.	ओडिशा (xii)	बरगांव ब्लॉक में वर्ष 2008-09 हेतु, ₹0.11 करोड़ की कुल राशि स्टॉक एवं भण्डार (ए.सी. चादरों, रिजों एवं एम.एस. रॉड) हेतु अदा की गयी थी, जो ब्लॉ.वि.अ. बरगांव द्वारा इं.आ.यो. निधियों से 2007-08 (₹0.03 करोड़) एवं 2008-09 (₹0.08 करोड़) के दौरान सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के बगैर अधिप्राप्त की गई थी। बलॉ.वि.अ. सामग्री के उपयोग के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे।	0.11
8.	पंजाब (xiii)	बी.डी.पी.ओ. अउर (जिला नवांशहर) ने ₹0.01 करोड़ (20 जुलाई एवं 09 अगस्त 2011 के मध्य) इं.आ.यो. के पाँच लाभार्थियों को तीन धारक एवं दो खाता आदाता चैक जारी करके संवितरित किया था। बी.डी.पी.ओ. अउर ने न तो इन लेन-देनों को रोकड़ बही में प्रविष्ट किया और न ही भुगतान के समर्थन में वाउचर/वास्तविक अदाता प्राप्तियां लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी।	0.01
9.	उत्तर प्रदेश (xiv)	देवरिया जिले में यह देखा गया था कि ₹1.63 करोड़ की धनराशि के 2008-10 में ब्लॉक भागलपुर के 1858 लाभार्थियो को दूसरी किस्तों के भुगतान हेतु जि.ग्रा.वि.प्रा. द्वारा इं.आ.यो. निधि से तैयार 31 बैंकरो बैंकों को लाभार्थियों के खाते में जमा करने के लिए ब्लॉ.वि.अ. को भेज दिया गया था। परंतु लाभार्थियों में से किसी के खाते में पैसा जमा नहीं किया गया था और उन्हीं लाभार्थियों के लिए वर्तमान ब्लॉ.वि.अ. द्वारा नये मांग प्रस्तुत किये गये थे। संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में यह देखा गया था कि घर पूरे नहीं बनाये गये थे और केवल लिंटल स्तर तक ही बनाये गये थे। जि.ग्रा.वि.प्रा. ने लाभार्थी खाते में दूसरी किस्त के वास्तविक जमा को सुनिश्चित नहीं किया जबकि, जिले ने इन घरों को प्रगति रिपोर्टों में पूरा किया गया दिखाया था। अतः ₹1.63 करोड़ की धनराशि के दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता।	1.63

	(xv)	बदाऊं जिले में 2008-09 हेतु तुलन-पत्रों में दर्शायी गयी रोकड़ बही के अनुसार शेष ₹0.11 करोड़ थे। तथापि, बैंक पास बुकों के अनुसार शेष शून्य थे और दो बैंक खातों को स्थायी रूप से बंद नहीं किया गया था। जिले द्वारा अंतरों को लेखापरीक्षा की तिथि तक सुमेलित नहीं किया गया था। निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता।	0.11
	(a).	संदिग्ध दुर्विनियोजन के मामले **(15)**	**9.76**
	(b).	दुर्विनियोजन के पुष्ट मामले **(15)**	**4.91**
		कुल मामले **(30)**	**14.67**

अनुबंध-5.8

गैर-कथित आधार पर सहायता का भुगतान

(पैरा 5.17.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	लाभार्थियों	के दौरान भुगतान	अदा राशि (₹ करोड़ में)
1.	असम	3	7		4777	2008-12	21.40
2.	बिहार	10	30		66300	2008-10	72.94
3.	झारखंड	1	1		13	2009-10	0.04
4.	मध्य प्रदेश	1	6		545	2010-12	2.45
5.	महाराष्ट्र	1	1	2	3	2008-11	0.02
6.	ओडिशा	1	2	12	131	2008-12	0.58
7.	पंजाब	1	1	8	602	2010-12	2.71
8.	राजस्थान	2	1		1128	2008-11	2.51
9.	तमिलनाडु	1	1	13	85	2009-10	0.31
10.	उत्तर प्रदेश	5			1273	2008-11	4.52
11.	पश्चिम बंगाल	1	1	1	15	2008-10	0.05
	कुल	**32**			**74, 872**		**107.53**

अनुबंध-5.9.1

लाभार्थियों को सहायता के भुगतान में विलंब

(पैरा 5.17.2 के संदर्भ में)

क्र.स.	राज्य/सं.शा.क्षे.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	लाभार्थी	के दौरान भुगतान	अदा राशि (₹करोड़ में)	विलंब के दिन
1.	असम	4	6			2008-13		14 से 523
2.	गोवा	1				2011-12	1.42	240
3.	गुजरात	1	2			2008-13	4.22	37 से 291
4.	ओडिशा	5	6	26	350	2008-13	0.53	30 से 1140
5.	राजस्थान	2			4330	2008-09 एवं 2010-2013	9.51	21 से 300
6.	तमिलनाडु	1	14		6830	2011-12	3.65	365 से 730
	कुल	**14**						

अनुबंध-5.9.2

दूसरी किस्त का गैर-भुगतान

(पैराग्राफ 5.17.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	लाभार्थियों	के दौरान भुगतान	पहली किस्त की अदा राशि (₹लाख में)
1.	हरियाणा	6	13		1174	2008-13	287.65
2.	जम्मू एवं कश्मीर	6	12		1,903	2008-13	386.88
2.	उत्तर प्रदेश	4			9,896	2009-13	-
3.	पश्चिम बंगाल	1	4	15	65	-	11.00
	कुल	**17**			**13,038**	**-**	

अनुबंध-5.10

लाभार्थियों को सहायता का कम भुगतान

(पैरा 5.17.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पा.	लाभार्थी	के दौरान भुगतान	कम भुगतान की राशि (₹ करोड़ में)
1.	असम	3	43		15542	2008-09 एवं 2010-11	16.32
2.	गुजरात	2	4		514	2008-13	0.54
3.	जम्मू एवं कश्मीर	6	11	-	2944	2008-13	1.32
4.	पंजाब	1	1	1	43	2010-11	0.04
5.	तमिलनाडु	1			2327		0.81
6.	उत्तराखण्ड	1	2	17	43	2010-11	0.04
	कुल	**16**			**21,413**		**19.07**

अनुबंध-5.11

नगद/धारक चैक/सेल्फ चैक में किये गये भुगतान

(पैरा 5.17.5 के संदर्भ में)

क्र.स.	राज्य/सं.शा.क्षे.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	लाभार्थी	के दौरान भुगतान	राशि (₹करोड़ में)	भुगतान का माध्यम
1.	गुजरात	2	3		7,821	2008-13	6.80	व्यक्तिगत चैक
2.	झारखण्ड	1	1		529	2008-10	0.67	धारक चैक
3.	मणिपुर	4	8	58	521	2008-13	1.76	नगद
4.	मेघालय	2	4	40	-	2008-11	5.95	नगद
		4	8	74	-	2008-12	13.61	धारक चैक
5.	पंजाब	1	2	8	93	2010-13	0.18	धारक/सेल्फ चैक
	कुल	**12**			**8,964**		**28.97**	

अनुबंध-5.12

2008-09 के दौरान दुबारा/अतिरिक्त भुगतान

(पैरा 5.17.6 के संदर्भ में)

क्र.स.	राज्य	जिला	ब्लॉक	मामलों की संख्या	के दौरान भुगतान	राशि (₹लाख में)	टिप्पणी
1.	बिहार	3	7	28	2008-13	9.72	दुहरा भुगतान
2.	जम्मू एवं कश्मीर	5	7	20		5.60	दुहरा भगुतान
		6	11	3764	2008-13	695.63	नये निर्माण के लिए देय वित्तीय सहायता उन लाभार्थियों को दी गयी जिनके पास सर्वेक्षण के अनुसार कच्चे घर थे। वे केवल उन्नयन हेतु सहायता के लिए ही पात्र थे। तथापि, उन्हें नये घरों के निर्माण हेतु सहायता दी गयी थी। अत: उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान की गयी थी।
3.	राजस्थान	2	3	21	2008-10	4.76	35 लाभार्थियों को किये गये 11.56 लाख के दुहरे भुगतान में से, 6.80 लाख 35 लाभार्थियों से वसूल लिया गया था।
	कुल	**11**		**3,833**		**715.71**	

अनुबंध 6.1

बीरभूम जिला परिषद पश्चिम बंगाल की अभिसरण स्थिति

(पैराग्राफ 6.3 के संदर्भ में)

वर्ष	निर्मित मकानों की संख्या	डी.आर.आई. के अंतर्गत उठाए गए लाभ की संख्या	निर्मित स्वच्छ शौचालय की संख्या	निर्मित बिना धुंए के चुल्हों की संख्या	रा.गां.ग्रा.वि.यो; के अंतर्गत आवर्त्त मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जहाँ किचन गार्डन शुरू किए गए	जी.बी.नि. की योजना के अंतर्गत नामांकित मामलों की संख्या			स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नामांकित मामलों की संख्या		एस.एच.जी. के अंतर्गत प्राप्त सदस्यता की संख्या	मनरेगस के अंतर्गत जारी किए गए जॉब कार्ड की संख्या	लाभार्थियों की जमीन पर मनरेगस के अंतर्गत शुरू किए गए निर्माण कार्यकेे मामलों की संख्या
							जनश्री	आम आदमी	अन्य	अरोग्य	अन्य			
2008-09	3,933	0	1,826	1,025	0	15	0	0	0	0	0	182	957	67
2009-10	9,400	296	5,360	2,545	0	120	0	0	0	0	0	1,918	4,639	216
2010-11	9,478	171	6,192	1,840	676	157	0	330	15	20	776	2,494	7,005	1,359
2011-12	8,428	0	4,989	1,345	452	159	0	305	566	30	1,601	2,326	5,158	1,879
2012-13	10,659	0	5,083	2,799	870	0	0	216	0	1,165	0	0	0	0
कुल	41,898	467	23,450	9,554	1,998	451	0	851	581	1,215	2,377	6,920	17,759	3,521
अभिसरण की प्रतिशतता		1.11	55.97	22.80	4.77	1.08	0	2.03	1.39	2.90	5.67	16.52	42.39	8.40

अनुबंध-7.1

विभिन्न राज्यों में मा.प्र.रि./आवाससाफ्ट में अंतर दर्शाती विवरणी

(पैराग्राफ 7.2.1 के संदर्भ में)

(a) **(i)** आवाससाफ्ट तथा मा.प्र.रि. के बीच विसंगतियों को दर्शाती विवरणी (झारखण्ड)

निम्न से प्राप्त सूचना	विवरण	वर्ष	आवाससाफ्ट	मा.प्र.रि.
राज्य	संस्वीकृत घर	2012-13	85,848	62,829

(ii) झारखण्ड के छः चयनित जिलों में आवाशाफ्ट तथा मा.प्र.रि. के बीच विसंगतियों को दर्शाती विवरणी:

मा.प्र.नि. के अनुसार			आवाशाफ्ट के अनुसार			अंतर		
संस्वीकृत घर	पूर्ण किए घर	अपूर्ण घर	संस्वीकृत घर	पूर्ण किए घर	अपूर्ण घर	संस्वीकृत घर	पूर्ण किए घर	अपूर्ण घर
37,142	15,780	26,948	31,062	1,560	30,044	6,080	14,220	3,096

(iii) राजस्थान के सात चयनित जिलों में आवाशाफ्ट तथा मा.प्र.रि. के बीच विसंगतियों को दर्शाती विवरणी

वर्ष	संस्वीकृत घर	वर्ष के दौरान संस्वीकृत में से पूर्ण किए गए घर	वर्ष के अंत में निर्माणाधीन घर
	नए निर्माण कार्य	नए निर्माण कार्य	नए निर्माण कार्य
2011-12	1,120	10,842	18,622
2012-13	111	12,766	16,845

(ब) कर्नाटक में, लेखापरीक्षा ने 2008-09 से 2010-11 की अवधि हेतु मा.प्र.रि. में सूचित व्यय तथा मंत्रालय को सूचित उपयोग प्रमाणपत्रों (उ.प्र.) में ₹189.20 करोड़ का अंतर पाया। वर्ष 2011-12 हेतु ₹14.63 करोड़ का नकारात्मक अंतर भी था। मा.प्र.रि. में आंकड़ों को अधिक बताए जाने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण आवास निगम लिमिटेड के (रा.गां.आ.नि.लि.) द्वारा स्पष्ट नहीं किए किए थे।

(ग) ओडिशा में, गंजम जिले में मा.प्र.रि. आंकड़ों तथा कार्य रजिस्टर से प्राप्ति पूर्ण किए घरों की वास्तविक संख्या में 1586 घरों का अंतर था। चूंकि चयनित ब्लॉकों द्वारा चरण-वार प्रगति तथा परिवारों की स्थिति का कोई अभिलेख नहीं रखा गया था। इसलिए वर्ष के दौरान पूर्ण किए घरों की यथार्थ संख्या उनके पास उपलब्ध नही थी। तथापि, कुछ प्राधिकारियों को अच्छी प्रगति दर्शाने हेतु ब्लॉक स्तर पर आंकड़ों को भौतिक उपलब्धि के लिए बढ़ाया गया था। इसके अतिरिक्त, जिला गंजम के चयनित जिलों में चयनित लाभार्थियों को कार्य आदेश जारी करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर भौतिक उपलब्धि के अनुरूप लक्ष्यों की प्राप्ति में अंतर पाए गए थे।

(d) उत्तराखण्ड़ मे, लेखापरीक्षा ने पाया कि मा.प्र.प्र. में वर्णित वार्षिक व्यय उस वर्ष के लिए कैश बुक के अनुसार भारित वास्तविक व्यय के अनुसार मेल नहीं खाया जिसका विवरण नीचे अंकित किया गया है-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शुरूआती शेष	आबंटन		निर्गत[1]		विविध प्राप्रियां[2]	कुल उपलब्ध निधि (कु.उ.नि)	व्यय	अंत शेष (कु.उ.नि. की प्रतिशतता)	मा.प्र.प्र. के अनुसार वर्णित व्यय	अंतर
		केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य						
2008-09	9.21	25.23	8.41	36.20	12.67	1.67	59.76	30.95	28.81(48.21)	28.62	-0.19
2009-10	28.81	37.97	12.66	37.93	10.21	3.37	80.31	59.96	20.35(25.34)	56.76	36.41
2010-11	20.35	43.40	14.47	37.65	15.33	2.39	75.72	58.14	17.58(23.22)	59.68	42.10
2011-12	17.58	42.40	14.13	42.72	14.45	1.40	76.15	62.03	14.12(18.54)	55.11	40.99
2012-13	14.12	46.98	15.66	27.96	9.52	11.02	62.62	52.45	10.17(16.24)	41.07	30.90
Total		195.98	65.33	182.46	62.18	19.85		263.53	91.03	241.24	150.04

स्रोत: चयनित डी.आर.डी.ए.एस.

इसके अतिरिक्त, तीन चयनित जिलों जैसे हरिद्वार, देहरादुन, टेहरी में मंत्रालय को भेजे गए प्रतिवेदनों एंव ब्योरे वास्तविक तथ्य पर आधारित नहीं थे जैसा कि इं.आ.यो. घरों को लाभार्थियों को अंतिम किस्तों के भुगतान के पश्चात् समाप्त हुआ वर्णित किया गया था तथा न ही वास्तविक समाप्ति पर आधारित था।

[1] 2008-13 के दौरान सम्मिलित अतिरिक्त निर्गतें (सामान्य आबंटन के प्रति अन्य)

[2] प्रखंड़ो/लाभार्थियों से वापस निधियाँ, अन्य जिलों से विपथित तथा उपार्जित ब्याज।

अनुबंध-7.2

निगरानी मॉनीटरिंग समितियां

(पैराग्राफ 7.2.2 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य	रा.स्त.नि.मॉ.स.			जि.स्त.नि.मॉ.स.		
		होने वाली बैठकों की संख्या	वास्तविक रूप में हुई बैठकों की संख्या	मंत्रालय के नामांकित व्यक्ति की भागीदारी	चयनित जिलों की संख्या	होने वाली बैठकों की संख्या	वास्तविक रूप में हुई बैठकों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	20	5	नहीं	2	40	12
2.	अरूणाचल प्रदेश	20	4	नहीं	4	80	8
3.	असम	20	2	नहीं	8	160	50
4.	बिहार	20	4	नहीं	10	200	40
5.	छत्तीसगढ़	20	10	नहीं	5	100	डाटा उपलब्ध नहीं
6.	गोवा	20	शून्य	शून्य	2	40	12
7.	गुजरात	20	2	हाँ	7	140	74
8.	हरियाणा	20	3	नहीं	6	120	40
9.	हिमाचल प्रदेश	20	1	शून्य	4	80	20
10.	जम्मू एवं कश्मीर	20	शून्य	शून्य	6	120	21
11.	झारखण्ड	12	2	शून्य	6	120	23
12.	कर्नाटक	20	7	चार बैठकों में उपस्थित	8	160	47

क्र. सं.	राज्य	रा.स्त.नि.मॉ.स.			जि.स्त.नि.मॉ.स.		
		होने वाली बैठकों की संख्या	वास्तविक रूप में हुई बैठकों की संख्या	मंत्रालय के नामांकित व्यक्ति की भागीदारी	चयनित जिलों की संख्या	होने वाली बैठकों की संख्या	वास्तविक रूप में हुई बैठकों की संख्या
13.	केरल	20	2	नहीं	4	80	32
14.	मध्य प्रदेश	20	4	नहीं	13	260	107
15.	महाराष्ट्र	12	5	चार बैठकों में उपस्थित	8	160	49
16.	मणिपुर	10	4	नहीं	4	80	22
17.	मेघालय	20	5	नहीं	4	80	33
18.	मिजोरम	20	4	एक बैठक	2	40	24
19.	नागालैण्ड	20	5	नहीं	3	60	8
20.	ओडिशा	20	4	हाँ	8	160	57
21.	पंजाब	20	1	हाँ	6	120	28
22.	राजस्थान	20	1	नहीं	8	160	53
23.	तमिलनाडु	20	4	हाँ	8	160	19
24.	त्रिपुरा	20	8	नहीं	2	40	21
25.	उत्तराखण्ड	20	3	नहीं	5	100	18
26.	उत्तर प्रदेश	20	2	केवल एक बैठक	15	300	46
27.	पश्चिम बंगाल	20	तिथि उपलब्ध नहीं	-	5	100	49
28.	अं.एवं नि. द्वीपसूह	20	8	नहीं	2	40	12

अनुबंध-7.3

शिकायत मामलों में रा.स्त.मा. की रिपोर्टों पर कारवाई

(पैराग्राफ 7.2.2 (ii) के संदर्भ में)

असम में, जिला कर्बी एंग्लॉग के ब्लॉक रोगखांग के अंतर्गत वर्ष 2003-04 से 2007-08 से संबंधित निधियों के दुरूपयोग तथा 100 चयनित लाभार्थियों के इं.आ.यो. घरों के गैर-निर्माण के संबंध में एक निवासी की शिकायत पर मंत्रालय ने मामले की जांच करने हेतु एक रा.स्त.मा. को नियुक्त किया। रा.स्त.मा. ने इस उद्देश्य हेतु 14 से 20 दिसंबर 2010 तक जिले/ब्लॉक का दौरा किया। यद्यपि जांच दो वर्षों से अधिक पहले समाप्त हो गई थी परंतु इसके निष्कर्षों पर रिपोर्ट मई 2013 तक राज्य/जिला स्तर पर प्राप्त नहीं हुई थी।

असम में, दो चयनित जिलों (कर्बी एंग्लाँग तथा नागाँव) में लेखापरीक्षा ने पाया कि चार रा.स्त.मा. ने राज्य में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/योजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग हेतु मई 2010, मई तथा दिसम्बर 2012 में जिलों के दौरे किये थे। रा.स्त.मा. के चार दौरों में से केवल रा.स्त.मा. द्वारा स्वच्छ शौचालय हेतु अधिकतम आवृतन को सुनिश्चित करने की सिफारिश के साथ पूर्ण स्वच्छ अभियान के कार्यान्वयन पर गरीबी रेखा से नीचे (ग.रे.नी.) तथा स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची के बीच असंगति तथा निधियों के उपयोग पर अभ्युक्ति सहित निरीक्षण रिपोर्ट (नागॉव) प्रस्तुत की गई थी।

झारखण्ड में, जिला कोडरमा के ब्लॉक सदर में मुखिया तथा पंचायत सेवक द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में एक शिकायत प्राप्त (नवम्बर 2012) हुई थी। चूंकि शिकायत का निपटान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए इस मामले की जांच करने हेतु रा.स्त.मा.[3] की नियुक्ति की गई थी। रा.स्त.मा. की जाँच रिपोर्ट (मार्च 2013) में तीन आरोपो में से दो झूठें पाए गए थे, जबकि एक मामले[4] में (इसे आंशिक रूप सत्य पाया) गया था। मंत्रालय ने रा.स्त.मा. की रिपोर्ट को आर.डी.डी. (अप्रैल 2013) को प्रेषित किया तथा एक महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की। मई 2013 तक राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

मणिपुर में लेखापरीक्षा दल द्वारा दौरा किए चार चयनित जिलों में से केवल जिला सेनापती ही रा.स्त.मा. की रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सका। रा.स्त.मा. ने वहीं इ.आ.यो. के कार्यान्वयन का निर्धारण करने हेतु

---

[3] प्रबंधन अध्ययन अकादमी (प्रं.अ.अ.), लखनऊ, सांस्थनिक रा.स्त.मा.

[4] श्री किशुराम धोबी सुपुत्र स्व.बुधन धोबी पर निर्धारित योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 2012-13 के दौरान ठेकेदार ग्राम में एक आवसीय इकाई का आवंटन किए जाने का आरोप लगाया गया था। एक आवसीय इकाई पहले ही श्री किशुराम धोबी की बीबी को आवंटित की गई थी। रा.स्त.मा. ने पाया कि श्रीमती रोशनी देवी पत्नी श्री किशुराम धोबी को 2002-03 में एक आवासीय इकाई का आवंटन किया गया था जिसमें लाभार्थी ने कथित आवंटन के प्रति 19700 पाप्त किए थे।

सितम्बर 2008 में जिला सेनापती के प्रत्येक ब्लॉक तदूबी (लीराउचींग तथा मारम मथक सगेइ से गई) तथा ब्लॉक कांगपोकपी (चालवा तथा सेलसी) में दो ग्रामों को शामिल किया। लाभार्थियों से भेंट करने के अलावा रा.स्त.मा. ने प्रत्येक ब्लॉक में प्रमुख ग्रामवासियों के साथ एक आम बैठक भी की। रा.स्त.मा. के कुछ ध्यान देने योग्य निष्कर्ष थे कि केवल 57.64 प्रतिशत ग्राम प्राधिकारियों ने स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची तैयार की थी तथा प्रक्रिया पात्रता की जानकारी तथा इं.आ.यो. के अंतर्गत इकाई सहायता की राशि कम थी। सुस्पष्ट रूप से प्रतीक्षा सूची को प्रदर्शित न करने के अतिरिक्त, 2006-09 के दौरान प्रथम दो वर्षों में लाभार्थियों का चयन प्रतीक्षा सूची में से नहीं किया गया था। दौरा किए गए ग्रामों की सामाजिक न्यायिक स्थिति को दर्शाते हुए रा.स्त.मा. ने बताया कि छत बनाने हेतु प्रथम प्राथमिकता सी.जी.आई. चादर है कई ग्रामवासियोंकी पहुँच से परे है। उन्होंने इं.आ.यो. के घरों में छत बनाने हेतु थैच पौधे के स्थान पर टोकोपत्ता पौधे[5] को, थैच पौधे की तुलना में टिकाऊ तथा अग्नि प्रतिरोधी होने के कारण, उपयोग करने की सिफारिश की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.स्त. मा. की सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

[5] एक पौधा जो अरूणाचल प्रदेश तथा नागालैण्ड में छत डालने हेतु विसतृत रूप से उपयोग किया जाता है।

अनुबंध-7.4

2008-13 के दौरान चयनित जिलों में शिकायतों के निपटान की स्थिति

(पैराग्राफ 7.3.3 के संदर्भ में)

कं.सं.	राज्य	जिला/ब्लॉक/ग्रा.पं. के नाम			प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटान की गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
		जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.			
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	8	56	817	514	303
2.	बिहार	3	-	-	473	286	187
3.	झारखण्ड	4	-	-	139	0	139
4.	महाराष्ट्र	पूरे राज्य के लिए आर.डी.डी. मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत स्थिति			8	7	1
5.	ओडिशा	8	20	123	805	250	555
6.	पंजाब	सभी जिले	-	-	5*	0	5
7.	राजस्थान	2	-	-	107	77	30
8.	उत्राखण्ड	5			823	34	789
9.	पश्चिम बंगाल	2	3	-	260	259	1
	कुल				**3,437**	**1,427**	**2,010**

* वर्ष 2012-13 हेतु

अनुबंध-8.1

वासभूमि स्थल योजना प्रस्तावों का निष्फल होना

(पैराग्राफ 8.1.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/स.शा.क्षे.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	असम	आयुक्त पी. एवं आर.डी., असम, ने वासभूमि स्थल योजना के अंतर्गत 1000 ग.रे.नी. के परिवारों के संबंध में भूमि प्राप्त करने हेतु 2008-09 के दौरान ₹1.00 करोड़ की निधियां प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (फरवरी 2009)। प्रस्ताव के प्रति कोई निधियां जारी नहीं की गई थीं। उपायुक्त एवं कार्यकारी निदेशक, जि.ग्रा.वि.अ., जोरहट ने माजूली द्वीप समूह तथा जिला जोरहट में दो ब्लॉकों के 986 भूमिहीन/बेघर ग.रे.नी; के अपरदनग्रस्त परिवारों के संबंध में वासभूमि स्थल योजना (स्वच्छ शौचालय आदि के साथ निर्माण सहित) के अंतर्गत ₹9.12 करोड़ की निधियों के आवंटन हेतु पी.एवं आर.डी. विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मई 2012)। लेखापरीक्षा ने पाया कि जिले द्वारा पी. एवं आर.डी. विभाग को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्रस्तुत न किए जाने के कारण मई 2013 तक प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था।
2.	मणिपुर	जि.ग्रा.वि.अ. चूराचांदपुर ने नवम्बर 2009 ब्लॉ.वि.अ. से वासभूमि स्थल प्रदान कराने के उद्देश्य से स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची में दर्ज उन ग्रामीण ग.रे.नी. के परिवारों के ब्यौरे की मांग की जिनके पास न तो भूमि थी और न ही अपना घर स्थल था। अभिलेखों में आगे कोई कार्रवाई नहीं पाई गई।
3.	मेघालय	आठ चयनित जिलों से केवल ब्लॉक टिकरीकिला ने परियोजना निदेशक, जि.ग्रा.वि.अ., पश्चिमी गारो हिल्स को भूमिहीन ग्रामीण ग.रे.नी. के परिवारों की सूची प्रस्तुत की (जुलाई 2010)। अभिलेखों में आगे की गई कोई कार्रवाई नहीं पाई गई थी।
4.	पंजाब	मंसा ब्लॉक (जिला मंसा) में स्थायी इं.आ.यो. प्रतिक्षा सूची में से केवल चार लाभार्थियों ने वासभूमि स्थल योजना के अंतर्गत आवेदन किया था तथा इस संबंध में जे.डी.सी. कार्यालय को, सूचना, जि.प. द्वारा अक्तूबर 2012 में प्रेषित की गई थी। अभिलेखों ने आगे की गई कोई कार्रवाई नही पाई गई थी।
5.	उत्तराखण्ड	पांच चयनित जिलों में से चार चयनित जिलों में (देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, तथा यू.एस. नगर, टिहरी जिले में कोई भूमिहीन ग.रे.नी. का परिवार नहीं था) 12505[1] भूमीहीन ग.रे. ग.रे.नी. के परिवार स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची में थे।

[1] देहरादून: 339, हरिद्ववार: 146, नैनीताल: 4,573 तथा यू.एस.नगर: 7,447

		स्थलों के अधिग्रहण हेतु चार जिलों द्वारा 12,505 ग.रे.नी. के परिवारों को शामिल करते हुए कुल ₹184.19 करोड़[2] का प्रस्ताव सी.आर.डी.डी. को प्रेषित किया गया था। इसमें से सी.आर.डी.डी. द्वारा प्रति लाभार्थी 50 वर्ग मीटर भूमि की खरीद हेतु चार चयनित जिलों के 5163 भूमिहीन लाभार्थियों को शामिल करते हुए ₹23.23 करोड़ का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था (मार्च 2012) परंतु इसे सितम्बर 2013 तक भा.स. को प्रेषित नहीं किया गया था।
6.	अ. एवं नि. द्वीपसमूह	जि.ग्रा.वि.अ., एन. एवं एम. अण्डमान ने बिना भूमि वाले 135 ग.रे.नी. के परिवारों तथा अतिक्रमण के माध्यम से सरकारी भूमि पर रह रहे 536 परिवारों की सूची को निदेशालय आ.डी. को भूमि के आवंटन तथा अतिक्रमण की भूमि को नियमित करने के संबंध में लिए गए निर्णय सूचित करने का अनुरोध करते हुए प्रेषित (जुलाई 2011) किया। जि.ग्रा.वि.अ. ने भी भूमि के ऐसे टुकड़ों की पहचान की जिन्हें मंत्रालय की स्वीकृति के तहत वासभूमि स्थल योजना के अंतर्गत ग.रे.नी. के परिवारों आवंटित किया जा सकता था। तथापि, दो वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी जि.ग्रा.वि.अ. को इस संबंध में कोई निर्णय सूचित नहीं किया गया था। इस प्रकार आवश्यक स्वीकृति के आभाव में भूमि के आवंटन अथवा अतिक्रमण की भूमि को नियमित करने में कोई प्रगति नहीं की जा सकी थी।

[2] देहरादून: ₹3.61 करोड़, हरिद्वार: ₹1.17 करोड़, नैनीताल: ₹123.56 करोड़ तथा यू.एस.नगर: ₹55.85 करोड़

अनुबंध 8.2

वास भूमि स्थलों के क्रय हेतु जारी निधियां

पैराग्राफ 8.1.2(i) के संदर्भ में)

क्र.सं.	प्रस्तावित केन्द्र आवंटन (₹ करोड़ में)	राज्य	जिलों की संख्या	होम साइट की संख्या	जारी की गई निधियां (₹ करोड़ में)
2009-10					
1.	200	बिहारी	38	1,06,674	53.34
2.		कर्नाटक	11	1,08,000	54.00
3.		केरल	14	64,189	32.09
4.		सिक्किम	1	1,666	0.83
5.		राजस्थान	11	34,412	17.21
कुल			**75**	**3,14,941**	**157.47**
2010-11					
1.	300	आन्ध्र प्रदेश	22	2,04,568	102.28
2.		कर्नाटक	18	1,21,634	60.82
3.		महाराष्ट्र	33	50,000	25.00
4.		उत्तर प्रदेश	48	3,790	1.90
कुल			**121**	**3,79,992**	**190.00**
2011-12					
	500	निधियां जारी नहीं की गई थीं			
2012-13					
		निधियां जारी नहीं की गई थीं			
कुल योग	**1,000**		**196**	**6,94,933**	**347.47**

अनुबंध 8.3

वासभूमि की अप्रयुक्त निधियों का अपवर्तन

(पैराग्राफ 8.1.2 (ii) के संदर्भ में)

क.सं.	राज्य/सं.शा.झे.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1	आन्ध्र प्रदेश	लेखापरीक्षा ने पाया कि मत्रांलय ने 22 जिलों में ₹2.05 लाख वासभूमि स्थलों की खरीद हेतु ₹102.28 करोड़ (मार्च 2011) जारी किए थे। 22 जिलों[1] द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण ₹91.61 करोड़ का नियमित इं.आ.यो. के अतंर्गत देय उनके निर्गमों के प्रति फरवरी 2013 में समायोजन किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹91.61 करोड़ पर ₹7.02 करोड़ (अप्रैल 2011 से फरवरी 2-13 तक बचत खाते पर चार प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर) के ब्याज संघटक पर ध्यान नहीं दिया था।
2	बिहार	₹53.34 करोड़ के भा.स. के निर्गम (मार्च 2010) के प्रति इनमें 21 महीनों के अतंर के पश्चात दिसबंर 2011 में ₹53.34 करोड़ का अपना बराबर का अंश जारी किया। 10 चयनित जिलों में से ड़ाटा केवल जिला सुपौल में उपलब्ध था। तीन चयनित जिलों (मधुबनी, सुपौल तथा पश्चिम चंपारण) ने ₹90.60 लाख का व्यय किया था। निधियों के अनुपयोग के कारण मंत्रालय ने ₹48.21 करोड़ (2011-12 में ₹32.49 करोड़ तथा 2012-13 में ₹15.71 करोड़) को नियमित इं.आ.यो. के प्रति समायोजित किया था तथा ₹4.22 करोड़ की शेष राशि कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पड़ी थी। जिला मधुबनी के ब्लॉक जयनगर में तीन लाभार्थियों को 2007-08 में ₹72,000 (₹24,000 प्रत्येक) की इं.आ.यो. सहायता प्रदान की गई थी। चार वर्षों के बीत जाने के पश्चात, इन लाभार्थियों को फिर से वासभूमि योजना के अतंर्गत भूमि प्रदान की गई थीं जिसमें ₹30,000 (₹10,000 प्रत्येक) का व्यय शामिल था। राज्य सरकार ने निर्देश दिए (जून 2011) कि सभूमि स्थलों हेतु निधि की डी.एम. कार्यालय से ग.रे.नी. के लाभार्थियों, जिनको भूमि प्रदान की गई थी, की सूची की प्राप्ति के पश्चात विशिष्ट 'शीर्ष' को प्रतिपूर्ति की जानी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि जि.ग्रा.वि.अ. भागलपुर द्वारा ₹125.00 लाख की राशि का ऐसे लाभार्थियों की सूची प्राप्त किए बिना ए.डी.एम. भागलपुर को अंतरण किया गया था।
3	कर्नाटक	राज्य सरकार ने 10.43 लाख ग.रे.नी. परिवारों के संबंध में वासभूमि स्थल हेतु निधियाँ प्रदान करने के लिए मत्रांलय से अनुरोध किया (नवम्बर 2009)। मंत्रालय ने वासभूमि स्थलों को प्रदान करने के लिए 1,08,000 परिवारों के संबंध में 11 जिलों को ₹54 करोड़ (दिसंबर 2009) तथा 18 जिलों में 1,21,634 परिवारों के संबंध में ₹60.81 करोड़ (फरवरी 2011) वासभूमि स्थल प्रदान करने के लिए जारी किया। 2010-11 के दौरान, राज्य केवल 31,806 भूमिहीन ग्रामीण ग.रे.नी. के परिवारों को वासभूमि स्थल आवंटित कर सका। (31,751 परिवारों जिनके संबंध में राज्य द्वारा निधियाँ 2009-10 के दौरान तथा केवल 55 परिवार जिनके संबंध में निधियाँ 2010-11 के दौरान प्राप्त की गई थी)। मंत्रालय ने घरों के निर्माण हेतु केवल 31,806 परिवारों, जिनकों राज्य द्वारा भूमि आवंटित की गई थी, के संबंध में प्रोत्साहन के रूप में ₹53.67 करोड़ की अतिरिक्त

[1] अदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, कुड़प, पूर्वी गोदावरी, गुंटुर, करीम नगर, खम्माम, कृष्णा, कुरनूल, मेडक, मेहबूब नगर, नलगोण्ड़ा, नेल्लोर, नजीमाबाद, प्रकासम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विशाखापतनम, विजयानगरम, वारंगल एवं पश्चिमी गोदावरी।

क.सं.	राज्य/सं.शा.झे.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
		निधियां जारी की। राज्य में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया कि वासभूमि स्थलों को तैयार किए जाने हेतु केवल ₹121.73 करोड़ (राज्य के अंश सहित) का उपयोग किया गया था। 2010-11 तक नवीनतम प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्रों के अनुसार तैयार किए गए स्थलों का लाभार्थियों को संवितरण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि चयनित जिलों चिकमगलूर तथा धारवाड़ ने शहरी आवास योजना तथा बाढ़ पीड़ितों हेतु 2010-11 के दौरान ₹4.17 करोड़ का अपवर्तन किया था।
4	केरल	मंत्रालय ने 64,192 वासभूमि स्थलों की खरीद प्राप्त करने हेतु ₹32.09 करोड़ (14 जिलों के लिए) जारी किए (दिसबंर 2009)। चार चयनित जिलें (जिसमें 45,804 भूमिहीन परिवार थे) को 23,341 वासभूमि स्थलों की प्राप्ति हेतु ₹23.34 करोड़ (राज्य के अंश सहित) जारी किए थे तथा 2011-13 के दौरान 3,046 वासभूमि स्थलों की प्राप्ति हेतु केवल ₹3.05 करोड़ का व्यय किया था। जिला मालापूरम तथा अल्पोझा ने ₹4.57 करोड़ का नियमित इं.आ.यो. के प्रति अपवर्तन किया था। इस प्रकार, ₹17.95 करोड़ (ब्याज सहित) चार चयनित जिलों के पास अप्रयुक्त रहे।
5	महाराष्ट्र	राज्य सरकार ने 50,000 वासभूमि स्थलों के अधिग्रहण हेतु भा.स. से ₹25.00 करोड़ (2010-11) प्राप्त किए थे। राज्य ने 2011-12 में ₹5 करोड़ के अतिरिक्त अंश सहित ₹25 करोड़ के अपने अंश को संस्वीकृत किया। इस निधि मे से तीन चयनित जिलों (नांदेड़- ₹33.60 लाख, थाणे- ₹100.80 लाख भाद्रां- ₹53 लाख) ने ₹187.40 लाख प्राप्त किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि जिले नांदेड़ तथा बांद्रा ने निधियो का उपयोग नहीं किया था जबकि जिला थाणे में वासभूमि स्थल की खरीद हेतु ₹82.68 लाख का उपयोग किया था। इसके अतिरिक्त, चयनित जिलों में ग्राम, लाभार्थी का नाम, निर्गम की राशि तिथि, खरीदा गए स्थल, आदि के संबंध में विवरण अभिलेख में नहीं पाए गए थे।
6	राजस्थान	प्रस्ताव पर, 11 जिलों को ग्रामीण ग.रे.नी. को 34,412 वासभूमि स्थल प्रदान करने के प्रति ₹17.21 करोड़ जारी किए गए थे (मार्च 2011)। राज्य ने 11 जिलों को ₹17.21 करोड़ (मार्च 2011) का अपना देय अंश भी जारी किया था। राज्य ने नियमित इं.आ.यो./वासभूमि प्रोत्साहन हेतु ₹17.20 करोड़ का उपयोग करने हेतु उसको अनुमति प्रदान करने हेतु मंत्रालय से अनुरोध (मार्च 2011) किया क्योंकि भूमि की कीमत अधिक थी तथा लाभार्थी मत्रांलय द्वारा जारी इकाईं लागत से अपेक्षित भूमि क्षेत्र को खरीदने में असमर्थ थे। राज्य सरकार का तर्क सही नहीं था क्योंकि लाभार्थी को भूमि प्रदान करना राज्य सरकार (न की व्यक्तिगत लाभार्थी) का उत्तरदायित्व था तथा प्रस्ताव भेजने से पहले लाभार्थी को भूमि की खरीद प्राप्ति की लागत तथा औचित्य का निर्धारण करना चाहिए था। राज्य द्वारा नियमित इं.आ.यो. के प्रति 2012-13 तक ₹35.48 करोड़ (ब्याज सहित) की राशि का समायोजन किया गया था परंतु ₹58 लाख की शेष राशि संबधित जिलों के पास पड़ी थी जिसका जनवरी 2014 तक समायोजन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जिलों के पास अव्ययित शेष का समायोजन करते समय जिला उदयपुर छोड़कर, जिसने ₹1.10 करोड़ अनदेखा किया गया था। आगे यह पाया गया था कि ₹1.10 करोड़ के ब्याज की कुल राशि का मत्रांलय द्वारा गलत ढ़ंग से समायोजन किया गया था क्योंकि ₹1.10 करोड़ के कुल ब्याज में से ₹55 लाख जिले द्वारा राज्य के अंश पर प्राप्त किया गया था

क.सं.	राज्य/सं.शा.झे.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
7	उत्तर प्रदेश	मत्रांलय ने 2010-11 में ₹1.90 करोड़ जारी किए। राज्य सरकार ने 15 चयनित जिलों आठ को ₹18.75 लाख जारी किए (अम्बेड़कर नगर - ₹4.62 लाख, देवरिया - ₹3.85 लाख, फतेहपुर - ₹0.91 लाख, हमीरपुर - ₹2.73 लाख, कुशीनगर - ₹1.12 लाख, महाराजगंज - ₹4.76 लाख, मथुरा - ₹0.2 लाख तथा रामपुर - ₹0.56 लाख) इन जिलों ने निधियों का उपयोग नहीं किया था जिसका परिणाम निधियों के अवरोधन में हुआ। निधियों के गैर-उपयोग के पीछे मुख्य कारण वासभूमि स्थलों हेतु निर्धारित अपर्याप्त राशि, ब्लॉकों से कोई मांग न होना, आदि थे। जिला हमीरपुर तथा देवरिया ने बताया कि राशि का भा.स. द्वारा नियमित इं.आ.यो. के प्रति समायोजन किया गया था। राज्य सरकार अच्छा कार्य कर रहे जिलों में निधियों का उपयोग करने में विफल था। इसके अतिरिक्त, जिला बदायूँ ने बताया कि ₹5.10 लाख का 51 लाभार्थियों को वासभूमि स्थल हेतु संवितरण (2011-12) किया गया था परंतु लेखापरीक्षा ने पाया कि धन को ब्लॉ.वि.अ., दातागंज में बैंक खाते में रखा गया था। जिला गोंड़ा में ₹4.34 लाख की राशि वासभूमि स्थलों हेतु 2011-12 में 58 लाभार्थियों को अदा की गई थी परंतु उनको घरों के निर्माण हेतु निधियां प्रदान नहीं की गई थीं।

अनुबंध 8.4

वासभूमि प्रोत्साहन राशि

(पैराग्राफ 8.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय आवंटन (₹ करोड़ में)	जिलों की संख्या	संस्वीकृत अतिरिक्त मकान	जारी राशि (₹ करोड़ में)	नियमित इं.आ.यो. के अंतर्गत मकानों का लक्ष्य
2009-10						
1.	गुजरात	111.89	23	33,154	43.51	1,82,429
2010-11						
1.	गुजरात	61.90	18	18,342	124.80	1,26,090
2.	कर्नाटक	107.35	9	31,806	53.67	99,055
3.	मध्य प्रदेश	360.20	48	1,05,200	180.10	79,073
4.	राजस्थान	322.99	33	95,702	161.50	63,362
5.	त्रिपुरा	65.68	4	15,050	32.84	15,050
	कुल	**918.12**	**112**	**2,66,100**	**552.91**	
2011-12						
1.	छत्तीसगढ़	221.68	18	63,000	110.84	37,466
2.	झारखण्ड	21.83	1	6,000	10.91	63,477
3.	मध्य प्रदेश		47	2010-11 हेतु लक्ष्य के प्रति दूसरी किस्त	175.46	-
4.	महाराष्ट्र	18.19	1	5,000	9.09	1,51,063
5.	ओडिशा	362.26	28	99,986	181.13	1,42,082
6.	राजस्थान	68.33	25	20,247	34.17	61,894
			32	2010-11 हेतु लक्ष्य के प्रति दूसरी किस्त	161.46	-
7.	त्रिपुरा	30.87	4	7,072	15.43	14,704
			4	2010-11 हेतु लक्ष्य के प्रति दूसरी किस्त	32.85	-
8.	पश्चिम बंगाल	79.08	6	22,318	39.54	1,99,176
	कुल	**802.24**	**166**	**2,23,623**	**770.88**	

2012-13						
1.	छत्तीसगढ़		5		33.24	41,511
2.	मध्य प्रदेश		50	30,998	53.18	84,358
		184.22	48	53,360 (वन अधिकार अधिनियम)	92.11	
3.	राजस्थान	145.56	13	43,131 (पी.टी.जी.)	72.78	68,578
		85.88	5	25,447 (एफ.आर.ए.)	42.94	
4.	झारखण्ड	245.22	24	69,500	122.61	69,500
	कुल			**1,91,438**	**383.62**	
	कुल योग	**1,832.35**	**218**	**7,14,315**	**1,750.92**	

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in